VIDYA UNIVERSITY PRESS

TOUCH n PASS

सर्वश्रेष्ठ परीक्षा पथ-प्रदर्शक

B.A.
तृतीय वर्ष
(डिग्री कोर्स)
सेमेस्टर-V

भूगोल

क्षेत्रीय भूगोल

SYLLABUS

UNIT-I

Definition of Region, Evolution and objectives of regional planning, Planning practices in Ancient India.

UNIT-II

Types of Regional planning, Formal, Functional and Planning Regions.

UNIT-III

Delimitations of Region and Regional Planning.

UNIT-IV

Theories and Models for Regional Planning : Growth Pole Model of Perroux; Myrdal, Boudeville and R.P. Mishra.

UNIT-V

Sustainable Development, Concept of Development and Underdevelopment.

UNIT-VI

Efficiency-Equlity Debate : Definition, Components and Sustainability for Development.

UNIT-VII

Regional Development Indicators (Economic, Social and Environmental).

UNIT-VIII

Need for regional planning in India, Five Year Plans and Regional Planning, multi-level planning in India.

TOUCH n PASS

VIDYA UNIVERSITY PRESS

पंजीकृत कार्यालय
विद्या एम्पायर, बागपत रोड,
मेरठ, उत्तर प्रदेश (NCR) 250 002
www.vidyauniversitypress.com

© प्रकाशक

लेखन एवं सम्पादन
शोध एवं अनुसन्धान प्रकोष्ठ

मुद्रक
विद्या यूनिवर्सिटी प्रेस

TOUCH n' PASS

विषय-सूची

UNIT-I : प्रादेशिक नियोजन का विकास एवं उद्देश्य ...3
UNIT-II : प्रादेशिक योजना के प्रकार ...25
UNIT-III : प्रदेशों का परिसीमन और प्रादेशिक योजना ...45
UNIT-IV : प्रादेशिक योजना की विचारधाराएँ और मॉडल ...55
UNIT-V : सतत् आर्थिक विकास ...80
UNIT-VI : दक्षता-क्षमता डिबेट ...95
UNIT-VII : क्षेत्रीय विकास सूचक ...107
UNIT-VIII : भारत में प्रादेशिक योजना की आवश्यकता ...118

UNIT-I

प्रादेशिक नियोजन का विकास एवं उद्देश्य
Evolution and Objectives of Regional Planning

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. विश्वेश्वरैया योजना क्या है?
What is the Vishveswaryya Plan?

उत्तर यह योजना 1946 में अखिल भारतीय निर्माणक संगठन द्वारा प्रकाशित की गयी। इसका उद्देश्य जनसमुदाय के जीवन-स्तर में वृद्धि करना और देश की आर्थिक कुशलता (Skill) का विकास करना था। योजना में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण मण्डल की स्थापना की सिफारिश की गयी, जिसमें जनता के 6 और सरकार के 3 प्रतिनिधि रखने थे। योजना में एक पृथक् कृषि विभाग (Separate Agricultures at Department), जो एक मन्त्री के अधीन हो, की स्थापना करने की सिफारिश की गई।
योजना में ₹ 1,400 करोड़ व्यय करने की व्यवस्था की गयी जिसमें से उद्योग पर ₹ 790 करोड़, कृषि पर ₹ 200 करोड़, परिवहन पर ₹ 110 करोड़, शिक्षा पर ₹ 40 करोड़, स्वास्थ्य पर ₹ 40 करोड़, गृह-निर्माण पर ₹ 190 करोड़ और अन्य मदों पर ₹ 30 करोड़ व्यय करने का प्रस्ताव था।

प्र.2. विश्वेश्वरैया योजना के उद्देश्य लिखिए।
Write the objectives of Vishveswaryya Plan.

उत्तर इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार थे—

1. देश की राष्ट्रीय आय (National Income) को दुगना करना।
2. कारखानों के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास करना जिससे पुरानी कमियों को शीघ्रता से दूर किया जा सके।
3. व्यवसायों में सन्तुलन स्थापित करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
4. देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तरीकों को सही ढंग से अपनाना।
5. बड़े एवं छोटे पैमाने के उद्योगों (Industries) के विकास पर जोर डाला गया।

प्र.3. विश्वेश्वरैया योजना की कठिनाइयाँ लिखिए।
Write the difficulties of Vishveswaryya Plan.

उत्तर इस योजना के सुझाव देश के लिए महत्त्वपूर्ण होते हुए भी उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि—

1. परिस्थितियाँ देश के अनुकूल नहीं थीं।
2. उचित समंकों का अभाव रहा।
3. जनमत की उपेक्षा बनी रही।
4. योजना को कार्यान्वित करने हेतु वित्तीय साधनों (Financial Resources) का अभाव था।

प्र.4. गाँधीवादी योजना क्या है?
What is the Gandhian Plan?

उत्तर गाँधीजी ने आवश्यकताओं को कम करने एवं उच्च विचार रखने की सलाह दी थी। वास्तव में उन्होंने स्वयं कोई आर्थिक योजना का निर्माण नहीं किया था। वास्तव में यह योजना गाँधीजी के विचारों से प्रभावित होकर श्रीमन्नारायण अग्रवाल द्वारा 1944 में निर्मित की गयी थी। यह योजना सार्वजनिक कल्याण के सिद्धान्त पर आधारित थी और इसके चार अंग थे—(i) अहिंसा, (ii) श्रम को महत्त्व, (iii) सादगी (iv) मानवीय मूल्य (Human Values)। इसमें श्रम के महत्त्व और नैतिक उन्नति पर अधिक ध्यान दिया गया। गाँधीजी विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) को एवं समाज में श्रमिकों के शोषण को रोकने के पक्ष में थे। श्रम को अर्थव्यवस्था में उचित महत्त्व देने हेतु समस्त मानव समाज को लाभप्रद कार्य में लगाना गाँधीवादी योजना का मुख्य

TOUCH 'n PASS

उद्देश्य था। इसमें समाज के साधनों तथा अवसरों का समान वितरण (Equal distribution) करना भी आवश्यक बताया गया।

प्र.5. गाँधीवादी योजना के व्यय एवं वित्तीय व्यवस्था को समझाइए।
Explain the expenditure and financial system of Gandhian Plan.

उत्तर **व्यय**—इस योजना में 10 वर्ष की अवधि में ₹ 3,500 करोड़ व्यय किया जाना था।

वित्तीय व्यवस्था—गाँधीवादी योजना की वित्त व्यवस्था का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया था—आन्तरिक ऋण से ₹ 2,000 करोड़, मुद्रा प्रसार से ₹ 1,000 करोड़ और करारोपण से ₹ 500 करोड़ व्यय व्यवस्था की जानी थी। गाँधीवादी योजना में जहाँ एक ओर ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर महत्त्व दिया गया वहीं दूसरी ओर शहरों में बड़े उद्योगों की स्थापना की जानी थी। योजना वित्त-व्यवस्था में हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit Management) पर ध्यान दिया गया जो कि ₹ 1,000 करोड़ था। यह एक अच्छी योजना थी, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे कार्यान्वित न किया जा सका।

प्र.6. गाँधीवादी योजना के कोई तीन उद्देश्य लिखिए।
Write any three objectives of Gandhian Plan.

उत्तर गाँधीवादी योजना के तीन उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. **न्यूनतम आवश्यकताएँ**—देश के प्रत्येक नागरिक की, 2,600 कैलोरी वाला सन्तुलित भोजन, 20 गज कपड़ा एवं 100 वर्ग फुट निवास-स्थान की व्यवस्था करके न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
2. **ग्रामीण उत्थान**—आर्थिक पुनरुत्थान एवं आन्तरिक व्यवस्था के लिए ग्रामीण उत्थान के साथ पंचायतों की स्थापना पर जोर दिया गया।
3. **भारी उद्योग व जनोपयोगी सेवा**—इस योजना में भारी उद्योग (Heavy Industries) एवं जनोपयोगी सेवाओं को राज्य के तहत रखने का सुझाव दिया गया।

प्र.7. सर्वोदय योजना क्या है?
What is the Sarvodaya Plan?

उत्तर यह योजना मनुष्य के सर्वांगीण विकास (Overall Development)—आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक के उद्देश्य से **श्री जयप्रकाश नारायण** द्वारा 30 जनवरी, 1950 को प्रकाशित की गयी थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अहिंसात्मक, स्वायत्तशासी, शोषणविहीन सहकारी समाज की स्थापना करना था। योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि एवं इसमें होने वाले उच्चावचनों को कम करने का आयोजन किया गया था।

प्र.8. सर्वोदय योजना की कोई तीन विशेषताएँ लिखिए।
Write any three characteristics of the Sarvodaya Plan.

उत्तर 1. **सम्पत्ति व आय का वितरण**—इस योजना द्वारा आय व सम्पत्ति का समान वितरण करना था एवं आय की अधिकतम और न्यूनतम सीमा निर्धारित करना था।

2. **उद्योगों का संचालन**—वर्तमान उद्योगों का संचालन समाज को दे दिया जाये तथा वे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र या सहकारी संघ द्वारा चलाए जाएँ।
3. **भूमि से सम्बन्धित**—भूमि से सम्बन्धित अनेक समस्याओं के समाधान पर ध्यान दिया गया जैसे कि भूमि का पुनर्वितरण करना, सहकारी फर्म से सम्बन्ध जोड़ना एवं शोषण को रोकना।

प्र.9. कोलम्बो योजना को परिभाषित कीजिए।
Define the Colombo Plan.

उत्तर युद्धोपरान्त विश्व के राष्ट्रों ने यह अनुभव किया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन सम्भव बनाया जाए। अत: राष्ट्रमण्डल की राष्ट्रीय सरकारों के एक सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से एक सलाहकार समिति की स्थापना करके जनवरी 1950 में कोलम्बो योजना (Colombo Plan) का निर्माण किया गया, जिसकी अवधि 6 वर्ष रखी गयी। इस सभा में सर्वसम्मति से 1950 से 1957 तक की अवधि के लिए योजना बनाकर अपने-अपने कार्यक्रमों को पेश करने के लिए आमन्त्रित किया गया। इन समस्त योजनाओं को मिलाकर एक विशाल कार्यक्रम बनाया गया और इसके साथ तकनीकी सहकारी कार्यक्रम के चलाने की भी व्यवस्था की गयी।

TOUCH 'n PASS

प्र.10. कोलम्बो योजना के उद्देश्य बताइए।
State the objectives of Colombo Plan.

उत्तर इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का आर्थिक विकास करना,
2. जीवन-स्तर में सुधार करना (Improvement in life standard),
3. उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि बढ़ाना,
4. मुद्रा-स्फीति को रोकना आदि था। इस योजना का कुल व्यय सार्वजनिक विनियोगों में लगाना था।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. प्राचीन भारत में प्रादेशिक विचारधारा के विकास का उल्लेख कीजिए।
Explain the evolution of regional theory in ancient India.

उत्तर

प्राचीन भारत में प्रादेशिक विचारधारा का विकास
(Evolution of Regional Theory in Ancient India)

वैदिक काल (Vedic Period)—भारत के वैदिक साहित्य में अनेक प्रदेशों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में मगध देश का, जैमिनीय ब्राह्मण में विदर्भ का, शतपथ ब्राह्मण में मत्स्य देश का, गीता उपनिषद में कुरुक्षेत्र का, छान्दोग्य उपनिषद में गान्धार (सिन्धु नदी के दोनों ओर स्थित) का, छान्दोग्य उपनिषद में ही कैकेय (व्यास नदी के पास स्थित) का, उपनिषदों में उशीनर (हरिद्वार तथा कनखल), कुरु (वर्तमान में दिल्ली), काशी (वाराणसी), कोशल (अयोध्या) इत्यादि का प्रादेशिक वर्णन मिलता है।

पुराणों में समस्त पृथ्वी को 7 प्रदेशों (Land Masses) में बाँटा गया है, ये प्रदेश हैं—1. जम्बू द्वीप, 2. पुष्कर द्वीप, 3. शक द्वीप, 4. क्रौंच द्वीप, 5. प्लक्ष द्वीप, 6. कुश द्वीप एवं 7. शाल्मली द्वीप। इनमें जम्मू द्वीप को एस. एम. अली ने दक्षिण भारत से उत्तरी साइबेरिया तट तक विस्तृत मुख्य एशियाई भाग माना है।

महाकाव्य काल (Epic Period)—महाकाव्य काल के अन्तर्गत रामायण एवं महाभारत नामक दो महाकाव्यों की रचना की गयी। रामायण ग्रंथ में भारत के विभिन्न प्रदेशों का वर्णन मिलता है; जैसे—मत्स्य, कैकेय, सौराष्ट्र, कोशल, काशी, सुवीर, मगध, मिथिला, सिन्धु, अंग एवं बंग प्रदेश। रामायण काल के उपरांत महाभारत काल में भी अनेक प्रदेशों का वर्णन मिलता है। इसी काल में हस्तिनापुर राज्य था जिस पर आधिपत्य हेतु पाण्डवों एवं कौरवों के मध्य भीषण युद्ध हुआ था। इस काल में अनेक सुदृढ़ राज्यों की स्थापना हुई जिसमें मगध, मत्स्य, सिन्धु, कैकेय, सूरसेन, कम्बोज आदि प्रमुख हैं।

महाजनपद काल (Mahajanpada Period)—बौद्ध ग्रन्थ 'अंगुत्तर निकाय' एवं जैन ग्रन्थ 'भगवती सूत्र' से ज्ञात होता है कि छठी शताब्दी ई. पू. भारत में सोलह महाजनपदों का अस्तित्व था। इन महाजनपदों का नाम—काशी, कोशल, अंग, मगध, चेदि, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अवन्ति, गन्धार, कम्बोज, अश्मक, वज्जि एवं मल्ल हैं। इन 16 महाजनपदों में से चौदह में राजतंत्र एवं दो (वज्जि तथा मल्ल) में गणतन्त्र थे। अश्मक/अस्सक को छोड़कर अन्य सभी जनपद सामान्यतया उत्तर भारत में ही स्थित थे। जनपद मानव वर्गों के निवास का वह क्षेत्र या प्रदेश होता था जिसमें कोई एक गणतन्त्र राज्य या किसी राज्य की सत्ता या किसी जाति/जनजाति विशेष के संघ की बस्तियों का देश (Tribal State) हो। इस प्रकार प्रदेशों का नामकरण उनकी विशेषता के आधार पर होता था। उस समय नगर-राज्य (City-State) भी होता था, जो एक लघु प्रदेश (Micro Region) होता था; जैसे—काशी जनपद।

बुद्ध काल (Buddha Period)—बौद्धकालीन भौगोलिक वर्णन जातक-ग्रन्थों में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। उस समय के व्यापारी अन्तर-प्रादेशिक (Inter-Regional) व्यापार करते थे। 253 ईसा पूर्व में अशोक ने मौर्य साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारकों को भेजा। बौद्ध काल में महाजनपदों के अतिरिक्त दस गणराज्य—कपिलवस्तु के शाक्य, अल्लकय के वुलि, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोलिय, सुसभागिरि के भग्ग, पावा एवं कुशीनारा के मल्ल (दो), पिप्पली वन के मोरिय, मिथिला के विदेह एवं वैशाली के लिच्छिवी भी थे। बौद्ध ग्रंथों में भारत को पाँच भागों में विभाजित किया गया है—उत्तरापथ (पश्चिमोत्तर भाग), प्राची (पूर्वी भाग), अपरान्त (पश्चिमी भाग), मध्य प्रदेश एवं दक्षिणापथ। विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में व्यापारिक आधार पर भारत को दो प्रदेशों में विभाजित किया। उत्तरी प्रदेश व्यापारिक दृष्टि से दक्षिणी प्रदेश से अधिक सम्पन्न तथा महत्त्वपूर्ण था।

TOUCH 'n' PASS

प्र.2. प्राचीन यूनान, रोम एवं अन्ध युग में प्रादेशिक विचारधारा के विकास का उल्लेख कीजिए।
Explain the Evolution of regional in Ancient Greeak, Rome and Dark age.

उत्तर

प्राचीन यूनान एवं रोम में प्रादेशिक विचारधारा का विकास
(Evolution of Regional Concept in Ancient Greeak and Dark)

(अ) यूनानी भूगोलवेत्ताओं (Greeak Geographers) **का योगदान**—900 ईसा पूर्व से 300 ईसवी के मध्य यूनानी लेखों एवं कृतियों में भौगोलिक प्रादेशिक वर्णन पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। होमर के 'इलियड' एवं 'ओडिसी' नामक ग्रंथों में विभिन्न प्रदेशों का वर्णन मिलता है। हिकैटियस (Hecateaus) की प्रसिद्ध पुस्तक 'Ges-Periods' (जेस-पीरियोडस, पीरियोडस का शाब्दिक अर्थ—पृथ्वी का वर्णन होता है) जो 520 ईसा पूर्व दो खण्डों (Volumes) में प्रकाशित हुई, जिसके प्रथम खण्ड में यूरोप का और दूसरे खण्ड में एशिया का प्रादेशिक वर्णन मिलता है जिसमें अफ्रीका का वर्णन भी सम्मिलित था। उपर्युक्त योगदान के कारण हिकैटियस को 'प्रादेशिक भूगोल का जन्मदाता' माना जाता है। हिकैटियस के अलावा ग्रीक यात्री हेरोडोटस (Herodotus) महोदय (485-425 ईसा पूर्व) ने भी एशिया माइनर, यूनान, पर्शिया और नील नदी के बाढ़-मैदान का प्रादेशिक वर्णन किया जो उल्लेखनीय है।

(ब) रोमन भूगोलवेत्ताओं (Roman Geographers) **का योगदान**—स्ट्रैबो (64 ई. पू. से 20 ई. तक) एक उल्लेखनीय प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने क्षेत्रीय भिन्नताओं को स्पष्ट किया। स्ट्रौबो ने दो पुस्तकों में विश्व वर्णन, 6 पुस्तकों में एशिया का प्रादेशिक वर्णन, 8 पुस्तकों में यूरोप का प्रादेशिक वर्णन और अन्तिम पुस्तक में अफ्रीका का प्रादेशिक भौगोलिक वर्णन किया। इस प्रकार स्ट्रैबो ने भूगोल को एक प्रादेशिक विज्ञान के रूप में विकसित किया। उपरोक्त योगदान के कारण कुछ भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो को भी 'प्रादेशिक भूगोल का जन्मदाता' मानते हैं। रोमन साम्राज्य काल में जनगणना एवं कर वसूली हेतु प्रशासकों द्वारा देश को कई प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था।

अन्ध युग (Dark Age) में प्रादेशिक विचारधारा का विकास
(Evolution of Regional Concept in Dark Age)

तीसरी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी के मध्य (300 ई. से 1250 ई. तक) तक के समय को यूरोपीय इतिहास में अन्ध युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में यूरोपीय समाज पर धार्मिक मान्यताओं (Religions beliets) का प्रभाव इतना गहरा एवं व्यापक था कि उस समय ज्ञान-विज्ञान के विकास की सारी सम्भावनाएँ लगभग समाप्त हो गयी थीं। पहले से यूनान एवं रोम में संचित भौगोलिक ज्ञान भी विलुप्त होने लगा। अतएव इस समय यूरोप में प्रादेशिक विचारधारा का विकास पूरी तरह अवरुद्ध (Hindered) था।

इस अवधि में प्रादेशिक विकास में अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान उल्लेखनीय है। सुलेमान और अबू जैद ने भारत, हिन्द महासागरीय द्वीपों तथा चीन का प्रादेशिक भूगोल लिखा। इब्रे खुरदादबेह ने अरब, ईराक, फारस, हिन्देशियाई द्वीपों, मलाया, चीन, जापान और कोरिया का भौगोलिक (Geographical) वर्णन किया।

प्र.3. पुनर्जागरण काल में प्रादेशिक विचारधारा के विकास को लिखिए।
Write the evolution of regional concept in renaissance period.

उत्तर

पुनर्जागरण काल में प्रादेशिक विचारधारा का विकास
(Evolution Period of Regional Concept in Renaissance)

बारहवीं शताब्दी के मध्य से सत्रहवीं शताब्दी के मध्य (1250 ई. से 1650 ई. तक) का समय 'खोज एवं यात्राओं का युग' था। इस समय के भौगोलिक साहित्य में प्रादेशिक वर्णन अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। मार्को पोलो के लेखों में पूर्वी यूरोप के देशों रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, चीन, मलेशिया, श्रीलंका, भारत, ईरान इत्यादि का प्रादेशिक भौगोलिक वर्णन मिलता है। इस क्षेत्र में कोलम्बस (Christopher Columbus), वास्को-डिगामा (Vasco-Da-Gama), फर्डीनैण्ड मैगलन (Ferdinand Magellan) और अमेरिगो वेसपुस्सी (Amerigo Vespucci) जिसके नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ा। और यह नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

जर्मन विद्वान सेबैस्टियन मुस्टर (Sebastian Muster) पुनर्जागरण काल का प्रथम लेखक था जिसने 120 सहयोगी लेखकों के योगदान से सन् 1544 ई. में छः खण्डों में 'विश्व भूगोल' (*Cosmography Universal*) नामक पुस्तक प्रकाशित की। पुस्तक

TOUCH 'n PASS

के सभी खण्डों का प्रकाशन 18 वर्षों में सम्पन्न हुआ। पुस्तक के प्रथम खण्ड में समकालीन विश्व भूगोल का संक्षिप्त परिचय है और शेष पाँच खण्डों में विश्व के विभिन्न प्रदेशों का विस्तृत भौगोलिक वर्णन है।

जर्मन लेखक फिलिप क्लूवेरियस (Philip Cluverius) 1615 से 1622 (मृत्यु-पर्यन्त) ई. तक भूगोल सम्बन्धी लेखन कार्य करता रहा। उसने 'विश्व भूगोल का परिचय' (An Introduction to Universal Geography) नामक ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा जो छः खण्डों में 1616 ई. से लेकर 1624 ई. तक प्रकाशित हुई। इसका अन्तिम (छठा) अंक उसकी मृत्यु (1622 ई.) के बाद 1624 ई. प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम खण्ड में पृथ्वी का सामान्य विवरण और शेष पाँच खण्डों में यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और अन्य प्रदेशों का भौगोलिक विवरण दिया गया है।

17वीं शताब्दी के महान जर्मन भूगोलवेत्ता बर्नहार्ड वारेनियस (Bernhard Varenius, 1622-1650 A.D.) का ग्रन्थ 'ज्योग्राफिया जेनरलिस' (Georaphia Generalis) 1650 ई. में दो भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 'क्रमबद्ध भूगोल' (Systematic Geography) तथा दूसरा भाग विशिष्ट या प्रादेशिक भूगोल (Special or Regional Geography) था। इस प्रकार वारेनियस प्रथम भूगोलवेत्ता था जिसने क्रमबद्ध भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल के द्विभाजन (Dichotomy) की नींव रखी थी। इन्होंने बताया कि सामान्य भूगोल में विषय के सिद्धान्तों और नियमों की और प्रादेशिक भूगोल में विश्व के देशों एवं विभिन्न प्रदेशों के विशिष्ट स्वरूपों का वर्णन किया जाता है। वारेनियस ने प्रादेशिक भूगोल में मानवीय पक्ष पर विशेष बल दिया।

वारेनियस प्रथम भूगोलवेत्ता था जिसने बताया कि पृथ्वी पर अधिकतम तापमान भूमध्यरेखीय पेटी में नहीं वरन अयन रेखाओं (कर्क एवं मकर रेखाओं) के समीप स्थित मरुस्थलीय भागों में पाया जाता है। इस प्रकार वारेनियस को सत्रहवीं शताब्दी तक का श्रेष्ठतम् भूगोलवेत्ता माना जाता है।

प्र.4. प्रादेशिक नियोजन के विकास-क्रम का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
Briefly mention the evolution of regional planning.

उत्तर

प्रादेशिक नियोजन का विकास-क्रम
(Evolution of Regional Planning)

सर्वप्रथम 'प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना' (The Concept of Regional Planning) को ब्रिटिश (स्कॉटलैण्ड) विद्वान एवं नगर नियोजक पैट्रिक गेडीस (Patrick Geddes, 1854-1932) द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने 1915 ई. में प्रकाशित अपनी मौलिक पुस्तक *'Cities in Evolution : An Introduction to Town Planning Movement and the Study of Civics'* में प्रादेशिक नियोजन के व्यापक दर्शन को विकसित करना शुरु किया था। पैट्रिक गेडीस सन् 1915 से लेकर 1925 ई. तक भारत में रहे और इस दौरान उन्होंने भारत के कम-से-कम 18 नगरों पर ' विस्तृत नगर नियोजन प्रतिवेदन' (Exhaustive Town Planning Reports) की शृंखला तैयार की। पैट्रिक गेडीस 1919 से 1925 तक 'बॉम्बे विश्वविद्यालय' के समाजशास्त्र व राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यरत रहे। उन्होंने 'Bombay Town Planning Act-1915' के अन्तर्गत नगर नियोजन के अर्थ को स्पष्ट किया। उपर्युक्त योगदानों के कारण इनको **'प्रादेशिक नियोजन का पिता'** (Father of Regional Planning) कहा जाता है।

'प्रादेशिक नियोजन' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान बेन्टन मैकाय (Benton Mackaye) द्वारा 1927 ई. में किया गया। इन्होंने 1928 ई. में प्रकाशित अपनी पुस्तक *'The New Exploration : A Philosophy of Regional Planning'* (नया अन्वेषण-प्रादेशिक नियोजन का दर्शनशास्त्र) के माध्यम से प्रादेशिक नियोजन विषय की दार्शनिक पृष्ठभूमि रखी। इस पुस्तक में इन्होंने आर्थिक विकास की अंधाधुंध प्रक्रिया में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्राकृतिक सीमाओं के उल्लंघन से उत्पन्न दुष्परिणामों के प्रति सचेत करने का प्रयास किया। बेन्टन मैकाय ने प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में व्यापक कार्य किया है इसलिए कुछ विद्वान बेन्टन मैकाय को भी 'प्रादेशिक नियोजन का पिता' मानते हैं। प्रादेशिक नियोजन के दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक पक्ष में मैकाय से लेकर आज तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, किन्तु 1920 के दशक में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित भूमि उपयोग उपागम पर आधारित इसके विषय क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र (Field of Action) की तुलना में आज के प्रादेशिक नियोजन की विषय क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ है।

प्रादेशिक नियोजन एक व्यावहारिक विज्ञान (Applied Science) है, जिसका विकास एक अन्तर्विषयक (Interdisciplinary) विषय के रूप में 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में शुरू हुआ, यद्यपि इसके पूर्व एडम स्मिथ (1723-1790 ई.) द्वारा 1776 ई. में लिखित पुस्तक *'The Wealth of Nations'* में दिए गए विकास सम्बन्धी अवधारणा से यूरोपीय समाज अत्यधिक उत्पादन के दौर में उत्पादन एवं श्रम के असन्तोष (Resentment of Labour) का सामना कर चुका था, जिसमें असमानता,

बेरोजगारी, संसाधनों का ह्रास आदि दुष्परिणाम यूरोपीय समाज में आ चुके। 19वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में मानव के आर्थिक कार्यों को नियोजित करने की बात सोची जाने लगी। अनेक अर्थशास्त्रियों, राजनीतिशास्त्रियों आदि ने इस दिशा में कार्य करना आरम्भ किया। आरम्भ में यह एक विषय के रूप में न होकर अर्थशास्त्र की एक शाखा के रूप में था, जिसका अधिकतम उपयोग राज्यसत्ताओं द्वारा किया जाता था। विभिन्न देशों में राज्यसत्ता अपने शासन के स्थायित्व के लिए ही अर्थतन्त्र, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों को नियोजित करती थी। राष्ट्रीय आय में अत्यधिक वृद्धि की पूँजीवादी विकास संकल्पना के दुष्परिणामों ने मार्क्स एवं एंजिल्स (Karl Marx and Engels) के रूप में समाजवादी चिन्तकों को जन्म दिया। मार्क्स ने उत्पादन और श्रम के अन्तर्सम्बन्धों की ऐतिहासिक व्याख्या करके इन सम्बन्धों के पुनर्गठन को प्रतिपादित किया। सम्भवत: नियोजन का संकल्पनात्मक प्रारम्भ तभी से हुआ।

प्र.5. जन-योजना का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए।

Explain the people's plan in short.

उत्तर

जन-योजना
(People's Plan)

अप्रैल 1944 में साम्यवादी (Communist) दल के नेता **श्री एम. एन. राय** द्वारा जन-योजना प्रकाशित की गयी। इसमें साम्यवादी विचारों (Communist Thoughts) की प्रधानता रही, क्योंकि इसमें श्रमिकों के हितों को विशेष स्थान दिया गया। इस योजना में साम्यवादी सिद्धान्तों के लक्षणों का समन्वय किया गया था और नियोजकों ने योजना के कार्यक्रमों को श्रमिकों के दृष्टिकोण से बनाने का प्रयास किया था। इस योजना के तीन प्रमुख सिद्धान्त हैं—

1. लाभ व्यवस्था पर राज्य को कठोर नियन्त्रण रखना चाहिए।
2. उत्पादन विनिमय के लिए न होकर उपभोग (Consumption) हेतु किया जाना चाहिए।
3. लाभ हेतु व्यवस्था पर आधारित अर्थव्यवस्था समाज के हितों के विरुद्ध मानी गयी है। इस योजना की विशेषताएँ निम्नलिखित थीं—

(अ) **मूल तत्त्व**—योजना में भूमि के राष्ट्रीयकरण, सहकारी कृषि, लाभ की प्रवृत्ति पर रोक, कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि, व्यवसाय के सम्बन्ध में कठोर नीति, लोकतन्त्रीय राज्य की स्थापना, नि:शुल्क शिक्षा, आवश्यकताओं की व्यवस्था, ग्रामीण ऋणग्रस्तता की 75% तक समाप्ति एवं बड़े कुटीर उद्योगों के विकास पर विशेष महत्त्व दिया गया।

(ब) **जन-योजना का व्यय**—यह योजना दस-वर्षीय थी जिस पर ₹ 15,000 करोड़ इस प्रकार व्यय करने थे, जिसमें से उद्योग पर ₹ 5,600 करोड़, गृह-निर्माण पर ₹ 3,150 करोड़, कृषि पर ₹ 2,950 करोड़, परिवहन पर ₹ 1,500 करोड़ शिक्षा पर ₹ 1,040 करोड़ और स्वास्थ्य पर ₹ 760 व्यय किये जाने थे।

(स) **वित्त व्यवस्था**—इस योजना में प्रस्तावित ₹ 15,000 करोड़ परिव्यय की व्यवस्था निम्नलिखित स्रोतों से की जानी थी—कृषि आय से ₹ 10,816 करोड़, औद्योगिक आय से ₹ 2,834 करोड़, प्रारंभिक अर्थव्यवस्था से ₹ 810 करोड़, पॉण्ड पावना से ₹ 450 करोड़ और भूमि के राष्ट्रीयकरण से ₹ 90 करोड़।

इस 10 वर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं की शीघ्रातिशीघ्र पूर्ति करना था, निजी लाभ को समाप्त करके, सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) में उद्योगों की स्थापना करके, आय की असमानता (Disparity) को दूर करके रोजगार एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना था।

प्र.6. जन-योजना की प्रमुख बातों को लिखिए।

Write the salient features of people's plan.

उत्तर

योजना की प्रमुख बातें
(Salient Features of People's Plan)

इस योजना की प्रमुख बातें निम्न थीं—

1. **औद्योगिक क्षेत्र**—योजना में उपभोग-प्रधान उद्योगों के विकास पर अधिक महत्त्व दिया गया। योजना में उद्योगों के विकास पर ₹ 5,600 करोड़ व्यय होना था, जिसमें से उपभोग-प्रधान उद्योगों पर ₹ 3,000 करोड़ व आधारभूत उद्योगों (Fundamental Industries) के विकास पर ₹ 2,600 करोड़ व्यय करने का कार्यक्रम बनाया गया।

TOUCH 'n PASS

2. **कृषि क्षेत्र**—इसमें कृषि भूमि को अधिक उपयोगी बनाने के प्रयास किए गए। इसी प्रकार सिंचाई के साधनों के विकास पर 400% से वृद्धि करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। कृषि कार्य पर कुल मिलाकर ₹ 2,950 करोड़ व्यय करने का प्रावधान था, जिसमें से ₹ 2,795 करोड़ अनावर्तक व्यय के रूप में तथा ₹ 155 करोड़ आवर्तक व्यय के रूप में थे।
3. **परिवहन एवं संवहन**—इस पर ₹ 1,500 करोड़ व्यय करने का प्रावधान रखा गया, जिसमें से जहाजरानी के विकास पर ₹ 155 करोड़ व्यय करने थे। इस योजना में रेलों में 38,400 किलोमीटर से और सड़कों में 7,20,000 किलोमीटर से वृद्धि करने का प्रावधान (Provision) रखा गया।
4. **अन्य व्यय**—इसमें शिक्षा पर ₹ 1,040 करोड़, गृह व्यवस्था पर ₹ 3,150 करोड़ व स्वास्थ्य पर ₹ 760 करोड़ व्यय करने का प्रावधान रखा गया।

आलोचना (Criticism)

इस योजना की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है—

1. **कृषि पर अधिक बल**—इस योजना में कृषि के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया और इससे सम्बन्धित उद्योगों के विकास को भुला दिया गया।
2. **कुटीर उद्योगों की अवहेलना**—योजना में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि देश की आवश्यकता को देखते हुए कुटीर उद्योगों के विकास पर महत्त्व देना आवश्यक था।
3. **सम्बन्धित उद्योगों पर ध्यान का अभाव**-योजना में कृषि से सम्बन्धित अन्य उद्योगों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप कृषि योजनाओं को कार्यान्वित करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
4. **कृषि आय महत्त्वाकांक्षी**—योजना में कृषि से प्राप्त होने वाली वित्तीय आय को काफी बढ़ाकर दिखाया गया, जो कि व्यवहार में सम्भव नहीं थी।

अनुमान था कि योजना के पूर्ण होने पर औद्योगिक उत्पादन में 600%, कृषि उत्पादन में 400% से वृद्धि होगी। इस योजना को पूर्णरूप से कार्यान्वित करने पर जनता के जीवन-स्तर पर चार गुने से वृद्धि हो जाने की सम्भावना थी, लेकिन आर्थिक एवं अन्य कठिनाइयों के कारण इस योजना को कार्यान्वित न किया जा सका।

प्र.7. गाँधीवादी योजना की प्रमुख बातें और आलोचनाओं का उल्लेख कीजिए।
Explain the salient features and criticism of the Gandhian plan.

उत्तर

योजना की प्रमुख बातें
(Salient Features of the Plan)

इस योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं—

1. **कृषि विकास**—इस योजना में अनावर्तक एवं आवर्तक व्यय दोनों को मिलाकर, ₹ 1,215 करोड़ व्यय का प्रावधान रखा गया। इस योजना में कृषि का सर्वांगीण विकास (Overall Development) करके खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इस योजना का उद्देश्य सहकारी कृषि एवं भूमि का ऐच्छिक एकीकरण करके जमींदारी और रैयतवारी को समाप्त करके ग्रामवादी व बन्दोबस्त को कार्यान्वित करना था। भूमि वितरण की समस्त व्यवस्था को ग्राम पंचायत के तहत लेना स्वीकार किया गया और लगान वसूली के लिए व्यक्ति के स्थान पर पंचायतों को उत्तरदायी बनाया गया। पंचायतों से कृषकों को सम्बद्ध करना भी इस योजना का उद्देश्य था। इसी प्रकार सिंचाई की शक्ति को दुगना, भूमि का राष्ट्रीयकरण, भूमि कटाव पर रोक, अन्वेषण, कृषि फॉर्म की स्थापना, भूमि सुधार, साख-सुविधाओं में वृद्धि करके ग्रामीण ऋणग्रस्तता (Rural Debtness) को समाप्त करने के कार्यक्रम निर्धारित किए गए।
2. **आधारभूत उद्योग धन्धे**—इन उद्योगों में वन, जल, रक्षा सम्बन्धी, मशीन, उपकरण, बड़े रसायन व इन्जीनियरिंग उद्योगों को शामिल किया गया। इन उद्योगों का संचालन सरकार के द्वारा होगा और निजी साहसियों के उद्योगों पर भी सरकार का पूर्ण नियन्त्रण बना रहेगा। वृहत् उद्योगों (Heavy Industries) को इस ढंग से नियमित रूप से संचालित करना था कि ये गृह उद्योगों से प्रतियोगिता करने के स्थान पर गृह उद्योगों के विकास में सहायक हों। बड़े उद्योगों का विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) आर्थिक, सामाजिक और सैनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया गया था।

TOUCH 'n PASS

3. **ग्रामीण उद्योगों का विकास**—योजना में ग्रामीण उद्योगों के विकास के विशेष कार्यक्रम निर्धारित किए गए। ग्रामीण उद्योगों के विकास को सहायता देने के उद्देश्य से सहकारी समितियों (Cooperative Societies) को कम ब्याज पर ऋण देने, संरक्षण प्रदान करने, यान्त्रिक व आर्थिक सहायता आदि देने की उचित व्यवस्था की गयी।

आलोचनाएँ (Criticism)

इस योजना की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित थीं—

1. **नागरिक एवं ग्रामीण जीवन में सामंजस्य का अभाव**—इस योजना में ग्रामीण एवं नागरिक जीवन में समन्वय का अभाव पाया गया।
2. **अपर्याप्त मुद्रा**—योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को प्रधानता दी गयी, लेकिन मुद्रा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गयी जिससे कृषि क्षेत्र के निर्धारित लक्ष्यों (Targets) को प्राप्त करना कठिन था।
3. **हीनार्थ प्रबन्धन**—योजना की वित्तीय व्यवस्था का 1/3 भाग हीनार्थ प्रबन्धन (Deficitmangement) द्वारा प्राप्त करना था, जिससे मुद्रा प्रसार के भय बने रहे जिस पर किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण न होने से अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा।
4. **आत्मप्रतिरोध का मार्ग**—योजना में पूँजीवाद के दोषों को दूर करने के लिए आर्थिक साधनों एवं क्रियाओं पर शासकीय नियन्त्रण न करके आत्मप्रतिरोध का मार्ग बताया गया जो कि व्यावहारिक नहीं था।
5. **आदर्शवादी योजना**—योजना में आदर्श बातों पर अधिक ध्यान देने से यह योजना केवल आदर्शवादी योजना बनकर रह गयी और व्यवहार में इसे उपयोग न किया जा सका, जिससे योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो गया।

प्र.8. कोलम्बो योजना के व्यय, लाभ एवं भारत की प्रगति का उल्लेख कीजिए।
Describe the expenditure, advantage of colombo plan and progress of India.

उत्तर कोलम्बो योजना के व्यय—इस योजना में 1,868 मिलियन पॉण्ड विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर व्यय करने थे। भारत के लिए ₹ 23,337 मिलियन की व्यवस्था की गयी थी।

कोलम्बो योजना से लाभ—इस योजना से भारत ही नहीं वरन् विश्व के अनेक राष्ट्र लाभान्वित हुए और उनकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए योजना के विकास कार्यक्रम बनाए गए। कोलम्बो योजना से समस्त राष्ट्रों को जो लाभ प्राप्त हुए वे निम्न प्रकार हैं—

1. **प्रेम व सद्भावना**—इस योजना से सदस्य राष्ट्रों में प्रेम व सद्भावना में वृद्धि हुई है।
2. **तकनीकी सहायता**—इस योजना में तकनीकी सहायता का कार्यक्रम भी शामिल किया गया था, जिससे अविकसित राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्राप्त होने की सुविधा बनी रही।
3. **योजना के प्रति विश्वास**—इस योजना की सफलता से प्रभावित होकर कुछ सदस्य राष्ट्रों में नियोजन के प्रति उत्साह व विश्वास उत्पन्न हो गया।
4. **आर्थिक प्रयासों में तीव्रता**—इस योजना के निर्माण में विनिमय कार्यक्रमों एवं तकनीकी ज्ञान के कारण विभिन्न राष्ट्रों को आर्थिक प्रयासों में तीव्रता लाने में काफी सहायता प्राप्त हुई।
5. **भारत को लाभ**—कोलम्बो योजना से भारत को अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुए।
6. **जीवन-स्तर में वृद्धि**—सदस्य राष्ट्रों को इस योजना की सहायता से जनता के जीवन-स्तर में वृद्धि करने में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई।
7. **अविकसित राष्ट्रों को लाभ**—इस योजना की सहायता से अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक विकास करने के लिए विकसित राष्ट्रों से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई और उन्होंने आर्थिक प्रगति की।

कोलम्बो योजना से भारत की प्रगति—कोलम्बो योजना से भारत के आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और आर्थिक प्रगति के सम्बन्ध में निम्न तथ्य रखे जा सकते हैं—

1. **कीमतों में वृद्धि**—योजना के आरम्भ में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो जाने से लागत-व्ययों में काफी वृद्धि हो गयी, जिससे सामान्य सन्तुलन प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुई।
2. **प्राकृतिक प्रकोप के वर्णन का अभाव**—इस योजना में प्राकृतिक प्रकोपों एवं सूखे के विरुद्ध कोई व्यवस्था न होने से भारत को भारी खाद्यान्न आयात करने से व्यापार सन्तुलन में कमी हो गयी।
3. **व्यापार सन्तुलन**—इस योजना के निर्माण के समय व्यापार सन्तुलन (Trade Balance) में घाटे का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वास्तव में यह सन्तुलन आधिक्य में रहा।

TOUCH 'n PASS

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. आधुनिक काल में प्रादेशिक विचारधारा के विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए।

Describe the evolution of regional concept in modern age.

उत्तर

आधुनिक काल में प्रादेशिक विचारधारा का विकास (Evolution of Regional Concept in Modern Age)

अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक भूगोलवेत्ता प्राकृतिक प्रदेशों की उपयोगिता से अनभिज्ञ थे। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक प्रादेशिक भूगोल का स्वरूप विकसित हो चुका था। आधुनिक काल में प्रादेशिक विचारधारा का विकास का वर्णन निम्नलिखित है—

(अ) जर्मनी में प्रादेशिक विचारधारा का विकास (Evolution of Regional Concept in Germany)

उन्नीसवीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ता वॉन हम्बोल्ट (1769-1859 ई.) प्रथम प्राकृतिक भूगोलवेत्ता (Geologist) थे, जिसने मानव जीवन पर प्राकृतिक प्रदेशों के प्रभाव का वर्णन किया था। हम्बोल्ट (Humboldt) का ग्रन्थ 'कॉसमॉस' (Cosmos) विश्व भूगोल 5 खण्डों और 'एशिया सेन्ट्रल' (Asia Centrale) प्रादेशिक भूगोल 2 खण्डों में प्रकाशित हुआ। आगे चलकर जर्मन भूगोलवत्ताओं ने प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया।

कार्ल रिटर (1779-1859 ई.) द्वारा प्रकाशित 'अर्डकुण्डे' से 'प्रादेशिक भूगोल का प्रारम्भ' माना जाता है। यह एक भौगोलिक ग्रंथमाला है। रिटर ने भूगोल के लिए जर्मन में 'अर्डकुण्डे' शब्द का प्रयोग किया था। अर्डकुण्डे के प्रथम दो खण्ड क्रमश: 1817 एवं 1818 में प्रकाशित हुए थे। प्रथम खण्ड में अफ्रीका महाद्वीप एवं द्वितीय खण्ड में एशिया महाद्वीप का भौगोलिक वर्णन किया गया था। 1817 से 1859 तक अर्डकुण्डे के कुल 19 खण्ड प्रकाशित हुए, लेकिन उन सभी खण्डों में अफ्रीका एवं एशिया के भूगोल का ही वर्णन किया गया था। रिट्टर ने प्रदेशों के निर्धारण के लिए राजनीतिक सीमा का परित्याग किया एवं प्राकृतिक सीमाओं को अपनाया और प्रादेशिक अध्ययन के लिए 'लाण्डेरकुण्डे' (Lander Kunde) शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक प्रदेश। रिटर ने सर्वप्रथम छोटे-छोटे प्रदेशों का अध्ययन किया फिर उनको मिलाकर एक बड़े प्रदेश के रूप में अध्ययन किया।

सर्वप्रथम जर्मन भूगोलवेत्ता **रिचथोफेन** (1833-1905 ई.) ने 1883 ई. में आधुनिक भूगोल में प्रादेशिक और क्षेत्रीय स्तर पर पृथ्वी के परिवर्तनशील स्वरूप के अध्ययन के लिए उसे लघु क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजन की पद्धति प्रतिपादित की थी। इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रादेशिक अध्ययन के लिए 'Chorology' शब्द दिया। इनकी मौलिक विचारधारा भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नता से सम्बन्धित थी। इन्होंने भूगोल को क्षेत्रवर्णनी विज्ञान (Chorological Science) बताया था। रिचथोफेन का मानना था कि सम्पूर्ण पृथ्वी का तल एक है, लेकिन उसको छोटे-छोटे क्षेत्रों व प्रदेशों में बाँटकर अध्ययन करना आवश्यक है। इसीलिए रिचथोफेन ने विश्व को वृहद् प्रदेशों व वृहद् प्रदेशों को छोटे-छोटे प्रदेशों में विभक्त किया जिनका नाम घटते क्रम में निम्न है—Erdteile—पृथ्वी के मुख्य विभाग, Lander-मुख्य प्रदेश, Land schaften—लघु प्रदेश एवं Ortlickkeiten—स्थानीय। इस प्रकार एक क्रम में समग्र पृथ्वी तल का वृहद् से लघु स्तर पर विभाजन प्रस्तुत किया।

भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक पद्धति के विकास में **अल्फ्रेड हेटनर** (1859-1941 ई.) का महत्त्वपूर्ण योगदान है। हेटनर रिचथोफेन के सहयोगी और शिष्य थे। भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय परिदृष्टि की प्रेरणा उन्हें रिचथोफेन से ही प्राप्त हुई थी। भौगोलिक चिन्तन की समीक्षा करते हुए हेटनर ने जोर देकर कहा कि भूगोल मूलत: पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूगोल भूतल की क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता (Areal Variability) पर केन्द्रित अध्ययन है। हेटनर के अनुसार भूगोल अलग-अलग तत्त्वों का सविस्तार अध्ययन न होकर उनके सह-अस्तित्व और उनकी पारस्परिकता पर आधारित क्षेत्रीय इकाइयों का अध्ययन है। भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई के भौगोलिक स्वरूप की मौलिक विशिष्टता का उद्घाटन करना है। हेटनर की अधिकांश रचनाएँ प्रादेशिक अध्ययन से सम्बन्धित थीं। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध विशेषतया प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् जर्मनी और अन्य कई यूरोपीय देशों में गहन प्रादेशिक अध्ययन को विशेष प्रोत्साहन मिला। हेटनर ने 1933 में प्रकाशित एक लेख में प्रादेशिक अध्ययन पद्धति पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जो बाद में प्रादेशिक अध्ययन का आदर्श प्रारूप बन गया। इस प्रादेशिक अध्ययन पद्धति के तहत अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख भौगोलिक तत्त्वों जैसे स्थिति, भूगर्भिक संरचना, स्थलाकृति

TOUCHI PASS

(उच्चावच), जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जनसंख्या की वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, अधिवासों का स्वरूप एवं वितरण, अर्थव्यवस्था (प्रमुख मानव व्यवसाय) और राजनीतिक-प्रशासनिक विभाजन आदि का क्रमशः वर्णन किया जाता था। यह अध्ययन पद्धति रिचथोफेन के समय से ही जर्मनी में भूगोल में आदर्श पद्धति के रूप में प्रयोग की जाने लगी थी। हेटनर ने बताया कि भूगोल का उद्देश्य प्राथमिक रूप से क्षेत्रों अथवा प्रदेशों का अध्ययन करना होता है।

(ब) फ्रांस में प्रादेशिक विचारधारा का विकास
(Evolution of Regional Concept in France)

प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता एलिसी रेकलस (1830-1905 ई.) जो कि जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर के शिष्य एवं उनके अनुयायी थे, उन्होंने रिटर की ग्रंथमाला 'अर्डकुण्डे' की प्रादेशिक विधि का अनुसरण करते हुए 1875 से 1894 के मध्य 19 खण्डों में 'विश्व का नवीन भूगोल' (Nouvelle Geographie Universelle) लिखा जिसमें इन्होंने सम्पूर्ण विश्व का प्रादेशिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इस तरह फ्रांस में भी प्रादेशिक भूगोल की परम्परा (Tradition) की शुरुआत हुई।

20वीं शताब्दी में भूगोलवेत्ता प्रादेशिक अध्ययन में दो उपागमों का प्रयोग करते थे। प्रथम में वे किसी स्थान या संश्लिष्ट की विशिष्टताओं का अध्ययन करते थे, जबकि दूसरे में वे समांगता वाले क्षेत्रों के सीमांकन का प्रयास करते थे। 20वीं शताब्दी में फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं ने प्रादेशिक अध्ययनों को प्रमुखता प्रदान की। इन भूगोलवेत्ताओं में ब्लाश, डिमांजिया, ब्लैंचार्ड, गालो, सोरे और डि मार्तोने के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

फ्रांस में वाइडल डी ला ब्लाश (1845-1918 ई.) के नेतृत्व में प्रादेशिक उपागम पर विशेष जोर दिया जाने लगा। इससे लोगों को क्षेत्र विशेष के बारे में सही और यथोचित जानकारी मिलने लगी। प्रादेशिक विवरण के आधार पर ही लोग वहाँ के निवासियों और उसके पर्यावरण के अन्तर्सम्बन्ध का अनुमान लगाने में समर्थ हो गये। ब्लाश ने फ्रांस को छोटे-छोटे प्राकृतिक प्रदेशों या लघु प्रदेशों या पेज (Pays) की विचारधारा का समर्थन करते हुए बताया कि प्रत्येक पेज में मिट्टी एवं जल आपूर्ति के आधार पर अपनी निजी विशिष्ट कृषि होती है साथ ही आर्थिक विकास का स्वरूप भी समान होता है। ब्लाश ने मानव-प्राकृतिक वातावरण के के अन्तर्सम्बन्धों से निर्मित विशिष्ट जीवन पद्धति युक्त प्रदेश को पेज की संज्ञा दी। ब्लाश के लघु प्रदेशों की अध्ययन पद्धति आज भी फ्रांस में प्रचलित है। ब्लाश का कहना था कि भूगोलवेत्ता का प्रमुख योगदान किसी देश लघु प्राकृतिक प्रदेशों या पेज का निर्धारण करना है। सन् 1920 में ब्लाश की मृत्यु के बाद उनके शिष्य **लुसियन गेलाय** (1857-1941) ने ब्लाश के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए **विश्व भूगोल** (Geography Universelle) नामक ग्रन्थ शृंखला प्रकाशित की जो प्रादेशिक अध्ययन के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास माना गया।

फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता डिमांजिया (1872-1940 ई.) ने प्रदेश के सन्दर्भ में लिखा, 'प्रत्येक प्रदेश अपनी अलग विशेषताएँ रखता है जिसमें मिट्टी, वायुमण्डल, पौधों तथा मानव का योगदान रहता है। सभी शोधों का लक्ष्य इन विशेषताओं का विश्लेषण करना होता है, साथ ही इनके वर्णनों में उन सभी विशेषताओं को एक-दूसरे से जोड़ना तथा अन्तर्सम्बन्धों को प्रदर्शित करना होता है जो उस प्रदेश के व्यक्तित्त्व को निर्धारित करते हैं।'

वस्तुतः फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने प्रदेशों का अध्ययन प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक (Cultural) तत्त्वों के आधार पर न कर विशिष्ट जीवन पद्धति (जेनरे द वी) के आधार पर किया।

फ्रांस में प्रथम महायुद्ध के पूर्व और बाद में प्रादेशिक भूगोल ने समाज के चिन्तन को काफी प्रभावित किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक तो प्रादेशिक भूगोल ही भूगोल के पर्याय के रूप में था, लेकिन कालान्तर में पश्चिमी देशों में बढ़ते नगरीकरण ने प्रादेशिक विशिष्टताओं को लगभग समाप्त कर दिया। इसलिए प्रादेशिक अध्ययन में कठोरता को गौण माना गया। विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन के कारण क्षेत्रीय अन्तर्सम्बन्धों का क्रमबद्ध अध्ययन विकसित होने लगा। फिर भी बदलते भौगोलिक दर्शन में प्रादेशिक अध्ययन नगर के समीपवर्ती प्रदेशों अथवा कार्यात्मक प्रदेशों की जटिलताओं (Complexity) के अध्ययन के रूप में 1950 के बाद सामने आया। आगे चलकर 1962 में एटिनी जुबीलार्ड द्वारा प्रकाशित *'The Idea of Region'* से इस प्रकार के अध्ययन को काफी बल मिला। 1970 के बाद यूरोप में प्रादेशिक अध्ययन की यह विधि भी धीरे-धीरे कम होने लगी।

(स) ब्रिटेन में प्रादेशिक विचारधारा का विकास
(Evolution of Regionat Concept in Britain)

ब्रिटिश भूगोलवेत्ता पैट्रिक गिडिस (1854-1932 ई.) ने विश्व को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रदेशों में विभक्त किया। गिडिस ने प्रादेशीकरण के साथ-साथ प्रादेशिक सर्वेक्षणों पर भी जोर दिया। पैट्रिक गिडिस के प्रादेशिक भूगोल से प्रभावित

TOUCH 'n' PASS

होकर ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हरबर्टसन ने भौगोलिक अध्ययनों के लिए राजनीतिक विभागों के स्थान पर प्राकृतिक प्रदेशों को एक इकाई (Unit) के रूप में मान्यता प्रदान की। उसका मानना था कि विश्व का प्रदेशों में विभाजन राजनीतिक सीमाओं के आधार पर न होकर प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर होना चाहिए (रिटर की विचारधारा का समर्थन)। उन्होंने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करने के लिए जलवायु (Climate) और वनस्पति को आधार माना।

भूगोल में प्रादेशिक संकल्पना को व्यवस्थित रूप से विकसित करने का श्रेय ब्रिटिश भूगोलवेत्ता एण्ड्रयू जॉन हरबर्टसन (1865-1915 ई.) को है। उन्होंने सर्वप्रथम 1904 में 'रायल जिओग्राफिकल सोसाइटी' की बैठक में प्राकृतिक प्रदेशों (Natural Regions) पर अपना शोधपत्र पढ़ा जो 1905 में भौगोलिक पत्रिका 'जिओग्राफिकल जर्नल' में 'बृहत् प्राकृतिक प्रदेश' (The Major Natural Regions) नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया। प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन में उन्होंने राजनीतिक खण्डों की जगह प्राकृतिक प्रदेशों को भौगोलिक अध्ययन की इकाई माना। उन्होंने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण में मानवीय क्रियाकलापों को कोई स्थान नहीं दिया (यद्यपि उनका विश्वास था कि उनके द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक प्रदेश उन प्रदेशों में निवास करने वाले मानवीय समूहों के लिए उपयोगी आधार प्रदान करते हैं)। उन्होंने वृहद् प्राकृतिक प्रदेशों का निर्धारण धरातलीय स्वरूपों, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की समरूपता के आधार पर किए जाने पर बल दिया। इसी कारण कुछ विद्वानों ने हरबर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों को 'जलवायु-वनस्पति प्रदेश' कहा। साथ ही उन्हें शुद्ध भूगोल (Rain Geography) का समर्थक माना गया। प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण में मानवीय क्रिया-कलापों की उपेक्षा करने के कारण ब्रिटेन में भी इनकी विचारधारा की कटु आलोचनाएँ की गयीं जिसका प्रभाव हरबर्टसन के भौगोलिक चिन्तन पर पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि सन् 1910 के बाद स्वयं हरबर्टसन ने प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण में मानवीय क्रिया-कलापों के महत्त्व को स्वीकारा और उन्होंने सन् 1911 में प्रकाशित अपनी पुस्तक **'मानव तथा उसके कार्य'** (Main and his Work) में 'प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश' के स्थान पर 'प्रमुख प्रदेश' (Major Regions) शब्द का प्रयोग किया और प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव के बीच सम्बन्धों की विवेचना करते हुए माना कि प्राकृतिक शक्तियाँ मानवीय कार्यों में दृष्टिगोचर होती हैं। प्राकृतिक प्रदेश निरपेक्ष प्रदेश न होकर सापेक्षिक क्षेत्र होते हैं। हरबर्टसन द्वारा प्रस्तुत बृहत् प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना यूरोप में भूगोल के शिक्षण योजना में मॉडल के रूप में प्रयुक्त हुई और यह शीघ्र ही विद्यालय स्तरीय शिक्षण पद्धति में मौलिक संकल्पना के रूप में स्थापित हो गयी। परवर्ती वर्षों में विद्यार्थियों में यह सामान्य धारणा बन गयी कि पृथ्वी तल स्पष्ट रूप से अलग-अलग प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त है। इसी तरह यह धारणा भी प्रबल हो गयी कि प्रत्येक प्राकृतिक प्रदेश एक सुनिश्चित ऐतिहासिक विकास-क्रम और जीवन पद्धति को जन्म देता है। हरबर्टसन के प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना भूगोल की संकल्पना का ही एक प्रतिबिम्ब है। हरबर्टसन लिखते हैं, 'भूगोल प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वातावरण के क्रमिक स्तरों या पदानुक्रमों का अध्ययन है।' इस प्रकार उन्होंने प्राकृतिक प्रदेश को भौतिक एवं मानवीय तत्त्वों की संयुक्त रचना माना।

डडले स्टाम्प (1898-1967 ई.) ने भी ब्रिटेन, एशिया तथा अफ्रीका का प्रादेशिक भूगोल लिखा था।

(द) अमेरिका में प्रादेशिक विचारधारा का विकास
(Evolution of Regional Concept in America)

भूगोल में प्रादेशिक संकल्पना के विकास में अमेरिकन भूगोलवेत्ता **डी. ह्वीटलसी** (1890-1956 ई.) का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ (Association of American Geographers) ने प्रादेशिक भूगोल की प्रकृति एवं स्वरूप और उसकी प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से डी. ह्वीटलसी के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी। डी. ह्वीटलसी ने पाँच आधार तत्त्वों का उपयोग करके विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बाँटा है। डी. ह्वीटलसी ने सन् 1956 में अपने एक शोध पत्र में प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन में प्रदेश के लिए **कम्पेज** (Compage) शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार कम्पेज पृथ्वी के किसी भाग में भौतिक, जैविक और मानवीय पर्यावरण के बीच मानव अधिधारण (Human occupance) के परिणामस्वरूप उत्पन्न कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्धों के फलस्वरूप निर्मित एकात्मक क्षेत्रीय इकाई (Regional Unit) होती है।

उनका मानना था कि कम्पेज के तहत समस्त प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों की विशेषताओं, जीवनयापन की विधियों और सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इस संकल्पना के उदय के साथ ही प्रादेशिक इकाइयों को विविधतापूर्ण किन्तु कार्यात्मक रूप से सुसम्बद्ध और संघटित इकाइयों के रूप में देखा जाने लगा।

ईसा बोमेन का चिन्तन फ्रांसीसी विचारधारा से प्रभावित था। अमेरिकन भौगोलिक समिति के निदेशक पद पर कार्य करते हुए इन्होंने प्रादेशिक भूगोल का विकास किया। इन्होंने प्रदेशों के निर्धारण में भौतिक विशेषताओं के साथ-साथ मानवीय विशेषताओं को भी आधार माना। इन्होंने अमेरिका एवं लैटिन अमेरिका के प्रदेशों का मानचित्र अपने संरक्षण में तैयार कराया।

प्र.2. हफ्शमिट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष संदर्भ में प्रस्तुत किए गए प्रादेशिक नियोजन के विकास-क्रम की अवस्थाओं का विस्तृत विवरण दीजिए।

Give a detailed description of the stages of development of regional planning presented by Hufschmidt with special reference to USA.

उत्तर

विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन
(Regional Planning in Developed Countries)

वे देश जिनमें राष्ट्रीय एवं प्रतिव्यक्ति आय उच्च, उद्योग-धंधों पर आधारित अर्थव्यवस्था, वृहत् स्तर पर औद्योगीकरण, उच्च नगरीकरण, उन्नत तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था, लैंगिक समानता, एकल परिवार (Nuclear Family), उच्च जीवन प्रत्याशा, उच्च साक्षरता, निम्न गरीबी, निम्न जनसंख्या वृद्धि दर (Population Growth Rate), निम्न शिशु मृत्यु दर, कृषि का यन्त्रीकरण, विस्तृत एवं व्यापारिक कृषि, उन्नत स्तर पर पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय का विकास आदि विशेषता पायी जाती है, विकसित देश कहलाते है। सन् 1990 ई. से प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा 'मानव विकास सूचकांक' (HDI) (राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा एवं शिक्षा) जारी किया जाता है इसमें उच्च मानव विकास सूचकांक वाले अधिकांश देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हैं। विकसित देशों में शामिल करने के लिए उसके आधारों में स्वच्छ पर्यावरण (Clean Environment), खुशहाली सूचकांक (Happiness Index), उच्च मानवीय मूल्यों (High Human Values), निम्न भ्रष्टाचार (Low Corruption) आदि मानकों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत 1920 के दशक में यहाँ के नगरों व महानगरों के अव्यवस्थित भौतिक विस्तार, प्रशासनिक सेवाओं के तीव्र विस्तार एवं अन्धाधुंध आर्थिक विकास के प्रति जनसाधारण की बढ़ती हुई चेतना तथा चिन्ताओं के कारण शुरू हुई। धीरे-धीरे औद्योगिक एवं कृषीय दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों तथा तीव्रता से बढ़ते महानगरीयकरण (Metropolisation) से उत्पन्न समस्याओं ने नियोजकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू किया। प्रादेशिक नियोजन के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर विकास विकसित देशों में ही आरम्भ हुआ।

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)—विश्व में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन (Regional Planning) की शुरुआत की गयी। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन का आरम्भ सन् 1922 में एक प्रादेशिक नियोजन संघ (Regional Planning Association) नामक निजी संस्था के स्थापन से हुआ। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य न्यूयॉर्क प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण (Analysis) करना था। इस बात का श्रेय इस संस्था को अवश्य दिया जाना चाहिए कि आज इसके स्थापन के 100 वर्षों के बाद भी यह देश की एकमात्र संस्था है, जो वृहत् महानगरीय प्रदेशों की समस्याओं के समाधान (Adjustment) हेतु इनका गम्भीरता (Sincerly) से अध्ययन करती रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम प्रादेशिक परियोजना सन् 1929 में न्यूयॉर्क के लिए ही तैयार की गयी थी। इस परियोजना की लुइस ममफोर्ड (Luis Mumford) सहित अनेक आलोचकों ने तीखी आलोचना की थी हालाँकि लुइस ममफोर्ड स्वयं उस प्रादेशिक नियोजन संघ के एक सक्रिय सदस्य थे जिसने न्यूयॉर्क प्रदेश की यह योजना तैयार की थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रादेशिक नियोजन (Regional Planning) की व्यापक शुरुआत तब की गयी जब 1933 ई. में 'Tennessee Valley Authority' की स्थापना हुई, यह दक्षिण-पूर्वी अमेरिका में बड़े पैमाने पर पुनरुद्धार कार्यक्रम था, जिसमें उसके सात राज्यों (टेनेसी, अल्बामा, मिसिसिपी, केन्टुकी, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना एवं जार्जिया) के हिस्से सम्मिलित थे। सन् 1933 ई. के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना को स्वीकार किया जाने लगा। इससे पूर्व सभी लोग राष्ट्रीय नियोजन से परिचित थे। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ में वृद्धि ध्रुव तकनीक (Growth Pole Technique) प्रचलित थी। अब तक प्रचलित सभी नियोजन 'संसाधन नियोजन' (Resources Planning) से सम्बन्धित थे। 1935 ई. में डब्ल्यू. एच. ओल्डहैम (W.H. Oldham) ने 'सांस्कृतिक प्रादेशीकरण की संकल्पना' (Concept of Cultural Regionalisation) का प्रतिपादन किया। इसके बाद सांस्कृतिक एवं मानव संसाधनों (Human Resources) पर ध्यान दिया जाने लगा और वास्तविक रूप में यहीं से प्रादेशिक नियोजन का सूत्रपात हुआ।

हफ्शमिट (Hufschmidt) ने 1969 ई. संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष संदर्भ में प्रादेशिक नियोजन के क्रम-विकास में सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों पक्षों को सम्मिलित करते हुए पाँच अवस्थाओं (Phases) में विभक्त किया है जिसका विवरण अग्रलिखित है—

1. **प्राकृतिक संसाधन अभिविन्यास** (Natural Resource Orientation)—प्राकृतिक संसाधन अभिविन्यास के तहत बीसवीं शताब्दी के चौथे एवं पाँचवें दशक को शामिल किया जाता है। 1993 ई. में संयुक्त राज्य में टेनेसी घाटी प्राधिकरण (TVA) की स्थापना हुई इसी के साथ प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित उपयोग हेतु परियोजना का शुभारम्भ हुआ। टेनेसी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक अत्यंत पिछड़े प्रदेश का वहां के स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए समन्वित विकास करना था। उस समय पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित टेनेसी घाटी क्षेत्र देश का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। टेनेसी घाटी परियोजना अपने उद्देश्य में सफल रही और इसको मॉडल मानते हुए इसके आधार पर विश्व के अनेक देशों में भी इस प्रकार की परियोजनाएँ आरंभ की गयीं। जिसमें नीदरलैंड में पोल्डर निर्माण, इजरायल में जैजरील घाटी और भारत में दामोदर घाटी परियोजना मुख्य उदाहरण हैं, इसकी ख्याति इस स्तर पर पहुँची कि 'टेनेसी घाटी परियोजना' को 'प्रादेशिक नियोजन' का पर्यायवाची माना जाने लगा।
2. **प्रादेशिक आर्थिक विकास उपागम** (Regional Economic Development Approach)—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित तथा विकासशील दोनों श्रेणी के देशों में त्वरित आर्थिक उत्थान हेतु प्रादेशिक आर्थिक विकास के महत्त्व पर बल दिया गया। यह वह समय था जब विकसित देश युद्ध से हुए बर्बादी की भरपाई करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्संगठित करने में संलग्न थे। अधिकांश विकासशील देश विदेशी उपनिवेशवाद से अभी-अभी मुक्त हुए थे और उनकी अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी थी। अतएव विकासशील देशों के सम्मुख अर्थव्यवस्था के उत्थान की बड़ी चुनौती विद्यमान थीं। अत: विश्व के नवोदित राष्ट्रों में तीव्रता से आर्थिक विकास की आवश्यकता के प्रति बढ़ती चेतना के कारण प्रादेशिक आर्थिक विकास की विचारधारा को प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रादेशिक आर्थिक विकास उपागम विकासशील देशों के आर्थिक विकास हेतु ही सार्थक उपकरण सिद्ध नहीं हुआ वरन विकसित देशों के आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध हुआ।
3. **सांस्कृतिक प्रादेशिकता अभिविन्यास** (Cultural Regionalism Orientation)—सांस्कृतिक प्रादेशिकता अभिविन्यास के तहत बीसवीं शताब्दी के पाँचवें एवं छठे दशक को सम्मिलित किया जाता है। अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्री ओडम (Odum, H. W.) और वेन्स (Vance. R.) को अमेरिका के 'सांस्कृतिक प्रादेशिकता' का प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। इन दोनों विद्वानों ने प्रादेशिक संकल्पनाओं को सामाजिक-सांस्कृतिक शोध में एक अति महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। अतएव उस समय प्रादेशिक नियोजन का दर्शनशास्त्र, सांस्कृतिक प्रादेशिकता अभिविन्यास के रंग में रंग जाने से बच नहीं पाया। इस तरह सामाजिक-सांस्कृतिक शोध में स्थानिक पहलू (Spatial Dimension) एक उभरते हुए सांस्कृतिक-प्रादेशिकता के रूप में अवतरित हो गया।
4. **प्रादेशिक विज्ञान उपागम** (Regional Science Approach)—प्रादेशिक विज्ञान उपागम के अन्तर्गत बीसवीं शताब्दी के सातवें दशक को सम्मिलित किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री वाल्टर ईजार्ड (Walter Isard) को प्रादेशिक विज्ञान का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। इन्हीं के प्रयास से प्रादेशिक नियोजन की विचारधारा को वास्तविक रूप में एक प्रादेशिक या स्थानिक (Spatial) स्वरूप प्राप्त हुआ। वाल्टर ईजार्ड के अनुसार प्रदेश एक गत्यात्मक जैवतंत्र (Dynamic Organism) होता है जिसका सार्थक अध्ययन प्रादेशिक विज्ञान उपागम के बिना असम्भव (Imposible) होता है। वे इस बात के प्रबल समर्थक रहे हैं कि प्रादेशिक उपागम के बिना स्थानिक संगठन (Spatial Organisation) की प्रक्रियाओं की पहचान करना और उन्हें विशिष्टता प्रदान करना सम्भव नहीं लगता है। अतएव यह कहा गया कि प्रादेशिक विज्ञान उपागम में ही स्थानिक तंत्र (Spatial System) की नियोजन कला का समुचित संश्लेषण प्रस्तुत करने की क्षमता है। इस प्रकार ईजार्ड महोदय के नेतृत्व में प्रादेशिक नियोजन में प्रादेशिक विज्ञान उपागम का समावेश हुआ।
5. **नगरीय-महानगरीय उपागम** (Urban Metropolitan Approach)—नगरीय-महानगरीय उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में सातवें दशक में आरम्भ हुआ। अमेरिकी भूगोलवेत्ता जॉन फ्रीडमैन (John Friedman) को नगरीय-महानगरीय उपागम का प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है इन्होंने 1966 ई. में प्रादेशिक/क्षेत्रीय विकास (Regional Development) की व्याख्या हेतु अपना केन्द्र-परिधि मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रादेशिक समस्याओं और मुद्दों की प्रकृति नगरीय महानगरीय प्रकृति से सम्बन्धित होती है। उस समय अमेरिका में नगरीकरण और महानगरीकरण की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र थी और नए-नए नगरीय केन्द्रों के

TOUCH 'n PASS

उद्‌भव के साथ ही मध्यम आकार के नगर एवं महानगरों के आकार में परिवर्तन होने लगा था। तीव्र नगरीकरण की इस प्रक्रिया का प्रभाव विश्व के अन्य देशों विशेष रूप से यूरोपीय देशों पर भी पड़ा। तीव्र औद्योगीकरण और महानगरीकरण के परिणामस्वरूप अनेक प्रकार की नगरीय समस्याओं का उदय एवं प्रसार हुआ। इस प्रकार विकसित देशों में महानगरीकरण (Metropolisation) के कारण उत्पन्न नगरीय समस्याएँ प्रादेशिक नियोजन का मुख्य केन्द्र बिन्दु बन गयीं।

सन् 1971 ई. में जी. चाडविक (George Chadwich) ने अपनी पुस्तक *'A Systems View of Planning'* नामक पुस्तक में प्रादेशिक नियोजन को एक 'भू-तकनीकी' (Geotechnology) की संज्ञा दी है। जिसका तात्पर्य है कि हमें प्रादेशिक नियोजन हेतु चयनित किसी भी नियोजन प्रदेश को एक प्रादेशिक तंत्र (System of region) का अभिन्न अंग (Part and Parcel) मानकर कार्य करना चाहिए जिससे विभिन्न प्रदेशों के पुनर्गठन को व उसमें विद्यमान जीवन और उसकी सतत् उपस्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। ऐसी धारणा वाली विचारधारा के तहत प्रत्येक प्रदेश के संपोषणीय विकास (Sustainable Development) हेतु उसकी संभावनाओं (Potentialities), प्रत्याशित अपेक्षाओं (Prospects) और समस्याओं (Problems) का सही-सही आकलन बहुत जरूरी होता है।

प्र.3. प्रमुख विकासशील देशों में प्रादेशिक नियोजन के विकास-क्रम का वर्णन कीजिए।

Describe the stages of development of regional planning in main developing countries.

उत्तर

विकासशील देशों में प्रादेशिक नियोजन
(Regional Planning in Developing Countries)

वे देश जिनमें प्राथमिक क्रियाकलाप पर आधारित अर्थव्यवस्था, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, उच्च शिशु मृत्यु दर, गरीबी, निम्न साक्षरता, लैंगिक असमानता, संयुक्त परिवार (Joint family), निम्न औद्योगीकरण एवं नगरीकरण, निम्न जीवन प्रत्याशा, गहन एवं परम्परागत कृषि आदि विशेषता पायी जाती है, विकासशील देश कहलाते हैं। सन् 1990 से प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा 'मानव विकास सूचकांक' (HDI) (राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा एवं शिक्षा) जारी किया जाता है, इसमें मध्यम एवं निम्न मानव विकास सूचकांक वाले अधिकांश देश विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल है। अधिकांश विकासशील देश औपनिवेशिक सत्ता के अधीन रहे हैं जिनको द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद आजादी प्राप्त हुई है। अत: ये देश आज भी आर्थिक रूप से काफी पिछड़े (Backward) हुए हैं।

विकासशील देशों में प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत काफी देर से हुई है, क्योंकि ये देश लम्बे समय तक दूसरे देशों के अधीन रहे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ये देश आजाद हुए। तब इन देशों में प्रादेशिक नियोजन यहाँ की केन्द्रीय सरकारों द्वारा शुरु किया गया।

भारत में प्रादेशिक नियोजन (Regional Planning in India)

भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवाँ वृहत्तम देश (रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद) है जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। 19 अप्रैल, 2023 को जारी 'संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष' (UNFPA) के 'The State of World Population Report, 2023' के अनुसार जनसंख्या के मामले में भारत अब विश्व का विशालतम देश (अब चीन का स्थान दूसरा-142.57 करोड़) हो गया है जिसकी कुल जनसंख्या 142.86 करोड़ है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29.1 प्रतिशत भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का लगभग 27.7 प्रतिशत भाग पर पठारी भूमि का और 43.2 प्रतिशत भूमि पर मैदानों का विस्तार है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 58 प्रतिशत भू-भाग कृषि योग्य है, जो चीन के कृषि योग्य भूमि से भी अधिक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की लगभग 54.6 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। भारत के अधिकांश कृषि योग्य भूमि पर गहन कृषि (Intensive Agriculture) की जाती है। भारत खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न देश है।

भारत में नियोजन का एक लम्बा इतिहास रहा है, नियोजन के साक्ष्य सिन्धु घाटी सभ्यता में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो (2600 ईसा पूर्व) जैसे नगरों से प्राप्त होते हैं। मध्यकालीन भारत में निर्मित जयपुर भारत का पहला नियोजित (Planned) शहर माना जाता है। इसकी स्थापना नवम्बर 1727 ई. में महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी, जो सन् 1730 ई. में बनकर तैयार हुआ। जयपुर एक मात्र ऐसा शहर है जिसे वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र के नियमों के अनुसार प्लान किया गया है।

आधुनिक काल में भारत के नियोजित विकास पर सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं फ्रांस जैसे देशों की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पाया गया है। भारत में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 1929 ई. में सोवियत नियोजन (*Soviet Russia : Some Random Sketches and Impressions*) पर लिखी पुस्तकों और 1936 ई. में एम. विश्वेश्वरैया द्वारा रचित पुस्तक 'भारत

TOUCH 'n PASS

का नियोजित अर्थतन्त्र' (Planned Economy for India) ने भारत में सामाजिक-आर्थिक तन्त्र के नियोजनात्मक विकास को बल दिया इसके द्वारा नियोजित औद्योगीकरण से देश के अर्थतन्त्र को रूपान्तरित करने का सुझाव दिया गया था। 1938 ई. में हरिपुरा में इन्हीं नियोजनात्मक नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक 'राष्ट्रीय योजना समिति' की स्थापना की, लेकिन तत्त्कालीन सरकार द्वारा कोई मान्यता न दिए जाने के कारण इस समिति ने किसी नीति का सूत्रपात नहीं किया। 1941 में प्रो. रामास्वामी मुदलियार समिति ने परिवहन, बैंकिंग उद्योग, वाणिज्य तथा विदेशी निवेश के विकास के लिए नीति निर्माण की जरूरत पर बल दिया। 1943 में श्रीमन्ननारायण द्वारा गाँधी योजना (Gandhi Plan) तैयार की गयी। 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग (Planning and Development Department) की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य संसाधन आधारित औद्योगीकरण को बढ़ावा देना था। इसी समय तत्त्कालीन बम्बई के आठ उद्योगपतियों ने भावी विकास का अनुमान लगाकर भारत के आर्थिक विकास की रूपरेखा हेतु संक्षिप्त ज्ञापन (Brief Memorandum Outlining A Plan of Economic Development of India) प्रस्तावित किया। इसी प्रस्ताव को 'बाम्बे प्लान' (Bambay Plan) के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष जे. आर. डी. टाटा तथा उपाध्यक्ष दामोदार दास बिड़ला थे। इसीलिए इसे 'टाटा बिरला प्लान' भी कहा जाता है। इसमें निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करके औद्योगीकरण को गति प्रदान करने का सुझाव दिया गया था। इसमें आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल, 15 वर्षों में प्रतिव्यक्ति आय ₹ 65 से बढ़ाकर ₹ 130 करना तथा योजना का आकार ₹ 10,000 करोड़ था। इसी समय बॉम्बे प्लान के एक लेखक अर्देशिर दलाल की देख-रेख में 'आयोजन तथा विकास विभाग' (Department of Planning and Development) की स्थापना हुई। 1945 में एम. एन. राय द्वारा प्रस्तावित 'पीपुल्स प्लान' कार्ल मार्क्स के समाजवाद के अनुरूप था। 1946 में के. सी. नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकारी योजना परिषद् (Advisory Planning Board) की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य स्वातन्त्र्योत्तर भारत में विकास प्रतिरूप को प्रारम्भ करने हेतु सांगठनिक एवं संस्थागत तन्त्रों के निर्माण सम्बन्धी नीतियों को प्रस्तावित करना था। 1948 में राष्ट्रीय योजना समिति (1938) की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि समस्त आधारभूत उद्योगों एवं सेवाओं, खनिज, रेल, जलमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोगिता वाले उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व होगा। 1950 में जय प्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय की बात कही गयी। 15 मार्च, 1950 को जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में 'भारतीय योजना आयोग' का गठन किया गया तथा 1 अप्रैल, 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई।

इस तरह स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में नियोजन सम्बन्धी जितनी अवधारणाएँ प्रचलित थीं। सभी में औद्योगीकरण द्वारा ही आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन इसी के साथ-साथ 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में ही गाँधीजी द्वारा बिहार के चम्पारण से सत्याग्रह के आलोक में प्रस्तावित 'ग्राम विकास नीति' का भी भारतीय नियोजन तन्त्र पर असर रहा। इसीलिए स्वतन्त्रता के बाद जब भारत में अर्थतन्त्र के नियोजित विकास की बात सामने आयी तो उस समय निम्न तत्त्व नियोजन नीतियों को प्रभावी बनाने में समर्थ रहे—

1. भारतीय राजनीति में कांग्रेस के विशिष्ट राजनीतिक दर्शन का प्रभाव।
2. पंडित नेहरू के प्रजातान्त्रिक समाजवाद का प्रभाव।
3. गाँधी जी के ग्राम विकास से नियोजित अर्थतन्त्र की नीतियों का प्रभाव।

किसी भी नियोजन में संरचनात्मक (Strutural) व्यवस्थापन हेतु स्पष्ट नियमन की आवश्यकता होती है और यह नियमन विशिष्ट राजनीतिक दर्शन का परिणाम होता है। चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक वर्ग समाजवादियों का था और पंडित नेहरू स्वयं भी उससे प्रभावित थे। देश में व्याप्त असमानता को दृष्टिगत रखकर ही गाँधीजी ने भी ग्राम विकास की नीतियों पर जोर दिया था। इसलिए भारतीय नियोजन के पीछे मिश्रित अर्थतन्त्र का दर्शन था। इस तरह स्वातन्त्र्योत्तर भारत में यदि भारतीय नियोजन का मूल्यांकन किया जाए तो उस पर निम्नलिखित चार तत्त्वों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है—

1. केन्द्रीकृत नियोजन का सोवियत मार्क्सवादी मॉडल; (Central Planned Model of Soviet Marxist)
2. प्रजातान्त्रिक सांगठनिक आधार वाला संस्थागत तन्त्र;
3. गाँधीवादी विचारधारा (Gandhian Ideology)
4. पंडित जवाहर लाल नेहरू का फेबियनवाद।

इन्हीं तत्त्वों के प्रभाव के कारण ही स्वतन्त्र भारत की नियोजन नीति में गाँधीवादी विचारधारा और केन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली का द्वन्द्व अब तक देखा जा सकता है। यही कारण है कि आज तक नियोजन नीति में किसी एक स्पष्ट विचारधारा का अभाव है। यह भारतीय नियोजन की एक महत्त्वपूर्ण कमी है, क्योंकि सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य क्या है? प्राथमिकताएँ क्या हैं? उनको प्राप्त करने

का सही प्रयास क्या है। इन प्रश्नों पर स्पष्ट विचारधारा रखना ही नियोजन नीति की सफलता है। अतएव नियोजन का एक स्पष्ट सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक दर्शन होना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है कि नियोजन बिना किसी दार्शनिक आधार के विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप में निर्धारित नहीं कर सकता है। जब तक हम यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि किस प्रकार का समाज निर्मित करना है, तब तक हम नियोजन की कोई रूपरेखा नहीं बना सकते हैं। नियोजन निश्चित विकास प्रतिरूप को प्राप्त करने का एक साधन है और यह विकास मात्र आर्थिक वृद्धि ही नहीं वरन देश, क्षेत्र या समाज विशेष के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्राकृतिक परिवेश से जुड़ा होता है। इसे प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के सम्यक उपयोग हेतु सम्बन्धित क्षेत्र की परिस्थितियों से ही नियोजन तंत्र का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए विभिन्न प्राकृतिक, सामाजकि एवं राजनीतिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में नियोजन का स्पष्ट दार्शनिक आधार होना जरूरी है। फिर भी भारत में नियोजन विभाग की स्थापना के बाद केन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के तहत 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इन योजनाओं को संघीय सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से लागू किया जाता है। इनमें योजना आयोग द्वारा निश्चित लक्ष्यों के आधार पर सम्पूर्ण देश के लिए केन्द्र सरकार के उत्तरदायित्व वाली योजनाएँ पूरी की जाती हैं। पूरा करने के साथ ही अनेक तरह की योजनाओं का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जो भी राजनीतिक पार्टी संघीय सत्ता में रहती है। वह अपने दर्शन के अनुसार योजना अभिकल्पित करती है। कभी-कभी पार्टी विशेष के विशिष्ट राजनीतिक स्वार्थ भी उसमें हावी हो जाते हैं।

भारत में सर्वप्रथम जनता सरकार (1977 से 1979) विकेन्द्रीकृत योजना मॉडल (Decentralised Plan Model) को प्रयोग में लायी थी। भारत में वर्ष 1992 में किए गए संवैधानिक संशोधनों (73वें एवं 74वें) एवं 1993 में जब पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गयी तब से बहुस्तरीय नियोजन का उपयोग किया जाने लगा है। 1993 के पहले देश में नियोजन केन्द्र एवं राज्यों द्वारा ही किया जाता था बाद निचले स्तर (जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम) इस प्रक्रिया का अंग सिर्फ कार्यान्वयन के स्तर पर ही बन पाते थे, परन्तु इन संशोधनों के बाद स्थानीय स्तर का नियोजन न सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया बन गया है बल्कि इन्हें अपने समुचित विकास के लिए योजना बनाने एवं वित्तीय शक्तियाँ भी मिल गयी हैं। भारत में बहु-स्तरीय नियोजन के कई स्तर हैं—(1) राष्ट्रीय स्तर, (2) राज्य स्तर, (3) जनपद स्तर, (4) विकासखण्ड स्तर एवं (5) पंचायत स्तर-ग्राम नियोजन।

प्र.4. भारत एवं चीन में प्रादेशिक नियोजन के विकास की विस्तृत विवेचना कीजिए।

Discuss in detail the evolution of regional planning in India and China.

उत्तर

भारतीय नियोजन नीतियों का मूल्यांकन
(Evolution of Policies of Indian Planning)

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाएँ नियोजन की बहुमुखी अभिव्यक्तियाँ मानी जा सकती हैं। दुर्भाग्यवश, भारत की पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में प्रादेशिक आयाम शामिल नहीं किए जा सके। प्रदेशों की तकनीकी पहचान नहीं किए जाने के कारण नियोजन प्रक्रिया में संतुलित प्रादेशिक विकास का सर्वथा अभाव रहा। प्रादेशिक एवं स्थानिक पहलुओं को तीसरी योजना में शामिल किया गया और इस प्रकार संतुलित प्रादेशिक विकास की दिशा में आधिकारिक नियोजन की शुरुआत हुई।

दामोदर घाटी निगम (DVC) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) भारत में प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में दो अति महत्त्वपूर्ण प्रयास माने जाते हैं। दोनों ही पंचवर्षीय योजनाओं की परिधि के बाहर के प्रयास थे, क्योंकि इन्हें एक से अधिक राज्यों में लागू किया जाना था। दामोदर घाटी परियोजना की असफलता एवं देश की राजधानी से जुड़े हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अत्यल्प उपलब्धि भारत में प्रादेशिक नियोजन के प्रति आधिकारिक अनदेखी के साक्षात प्रमाण (Evidence) हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) मुख्यत: शरणार्थियों (Refugees) की पुनर्वास की योजना रही। इस योजना में कृषि, सिंचाई तथा विद्युत् उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता (Top Priority) दी गयी। इस योजना अवधि में सिन्दरी में उर्वरक कारखाना एवं दामोदर घाटी, भाखडा-नंगल, कोसी और हीराकुड जैसी बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की नींव रखी गयी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) का उद्देश्य देश में आधारभूत एवं भारी उद्योगों की स्थापना के साथ-साथ तीव्र औद्योगीकरण (Rapid Industrialisation) करना था। इसी समय सार्वजनिक क्षेत्र में तीन इस्पात संयन्त्रों—भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर की स्थापना हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 'टेक ऑफ स्टेज' में प्रवेश किया। इसमें शक्ति, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में विकास तन्त्रों के विस्तार को सुनिश्चित करने की योजना थी, यह योजना सन्तुलित प्रादेशिक विकास के प्रति केन्द्रित थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) की पृष्ठभूमि में वार्षिक योजनाओं के द्वारा विशिष्ट कृषि विकास उपायों और सिंचाई सम्भावनाओं के अनुकूलतम उपयोग को सुदृढ़ (Endorse) करने का प्रयास किया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना

TOUCH 'n' PASS

(1974-79) में बेरोजगारी वृद्धि एवं जनसंख्या विस्फोट के प्रभावों पर नियन्त्रण की विफलता सामने आयी। छठीं पंचवर्षीय योजना (1980-85) में राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तकनीकों के आधुनिकीकरण, गरीबी तथा बेरोजगारी में कमी, शक्ति के क्षेत्र में विकास, सामान्य जीवन-स्तर में वृद्धि एवं आय और सम्पत्ति के संग्रह की असमानता (Unequality) में कमी के नियोजन को ध्यान में रखा गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में नियोजन का आधार पिछली योजनाओं के निवेशों का अनुकूलतम परिणाम हासिल करना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के 'एप्रोच पेपर' में रोजगार वृद्धि को केन्द्रीय बिन्दु के रूप में स्थान दिया गया। इसमें छोटे उद्योगों के विकास पर अनिवार्य बल प्रदान किया गया। इस योजना में मानव विकास (Human Development) को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में उदारीकरण, विदेशी निवेश, निर्यातपरक विकास के साथ-साथ मूलभूत विकास प्रक्रिया का लक्ष्य था। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन में गुणवत्ता लाना, प्रादेशिक असमानता में कमी लाना तथा विकास की प्रक्रिया में जन-सहभागिता लाना था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में तीव्र विकास तथा विकास का लाभ सभी वर्गों, विशेषकर गरीब, दरिद्र तथा पिछड़े वर्गों तक पहुँचाना था। इसका सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धनता उन्मूलन रखा गया था। इस योजना में मूलभूत सुविधाओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क तथा ऊर्जा पर बल दिया गया था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में मूलभूत सुविधाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया, ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा पर बल दिया गया।

पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियाँ (Achievements of Five Year Plans)

लगभग 65 वर्षों की योजना में, पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त करने में सफल नहीं रही है, किन्तु देश में सामाजिक-आर्थिक विकास में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 8 गुनी, राष्ट्रीय आय में आठ गुनी, प्रति व्यक्ति आय में 3 गुनी तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं—

1. आधारीय संरचना का विकास, जैसे—ऊर्जा, सिंचाई, सड़क, परिवहन (Transport) और संचार।
2. पूँजीगत वस्तु क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र (Publicsector) द्वारा प्रभावशाली औद्योगीकरण।
3. निर्यात विविधीकरण एवं आयात प्रतिस्थापन।
4. भारतीय लोगों की जीवन प्रत्याशा 1951 के 37 वर्षों से बढ़कर 2011 में 67 हुई।
5. शैक्षणिक व्यवस्था में विकास, जिससे साक्षरता दर 34 प्रतिशत (1951) से बढ़कर 74 प्रतिशत (2011) हुई।
6. विज्ञान और तकनीक (Science and Technology) में विकास और नाभिकीय शक्ति का शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग।
7. खाद्यान्न में लगभग आत्मनिर्भरता (Self sufficiency) प्राप्त की गयी। प्रतिव्यक्ति अनाज उपभोग 337 ग्राम प्रतिदिन (1951) से बढ़कर 514 ग्राम (2022) हुआ।
8. स्त्रियों की शिक्षा एवं रोजगार में तीव्र वृद्धि हुई।
9. उपर्युक्त तथ्यों के अलावा गरीबी उन्मूलन, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और शैक्षिक सुविधाओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किए गए प्रयासों का ही प्रतिफल है।

पंचवर्षीय योजनाओं की विफलताएँ (Failures of Five Year Plans)

भारतीय योजनाएँ दुर्भाग्यवश कुछ महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहीं जिसका विवरण निम्नलिखित है—

1. भारत में नियोजन अभी तक समानता तथा सामाजिक न्याय पर आधारित शोषणमुक्त समाज के निर्माण में लगभग असफल रहा है।
2. जमीन का फिर से वितरण और कृषि में प्रगतिशील विकास नहीं हुआ। वर्तमान में कृषि वृद्धि दर 2% के आस-पास है, जो कम-से-कम 4% होनी चाहिए।
3. योजना पद्धति कुपोषण (Malnutrition), भूख, बेरोजगारी, क्रूरता (Atrocity), असहनशीलता, बाल श्रम और अन्याय को समाप्त नहीं कर सकी।
4. योजना काल में सामाजिक, आर्थिक और प्रादेशिक असमानता की खाई बढ़ती गयी है।

TOUCH 'n' PASS

5. काले धन ने समानांतर अर्थव्यवस्था (Prallel Economy) को जन्म दिया है।
6. गरीबी उन्मूलन नहीं हो सका और आज भी लगभग 22 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है।
7. जनसंख्या नियन्त्रण (Population Control) में सरकार असफल रही।
8. योजनाएँ महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिला सकीं। लिंग भेद (Gender Discrimination) मिटाने की दिशा में व्यापक प्रयास की जरूरत है।
9. भूमि सुधार विकास (Land Reform Development) की गति बहुत धीमी है।
10. योजनाएँ प्रादेशिक विकास में असमानता को कम करने में असफल रही हैं।

योजना आयोग (Planning Commission) का गठन 15 मार्च, 1950 ई. को नई दिल्ली में किया गया था। जिसने पिछले 65 वर्षों में देश के विकास, समाजवादी समाज की स्थापना तथा संषोषणीय विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है, परन्तु 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग (नेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इण्डिया-NITI) का गठन किया गया।

वर्तमान में भारत में नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु स्थानीय स्तर पर विकास प्राधिकरणों की स्थापना कर दी गयी है। जैसे—लखनऊ के विकास हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority-LDA), गोरखपुर के विकास हेतु गोरखपुर विकास प्राधिकरण (Gorakhpur Development Authority-GDA) ठीक इसी प्रकार इन नगरों में औद्योगिक विकास हेतु शहर से दूर अलग से प्राधिकरण का गठन किया गया है, जैसे लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Lucknow Industrial Development Authority-LIDA) तथा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Gorakhpur Development Industrial Authority-GIDA) आदि।

प्रादेशिक नियोजन प्रक्रिया जनसाधारण को तभी स्वीकार्य होगी जब यह लगातार बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकताओं के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध (More Committed) होंगी। जब-जब विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की शुरुआत होती है। तब-तब स्थानीय स्तर पर इसका विरोध शुरू हो जाता है, इसका तात्कालिक उदाहरण गोरखपुर में बन रहे 'खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना' में इसके पहले भी जब-जब सड़क निकाली जाती है या उसका चौड़ीकरण किया जाता है। तब-तब स्थानीय जनता का विरोध सरकार को झेलना पड़ता है।

चीन में प्रादेशिक नियोजन (Regional Planning in China)

चीन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा वृहत्तम देश (प्रथम रूस एवं द्वितीय कनाडा) है जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (Geographical Area) 95.97 लाख वर्ग किमी है। 19 अप्रैल, 2023 को जारी 'संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष' (UNFPA) के 'The State of World Population Report, 2023' के अनुसार जनसंख्या के मामले में अब चीन विश्व का दूसरा विशालतम देश (प्रथम भारत ₹ 142.86 करोड़) हो गया है जिसकी कुल जनसंख्या ₹ 142.57 करोड़ है। चीन के कुल क्षेत्रफल के लगभग 47 प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का तथा लगभग 41 प्रतिशत भाग पर पठारी भूमि का विस्तार है। चीन के कुल क्षेत्रफल का केवल 12 प्रतिशत भाग ही कृषि योग्य है, जो भारत के कृषि योग्य भूमि से भी कम है। चीन एक कृषि प्रधान देश है और देश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। चीन के अधिकांश कृषि योग्य भूमि पर गहन कृषि (Intensive Agriculture) की जाती है पशुपालन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। चीन खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न देश है।

चीन 1 अक्टूबर, 1949 को स्वतंत्र हुआ और वहाँ साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। चीन ने सोवियत मॉडल का पूरी तरह अनुसरण करते हुए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपने विकास की शुरुआत की। सोवियत संघ से चीन को आर्थिक एवं तकनीकी दोनों तरह की सहायता प्राप्त हुई जिसके कारण वह तीव्र गति से आर्थिक विकास करने में सफल हो सका। चीन ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan) की घोषणा 1953 ई. में की और इसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना (1953-1957) पूरी तरह सफल रही। अब तक चीन में तेरह पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है और चौदहवीं पंचवर्षीय योजना (2021-2025) क्रियाशील है।

चीन में जनसंख्या को वृहत् ग्रामीण सहकारी समितियों (Rural Cooperative Societies) में संगठित किया गया। जिसे कम्यून (Commune) कहा गया। कम्यून का निर्माण पहले से विद्यमान गाँवों को पुनर्गठित करके किया गया था। बीसवीं शताब्दी के सातवें दशक तक चीन की विकास प्रक्रिया आत्मनिर्भरता स्तर की थी और इसका मुख्य उद्देश्य निर्धनता दूर करना और

TOUCH 'n PASS

मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। चीन के नियोजन में ग्रामीण विकास को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया और इसके लिए संरचनात्मक नियोजन (Structural Planning) को आधार बनाया गया। सातवें दशक के बाद चीन के विकास नियोजन में विकसित प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा आधुनिकीकरण (Modernization) पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। चीन के प्रादेशिक विकास नियोजन में ग्रामीण औद्योगीकरण पर अधिक ध्यान दिया गया। ग्रामीण औद्योगीकरण के अन्तर्गत लघु उद्योगों तथा कृषि एवं पशुपालन (Agriculture and Animal Husbandry) पर आधारित उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया। बड़े नगरों के बाहर औद्योगिक संरचनाओं को विकसित करके औद्योगिक विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा दिया गया जिससे कई प्रकार के राष्ट्रीय, वृहत् नगरीय उद्यमों का स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इससे ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या स्थानांतरण को रोकने में सहायता मिलती है। समस्त चीन में लगभग 50 हजार कम्यून हैं जिनका अपना वर्कशॉप (कारखाना) है। इस तरह चीन अपनी नियोजित नीतियों के द्वारा आज तीव्र गति से आर्थिक विकास कर रहा है और प्रत्येक मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है।

यह एक सन्तोषजनक बात है कि नाइजीरिया एवं घाना जैसे अफ्रीकी देशों में भी अब प्रादेशिक नियोजन को वहाँ की योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया का एक अति महत्त्वपूर्ण अंग स्वीकार किया जा चुका है। नाइजीरिया एक ऐसा देश है। जहाँ की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण नगरीकरण की समस्याओं से उत्पन्न संकट अधिक गम्भीर रूप धारण कर चुका है। यही कारण है कि यहाँ अधिकांश प्रादेशिक नियोजन कार्यक्रम बड़े-बड़े नगर क्षेत्रों जैसे कि लागोस, अबादान, पोर्ट हरकोर्ट, कॉनो, कादुना आदि में आवास विकास सम्बन्धित सुविधाओं में सुधारों पर केन्द्रित है। विकासशील देशों में भारत, चीन, नाइजीरिया, पाकिस्तान ऐसे देश हैं। जहाँ प्रादेशिक परियोजनाओं को कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई है। इन्हीं सफलताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रादेशिक नियोजन के तहत व्यापक योजनाएँ बनाने के प्रस्ताव भी हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन ने अपना आधार काफी मजबूत बना लिया है, लेकिन विकासशील देशों में इस दिशा में अभी भी बहुत कमियाँ हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। यद्यपि लगभग सभी देशों में नियोजन संगठन संस्थाएँ अपने-अपने देश में पिछड़े क्षेत्रों (Backward Areas) की समस्याओं के समाधान हेतु जाग्रत और कार्यरत भी हैं, परन्तु अभी भी इस दिशा में दिशा-निर्धारण तथा नीति-निर्धारण में काफी कमियाँ हैं। अत: ऐसे संस्थानों/संगठनों को कार्यगत मजबूती प्रदान करने हेतु इनमें महत्त्वपूर्ण संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। इन संस्थानों को विकास का एक शक्तिशाली साधन बनाने हेतु इन्हें अधिक-से-अधिक स्वायतत्ता (Autonomy) प्रदान करने की भी आवश्यकता है। तभी ये संस्थान/संगठन योजना निर्माण कार्यों को अधिक-से-अधिक मजबूती प्रदान कर पायेंगे। विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति अभी भी काफी कमजोर है, इसलिए ये देश अपने लिए नियोजन तो कर लेते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं कर पाते। विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या वहाँ की अशिक्षित जनता, भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधि आदि है, ये सभी नियोजित विकास के राह में अडंगे अटकाते रहते हैं।

प्र.5. प्राचीन भारत में नियोजन पद्धति में बम्बई योजना वर्णन कीजिए।
Describe the Bombay Plan in planning practices in Ancient India.

उत्तर

प्राचीन भारत में नियोजन पद्धतियाँ
(Planning Practices in Ancient India)

अल्पविकसित राष्ट्रों में नियोजन की आवश्यकता महती होती है। देश में उत्पत्ति के साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने और उनमें वृद्धि करने हेतु योजनाबद्ध एवं समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है। पारस्परिक सामंजस्य के अभाव में राष्ट्र का चतुर्मुखी आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो पाता। प्राचीन भारत में नियोजन की पद्धतियों का क्रमबद्ध अध्ययन अग्र रूप में किया जा सकता है—

सन् 1947 से पूर्व भारत अंग्रेजों के अधीन रहा, किन्तु उस समय भी देश में महान अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने नियोजन के क्षेत्र में अपने प्रयास किए जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

बम्बई योजना (Bombay Plan)

जनवरी 1944 में बम्बई के आठ प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर एक योजना का निर्माण किया जिसका नाम 'बम्बई योजना (Bombay Plan)' रखा गया।

बम्बई योजना के उद्देश्य—इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे—

1. **आय**—योजनाकाल में राष्ट्रीय आय को तिगुना एवं प्रति व्यक्ति आय (PCI) को दुगना करना।
2. **शिक्षा एवं उद्योग**—देश में शिक्षा एवं प्रमुख उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता (Priority) दी गयी।

3. **परिवहन एवं सन्देशवाहन**—योजना में परिवहन एवं सन्देशवाहन के साधनों के विकास पर अधिक जोर दिया गया।
4. **निजी उपक्रम को महत्त्व**—देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए राज्य के अलावा निजी उपक्रमों को महत्त्व दिया गया।
5. **भौतिक पद्धति पर बल**—इस योजना में हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit Management) को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए वित्तीय पद्धति के स्थान पर भौतिक पद्धति को अधिक महत्त्व दिया गया।
6. **न्यूनतम आवश्यकताएँ**—योजना में नागरिकों को 2,600 कैलोरी भोजन, 30 गज कपड़ा और 130 वर्ग फीट भूमि की न्यूनतम (Minimum) आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया।
7. **कृषि क्षेत्र**—योजना में कृषि क्षेत्र में 13% से वृद्धि करने का लक्ष्य निश्चित किया गया।
8. **अनिवार्य शिक्षा**—देश में 6 वर्ष से 11 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा (Compulsery Education) का प्रबन्ध किया गया।

कठिनाइयाँ—इस योजना की प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित थीं—

1. **राजनीतिक उलझन**—देश में राजनीतिक उलझनों के कारण योजना का विकास सम्भव न हो सका।
2. **जनता के विरुद्ध**—यह योजना भारतीय नियमों एवं अन्धविश्वासों के विरुद्ध थी।
3. **सत्य का अभाव**—योजना की सफलता के लिए कठिनाइयों एवं त्याग करने की जरूरत थी, जो देश में सम्भव न होने से योजना कार्यान्वित न हो सकी।

यह योजना युद्धोपरान्त 1944 से शुरू होनी थी, परन्तु उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

योजना की प्रमुख बातें (Salient Features of the Plan)

इस योजना की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं—

1. **कृषि** (Agriculture)—इस योजना में कृषि क्षेत्र में 130% से वृद्धि करने के अनुमान लगाए गए। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने हेतु यह आवश्यक समझा गया कि भूमि के उपखण्डन एवं उपविभाजन को समाप्त करने हेतु सहकारी कृषि को अपनाना, जंगल रोपण करके भूमि के कटाव को रोकना, ऋणग्रस्तता (Debtness) को समाप्त करने हेतु समझौता विधि को अपनाया जाना चाहिए। कृषि में कुल व्यय ₹ 1,240 करोड़ रखे गये, जिसमें से अनावर्तक राशि, ₹ 1,090 करोड़ और आवर्तक व्यय राशि ₹ 150 करोड़ रखी गयी।
2. **शिक्षा** (Education)—इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त होना जरूरी है, जिसके लिए व्यक्ति का पढ़ा-लिखा होना आवश्यक है। देश में प्राकृतिक साधनों के सर्वेक्षण के लिए भी विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी। शिक्षा में प्राथमिक कॉलेज, तकनीकी एवं अनुसंधान को शामिल किया जाता है। शिक्षा पर कुल व्यय ₹ 490 करोड़ रखा गया, जिसमें से अनावर्तक व्यय के रूप में ₹ 267 करोड़ व आवर्तक व्यय के रूप में ₹ 227 करोड़ व्यय होने थे।
3. **उद्योग** (Industry)—योजना में उद्योग के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की गयी—
   (i) **कुटीर एवं लघु उद्योग**—बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास के साथ-साथ कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त क्षेत्र रखा गया।
   (ii) **शुद्ध उत्पाद अनुपात**—उद्योगों एवं उत्पादन के पूँजीगत पद्धति के आधार पर पूँजी पर शुद्ध उत्पाद अनुपात का निर्धारण किए जाने की व्यवस्था रखी गयी।
   (iii) **आधारभूत उद्योग**—योजना में आधारभूत उद्योगों (Fundamental Industries) के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया। इस प्रकार पूँजी पर शुद्ध-उत्पाद अनुपात 2% निर्धारित करते हुए ₹ 2,240 करोड़ के शुद्ध औद्योगिक उत्पादन के लिए ₹ 4,480 करोड़ का विनियोजन औद्योगिक क्षेत्र में किया जाना जरूरी समझा गया।
4. **परिवहन एवं संवहन** (Transport and Communication)—परिवहन के क्षेत्र में इस योजना में रेलवे, सड़कों एवं जहाजरानी के विकास को शामिल किया गया। योजना में इन पर व्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार थी—
   (i) **रेलवे**—1938-1939 में 41,000 मील लम्बे रेलमार्ग में ₹ 434 करोड़ की लागत से 21,000 मील की वृद्धि करके कुल लम्बाई 62,000 मील करने का अनुमान लगाया गया जिन पर आवर्तक व्यय के रूप में ₹ 9 करोड़ व्यय होंगे।
   (ii) **सड़कें**—74,000 मील पक्की सड़क एवं 2,26,000 मील कच्ची सड़क में ₹ 30 करोड़ की लागत से 3,00,000 मील सड़कों को बढ़ाने का कार्यक्रम था। वर्तमान कच्ची सड़क को पक्की सड़क में बदलने के लिए ₹ 113 करोड़ का व्यय करने का अनुमान था।

TOUCH 'n' PASS

(iii) **जहाजरानी**—जहाजरानी के विस्तार के लिए ₹ 50 करोड़ की लागत से बन्दरगाह की संख्या में और अधिक वृद्धि करने का प्रावधान रखा गया। इन पर ₹ 5 करोड़ व्यय होने का अनुमान था।

इस तरह समस्त परिवहन व संवहन पर ₹ 946 करोड़ व्यय करने थे। जिसमें से अनावर्तक व्यय ₹ 897 करोड़ एवं आवर्तक व्यय ₹ 49 करोड़ निश्चित किया गया।

5. **गृह-व्यवस्था** (Housing)—जनसंख्या के निवास के लिए गृह-व्यवस्था करना जरूरी था जिस पर कुल ₹ 2,518 करोड़ व्यय करने थे, जिसमें से अनावर्तक व्यय के रूप में ₹ 2,200 करोड़ व आवर्तक व्यय के रूप में ₹ 318 करोड़ व्यय होने के अनुमान थे।

अलोचनाएँ (Criticism)

इस योजना में समाजवादी नियोजन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। नियोजकों का विचार था कि नियोजन तथा लोकतन्त्रीय समाज दोनों एक साथ संचालित किए जा सकते हैं। बम्बई योजना की आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

1. **कृषि पर कम महत्त्व**—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के प्रारम्भिक वर्षों में कृषि का महत्त्व अधिक रहता है और उसी पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, परन्तु इस योजना में उद्योगों पर अधिक एवं कृषि पर कम ध्यान दिया गया।
2. **कुटीर उद्योग के कार्यकर्मों का अभाव**—पूँजी की कमी एवं रोजगार में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत जैसे अविकसित राष्ट्रों में कुटीर उद्योगों के विकास पर अधिक महत्त्व दिया जाना था, लेकिन इन उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।
3. **परिवहन की कमी**—योजना के 15 वर्षों की अवधि में उद्योगों व कृषि के विकास के फलस्वरूप परिवहन की अधिक जरूरत पड़ती, परन्तु इस योजना में इसके विकास की ओर अधिक ध्यान न देकर त्रुटिपूर्ण योजना का निर्माण किया।
4. **निजी क्षेत्र का विस्तार**—इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र पर कम तथा निजी क्षेत्र के विस्तार पर अधिक महत्त्व दिया गया। योजना में सरकार को नियन्त्रण के अधिकार प्रदान किए गए, परन्तु 15 वर्षों के उपरान्त क्षेत्र का अधिक विकास होने से यह योजना पूँजीवादी प्रकृति की थी।
5. **त्रुटिपूर्ण वित्तीय अनुमान**—इस योजना में वित्तीय अनुमान त्रुटिपूर्ण ढंग से लगाए गए, जो योजना की सफलता हेतु घातक सिद्ध हुए। मुद्रा प्रसार की राशि ₹ 3,400 करोड़ रखी गयी जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ता।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. किस बौद्ध ग्रन्थ से छठी शताब्दी ई०पू० भारत में सोलह महाजनपदों के अस्तित्व का ज्ञान होता है?

(क) विनयपिटक (ख) सुत्तपिटक (ग) अभिधम्प पिटक (घ) अंगुत्तर निकाय

उत्तर (घ) अंगुत्तर निकाय

प्र.2. प्रादेशिक भूगोल का जन्मदाता किसको माना जाता है?

(क) होमर (ख) हिकेटियस (ग) क्लूवेरियस (घ) वारेनियस

उत्तर (ख) हिकेटियस

प्र.3. हिकेटियस की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है?

(क) ओडिसी (ख) विश्व भूगोल का परिचय

(ग) जस-पीरियोडस (घ) सामान्य भूगोल

उत्तर (ग) जस-पीरियोडस

प्र.4. किस भूगोलवेत्ता ने विश्व के विभिन्न प्रदेशों के प्रादेशिक वर्णनों के लिए राजनीतिक-सांख्यिकी विचारधारा को आधार माना?

(क) फ्रेडरिक बुश्चिंग (ख) फिलिप्प बुआचे

(ग) क्रिस्टाफ गाटेरर (घ) ऑगस्त ज्यूने

उत्तर (क) फ्रेडरिक बुश्चिंग

TOUCH 'n PASS

प्र.5. प्रादेशिक अध्ययन के लिए किसने 'लाण्डेरकुण्डे' (Lander Kunde) शब्द का प्रयोग किया?
(क) कार्ल रिटर (ख) वॉन हम्बोल्ट (ग) वॉन रिचथोफेन (घ) अल्फ्रेड हेटनर
उत्तर (क) कार्ल रिटर

प्र.6. *'The New Exploration : A Philosophy of Regional planning'* नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
(क) पैट्रिक गेडीस (ख) बेन्टन मैकाय (ग) डब्ल्यू-एच० ओल्डहैम (घ) एडम स्मिथ
उत्तर (ख) बेन्टन मैकाय

प्र.7. विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत किस दशक में हुई?
(क) 1900 के दशक (ख) 1920 के दशक (ग) 1940 के दशक (घ) 1960 के दशक
उत्तर (ख) 1920 के दशक

प्र.8. विश्व में सर्वप्रथम प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत किस देश में की गई?
(क) चीन (ख) भारत (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका (घ) जर्मनी
उत्तर (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका

प्र.9. किस संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष 'मानव विकास सूचकांक' जारी किया जाता है?
(क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) (ख) विश्व व्यापार संगठन (WTO)
(ग) विश्व मौसम विज्ञान संस्थान (WMO) (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
उत्तर (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)

प्र.10. विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है?
(क) संयुक्त राज्य अमेरिका (ख) इण्डोनेशिया (ग) भारत (घ) ब्राजील
उत्तर (ग) भारत

प्र.11. बम्बई योजना का निर्माण का वर्ष है–
(क) 1934 (ख) 1944 (ग) 1946 (घ) 1947
उत्तर (ख) 1944

प्र.12. जनयोजना का प्रकाशन निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया?
(क) एम०एन० राय (ख) जय प्रकाश नारायण (ग) महात्मा गाँधी (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (क) एम०एन० राय

प्र.13. गाँधीवादी योजना के प्रतिपादक थे–
(क) जय प्रकाश नारायण (ख) महात्मा गाँधी (ग) श्रीमन्नारायण (घ) जवाहरलाल नेहरू
उत्तर (ग) श्रीमन्नारायण

प्र.14. सर्वोदय योजना के प्रतिपादक थे–
(क) महात्मा गाँधी (ख) एम०एन० राय (ग) विनोबा भावे (घ) जयप्रकाश नारायण
उत्तर (घ) जयप्रकाश नारायण

प्र.15. निम्नलिखित में से कौन-सी योजना स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की है?
(क) बम्बई योजना (ख) जनयोजना (ग) गाँधीवादी योजना (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

❑

TOUCH 'n PASS

UNIT-II

प्रादेशिक योजना के प्रकार
Types of Regional Planning

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय नियोजन को परिभाषित कीजिए।

Define the regional and national planning.

उत्तर जब किसी अर्थव्यवस्था के एक विशिष्ट क्षेत्र या भाग तक ही आयोजन सीमित रहता है तो इसे क्षेत्रीय नियोजन (Regional Planning) कहते हैं। क्षेत्रीय नियोजन को आंशिक (Partial) नियोजन भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय नियोजन सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को एक समष्टि मानकर नियोजन करता है जिसका संचालन देश में किसी केन्द्रीय निकाय (Central Body) द्वारा होता है। राष्ट्रीय नियोजन को हम विस्तृत नियोजन कह सकते हैं। प्राय: क्षेत्रीय नियोजन, राष्ट्रीय नियोजन का ही अंग होता है और विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) की नीति के कारण क्षेत्र विशेष का प्रभार क्षेत्रीय अधिकारियों को दे दिया जाता है।

प्र.2. साम्यवादी तथा प्रजातांत्रिक नियोजन से आप क्या समझते हैं?

What do you understand by communist and democratic planning?

उत्तर साम्यवादी नियोजन जिसमें एक पूर्णतया कट्टर केन्द्रीकृत व्यवस्था होती है और जिसमें निजी क्षेत्र एवं बाजार व्यवस्था बिल्कुल समाप्त कर दी जाती है। सभी आर्थिक निर्णय केन्द्रीय संगठन द्वारा होता है। प्रजातान्त्रिक नियोजन इससे सर्वथा विपरीत स्थिति है। प्रजातान्त्रिक नियोजन के दो रूप हो सकते हैं-उदार या नरम प्रकार का प्रजातान्त्रिक नियोजन जिसका प्रयोग कीन्स के सुझाव पर तीसा (1930) की मन्दी से बाहर निकालने के लिए यू. एस. ए. और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पुनर्गठित करनें के लिए किया गया। ऐसी स्थिति में राज्य की भूमिका बाजार यन्त्र की पूरक व्यवस्था के रूप में होती है जिससे लोगों की स्थिति में सुधार हो इसे हम लोगों ने बाजार मिश्रित प्रणाली (Market Mixed System) कहा। प्रजातान्त्रिक नियोजन की दूसरी प्रणाली अपेक्षाकृत अधिक केन्द्रीकृत (Centralised) होती है, इसमें राज्य केवल बाजार यन्त्र की पूरक इकाई नहीं होती वरन उसमें हस्तक्षेप करने वाली व्यवस्था होती है।

प्र.3. संरचनात्मक एवं क्रियात्मक नियोजन क्या है?

What is the structural and functional planning?

उत्तर संरचनात्मक नियोजन आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक ढाँचे में वांछित परिवर्तन को महत्त्व देता है। इस नियोजन का उद्देश्य ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को प्राप्त करना है, जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान कर सके। यह तुलनात्मक रूप से दीर्घकालिक (Longterm) नियोजन है और सामान्यतया विकासशील एवं समाजवादी देश इसी का अनुकरण करते हैं। क्रियात्मक नियोजन समय विशेष पर प्रचलित अथवा अस्तित्ववान सामाजिक आर्थिक ढाँचे को बनाये रखने और उसको मजबूती देने अथवा वर्तमान ढाँचे में मरम्मत को अपना लक्ष्य मानता है। प्राय: इसका सम्बन्ध विकसित देशों से है।

प्र.4. भौतिक तथा वित्तीय नियोजन को लिखिए।

Write the physical and financial planning.

उत्तर भौतिक नियोजन का सम्बन्ध मानव शक्ति, मशीनों और कच्चे माल (आगतों) के अनुकूलतम वितरण एवं राशनिंग से है, जो देश के उत्पादन में वृद्धि करके विकास प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकें। वित्तीय नियोजन का सम्बन्ध मुद्रा के रूप में संसाधनों की व्यवस्था एवं वितरण (Distribution) से है जो विकास प्रक्रिया हेतु वांछित हो।

प्र.5. क्षेत्रीय योजना से आप क्या समझते हैं?

What do you understand by regional planning?

उत्तर क्षेत्रीय नियोजन का अर्थ है विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं या कार्यक्रमों का निर्माण और कार्यान्वयन। क्षेत्रीय नियोजन को स्थानिक रूप से सीमित क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और भौतिक संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन के रूप में परिभाषित (Define) किया जा सकता है।

TOUCH 'n PASS

प्र.6. क्षेत्रीय नियोजन को सरल शब्दों में क्या कहते हैं?
What is regional planning in simple words?

उत्तर क्षेत्रीय योजना एक व्यक्तिगत शहर या कस्बे की तुलना में भूमि के एक बड़े क्षेत्र में भूमि उपयोग गतिविधियों, बुनियादी ढाँचे और निपटान वृद्धि के कुशल प्लेसमेंट से संबंधित है। क्षेत्रीय योजना शहरी नियोजन से संबंधित है क्योंकि यह व्यापक पैमाने पर भूमि उपयोग प्रथाओं से संबंधित है।

प्र.7. क्षेत्रीय विकास से क्या तात्पर्य है?
What is meant by regional development?

उत्तर बहुविषयक स्वरुप तथा केंद्र के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ये कार्यक्रम बहु-विभिन्न तथा बहुवादी में क्षेत्रीय विकास के मुद्दों के साथ सामाजिक-आर्थिक, मानव, संस्थागत, प्रौद्योगिकीय, मूल संरचनात्मक और पर्यावरणीय कारको से जुड़े होते हैं।

प्र.8. विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं?
What are the main areas of development?

उत्तर 1. शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक,
2. संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक,
3. शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक,
4. संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और भावनात्मक।

प्र.9. सूक्ष्म आर्थिक योजना क्या है?
What is micro economic planning?

उत्तर विकेन्द्रीकृत योजना या सूक्ष्म स्तरीय योजना, योजना गतिविधियों का एक प्रकार है। यह केंद्र से उप-राज्य स्तर, यानी जिला उप-मंडल, ब्लॉक और गाँव स्तर तक की प्रक्रिया है।

प्र.10. आर्थिक नियोजन की सीमाएँ क्या हैं?
What are the limitations of economic planning?

उत्तर भारत में आर्थिक नियोजन की सबसे बड़ी सीमाओं में दोषपूर्ण कार्यान्वयन, व्यावहारिक दृष्टिकोण की कमी और प्रशासनिक अक्षमता शामिल है। दोषपूर्ण कार्यान्वयन से अप्रभावी नीतियाँ बन सकती हैं, जबकि व्यावहारिक दृष्टिकोण की कमी के परिणामस्वरूप अवास्तविक लक्ष्य और रणनीतियाँ हो सकती हैं।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. केन्द्रीकृत या एक स्तरीय एवं विकेन्द्रीकृत या बहुस्तरीय नियोजन का उल्लेख कीजिए।
Explain the centralised or single level and decentralised or multi level planning.

उत्तर

केन्द्रीकृत या एक स्तरीय एवं विकेन्द्रीकृत या बहुस्तरीय नियोजन
(Centralised or Single Level and Decentralised or Multi Level Planning)

नियोजन की प्रक्रिया केन्द्रीकृत या एक स्तरीय एवं विकेन्द्रीकृत या बहुस्तरीय होती है। केन्द्रीकृत नियोजन में योजना को बनाने, पूरा करने, निरीक्षण करने आदि का उत्तरदायित्व एक केन्द्रीय संगठन या राष्ट्रीय स्तर पर होता है अर्थात् एक स्तरीय नियोजन में सभी निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिये जाते हैं जिनके क्रियान्वयन के लिए ही निचले क्षेत्रीय स्तरों का सहारा लिया जाता है। इसे हम 'ऊपर से नीचे की ओर नियोजन' (Planning) भी कहते हैं। भारत में ऐसे ही केन्द्रीकृत नियोजन का प्रचलन रहा है।

विकेन्द्रीय/बहुस्तरीय नियोजन में कार्यों का विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) होता है। बहुस्तरीय नियोजन में राष्ट्रीय प्रदेश को छोटी इकाइयों में बाँटा जाता है और उन सभी स्तरों पर नियोजन किया जाता है। बहुस्तरीय नियोजन की अवधारणा (Conception) वास्तव में विभिन्न प्रकार के प्रदेशों का नियोजन है, जो साथ मिलकर एक समष्टि तन्त्र (Macro System) का निर्माण करते हैं। ये सभी प्रादेशिक इकाइयाँ एक-दूसरे की पूरक होती है। इसमें सरकार, स्थानीय निकाय, व्यक्तिगत उद्यमी आदि मिलकर योजना सम्बन्धी निर्णय लेते हैं। इसे हम 'नीचे से ऊपर की ओर नियोजन' भी कहते हैं। इस तरह के नियोजन में ग्राम पंचायतों की भागीदारी में वृद्धि होगी। उच्चस्तरीय नियोजन निम्न स्तरीय नियोजन के लिए ढाँचा तैयार करता है। इसमें जनता की सीधी भागीदारी होती है और योजना के लाभ सबसे निचले स्तर तक पहुँच जाते हैं। इस तरह के नियोजन में प्रत्येक निचला स्तर

TOUCH n' PASS

ऊपर के स्तरों की योजना का आधार बनता है, चूँकि इसमें सहभागिता (Participation) उच्च स्तर की होती है, इसलिए यह नियोजन के लिए अधिक प्रभावी है।

भारत में सर्वप्रथम जनता सरकार (1977 से 1979) विकेन्द्रीकृत योजना मॉडल को प्रयोग में लायी थी। भारत में वर्ष 1992 में किए गए संवैधानिक संशोधनों (Constitutional Amendments) (73वें एवं 74वें) एवं 1993 में जब पंयायती राज्य व्यवस्था लागू की गयी तब से बहुस्तरीय नियोजन का उपयोग किया जाने लगा है। 1993 के पहले देश में नियोजन केन्द्र एवं राज्यों द्वारा ही किया जाता था और निचले स्तर (जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम) इस प्रक्रिया का अंग सिर्फ कार्यान्वयन के स्तर पर ही बन पाते थे, लेकिन इन संशोधनों के पश्चात् स्थानीय स्तर का नियोजन न केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया बन गया है वरन इन्हें अपने समुचित विकास के लिए योजना बनाने एवं वित्तीय शाक्तियाँ भी मिल गयी हैं। भारत में बहु-स्तरीय नियोजन के कई स्तर हैं—(1) राष्ट्रीय स्तर, (2) राज्य स्तर, (3) जनपद स्तर, (4) विकासखण्ड स्तर, (5) पंचायत स्तर-ग्राम नियोजन।

प्र.2. आगनात्मक एवं निगमात्मक नियोजन पर टिप्पणी लिखिए।

Write the note on inductive and deductive planning.

उत्तर

आगनात्मक एवं निगमात्मक नियोजन
(Inductive and Deductive Planning)

नियोजन की विधियों के आधार पर नियोजन को दो प्रकारों में बाँटा जा सकता है-आगनात्मक एवं निगमात्मक नियोजन।

आगनात्मक नियोजन में नियोजन प्रक्रिया विशिष्ट से सामान्य क्रिया की तरफ होती है। क्षेत्रों के विकास के लिए योजना क्षेत्रीय स्तर पर बनती है। प्रदेश एवं क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर परियोजनाओं की खोज की जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रादेशिक वर्गीकरण एवं बाजार अध्ययन पहले से उपलब्ध होता है। क्षेत्रीय और खण्डीय कार्यक्रमों हेतु बनायी गई परियोजनाओं को विकास योजना में समन्वित किया जाता है। इस नियोजन विधि की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें सम्पूर्ण निवेश, रोजगार इत्यादि के बारे में पूर्ण जानकारी एवं पर्याप्त नियंत्रण का अभाव होता है। पूरी पद्धति के बारे में स्पष्ट-विचार नहीं बन पाता है। यह नियोजन सदैव छोटे स्तर पर बनाकर और उनको समन्वित कर बृहद् स्तर पर लाया जाता है। इसमें नीचे से ऊपर की तरफ प्रक्रिया (Process) अपनाई जाती है।

निगमात्मक नियोजन में नियोजन प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट क्रिया की तरफ होती है। उदाहरणस्वरूप पहले प्राथमिक (Primary) आर्थिक प्रवृत्तियों, उपलब्ध संसाधनों और संरचनात्मक (Structural) ढाँचा के आधार पर सामान्य विकास का लक्ष्य निर्धारित होता है। दोबारा इसको रणनीतिक खण्डों (Strategic Sectors) में क्षेत्र एवं कटिबन्ध के अनुसार बाँटा जाता है। तदुपरान्त सम्पूर्ण, खण्डीय और कटिबन्धीय संसाधन आवश्यकता की गणना की जाती है। लक्ष्यों को उपलक्ष्यों में बाँटा जाता है। बाजार अध्ययन के बाद विभिन्न उद्योगों एवं कृषि के लिए यथार्थ उत्पादन कार्य निर्धारित किये जाते हैं। इस नियोजन में ऊपर से नीचे की तरफ की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यद्यपि इस नियोजन को पर्याप्त नहीं माना जाता, क्योंकि यह कैबिनेट स्तर पर द्वितीयक स्रोतों के आधार पर बनाई जाती है। यह नियोजन राष्ट्रीय योजना के सामान्य दिशानिर्देश के अनुरूप होते हैं। अतएव कहा जा सकता है कि यह नियोजन देश स्तर पर बनाकर छोटे स्तरों जैसे राज्य, जिला, विकासखण्ड इत्यादि पर बाँटा जाता है अर्थात् वृहद् खण्ड हेतु नियोजन लक्ष्य बनाकर उपखण्डों हेतु नियोजन कार्यक्रम बनाया जाता है।

प्र.3. मध्यम नियोजन प्रदेश पर टिप्पणी लिखिए।

Write the note on meso planning regions.

उत्तर

मध्यम नियोजन प्रदेश
(Meso Planning Regions)

मध्यम नियोजन प्रदेश द्वितीय आर्थिक इकाई के रूप में होते हैं। ये वृहत् नियोजन प्रदेशों के अंग या उपविभाग होते हैं, जो संसाधनों के निष्कर्षण, संरक्षण एवं उपयोग के लिए एक तर्कयुक्त इकाई बनते हैं। प्रत्येक मध्य-स्तरीय प्रदेश प्रादेशिक पदानुक्रम का मध्य-स्तरीय भाग होता है, जिसमें एक से अधिक लघु स्तरीय प्रदेश समाहित होते हैं। हालांकि, एक मध्य स्तरीय प्रदेश में कम-से-कम दो लघु स्तरीय प्रदेशों का होना जरूरी है, लेकिन अधिकतम कितने लघु स्तरीय प्रदेश इसमें समाहित हो सकते हैं, इसका मानकीकरण सम्भव नहीं है। ऐसे लघु-स्तरीय प्रदेश जिनका एक ही भाग मध्य स्तरीय प्रदेश में समाहित किया जाता है। इन सभी में कुछ-न-कुछ एकसमान विशेषताएँ पायी जाती हैं, चाहे वह भौतिकी, स्थलाकृतिक, जनसांख्यिकीय, सांस्कृतिक, पर्यटन आदि के क्षेत्र से हो या समस्याओं की एक समानता के रूप में हो। इन सभी को एक मध्य-स्तरीय प्रदेश में संयुक्त करने का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना होता है। इसकी पहचान प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति भूमि उपयोग उपलब्धता, उत्पादन सूचकांक, (Production Index) वस्तु निर्माण संभाव्यता आदि से की जा सकती है।

TOUCH 'n' PASS

मध्यम नियोजन प्रदेशों में वृहत् प्रदेशों की तुलना में स्थानिक सम्बद्धता और समरूपता (Uniformity) अधिक पायी जाती है। मध्यम प्रदेश कुछ वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता भी रखते हैं; साथ ही संसाधनों, सामाजिक-आर्थिक समस्याओं, सामाजिक-सांस्कृतिक विभेद, जीवन स्तर, आर्थिक क्रियाओं आदि में अन्य पड़ोसी प्रदेशों से विभेद पाया जाता है। लघु-स्तरीय प्रदेशों के विपरीत सभी मध्य-स्तरीय प्रदेश बहु-दिशा विकास की ओर अग्रसर होते हैं। इनमें कम-से-कम एक विशिष्टता (Specialisation) राष्ट्रीय स्तर के उत्पादन तन्त्र (Production System) के लिए महत्त्वपूर्ण होती है। भारत में दामोदर घाटी प्रदेश एक मध्य-स्तरीय प्रदेश का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें तीन लघु-स्तरीय प्रदेश समाहित माने जाते हैं; जैसे कि घाटी के कोयला खनन (Coalmining) क्षेत्र जिनका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक महत्त्व है, पहाड़ी व पठार के वन क्षेत्र जिनका प्रादेशिक स्तर पर बहुत अधिक महत्त्व है और कृषीय भूमि जिसका स्थानिक स्तर पर बहुत अधिक महत्त्व है। हालाँकि ये तीनों उत्पादन तन्त्र अलग-अलग रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी घाटी के सन्दर्भ में परस्पर एकीकृत हैं जिसका मुख्य स्रोत नदी-घाटी है। भारत के सन्दर्भ में सामान्यतया इसके अन्तर्गत एक या एक से अधिक संलग्न जनपदों को सम्मिलित किया जा सकता है।

प्र.4. लघु नियोजन प्रदेश का उल्लेख कीजिए।

Explain the micro planning regions.

उत्तर

लघु नियोजन प्रदेश
(Micro Planning Regions)

लघु नियोजन प्रदेश, मध्यम प्रदेशों के वे भाग होते हैं, जो किसी विशेष समस्या का उद्बोधन करते हैं। ये प्रदेश तृतीय आर्थिक इकाई के रूप में होते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान आपसी टकराहट या विरोधाभास की अनुपस्थिति है। ये प्रदेश, नियोजन प्रादेशिक तन्त्र के पदानुक्रम के सबसे निम्न स्तर पर स्थित सबसे छोटे प्रदेश होते हैं। हाँ, ऐसे लघु स्तर के नियोजन प्रदेशों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे स्वयं में इतने विशेष हों कि वे अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से भिन्न हों। लघु प्रदेश में किसी समुदाय विशेष की इच्छाओं का भी समन्वय किया जाता है।

लघु प्रदेश में सौभाग्यवश कुछ ऐसी विशिष्ट क्षमता होती है, जो किसी अन्य प्रदेश में नहीं पायी जाती। जैसे कि किसी प्रदेश में कृषीय विकास की असीम क्षमता (जैसा कि पंजाब एवं हरियाणा में), खनन की विशिष्ट क्षमता (जैसे कि झारखण्ड एवं ओडिसा में) पर्यटन के विकास की विशिष्ट क्षमता (जैसे कि उत्तराखण्ड एवं जम्मू-कश्मीर में), जल-विद्युत उत्पादन की असीम क्षमता (जैसे कि हिमाचल प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश में) होती है। ये सभी क्षेत्र लघु-स्तर के नियोजन प्रदेश माने जा सकते हैं। ऐसे प्रदेशों के क्षेत्रफल/आकार का मानकीकरण भी सम्भव नहीं होता। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक ही स्थान पर विभिन्न समय पर भिन्न-भिन्न आकार के हो सकते हैं।

प्राय: तहसील स्तरीय, विकासखण्ड स्तरीय और ग्राम पंचायत स्तरीय नियोजन प्रदेश, लघु नियोजन प्रदेश के तहत सम्मिलित किए जाते हैं। किसी अत्यंत स्थानीय या लघु क्षेत्र में व्याप्त किसी समस्या या समस्याओं के निराकरण के लिए लघु स्तरीय नियोजन ही उपयुक्त होता है। लघु प्रदेशों के संसाधनों के साथ ही वहाँ के निवासियों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं तथा पारस्परिक सम्बन्धों में सर्वाधिक समरूपता पायी जाती है। यही कारण है कि क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए लघु नियोजन प्रदेश को सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्रीय इकाई माना जाता है। लघु स्तरीय प्रदेश चाहे अपने आप में सुस्पष्ट विभेद्य हों, लेकिन फिर भी वे सम्पूर्ण प्रादेशिक तन्त्र का ही अंश होते हैं। लघु प्रदेश सबसे नीचे के स्तर के क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, इसलिए क्षेत्र के विकास नियोजन हेतु ये सर्वाधिक उपयुक्त इकाई होते हैं।

नियोजन प्रदेशों में प्राय: तीन-स्तरीय पदानुक्रमिक तन्त्र पाया जाता है। इनमें वृहद्-स्तरीय, मध्य-स्तरीय एवं लघु-स्तरीय प्रदेश होते हैं। प्रथम स्तर पर वृहद् प्रदेश आते हैं जिनमें दो या दो से अधिक मध्य-स्तरीय प्रदेश आर्थिक अनुरूपता के आधार पर शामिल किए जाते हैं। दूसरे स्तर पर मध्य-स्तरीय प्रदेश आते हैं जिनमें दो या दो से अधिक सूक्ष्म-प्रदेश शामिल होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और सामान्य जीवन गुणवत्ता (Quality) भी उच्च होती है। मध्य-स्तरीय प्रदेश में प्राकृतिक अनुरूपता, समस्याओं की अनुरूपता या क्षमताओं के आधार पर लघु-स्तरीय प्रदेशों को समाहित किया जाता है। लघु-स्तरीय प्रदेश सबसे छोटे होते हैं, लेकिन इनमें से प्रत्येक में कोई-न-कोई विशिष्टता अवश्य होती है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्त्व होता है। इन तीनों में से किसी स्तर के प्रदेश के क्षेत्र व आकार का मानवीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह समय और देश के अनुसार बदलाव होते रहते हैं।

TOUCH 'n PASS

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. प्रादेशिक नियोजन के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
Describe the types of regional planning.

उत्तर नियोजन प्रक्रिया को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसके विभिन्न घटक (Component) परस्पर इतने घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होते हैं कि इसका स्पष्ट वर्गीकरण कर पाना बहुत दुष्कर है। फिर भी नियोजन की अवधि, उद्देश्य, नियोजन के सामाजिक-आर्थिक प्रखण्ड, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय, प्रादेशिक स्तर आदि के आधार पर प्रादेशिक नियोजन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह प्रादेशिक नियोजन के प्रमुख प्रकार निम्नांकित हैं—

1. **अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक नियोजन** (Short and Long term Planning)—नियोजन प्रक्रिया में लगने वाले समय के आधार पर नियोजन अल्पकालीन या दीर्घकालीन हो सकते हैं। वे नियोजन जो 12 महीने/एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए बनाये जाते हैं, अल्पकालीन नियोजन (Short term Planning) कहलाते हैं। अल्पकालिक नियोजन कुछ तत्त्कालिक एवं गम्भीर समस्याओं को हल करने के लिए बनाये जाते हैं, जिनके लिए सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत नहीं होती। इसका उपयोग उत्पादन एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा बाढ़, सूखा, भूकम्प, सुनामी जैसी आकस्मिक विपदाओं का मुकाबला करने के लिए प्राय: अल्पकालीन नियोजन ही अनुकूल पड़ता है। 1965 ई. में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद लगातार सूखा एवं मुद्रा में अवमूल्यन के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना समय से शुरू नहीं हो पायी इसलिए 1966-67, 1967-68 एवं 1968-69 में तीन वार्षिक योजनाएँ लागू की गयीं। ये योजनाएँ अल्मकालीन योजना के ही उदाहरण हैं। इसे परिचालनात्मक (Action or Operational) नियोजन भी कहा जाता है।
   मध्यकालिक नियोजन (Midterm Planning) प्राय: एक वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम की अवधि का होता है और इनमें उन तमाम क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है, जिससे आधारभूत समस्या का समाधान करने में मदद मिल सके।
   दीर्घकालीन नियोजन (Long term Planning) वे नियोजन हैं जो 5 वर्ष या उससे अधिक (20 या 40 वर्षों तक) की अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं। इसे व्यूहरचनात्मक (Strategic) नियोजन भी कहा जाता है। किसी क्षेत्र के आर्थिक तन्त्र में बड़े पैमाने पर परिवर्तन, शोध, विकास, क्षमता निर्माण, सशक्तिकरण, न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था आदि के लिए दीर्घकालीन नियोजन करना होता है। दीर्घकालीन नियोजन का कार्यान्वयन साधारणतया कई चरणों में किया जाता है। इसमें अनिश्चितता होती है और खण्ड मूल्यांकन की जरूरत होती है। दीर्घकालीन नियोजन पूरे समाज के सामाजिक एवं आर्थिक समुन्नति के लिए तैयार किया जाता है। साधारणतया इस प्रकार के नियोजन में आधारभूत समस्याओं को पूर्व में ही पहचानने और उनके बारे में निर्णय लेने की बात निहित होती है। किसी क्षेत्र में निर्मित जल विद्युत परियोजना, विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार नियोजन, भूमि सुधार, इंसेफेलाइटिस निवारण कार्यक्रम भारत में क्रियान्वित अभी तक की 12 पंचवर्षीय योजनाएँ दीर्घकालीन नियोजन के ही उदाहरण हैं।
2. **आर्थिक, सामाजिक एवं विकास नियोजन** (Economic, Social and Development Planning)—कार्यक्रम के आधार पर नियोजन को तीन भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम को आर्थिक नियोजन, दूसरे को सामाजिक नियोजन और तीसरे को विकास नियोजन कहा जाता है।
   आर्थिक नियोजन में किसी देश के आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। आर्थिक नियोजन का प्रयोग प्राय: विकसित देशों में किया जाता है, जहाँ आर्थिक तन्त्र के विकास एवं परिवर्तन के लिए पर्याप्त पूँजी एवं अवस्थापना (Infrastructure) सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। आर्थिक नियोजन का उपयोग साधारणतया सभी पश्चिमी विकसित देशों, विकसित देशों एवं आंग्ल अमेरिकी देशों में किया जाता है।
   सामाजिक नियोजन के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं जैसे तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, कुपोषण, निर्धनता एवं स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है। प्राय: यह नियोजन आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अति पिछड़े क्षेत्रों हेतु बनाया जाता है। इतना ही नहीं, इसका उद्देश्य किसी पिछड़े समुदाय विशेष की प्रगति सुनिश्चित करना भी है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि स्वस्थ एवं शिक्षित व्यक्ति प्रत्येक विकास के लिए जरूरी है। इसलिए सामाजिक नियोजन में विभिन्न सामाजिक वर्ग के आँकड़ों को उपलब्ध कराकर और समुदाय विशेष के धर्मगुरु, शिक्षक, डॉक्टर, जनप्रतिनिधि एवं म्यूनीसीपल अधिकारी को शामिल कर प्रदेश के विकास पर जोर दिया जाता है। साथ ही किसानों की सभा आयोजित की

जाती है जिससे वे अपनी समस्याओं को रख सकें तथा असन्तुष्ट नवयुवकों को भी अपने विचार रखने हेतु बुलाया जाता है। भारत के साथ कई देशों में यह नियोजन प्रचलित है। कुकलिंस्की (A. Kuklinski) ने सामाजिक नियोजन में तीन बातों पर ध्यान आकर्षित किया है। प्रथम सामाजिक बराबरी (Social Equality), द्वितीय सामाजिक परिवर्तन (Social Transformation) और तृतीय सामाजिक अवस्थापना (Social Infrastructure) का है।

विकास नियोजन विकासशील देशों के लिए ही अधिक उपयोगी होता है जहाँ आर्थिक आधार या तो बहुत कम है अथवा नगण्य है। यह उन देशों में पाया जाता है जहाँ श्रम-उत्पादकता, प्रति व्यक्ति आय तथा रहन-सहन का स्तर काफी निम्न होता है। आमतौर पर लघु औद्योगिक सेक्टर एवं संस्थागत बाधाएँ भी यहाँ मिलती हैं। अतएव विकास नियोजन आर्थिक, सामाजिक एवं संस्थापक सुधार को पूर्ण करने वाली मध्यस्थ नीति अपनाता है तथा आर्थिक वृद्धि का जनक होता है। इस प्रकार का नियोजन एशिया के अधिकांश विकासशील देशों, अफ्रीका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में मिलता है। विकास नियोजन की सफलता कुछ हद तक प्रशासनिक व्यवस्था एवं उससे भागीदार जनता की क्षमता पर निर्भर करती है।

3. **आदेशात्मक एवं निर्देशात्मक नियोजन** (Imperative and Indicative Planning)—संगठनात्मक दृष्टिकोण से नियोजन को दो भागों- आदेशात्मक एवं निर्देशात्मक नियोजन में बाँटते हैं—आदेशात्मक नियोजन में अनिवार्यता का अंश रहता है। जब सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) द्वारा देश के संसाधन का विकास आर्थिक वृद्धि हेतु किया जाता है तो इसको आदेशात्मक नियोजन कहते हैं जहाँ व्यक्तिगत क्षेत्र (Individual Area) का सहयोग नगण्य होता है। भारत में पहली से चौथी योजना के दौरान आदेशात्मक नियोजन के महत्त्वपूर्ण लक्षण मिलते हैं। सोवियत संघ एवं अन्य साम्यवादी देशों में प्राय: ऐसा नियोजन किया जाता है जहाँ अधिकांश उत्पादन सरकार द्वारा किया जाता है। पूँजी निवेश निर्धारण सम्बन्धी नीति-निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन सरकार द्वारा ही सम्पादित होता है। इस तरह यह नियोजन केन्द्रीय निर्देशक नियोजन कहलाता है।

   निर्देशात्मक नियोजन के तरह केन्द्रीय नियोजन संस्था द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। इस नियोजन में व्यक्तिगत क्षेत्र का महत्त्व सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है। पश्चिमी यूरोपीय देशों में निर्देशात्मक नियोजन ही अधिक लोकप्रिय है। सरकार व्यक्तिगत क्षेत्र के कार्यों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करती जब तक सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक नीतियों का पालन होता रहता है। इस नियोजन में व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इस तरह नियोजन की प्रक्रिया सहभागिता पर आधारित होती है, उत्पीड़न पर नहीं। इस प्रकार का नियोजन हम फ्रांस में पाते हैं। भारत में भी आठवीं योजना में निर्देशात्मक नियोजन की बात स्वीकार की गयी। 1991 के बाद नव आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में इसे फिर से दोबारा स्वीकार किया गया।

4. **खण्डीय एवं स्थानिक नियोजन** (Sectoral and Spatial Planning)—खण्डीय नियोजन का आशय उस उद्देश्यपूर्ण नियोजन से है जिसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों प्राथमिक (कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन आदि), द्वितीयक (वाणिज्यिक कृषि, विनिर्माण), तृतीयक (परिवहन एवं संचार) एवं चतुर्थक (वित्तीय, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना आदि) का अलग-अलग विकास किया जाता है। भौतिक, सामाजिक-आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता, जनसंख्या एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, भविष्य की माँगों तथा निर्यात आदि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न खण्डों के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

   यद्यपि यह प्रयास करते हैं कि सभी खण्डों में तालमेल हो, परन्तु प्राय: ऐसा नहीं हो पाता है। इस खण्डीय नियोजन के कुछ दोष भी हैं। पहला, इसमें समन्वय-संरचना की कमी हो जाती है जिससे वातावरण प्रदूषण एवं अन्य समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा, खण्डीय नियोजन का समाज पर सम्पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, यह नियोजन एक आर्थिक नियोजन मात्र ही बनकर रह जाता है। खण्डीय नियोजन में चौथी कमी स्थान सम्बन्धी है अर्थात् यह क्षेत्र या प्रदेश विशेष तक ही सीमित रह जाता है, सम्पूर्ण प्रदेश को समाहित नहीं कर पाता।

स्थानीय स्तर की समस्याएँ और मुद्दों के समापन से सम्बन्धित योजना बनाने की प्रक्रिया स्थानीय नियोजन कहलाता है। स्थानीय क्षेत्र नियोजन छोटे क्षेत्रों जैसे—गाँव, बस्ती या मौहल्ले के लिए होता है। स्थानिक नियोजन चार संकल्पनाओं (आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक घटक) को एकीकृत करता है। स्थानीय क्षेत्र का पूर्ण विकास वहाँ के लोगों का कल्याण (Welfare) करना इसकी मुख्य प्राथमिकता (Priority) है। जब तक स्थानिक ढाँचे (Spatial Structure) में परिवर्तन नहीं होता तब तक सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होगी। कभी-कभी आर्थिक तन्त्र के एक खण्ड की विशेष उन्नति से दूसरे खण्ड की उन्नति के लिए अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उद्देश्य के अनुसार स्थानिक नियोजन दो प्रकार

का होता है—(1) समायोजनवादी (Adaptive), एवं (2) विकासोन्मुख (Developmental)। समायोजनवादी नियोजन स्थानिक उद्‌भव की प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है जिससे एक निर्धारित समय में स्थानिक संरचना विकसित हो सके जो विकास एवं क्षमता हेतु उद्योग की जरूरतों के अनुरूप मिल सके। विकासोन्मुख स्थानिक नियोजन राष्ट्रीय आर्थिक विकास की आवश्यकता की प्रतिक्रिया स्वरूप उभरते हैं। विकासोन्मुख अथवा क्रियाशील स्थानिक नियोजन अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वाकांक्षी कार्य है। इसमें आर्थिक तथा स्थानिक विकास क्रम के अन्तर्सम्बन्धों की व्याख्या करके गतिमान एवं ऐतिहासिक सम्बन्ध में स्थानिक संरचना के विकास का एक प्रतिरूप पहचानकर तीव्र आर्थिक विकास (Rapid economic Development) हेतु नियोजन प्रक्रिया को निर्धारित करना पड़ता है। इस तरह आर्थिक-सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का स्थानिक संगठन दीर्घकालीन नियोजन को गतिमान करने में महत्त्वपूर्ण साधन बन जाता है।

प्र.2. प्रादेशिक नियोजन की कार्य पद्धति या विधितन्त्र की विवेचना कीजिए।
Discuss the methodology of regional planning.

उत्तर

प्रादेशिक नियोजन की कार्य-पद्धति या विधितन्त्र (Methodology of Regional Planning)

प्रादेशिक नियोजन की कार्य-पद्धति से अभिप्राय, प्रदेश विशेष के समन्वित विकास हेतु उठाये जाने वाले ठोस कदमों से है। प्रादेशिक नियोजन की कार्य-पद्धति या विधितन्त्र का तात्पर्य नियोजन प्रक्रिया के विधि तन्त्र से है, अर्थात् जब प्रादेशिक नियोजन का उपागम निश्चित हो जाता है, तो सम्बन्धित क्षेत्र में नियोजन की प्रक्रिया क्या अपनायी जाए, उसका अध्ययन विधि तंत्र के तहत आता है। प्रादेशिक नियोजन प्रदेश विशेष के सन्दर्भ में मनुष्य एवं पारिस्थितिकी के आधार पर निश्चित लक्ष्यों को निश्चित अवधि में प्राप्त करने का प्रयास है। इससे स्पष्ट है कि प्रादेशिक नियोजन की कार्य-पद्धति में सर्वप्रथम वर्तमान प्रादेशिकता की पहचान, नियोजन प्रदेश का सीमांकन, प्रदेश की आवश्यकताओं का निर्धारण, प्रदेश के संसाधनों का मूल्यांकन (Evaluation) या भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक तथ्यों का गहन सर्वेक्षण, संसाधनों के आधार पर विकास योजनाओं का निर्माण, कार्यान्वयन एवं परिणामों का आकलन सभी विधितन्त्र के अन्तर्गत आते हैं। क्षेत्र विशेष, उपलब्ध संसाधनों तथा उद्‌देश्यों के अनुसार विधितंत्र भी अलग-अलग अपनाये जाते हैं। इसलिए नियोजन को स्वयं गत्यात्मक प्रक्रिया का परिणाम बताया गया है। प्रादेशिक नियोजन की कार्य-पद्धति या विधितंत्र को निम्नांकित क्रमबद्ध चरणों में विभक्त किया जाता है—

1. **वर्तमान प्रादेशिकता की पहचान** (Identification of Existing Regionalism)—प्रादेशिक नियोजन की कार्यपद्धति के प्रथम चरण में सर्वप्रथम उस प्रदेश के प्रादेशिकता की पहचान की जाती है जिस प्रदेश का नियोजन करना होता है। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश का नियोजन करने से पूर्व नियोजन का उद्‌देश्य ज्ञात होना चाहिए। इसके लिए भौगोलिक क्षेत्र में या देश के अन्दर प्रदेश की पहचान होनी चाहिए। सभी तरह के प्रदेशों के लिए एकसमान नियोजन पद्धति नहीं अपनायी जाती है, वरन भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की नियोजन पद्धति अपनानी पड़ती है। यदि औद्योगिक संसाधन से विपन्न किसी कृषि प्रधान क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनानी है तो उसे कृषि के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा और यदि उसी प्रदेश में औद्योगिक विकास करना भी आवश्यक समझा जाता है तो वहाँ कृषि पर आधारित एवं उससे सम्बन्धित उद्योगों का विकास करना ही व्यावहारिक होगा। इसी प्रकार पर्वतीय प्रदेश, नदी बेसिन क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र, सूखाग्रस्त क्षेत्र, जनजातीय प्रदेश, महानगरीय क्षेत्र आदि के विकास के लिए अलग-अलग प्रकार के नियोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रदेश की वर्तमान वास्तविक स्थिति की पहचान करना अनिवार्य होता है।
2. **नियोजन प्रदेश का निर्धारण/सीमांकन** (Delimitation of Planning Region)—नियोजन के द्वितीय चरण में नियोजन प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। नियोजन प्रदेशों का सीमांकन सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है। एकस्तरीय एवं बहुस्तरीय नियोजन दोनों के लिए प्रदेशों का निर्धारण अनिवार्य है। समग्र रूप में या विभिन्न उद्‌देश्यों के अनुसार विभिन्न पदानुक्रम (Hierarchy) वाले प्रदेशों का निर्धारण करके प्रत्येक प्रदेश के लिए नियोजन प्रस्तावित किया जाता है। प्रदेशों के निर्धारण में वहाँ पाये जाने वाले प्राकृतिक पर्यावरण, मानव समुदाय, विभिन्न प्रकार के संसाधनों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसमें प्राथमिकता वाले प्रदेशों की भी पहचान की जा सकती है।
3. **प्रदेश की आवश्यकताओं का निर्धारण** (Determining the Needs of the Region)—नियोजन के तीसरे चरण में चयनित प्रदेश की आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है। नियोजन प्रदेश की आवश्यकताओं का निर्धारण जितना ही यथार्थ होगा उस प्रदेश का उतना ही बेहतर विकास होगा। इसमें संसाधनों का आकलन कर यह देखा जाता है कि प्रदेश का कौन-सा हिस्सा अभावग्रस्त (Deficit) तथा कौन-सा अतिरेक (Surplus) विशेषता वाला है। अतिरेक या बाहुल्य प्रदेश के आर्थिक विकेन्द्रीकरण तो अभावग्रस्त प्रदेश में मानव की मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना होगा।

इसलिए नियोजन प्रदेश के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा औद्योगिक विशेषताओं का सर्वेक्षण जरूरी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश में विकास के कहाँ एवं किस घटक में कमजोरी है तथा विकास के कौन-कौन लक्ष्य बनते हैं। इसके अनुसार विकास के विभिन्न प्रखण्डों एवं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों एवं समस्याओं का निर्धारण किया जाता है।

4. **प्रदेश के संसाधनों का मूल्यांकन** (Evaluation of Regional Resources)—जिस प्रदेश का नियोजन प्रस्तावित करना है उसके भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विशिष्टिताओं की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। इसमें दो प्रविधियाँ शामिल हैं—

(अ) **साधनों का सर्वेक्षण**—नियोजन प्रदेश का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य सर्वेक्षण है। इसके तहत उन प्राकृतिक एवं मानवीय तथ्यों की सूचनाएँ एकत्र की जाती हैं, जो कि किसी भी स्तर पर प्रादेशिक नियोजन (Regional Planning) को प्रभावित करते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाते हैं—

(i) नियोजन प्रदेश का ऐतिहासिक विकास-क्रम।

(ii) भौतिक तथ्यों का सर्वेक्षण प्राकृतिक बनावट, संरचना, मिट्टी, वनस्पति, संसाधन जलवायु, प्राकृतिक आदि।

(iii) सामान्य भूमि उपयोग—कृषित भूमि, वन भूमि, परती भूमि, अन्य भूमि उपयोग आदि।

(iv) अवस्थानात्मक तत्त्व—ऊर्जा आपूर्ति, जलापूर्ति साधन, वित्तीय संस्थान, शिक्षण-प्रशिक्षण सुविधाएँ, चिकित्सा केन्द्र, परिवहन, संचार एवं सूचना साधनों का सर्वेक्षण आदि।

(v) वाणिज्यिक विशिष्टताएँ, विभिन्न सेवाओं की स्थिति, वितरण एवं प्रकार।

(vi) जनसंख्या और उसकी विशिष्टताएँ-आयु, स्वास्थ्य, पारिवारिक एवं व्यावसायिक संरचना आदि।

(vii) सामाजिक—शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ।

(viii) नगर सर्वेक्षण—ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नगर विकास, आकारिकी, व्यावसायिक संरचना, परिवहन, नगर प्रदेश आधारित नगर-ग्राम सम्बन्ध आदि।

उपर्युक्त शीर्षकों के अन्तर्गत व्यापक सर्वेक्षण करके योजना प्रदेश के बारे में प्रारम्भिक सूचनाएँ प्राप्त की जाती हैं।

(ब) **मॉनीटर करना** (Monitoring)—इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके योजना प्रदेश के सन्दर्भ में वर्तमान विकास प्रतिरूप का निर्देशात्मक आकलन किया जाता है। उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है, जिनको शीघ्र विकसित करना है। विभिन्न संसाधनों के उपयोग के पुनर्गठन का भी अनुमान लगाया जाता है।

5. **प्रदेश की विकास योजना का निर्माण** (Making a Development Plan for the Region)—उपर्युक्त सूचनाओं से प्रदेश के संसाधन सम्बन्धी गुणात्मक सूचनाएँ उपलब्ध रहती हैं। तब सम्पूर्ण प्रदेश को विभिन्न स्तरों एवं क्रमों में बाँटकर योजनाएँ बनायी जाती है। सर्वाधिक महत्त्व उन योजनाओं को प्रदान किया जाता है, जो उस प्रदेश विशेष के त्वरित विकास के लिए आवश्यक हैं। इस विधि में प्रदेश के लिए एक विकास योजना बनायी जाती है। यह योजना एक निश्चित अवधि के लिए तैयार की जाती है। कुछ योजनाएँ अल्पकालीन (Short-term) तथा कुछ दीर्घकालीन (Long-term) होती हैं। कभी-कभी प्रदेश में दोनों ही प्रकार की योजनाएँ जरूरत के अनुरूप बनानी पड़ती हैं।

प्रदेश की विकास योजना निर्माण के अन्तर्गत प्राथमिक, द्वितीयक आर्थिक कार्यों में समन्वयन स्थापित करके क्रमशः इनके स्तर में अभिवृद्धि करना होता है। दूसरे शब्दों में, प्रदेश विशेष में संसाधन उपलब्धता अनुसार विविध प्रकार के प्राथमिक कार्य जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन आदि का सम्बन्धित उद्योगों से इस प्रकार का घनिष्ठ अन्तर्सम्बन्ध करना है कि सभी का सम्यक् विकास हो सके। एतदर्थ (अ) एक ओर अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक नियोजन-उत्पादन लक्ष्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता पड़ती है तो दूसरी ओर (ब) प्रदेश पदानुक्रम में विभिन्न स्तर के उद्योगों की अवस्थिति का निर्धारण एवं उनकी पारस्परिक शृंखलाबद्धता का स्वरूप निरूपण करना पड़ता है।

6. **योजना का कार्यान्वयन** (Implementation of the Plan)—योजनाएँ बनाने के बाद उसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संस्थागत संगठनों/प्रशासनिक अधिकारियों पर रहता है। योजना की रचना से अधिक महत्त्वपूर्ण उसका कार्यान्वयन होता है। भारत में आमतौर पर योजनाएँ बड़ी उत्सुकता से बनती हैं, परन्तु उनके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। कार्यान्वयन में प्रशासनिक संगठनों के अलावा विशेषज्ञ, स्थानीय जनता तथा जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

TOUCH 'n' PASS

7. **योजनाओं का मूल्यांकन** (Plan Assessment)—उपर्युक्त सभी प्रक्रियाएँ पूर्ण हो जाने पर एक ओर प्राकृतिक पर्यावरण पर आर्थिक क्रियाकलाप का प्रभाव तो दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था पर प्रतिक्रिया का आकलन और विश्लेषण (Analysis) प्रादेशिक नियोजन का अभिन्न अंग बन गया है। इसका मापदण्ड (Parameter) यह है कि क्या ये आर्थिक क्रियाकलाप प्रदेश में जनसामान्य के जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि में सहायक हैं। प्रदेश में योजनाओं के लागू करने की प्रक्रिया और लागू हो जाने के उपरांत समयानुसार उसके परिणामों का आकलन किया जाना चाहिए। इससे योजना कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों एवं विसंगतियों (Deformaties) को दूर करने में पर्याप्त मदद मिलती है। साथ ही योजना के गुण-दोष (Merit Demerit) की विवेचना भी समय-समय पर की जानी चाहिए। तभी वह योजना पूर्णतया सफल होगी।

वर्तमान में विद्वानों की सामान्य अवधारणा है कि नियोजन का कार्य एक बार पूर्ण होने तक ही नियोजक का कार्य सीमित नहीं होता है वरन उसके बाद भी परियोजना के निरीक्षण, परीक्षण, पुनरावलोकन, कार्यक्रम में सुधार आदि की जरूरत होती है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि जो परियोजना तैयार होने के बाद क्रियान्वित हो गयी उसकी सफलता सुनिश्चित ही है। सभी तैयार की गयी परियोजनाएँ हमेशा सफल नहीं होती हैं।

प्र.3. नियोजन प्रदेशों को समझाते हुए वृहत-प्रदेश का वर्णन कीजिए।

Describe the macro region and planning regions.

उत्तर वह विशिष्ट क्षेत्रीय इकाई जिसके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कोई सुनिश्चित योजना बनायी जाती है या बनायी जा सकती है, नियोजन प्रदेश (Planning region) कहलाता है। नियोजन क्षेत्रीय विकास की वह प्रणाली है। जिसके द्वारा किसी देश या क्षेत्र के संसाधनों का सर्वोत्तम (Optimum) उपयोग करते हुए उच्चतम सामाजिक-आर्थिक स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। **ए. ई. स्मेल्स** के अनुसार, 'नियोजन प्रादेशिक स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रादेशिक स्तर पर नियोजन किए अनेक तथ्यों का नियोजन छूट जाता है तथा अनेक का नियोजन वास्तविक स्तर के अनुकूल नहीं हो पाता है।' यह विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला संगठित, सचेतन तथा सतत् प्रयास है। नियोजन के तहत प्राय: किसी कल्याणकारी सरकार द्वारा किसी देश या प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु बनाए गए कार्यक्रम तथा उसके क्रियान्वयन को शामिल किया जाता है। सरकारी नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, प्रादेशिक तथा अन्तरप्रादेशिक विषमताओं (Disparities) को दूर करने और वहाँ के निवासियों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने तथा सुधारने का सुसंगठित प्रयास किया जाता है। नियोजन का उद्देश्य प्राय: क्षेत्र के दीर्घकालीन तथा संपोषणीय (Sustainable) सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित होता है। विकासशील देशों के पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए नियोजन एक अत्यंत उपयोगी, सार्थक तथा अपरिहार्य प्रणाली है। नियोजन एक संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई समाज अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करता है।

नियोजन के उद्देश्य से चयनित प्रदेश प्रशासनिक या राजनीतिक हो सकते हैं, जैसे—राज्य, जिला अथवा विकासखण्ड। प्राय: नियोजन के लिए आवश्यक आँकड़े प्रशासनिक (Administrative) प्रदेशों के लिए एकत्र किए जाते हैं। अत: नियोजन प्रदेश वास्तविक रूप में प्रशासनिक प्रदेश होते हैं। राष्ट्रीय नियोजन के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र, राज्य नियोजन के लिए सम्पूर्ण राज्य तथा लघु स्तर पर नियोजन के लिए जिला या विकासखण्ड नियोजन प्रदेश के रूप में चिह्नित किए जाते हैं। नियोजन प्रदेशों में धरातलीय एवं सामाजिक-सांस्कृतिक समांगता के साथ-साथ आर्थिक संरचना में भी समरूपता होना जरूरी है। नियोजन प्रदेश का विस्तार इतना होना चाहिए कि उसमें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों जो उसकी अर्थव्यवस्था के विकास को गति दे सकें। साथ ही आन्तरिक तथ्यों में समांगता होनी चाहिए। मानव एवं माल के प्रवाह की उपयुक्त गति से नियन्त्रित करने हेतु नियोजन प्रदेश में कुछ संकेन्द्रीय बिन्दु (Nodal Centre) होने जरूरी हैं।

एक श्रेष्ठ नियोजन प्रदेश में प्राकृतिक दशाओं, आर्थिक संसाधनों, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशाओं आदि में समांगता या समरूपता (Homogeneity) पायी जाती है। टेलर महोदय के अनुसार, 'नियोजन प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि अपने आस-पास के क्षेत्रों से बहुत भिन्न होते हुए भी उनसे जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि इसमें अभिकेन्द्रीय शक्तियाँ उपस्थित होती हैं, जो पूरे क्षेत्र को एकीकृत करके रखती हैं।' ऐसी अभिकेन्द्रीय शक्तियाँ या तो प्राकृतिक हो सकती हैं; जैसे—कि नदी घाटी में नदी जो सारे प्रदेश के एकीकरण का सूत्रधार होती है या ऐसी शक्तियाँ मानव प्रक्रिया जनित भी हो सकती हैं। जैसे कि महानगर और इसके चारों और के क्षेत्र में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध। इसलिए नियोजन प्रदेश एक ऐसी क्षेत्रीय इकाई होती है जिसे नियोजन का आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि एक ओर तो इसमें स्वयं में कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जो इसे अपने आस-पास के क्षेत्र से भिन्न बनाते हैं और दूसरी ओर यह क्षेत्र अन्य प्रदेशों से भी इस प्रकार से एकीकृत होता है कि इसे उनके सन्दर्भ के बिना ठीक तरह जाना ही नहीं जा सकता। कोई भी नियोजन प्रदेश सम्पूर्ण प्रादेशिक-स्थानिक तन्त्र का अभिन्न अंग (Part and Parcel) होता है। नियोजन प्रदेश राष्ट्रीय, प्रादेशिक अथवा अन्य लघु स्तरों पर अनुसार यह वृहद् स्तरीय, मध्यम स्तरीय और लघु स्तरीय होता है।

नियोजन प्रदेशों का प्रदर्शित पदानुक्रम सापेक्ष (Relative) है। भौगोलिक (Geographical) रूप में प्रादेशिकरण में वृहत् (Macro), मध्यम (Meso) एवं लघु (Micro) शब्दावलियों का प्रयोग सापेक्षिक सन्दर्भ में किया जाता है। सम्पूर्ण भौगोलिक इकाई या देश के सन्दर्भ में पदानुक्रम के क्षेत्रीय आकार अलग-अलग होते हैं; जैसे—भारत के सन्दर्भ में वृहत्, मध्यम एवं लघु के क्षेत्रीय विस्तार अलग-अलग होते हैं, जबकि किसी राज्य के सन्दर्भ में उक्त पदानुक्रम के क्षेत्रीय विस्तार अलग-अलग होंगे। जहाँ तक नियोजन प्रदेश का सवाल है। उसमें उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सामाजिक-आर्थिक तन्त्र का पुनर्व्यवस्थापन भविष्य के सन्दर्भ में किया जाता है। नियोजन प्रदेशों के अनुमाप अनुक्रम को निम्न रूप में प्रदर्शित किया जा सकता हैं—

नियोजन प्रदेशों के अनुमाप अनुक्रम

(अ)	प्रथम श्रेणी के नियोजन प्रदेश	वृहत् (Macro) अनुमाप के नियोजन प्रदेश
(ब)	द्वितीय श्रेणी के नियोजन प्रदेश	मध्यम (Meso) अनुमाप के नियोजन प्रदेश
(स)	तृतीय श्रेणी के नियोजन प्रदेश	लघु (Micro) अनुमाप के नियोजन प्रदेश

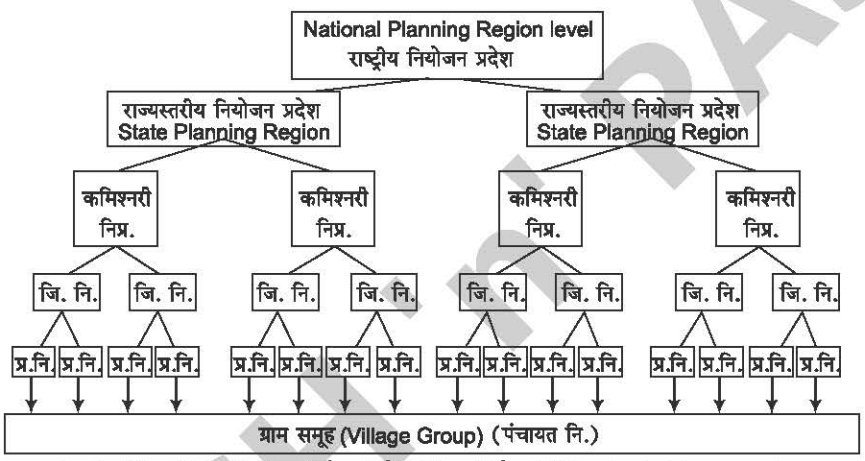

सूची—जि. = जिला, नि.प्र. = नियोजन प्रदेश, नि. = नियोजन, (Planning) प्र. = प्रखण्ड

चित्र–1

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नियोजन प्रदेश की संकल्पना, भौगोलिक प्रदेश की संकल्पना से थोड़ी अलग हटकर है, क्योंकि नियोजन प्रदेशों में सामाजिक-आर्थिक तन्त्र का सम्यक मूल्यांकन (Evaluation) उनसे सम्बन्धित सूचनाओं की सुलभता पर निर्भर करता है। संयोग से ये सूचनाएँ विभिन्न पदानुक्रम वर्ग की प्रशासकीय इकाइयों के सन्दर्भ में मिलती हैं और दूसरे नियोजन कार्यों के संचालन की मशीनरी भी उन्हीं इकाइयों के सन्दर्भ में उपलब्ध रहती है। अतएव नियोजन प्रदेश में सीमांकन का आधार प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं। और नियोजन प्रदेश का पदानुक्रम भी विभिन्न पदानुक्रम वर्ग की प्रशासनिक इकाइयों (Administrative Units) की सीमाओं के साथ किया जाता है। प्रशासनिक सीमाओं से परिसीमित नियोजन की प्रादेशिक इकाइयाँ योजनाओं के क्रियान्वयन की सुविधा प्रदान करती हैं। प्रशासनिक स्तर पर विकसित नियोजन प्रदेशों के लिए पूँजी निवेश तथा संसाधनों के अनुकूलतम आकलन और उपयोग को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रशासनिक अनुमाप अनुक्रम में भी पदानुक्रमण का गुण होता है, जिसके अनुरूप नियोजन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रम अन्तर्सम्बन्धित होता है। भारत में प्रचलित इस सन्दर्भ के नियोजन प्रदेशों के पदानुक्रमण अनुक्रम को निम्न रूप में प्रतिरूपित किया जा सकता है—

नियोजन प्रदेशों की अनुमापीय व्यवस्था में अन्त:क्रियात्मक सम्बन्ध का होना जरूरी होता है। इस दृष्टि से प्रत्येक अनुमाप श्रेणी में गुणों की समरूपता, मार्ग संगमता तथा प्रशासनिक सुविधाओं के बीच एक न्यूनतम साहचर्य का गुण आवश्यक होता है। नियोजन प्रदेशों की अनुमाप संकल्पना के अन्तर्गत नियोजन इकाइयों के समूहन की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए, एक गाँव प्राय: नियोजन प्रदेश का अनुमाप प्राप्त नहीं कर सकता है। यह मात्र एक नियोजन इकाई माना जा सकता है। पर्याप्त संख्या में गाँवों के समूहन से निर्मित ग्राम पंचायत निम्न अनुपात स्तरीय नियोजन प्रदेश के रूप में स्वीकारा जा सकता है।

सभी तरह के नियोजन प्रशासनिक सुविधा, विकास मापक, जीवनोपयोगी आर्थिक साधन इत्यादि के आधार पर अलग-अलग किए जाते हैं। सभी योजनाओं का क्रियान्वयन (Implementation) एवं संचालन विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्तरीय संगठनों द्वारा किया जाता है। अत: भौगोलिक विषय क्षेत्र के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से संगठित, संचालित तथा कार्यान्वित करने के लिए तीन कार्यक्रम स्तर-वृहत् (Macro), मध्यम (Meso) तथा लघु (Micro) निर्धारित किए गए हैं।

TOUCH 'n' PASS

इनका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है—

(अ) वृहद् नियोजन प्रदेश (Macro Planning Regions)

किसी बड़े क्षेत्र के संसाधन विकास के लिए चयनित प्रदेश को बृहत् नियोजन प्रदेश कहा जाता है। बृहत् नियोजन प्रदेश का क्षेत्रफल लघु एवं मध्यम प्रदेश की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। ये प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से तीनों प्रकार के प्रदेशों में से सबसे बड़े होते हैं। ये प्रदेश नियोजन के प्रथम आर्थिक इकाई के रूप में होते हैं। प्रत्येक वृहत् प्रदेश में दो या दो से अधिक मध्य-स्तरीय प्रदेश समाहित होते हैं। हाँ, यह कहना कठिन होगा कि एक वृहत् प्रदेश में अधिकतम कितने मध्य-स्तरीय प्रदेश हो सकते हैं। नियोजन के क्षेत्र में किसी भी स्तर के प्रदेश के क्षेत्र तथा आकार का मानकीकरण सम्भव नहीं होता। एक बृहत् प्रदेश का क्षेत्र व आकार उसके देश के क्षेत्रफल तथा स्थलाकृति पर निर्भर कर सकता है। इस प्रदेश के अन्तर्गत न्यूनतम एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के भाग (जिला) सम्मिलित होते हैं। इन प्रदेशों में संसाधन (Resources) की विशालता को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। ये प्रदेश चाहे स्वावलम्बी न भी हों तो भी इनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती है तथा यहाँ सामान्य जीवन गुणवत्ता भी उच्च कोटि की होती है। वृहत नियोजन प्रदेशों में विशद संसाधन विकास सम्बन्धी निर्णय भी लिए जाते हैं। उदाहरणार्थ, नदी-घाटी विकास कार्यक्रम, सिंचाई सम्बन्धी परियोजनाएँ, विद्युत उत्पादन सम्बन्धी परियोजनाएँ, कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम, खाद्यसामग्री सम्बन्धित आत्मनिर्भरता, औद्योगिक संरचना के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम तथा उद्योगों को ऊर्जा आपूर्ति आदि प्रधान कार्यक्रम हैं। चूँकि ये समस्याएँ राज्यों या उनसे बड़ी इकाइयों से सम्बन्धित हैं। अत: इस प्रदेश में कम-से-कम एक राज्य या दो अथवा तीन राज्यों के भाग सम्मिलित होते हैं।

वृहत् नियोजन प्रदेश ऐसे क्षेत्र होने चाहिए जिसमें पूर्ण आंतरिक आत्मनिर्भरता पायी जाती हो। इसमें उपलब्ध शक्ति संसाधन पर आधारित औद्योगिक संश्लिष्ट या संभावित औद्योगिक विकास के केन्द्रक भी होने चाहिए। इस केन्द्रक को भी उस प्रदेश में शीर्ष केन्द्रक के रूप में रहना चाहिए, जो प्रदेश के अन्य भागों से जुड़ा हो। इतना ही नहीं, वृहत् प्रदेशों में बड़े केन्द्रों (Nodes) की भी आवश्यकता पड़ती है, जो उस प्रदेश के विकास हेतु वित्तीय संगठन तथा तकनीक उपलब्ध करा सकें, लेकिन विकासशील देशों में ऐसे केन्द्रों का अभाव होता है। विकासशील देशों में सभी वृहत् प्रदेशों में बड़े औद्योगिक केन्द्र विकसित नहीं होते हैं। भारत में मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरू आदि बड़े औद्योगिक केन्द्र (Instustrial centre) के रूप में विद्यमान हैं।

वृहत् प्रदेशों में विद्यमान प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों (Human Resources) की उपलब्धता के अनुसार उसे खाद्य सामग्री, रोजगार तथा सेवाओं में आत्मनिर्भर होने की क्षमता भी आवश्यक मानी जाती है। भारत के सन्दर्भ में वृहत् नियोजन प्रदेशों का विस्तार राज्य स्तरीय होता है और ऐसे प्रत्येक प्रदेश में कम-से-कम एक राज्य अवश्य शामिल होना चाहिए। इसके तहत कुछ राज्यों के उपविभाग (जनपद या तहसीलें) भी शामिल हो सकते हैं। ये प्रदेश आर्थिक तंत्र में ऐसे जुड़े हों जो अपने आन्तरिक तथा बाह्य प्रदेशों में वस्तुओं, जनसंख्या एवं विचारों का सरलतापूर्वक आदान-प्रदान कर सकें। वृहत् प्रदेशों को खाद्य, रोजगार स्तर, सामग्रियों एवं सेवाओं को उत्पादित करने की सम्भावित क्षमता के अनुरूप आत्मनिर्भर (Self-sufficient) होना चाहिए, जो दूसरे क्षेत्रों के नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की तृतीयक आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकें। नियोजन प्रदेश में आवश्यक पारिस्थितिकी (Ecosystem) सन्तुलन भी इन्हीं वृहत् प्रदेशों द्वारा सम्भव होता है।

वृहत् प्रदेश मात्र ऐसे न हों जहाँ अन्तर्सम्बन्धीय समस्याओं का समाधान करना हो वरन् इसमें समन्वित विकास के लिए जरूरी संसाधनों का जाल भी विद्यमान हो। उदाहरणस्वरूप शक्ति संसाधन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। यह आर्थिक क्रियाओं के प्रसार एवं बिखराव में सहायक होता है।

प्र.4. प्रादेशिक पदानुक्रम के आधार पर प्रदेशों का वर्गीकरण दीजिए।
Give the classification of regions on the basis of Regional Hierarchy.

उत्तर

प्रादेशिक पदानुक्रम के आधार पर प्रदेशों का वर्गीकरण
(Classification of Regions on the Basis of Regional Hierarchy)

जब आरोही क्रम के अनुसार, पृथ्वीतल को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित किया जाता है तो उस प्रणाली को प्रादेशिक पदानुक्रम कहा जाता है। प्रादेशिक पदानुक्रम के आधार पर प्रदेशों के वर्गीकरण में जे. एफ. अनस्टेड (J. F. Unstead), डी. एल. लिण्टन (D. L. Linton), डी. ह्वीटलसी (D. Whittlesey, 1956) और प्रेस्टन जेम्स का योगदान (Contribution) महत्त्वपूर्ण रहा है।

1. **जे. एफ. अनस्टेड द्वारा वर्णित प्रादेशिक पदानुक्रम**—ब्रिटिश भूगोलवेत्ता अनस्टेड महोदय ने सन् 1933 में आरोही क्रम में प्रादेशिक पदानुक्रम को निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया है—(i) उप क्षेत्र (Stow), (ii) क्षेत्र (Tract), (iii) उप-प्रदेश (Sub-Region), (iv) सूक्ष्म प्रदेश (Minor Region) तथा (v) मुख्य प्रदेश (Major Region)।

2. **डी. एल. लिण्टन द्वारा वर्णित प्रादेशिक पदानुक्रम**—सन् 1949 में लिण्टन महोदय ने आरोही क्रम में आकृतिक प्रदेशों के सात अनुक्रम (Sequence) बताए हैं—(i) स्थल (Site) या ढाल (Slope) या फ्लैट्स (Flats), (ii) लघु क्षेत्र या उप-क्षेत्र (Stow), (iii) क्षेत्र (Tract), (iv) खण्ड (Section), (v) प्रान्त (Province), (vi) मुख्य विभाग (Major Division), (vii) महाद्वीप (Continent)।
3. **ह्विटलसी द्वारा वर्णित प्रादेशिक पदानुक्रम**—डी. ह्वीटलसी ने सन् 1956 में अपने एक शोध पत्र में भौगोलिक प्रदेश या सकल प्रदेश (Total Region) हेतु कम्पेज (Compage) शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कम्पेज का पदानुक्रम निर्धारित किया जो इस प्रकार है—(i) स्थानीय क्षेत्र (Locality), (ii) जनपद (District), (iii) प्रान्त (Province), (iv) परिमण्डल (Realm) को शामिल किया।
4. **ए. के. फिलब्रिक द्वारा वर्णित प्रादेशिक पदानुक्रम**—फिलब्रिक महोदय ने सन् 1957 में आरोही क्रम में सात वर्गीय प्रादेशिक पदानुक्रम को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है—(i) गाँव, (ii) कस्बा या सेवा केन्द्र, (iii) मध्य नगर, (iv) बड़ा नगर, (v) महानगर, (vi) महानगरीय प्रदेश (vii) प्राइमेट नगर को शामिल किया।

आर. पी. मिश्र ने अपनी सम्पादित पुस्तक 'Regional Planning' में प्रादेशिक इकाइयों के पदानुक्रम (Hierarchy of Regional Units) को निम्न आरेख द्वारा किया है—

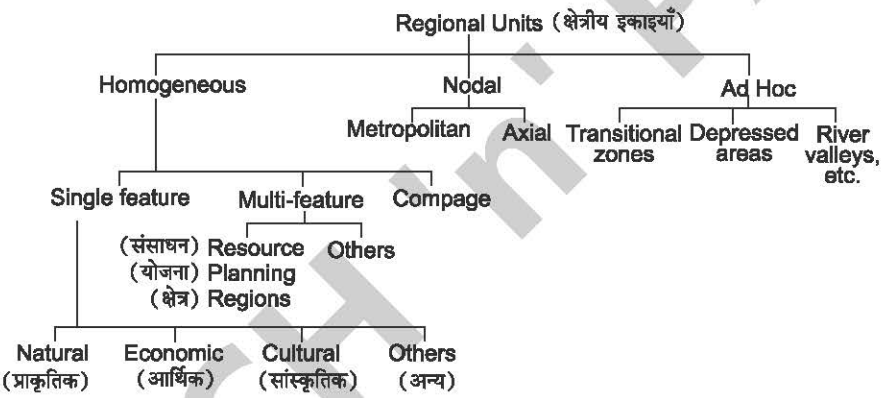

साधारणत: भौगोलिक अध्ययनों में प्रादेशिक पदानुक्रम इस प्रकार होता है-ग्राम, ग्राम पंचायत, विकासखण्ड, तहसील, जिला, मण्डल, प्रदेश/राज्य, देश तथा महाद्वीप। जल एवं स्थल तत्त्व के आधार पर महासागर एक प्रदेश है तो महाद्वीप (स्थलीय भाग) दूसरा प्रदेश है। इनको वृहत् प्रदेश कहा जाता है, किन्तु चयनित तत्त्व के क्षेत्रीय वितरण में जितनी अधिक भिन्नता मिलती है। प्रदेश का आकार उतना ही लघु होता है, जैसे—नगर प्रदेश। आकार की दृष्टि से किसी भी प्रदेश के पदानुक्रम के निम्न तीन वर्ग होते हैं—

1. व्यष्टि या वृहत् प्रदेश,
2. मध्यम प्रदेश,
3. सूक्ष्म या लघु प्रदेश।

1. **व्यष्टि या वृहत् प्रदेश** (Macro Regions)—सर्वप्रथम विश्व को वृहत् प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करने का महत्त्वपूर्ण प्रयास सन् 1905 ई. में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता (Geologist) एण्ड्रयू जॉन हरबर्टसन ने किया। हरबर्टसन का विश्व को वृहत् प्रदेशों में विभाजित करने का सर्वप्रमुख उद्देश्य यह था कि विश्व को वृहत् प्रदेशों में विभाजन राजनीतिक सीमाओं के आधार पर न होकर प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के आधार पर होना चाहिए। हरबर्टसन ने वृहत् प्रदेशों के सीमांकन में जलवायु (Climate) तथा प्राकृतिक वनस्पति की समरूपता को मुख्य रूप से आधार माना। प्रो. रामलोचन सिंह ने भारत को संरचना, उच्चावच तथा स्थलाकृति के आधार पर चार वृहत् प्रदेशों (हिमालय पर्वतीय प्रदेश, वृहद् मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि तथा भारतीय तट व द्वीपों) में विभक्त किया। वृहत् प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उसमें उन एक या दो तथ्यों की लगभग समरूपता (Uniformity) मिलती है। जिनके आधार पर व्यष्टि या वृहत् प्रदेशों को विभक्त किया जाता है। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि वृहत् प्रदेशों की सीमाएँ राजनीतिक सीमाओं से

TOUCH 'n' PASS

सम्बन्धित न होकर स्पष्ट प्राकृतिक सीमाओं का अनुसरण करती हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व के राष्ट्रीय प्रदेशों के सन्दर्भ में भारत एक वृहत् प्रदेश है। जबकि भारत के भौतिक प्रादेशिक विभाजन में प्रायद्वीपीय पठारी भाग एक वृहत् प्रदेश है। प्रायद्वीपीय पठारी वृहत् प्रदेश है को कई प्रदेशों में विभाजित किया जाता है; जैसे—छोटा नागपुर पठार, बुन्देलखण्ड पठार, बघेलखण्ड पठार इत्यादि। ये मध्यम स्तर के प्रदेश (Meso Regions) हैं तथा इनके उप-विभाग जैसे छोटा नागपुर पठार का उपविभाग रांची पठार तृतीय स्तर का प्रदेश अर्थात् लघु प्रदेश (Micro Region) है। इसके अलावा व्यष्टि या वृहत् प्रदेशों के सीमांकन में मानवीय क्रिया-कलापों तथा उनके अन्तर्सम्बन्धों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

2. **मध्यम प्रदेश** (Meso Regions)—वृहत् प्रदेशों के विस्तृत एवं वैज्ञानिक अध्ययन हेतु उन्हें पुनः कई मध्यम प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। मध्यम प्रदेश, वृहत् प्रदेशों की तुलना में छोटे क्षेत्रीय इकाई होते हैं। मध्यम प्रदेशों के सीमांकन हेतु कई अतिरिक्त कारकों को आधार माना जाता है। प्रो. रामलोचन सिंह ने भारत के 4 वृहत् प्रदेशों को पुनः 28 मध्यम आकार के प्रदेशों में विभक्त करते समय पाया कि कुछ मध्यम प्रदेशों की सीमाओं का निर्धारण उन प्रदेशों की पूर्व निर्धारित स्पष्ट भौतिक तथा सांस्कृतिक (Cultural) सीमाओं के कारण स्वयं ही हो जाता है, जैसे बुन्देलखण्ड प्रदेश। दूसरी ओर, कुछ मध्यम प्रदेशों को उनके केन्द्रीय भाग तथा केन्द्रीय भाग पर निर्भर समीपवर्ती भूमि के आधार पर सीमांकित किया जाता है, उदाहरण के लिए मालवा प्रदेश। मध्यम प्रदेश के द्वारा किसी क्षेत्र को अधिक गहनता से समझने में मदद मिलती है।
3. **सूक्ष्म या लघु प्रदेश** (Micro Regions)—ये प्रदेश किसी क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई होते हैं। मध्यम प्रदेशों की तरह सूक्ष्म या लघु प्रदेशों के सीमांकन के कोई निश्चित मापदण्ड नहीं होते फिर भी मध्यम प्रदेशों को सांस्कृतिक विकास स्तर, भौतिक विशेषताओं तथा स्थानीय समस्याओं की सघनता व विरलता के आधार पर लघु प्रदेशों में बाँटा जाता है। प्रो. रामलोचन सिंह के अनुसार, सामान्यतया लघु प्रदेशों का सीमांकन भौतिक दशाओं तथा सांस्कृतिक तथ्यों के स्वरूप के आधार पर किया जाता है। कभी-कभी आर्थिक विकास का स्तर भी इन प्रदेशों के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण आधार बन सकता है। वृहत् नगरीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा महानगर स्वयं में एक लघु प्रदेश हो सकते हैं। जिनकी अपनी अलग संस्कृति व आर्थिक विकास का स्तर तथा समस्याएँ होती है। दूसरी ओर एक विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र जिसमे पशुपालन, कृषि तथा अन्य कुटीर उद्योग होने के साथ-साथ अलग संस्कृति व आर्थिक विकास का स्तर मिलता है, एक सूक्ष्म या लघु प्रदेश हो सकता है। लघु प्रदेश के तहत किसी क्षेत्र का सर्वाधिक गहन अध्ययन किया जाता है। आज भूगोल में अनुसंधान कार्य लघु-प्रदेशों के चयन की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिससे लघु क्षेत्र के सभी संसाधनों का पता लगाकर विकास कार्य किया जा सके।

प्रदेशों का वृहत् प्रदेश, मध्यम प्रदेश तथा लघु प्रदेश में विभाजन सापेक्षिक (Relative) है। वहीं प्रदेश एक प्रकार की गणना में लघु प्रदेश होगा तथा दूसरी गणना में मध्यम प्रदेश तथा तीसरी में वृहत् प्रदेश। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे बिहार राज्य, राज्य के जिलों, तहसीलों तथा ब्लॉक के सापेक्ष में एक वृहत् प्रदेश (Macro-Region) है, जबकि बिहार भारत के राज्यों के आकार परिप्रेक्ष्य में मध्यम प्रदेश (Meso-Region) है तथा विश्व राजनीतिक प्रदेशों के सापेक्ष्य बिहार एक लघु प्रदेश (Micro-Region) है।

प्र.5. सामान्य लक्षणों तथा कार्यों के आधार पर प्रदेशों का सामान्य वर्गीकरण दीजिए।
Describe the general classification of regions on the basis of general characteristics and functions.

उत्तर

सामान्य लक्षणों तथा कार्यों के आधार पर प्रदेशों का सामान्य वर्गीकरण (General Classification of Regions on the Basis of General Characteristics and Functions)

विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने प्रदेशों को उनके सामान्य लक्षणों और कार्यों के आधार पर निम्न सात प्रदेशों में विभक्त किया है—

1. आकृतिक/आकारजनक/समरूपी प्रदेश;
2. सकेन्द्रीय/कार्यात्मक/कर्मोपलक्षी/कार्य प्रधान प्रदेश;
3. कम्पेज;
4. जननिक/सामान्य/जातीय प्रदेश;
5. विशिष्ट प्रदेश;

TOUCH 'n PASS

6. प्राकृतिक प्रदेश; Natural Region
7. भौगोलिक प्रदेश (Geographical Region)।

1. **आकृतिक/आकारजनक/समरूपी प्रदेश** (Formal/Uniform Regions)—सर्वप्रथम हंस करोल ने क्षेत्रीय इकाई में समरूपी प्रदेश की विवेचना की। फोके स्टीन महोदय के अनुसार, 'समरूपी प्रदेश ऐसा प्रदेश होता है जिसमें एक या अधिक लक्षणों की समानता मिलती है।' अर्थात् समरूपी प्रदेश में किसी एक या एक से अधिक तत्त्व के समांग वितरण को दर्शाया जाता है। समरूपी प्रदेश से स्थैतिक विचार (Static Concept) का बोध होता है। समरूपी प्रदेश का निर्धारण स्थैतिक लक्षणों के आधार पर होता है। 1950 तक इसी तरह के अध्ययन अधिक प्रचलित थे।
मानवीय या प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर समरूपी प्रदेश में निम्नलिखित 2 वर्ग हैं—

(i) **एकल तत्त्व प्रदेश** (Single Feature Region)—जब किसी प्रदेश में एक प्राकृतिक या मानवीय तत्त्व की समरूपता या समांगता (Homogeneity) होती है तो उसे एकल तत्त्व प्रदेश कहते हैं। इसमें एक तत्त्व के वितरण की समांगता तथा कई तत्त्वों का सम्मिश्रण (Mixture) रहता है; जैसे—भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश में एक प्रकार की समान (Uniform) जलवायु मिलती है, जो उस प्रदेश की प्रथम पहचान है, किन्तु उस प्रदेश के तहत सभी भौतिक तथा मानवीय भौगोलिक तत्त्वों का सम्मिश्रण तथा अन्तर्सम्बन्ध मिलता है। ये तत्त्व निम्न हो सकते हैं—

क्र० सं०	तत्त्व (Elements)	आकारजनक प्रदेश (Formal Regions)
1.	चट्टानें (Rocks)	संरचनात्मक प्रदेश (Structural Regions)
2.	उच्चावच (Relief)	भौतिक/स्थलाकृतिक/भू-आकृतिक प्रदेश (Physical/ Physiographic/Geomographic Regions)
3.	जलवायु (Climate)	जलवायु प्रदेश (Climate Regions)
4.	मिट्टी (Soil)	मृदा प्रदेश (Soil Regions)
5.	वनस्पति (Vegetation)	वनस्पति प्रदेश (Vegetation Regions)
6.	जीव (Animals)	जीव प्रदेश (Zoological Regions)
7.	वनस्पति एवं जीव (Plants and Animals)	जैविक प्रदेश (Biotic Regions)
8.	भाषा (language)	भाषा प्रदेश (Language Regions)

(ii) **बहुल तत्त्व प्रदेश** (Multi feature Region)—जब किसी प्रदेश में एक से अधिक मानवीय या प्राकृतिक तत्त्वों की समरूपता या समांगता (Homogeneity) होती है तो उसे बहुल तत्त्व प्रदेश कहते हैं। उदाहरण के लिए, भौतिक प्रदेश (भूगर्भिक संरचना, उच्चावचन तथा अपवाह), प्राकृतिक प्रदेश (Natural Regions) (उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति आदि) सांस्कृतिक प्रदेश (मानवीय प्रजाति, धर्म, भाषा, प्रथाऐं, जीवन पद्धति तथा दर्शन आदि तत्त्वों के आधार पर), भौगोलिक प्रदेश (विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय तत्त्वों के आधार पर), आर्थिक प्रदेश (Economic Regions) (कृषि, पशुपालन, उद्योग, परिवहन, व्यापार तथा सेवाएँ आदि तत्त्वों के आधार पर)।

2. **कार्यात्मक/कर्मोपलक्षी/कार्य प्रधान/सकेन्द्रीय प्रदेश** (Functional or Nodal Regions)—इसे सकेन्द्रीय प्रदेश (Nodal Regions) भी कहा जाता है। इस तरह के प्रदेश में केन्द्रीयता (Centrality) की उपस्थिति अनिवार्य होती है और ऐसे प्रदेश का विस्तार प्राय: एक केन्द्रीय स्थिति (केन्द्र, स्थल, नगर, समुद्री पत्तन आदि) के चारों ओर पाया जाता है। पी.ई. जेम्स के अनुसार, 'कार्यात्मक या नोडल प्रदेश एक ऐसे क्षेत्र होते हैं, जो एक नोड या अनेक नोड़ों से कार्यात्मक रूप से जुड़े होते हैं।' इस प्रकार के प्रदेश किसी तत्त्व विशेष की समरूपता (Uniformity) के आधार पर नहीं निरूपित किए जाते हैं, वरन इनका आधार संगठनात्मक होता है, जैसे—नगर प्रदेश, नगर प्रभाव क्षेत्र, बाजार क्षेत्र, बन्दरगाहों के पृष्ठ प्रदेश आदि। इस प्रकार के प्रदेश में एक केन्द्र से सम्बद्ध जितना क्षेत्र रहता है, उतना उसकी परिसीमा में आता है। इसे केन्द्रीकृत या केन्द्र आधारित प्रदेश या संगठनात्मक प्रदेश (Organizational regions) के नाम से भी जाना जाता है। संकेन्द्रीय प्रदेश में केन्द्र के निकटस्थ क्षेत्र में केन्द्र से कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध की गहनता सर्वाधिक होती है, लेकिन जैसे-जैसे केन्द्र से दूरी बढ़ती जाती है गहनता में क्रमश: कमी आती जाती है। केन्द्र अपने कार्यात्मक प्रदेश से परिसंचरण

TOUCH 'n' PASS

माध्यमों से जुड़ा होता है तथा प्रत्येक दिशा में अन्तर्प्रक्रिया समान नहीं होती। परिसंचरण मार्गों की सघनता क्षेत्रीय संसाधनों, जनसंख्या घनत्व एवं आर्थिक-सांस्कृतिक विकास पर निर्भर करता है।

कार्यात्मक प्रदेश, आकारजनक प्रदेश से भिन्न होते हैं। कार्यात्मक प्रदेश से गतिक विचार (Dynamic Concept) का बोध होता है। कार्यात्मक प्रदेश मानव एवं स्थान के मध्य क्रियात्मक सम्बन्ध (Functional Relations) द्वारा निर्धारित होते हैं। मानव क्रियाएँ हमेशा बदलती रहती हैं। अतएव कार्यात्मक प्रदेशों के आधार (Criteria) तथा विशेषताओं (Characteristics) में बदलाव होता रहता है, अर्थात् इसमें क्रिया (Action) पर बल दिया जाता है। इनमें कार्यों की समांगता मिलती है; जैसे—कृषि प्रदेश, जिसके निर्धारण का आधार मानव की कृषि क्रिया है। मानव-भूमि का यह क्रियात्मक सम्बन्ध ही कार्यात्मक प्रदेश के निर्धारण का आधार है। कार्यात्मक प्रदेशों का प्रादेशीकरण मानव क्रियाओं की समरूपता (Uniformity) पर निर्भर करता है।

क्र० सं०	मानव क्रियाएँ (Human Activities)	कार्यात्मक प्रदेश (Functional Regions)
1.	कृषि (Agriculture)	कृषि प्रदेश (Agriculture Regions)
2.	चारण (Postoral)	चारण प्रदेश (Postoral Regions)
3.	विर्निमाण (Manufacturing)	विर्निमाण प्रदेश (Manufacturing Regions)
4.	भूमि-उपयोग (Land-Use)	भूमि-उपयोग प्रदेश (Land-Use Regions)
5.	नगर (Cities)	नगर प्रदेश (Cities Regions)

उल्लेखनीय है कि सभी कार्यात्मक प्रदेशों का अस्तित्व मानव क्रियाओं तथा विभिन्न तत्त्वों के अन्तर्सम्बन्धों पर निर्भर करता है। अतएव ये प्रदेश गतिशील (Dynamic) होते हैं अर्थात् मानव क्रियाओं पर इनका विस्तृत तथा संकुचित होना निर्भर करता है। जैसे एक कृषि प्रदेश का अस्तित्व (Existence) तब तक बना रहेगा जब तक मानव का कृषि में लगाव रहेगा। मानव का दृष्टिकोण औद्योगिक होते ही औद्योगिक प्रदेश का विस्तार होना शुरू हो जाएगा तथा कृषि प्रदेश का संकुचित होना। ऐसे भूदृश्य वाले प्रदेश जिनका स्थायित्व गति (Movement) तथा प्रवाह (Flow) पर निर्भर करता है, गतिजन्य प्रदेश (Kinetic Regions) कहलाते हैं।

3. **कम्पेज** (Compage)—कार्यात्मक प्रदेश का जटिलतम रूप **कम्पेज** कहलाता है। इसमें तत्त्व सम्मिश्र की एकता होती है। इस तरह कम्पेज एक अत्यधिक जटिल एवं एकीकृत तत्त्व सम्मिश्र (A Highly Complex but Unified element Complex) है। एक कम्पेज के तहत सभी भौतिक तत्त्वों एवं सभी मानवीय तत्त्वों के संयोग की समरूपता होती है, जैसे महाराष्ट्र प्रदेश में जहाँ तक काली मिट्टी का विस्तार है, एक प्रदेश है, जो एक काली मिट्टी प्रदेश है। जिसे आकारजनक प्रदेश कहते हैं तथा वहीं क्षेत्र कपास कृषि प्रदेश है, जो एक कार्यात्मक प्रदेश है। इस तरह एक कम्पेज में कार्यात्मक तथा आकार जनक प्रदेश एक-दूसरे पर पूर्णत: अध्यारोपित (Superimposed) रहते हैं।

डी. ह्वीटलसी ने सन् 1956 में अपने एक शोध पत्र में सर्वप्रथम प्रदेश शब्द के स्थान पर कम्पेज (Compages) शब्द का प्रयोग किया। अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ (Association of American Geographers) ने प्रादेशिक भूगोल की प्रकृति एवं स्वरूप तथा उसकी प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से डी. ह्वीटलसी के नेतृत्व में एक समिति गठित की था। डी. ह्वीटलसी ने पाँच आधार तत्त्वों का उपयोग करके विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बाँटा। उनके अनुसार, 'कम्पेज पृथ्वी के किसी भाग में भौतिक, जैविक तथा मानवीय पर्यावरण के बीच मानव अधिधारण (Human occupance) के परिणामस्वरूप उत्पन्न कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्धों के परिणामस्वरूप निर्मित एकात्मक क्षेत्रीय इकाई होती है।' डी. ह्विटलसी ने कम्पेज (Compage) में निम्न 16 तथ्यों को सम्मिलित किया—

(अ) प्राकृतिक तथ्य		(ब) मानवीय क्रियाओं से निर्मित तथ्य			
(i)	भू-संरचना	(vii)	भोजन-संग्रह Food (Collecion)	(xii)	कृषि
(ii)	उच्चावच एवं अपवाह प्रणाल	(viii)	शिकार (Hunting)	(xiii)	निर्माण उद्योग (Manufacturing Industry)
(iii)	जलवायु (Climate)	(ix)	मत्स्यन (Fishery)	(xiv)	परिवहन
(iv)	मिट्टी (Soil)	(x)	खनन (Mining)	(xv)	अधिवास (Habitance)

(v)	प्राकृतिक वनस्पति (Natural Vegetation)	(xi)	वन काटना	(xvi)	जनसंख्या (Population)
(vi)	जंगली जीव-जन्तु (Forestis Animals)				

डी. ह्विटलसी के अनुसार, 'कम्पेज एक उच्चतम श्रेणी का प्रदेश है जो निश्चित प्रकरणों का अध्ययन करता है।' डी. ह्विटलसी का मानना था कि कम्पेज के तहत समस्त प्राकृतिक व सांस्कृतिक भूदृश्यों की विशेषताओं, जीवनयापन की विधियों तथा सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इस संकल्पना के उदय के साथ ही प्रादेशिक इकाइयों (Units) को विविधतापूर्ण लेकिन कार्यात्मक रूप से सुसम्बद्ध तथा संघटित इकाइयों के रूप में देखा जाने लगा।

4. **जननिक/सामान्य/जातीय प्रदेश** (Generic Regions)—किसी भूसतह पर समान विशेषताओं वाले क्षेत्र सामान्य या जातीय प्रदेश कहलाते हैं। सामान्य प्रदेशों के विभाजन हेतु जो आधार निश्चित किया जाता है, उसी आधार पर विश्व के अन्य प्रदेशों को भी ऐसे वर्गीकरण में शामिल किया जाता है। उदाहरणार्थ, लावा के प्रदेश, डेरी प्रदेश (Dairy Regions), सूती वस्त्र उद्योग की पट्टी या प्रदेश, फसल विशेष या व्यवसाय विशेष के प्रदेश आदि। भारत में यद्यपि 'लावा प्रदेश' एवं 'कपास की कृषि के प्रदेश' एक-दूसरे के प्राय: पर्याय ही हैं, लेकिन विश्व में अन्यत्र ऐसा नहीं है। अत: ऐसे प्रदेशों के आधार पर विश्व-विभाजन की कोई निश्चित योजना हरबर्टसन की भाँति नहीं बनायी जा सकती है। महत्त्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि यदि हम विशेष कृषि तकनीक, विशिष्ट औद्योगिक स्वरूप अथवा नगरीय बस्ती, व्यापारिक अथवा प्रवाह सम्बन्धी समरूपताओं को लेकर भी यदि सामान्य प्रदेश (Generic Regions) निर्धारित कर, उसके आधार पर उनसे समरूपी लगने वाले प्रदेशों को समूहीकृत (Grouping) करने का प्रयास करें तो उनमें से प्रत्येक के मध्य अथवा आपस में समरूपता तो कम एवं विभिन्नताएँ एवं विविधताएँ (Differentitation and Variations) अधिक दिखायी देंगी। ऐसे अन्तर प्राय: स्थिर अथवा सर्वत्र समान भी तो नहीं होते। इनके अन्तर स्तर में समय के आधार पर कार्य की नवीन पद्धति अथवा नवीन सांस्कृतिक (Cultural) लक्षणों का जुड़ जाना, आदि कारणों से भी तेजी से परिवर्तन आ सकता है। अतएव सामान्य प्रदेश किसी क्षेत्र विशेष के लिए ही उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे प्रदेश या उनसे निर्धारित कोई भी नियम या सूत्र सम्पूर्ण विश्व को प्रदेश विभाजन की कुँजी का कार्य नहीं कर सकते। यदि हमने बाह्य समरूपता के आधार पर उन्हें विभाजित करने का प्रयत्न भी किया तो वह सिर्फ नाममात्र (Nominal) के ही समरूपी रहेंगे। उनकी प्रत्येक की अन्त:क्रियाओं की प्रणाली, स्वरूप, गतिशीलता (Dymanism) एवं विकास सभी भिन्नरूपी होंगे। इसलिए सामान्य प्रदेश ऐसे कुछ तत्त्वों या तत्त्वों की समरूपता के वितरण (Distribution) पर निर्भर नहीं है जो कि उस क्षेत्र में या विस्तृत भू-खण्ड के किसी इकाई क्षेत्र में पायी जा सकती है, जबकि ऐसे प्रदेश विशेष इकाई क्षेत्र की सामान्य संरचना एवं उनके विविध लक्षणों का अध्ययन करने वाले होते हैं।
5. **विशिष्ट प्रदेश** (Specific Regions)—ऐसे प्रदेश इकाई क्षेत्र के विशिष्ट लक्षणों को दर्शाने वाले होते हैं। अतएव इनका निर्माण विशेष तत्त्व-जटिलताओं (Element Complexes) से विकसित स्वरूप के आधार पर होता है। इसलिए इन्हें प्रकरण (Topic) पर अधारित प्रदेश भी कहा गया। व्यवस्थित अथवा सांस्कृतिक (Cultural) भूगोल के विशेष तत्त्व स्वरूपों के विकास से निर्मित विशिष्ट प्रदेश के अध्ययन का वर्तमान भूगोल में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनका आधार बहुत व्यापक है, क्योंकि बहुस्वरूपीय विशिष्टता विशेष तत्त्वों के परिवर्तनशील अथवा गतिशील व्यवहार के कारण प्राय: जटिल (Complex) एवं बहुस्तरीय (Multi-level) भी हो सकती है। विशिष्ट प्रदेशों का आकार प्राय: बहुत सीमित रहता है। इनका निकटवर्ती प्रदेशों या क्षेत्रों से भिन्न प्रकार का सम्बन्ध रहता है। इसलिए ऐसे इकाई क्षेत्रों की सीमाएँ तत्त्व विशेष के लक्षणों के अनुसार निश्चित की जाती हैं। ऐसे प्रदेशों के अध्ययन के द्वारा नव तकनीक से विकसित भूतल-विशेष को समझने एवं उनके विश्लेषण का अवसर प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, विशेष इस्पात नगर विशेष औद्योगिक महानगर आदि। इनमें प्रदेशों के निकट के विशेष प्रभावित क्षेत्र भी शामिल रहते हैं।
6. **प्राकृतिक प्रदेश** (Natural Regions)—प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण में संरचना उच्चावच, (Relief) जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति जैसे प्राकृतिक कारकों को विशेष महत्त्व दिया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों (काण्ट, हम्बोल्ट तथा रिटर) ने मानव को भी एक प्राकृतिक कारक माना है, इसी आधार पर प्राकृतिक प्रदेश में मानवीय तत्त्वों के अध्ययन को भी कुछ विद्वान महत्त्व प्रदान करते हैं।

TOUCH 'n PASS

ब्रिटिश भूगोलवेत्ता एण्ड्रयू जॉन हरबर्टसन प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन में राजनीतिक खण्डों की जगह प्राकृतिक प्रदेशों को भौगोलिक अध्ययन की इकाई माना। उन्होंने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण में मानवीय क्रियाकलापों को कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने वृहत् प्राकृतिक प्रदेशों का निर्धारण धरातलीय स्वरूपों, जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की समरूपता (Uniformity) के आधार पर किए जाने पर बल दिया। प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण में मानवीय क्रियाकलापों की उपेक्षा करने के कारण ब्रिटेन में भी उनकी इस विचारधारा की कटु आलोचनाएँ की गयी। जिसका प्रभाव हरबर्टसन के भौगोलिक चिन्तन पर पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि सन् 1910 के बाद स्वयं हरबर्टसन ने प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण में मानवीय क्रिया-कलापों के महत्त्व को स्वीकारा तथा उन्होंने सन् 1911 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'मानव तथा उसके कार्य' (*Man and his Work*) में 'प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश' के स्थान पर 'प्रमुख प्रदेश' (Major Regions) शब्द का प्रयोग किया तथा प्राकृतिक प्रदेश तथा मानव के बीच सम्बन्धों की विवेचना करते हुए माना कि प्राकृतिक शक्तियाँ मानवीय कार्यों में परिलक्षित होती है। प्राकृतिक प्रदेश निरपेक्ष प्रदेश न होकर सापेक्षिक क्षेत्र होते हैं। हरबर्टसन के प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना भूगोल की संकल्पना का ही एक प्रतिबिम्ब है। हरबर्टसन लिखते हैं, 'भूगोल प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वातावरण के क्रमिक स्तरों या पदानुक्रमों का अध्ययन है।' इस तरह उन्होंने प्राकृतिक प्रदेश को भौतिक एवं मानवीय तत्त्वों की संयुक्त रचना माना।

7. **भौगोलिक प्रदेश** (Geographical Regions)—भौगोलिक प्रदेश की संकल्पना के प्रतिपादक **जे. एफ. अनस्टेड** महोदय के अनुसार, "भौगोलिक प्रदेशों में भौतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के अध्ययन व विश्लेषण को उनकी महत्ता के अनुसार समुचित रूप से शामिल करना होता है।" भौगोलिक प्रदेश एक ऐसी क्षेत्रीय इकाई होते हैं, जिनमें भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों प्रकार के तथ्यों की समरूपता (Uniformity) मिलती है। भौतिक समरूपता रखने वाले जितने क्षेत्र में सांस्कृतिक तथ्यों की समरूपता मिलती है, उतने क्षेत्र को भौगोलिक प्रदेश के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। भौगोलिक प्रदेशों की सीमाएँ प्राकृतिक सीमाओं तथा राजनीतिक सीमाओं से अलग होती हैं। वर्तमान में भूसतह के इकाई क्षेत्रों के रूप में भूगोलवेत्ताओं द्वारा भौगोलिक प्रदेश को अधिक उपयुक्त माना जाता है। भौगोलिक प्रदेश कम्पेज से इस आधार पर भिन्न होते हैं कि कम्पेज में अध्ययन का प्रमुख केन्द्र मानवीय लक्षण तथा क्रियाकलाप होते हैं, जबकि भौगोलिक प्रदेश में ऐसा नहीं होता।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. प्रादेशिक नियोजन के जनक कौन हैं?
(क) आर०पी० मिश्रा (ख) लेविस ममफोर्ड (ग) जॉन फ्रीडमैन (घ) पैट्रिक गेडीस

उत्तर (घ) पैट्रिक गेडीस

प्र.2. भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया किस देश के मॉडल पर आधारित है?
(क) संयुक्त राज्य अमेरिका (ख) ब्रिटेन
(ग) सोवियत रूस (घ) जर्मनी

उत्तर (ग) सोवियत रूस

प्र.3. "प्रादेशिक नियोजन का क्रिया स्थल 'प्रदेश' है, जिसके अन्तर्गत 'स्थान' (भूगोल), 'लोग' (समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र) एवं 'कार्य' (अर्थशास्त्र) आते हैं।" उपर्युक्त परिभाषा किसने दी है?
(क) लेविस ममफोर्ड (ख) जॉन फ्रीडमैन (ग) बेन्टन मैकाय (घ) पैट्रिक गेडीस

उत्तर (घ) पैट्रिक गेडीस

प्र.4. भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी?
(क) 15 मार्च, 1950 (ख) 1 अप्रैल, 1951 (ग) 1 जनवरी, 1951 (घ) 1 अप्रैल, 1956

उत्तर (ख) 1 अप्रैल, 1951

प्र.5. नीति (NITI) आयोग का गठन कब किया गया था?
(क) 1 जनवरी, 2010 (ख) 1 जनवरी, 2015 (ग) 1 अप्रैल, 2015 (घ) 1 जनवरी, 2020

उत्तर (ख) 1 जनवरी, 2015

TOUCH 'n PASS

प्र.6. सर्वप्रथम कम्पेज (Compage) शब्द का प्रयोग किसने किया?
(क) हरबर्टसन (ख) डी० ह्वीटलसी (ग) आर०पी० मिश्रा (घ) अनस्टेड

उत्तर (ख) डी० ह्वीटलसी

प्र.7. हरबर्टसन ने पृथ्वी तल को कितने मुख्य तथा उप-प्रदेशों में विभाजित किया है?
(क) 6 मुख्य तथा 13 उप प्रदेशों (ख) 6 मुख्य तथा 15 उप प्रदेशों
(ग) 8 मुख्य तथा 13 उप प्रदेशों (घ) 6 मुख्य तथा 18 उप प्रदेशों

उत्तर (क) 6 मुख्य तथा 13 उप प्रदेशों

प्र.8. डी० ह्वीटलसी के अनुसार एक प्रदेश में कम-से-कम कितने प्रकरणों या विषयों (topics) का अध्ययन किया जाता है?
(क) 10 (ख) 12 (ग) 14 (घ) 16

उत्तर (घ) 16

प्र.9. प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण में किन-किन तत्त्वों को शामिल किया जाता है?
(क) संरचना (ख) उच्चावच (ग) जलवायु (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.10. लिण्टन महोदय ने प्राकृतिक प्रदेशों के कितने अनुक्रम (Sequence) बताए हैं?
(क) पाँच (ख) सात (ग) आठ (घ) दस

उत्तर (ख) सात

प्र.11. किसी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बुनियादी अवधारणाओं में से एक का नाम बताइए–
(क) प्रबंध (ख) योजना (ग) समन्वय (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ख) योजना

प्र.12. योजना के किस चरण पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जा सकती है और लागू योजना लागू की जाएगी?
(क) उद्देश्य स्थापित करना (ख) परिसर का विकास करना
(ग) उद्देश्य का चयन करना (घ) कार्रवाई के वैकल्पिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना

उत्तर (ग) उद्देश्य का चयन करना

प्र.13. नियोजन प्रक्रिया की किस गति में प्रत्येक विकल्प के एक सिक्के के दो पहलुओं की जाँच की जाती है?
(क) उद्देश्य की स्थापना (ख) परिसर का विकास करना
(ग) वैकल्पिक परिसर का चयन करना (घ) कार्रवाई के वैकल्पिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना

उत्तर (घ) कार्यवाई के वैकल्पिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना

प्र.14. इसे नियोजन के रूप में जाना जाता है–
(क) प्रबंधक का अंतिम कार्य (ख) प्रबंधक का प्राथमिक/प्रथम कार्य
(ग) (क) और (ख) दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ख) प्रबंधक का प्राथमिक/प्रथम कार्य

प्र.15. भविष्य के आउटपुट के लिए सोचना ..... के रूप में माना जाता है।
(क) योजना परिसर की स्थापना (ख) व्युत्पन्न योजनाएँ बनाना
(ग) नीति बनाना (घ) ये सभी

उत्तर (क) योजना परिसर की स्थापना

प्र.16. संयुक्त योजना, जिसमें लंबी अवधि के लिए एक उद्देश्य स्थापित करना, कार्रवाई का समय ढूँढ़ना और संसाधनों की अनुमति की आवश्यकता होती है, कहलाती है–
(क) नीति (ख) प्रक्रिया (ग) रणनीति (घ) Program

उत्तर (ग) रणनीति

TOUCH 'n' PASS

प्र.17. वह योजना जिसमें कुछ प्रक्रिया और नियम शामिल हाते हैं, कहलाती है–
(क) प्रोग्राम (ख) रणनीति (ग) बजट (घ) ये सभी
उत्तर (क) प्रोग्राम

प्र.18. जिस रेजिमेंट तरीके से कोर को निष्पादित करना होता है वह है–
(क) रणनीति (ख) प्रक्रिया (ग) तरीका (घ) नीति
उत्तर (ग) तरीका

प्र.19. किसी नीति को क्रियान्वित करने और एक अनुमानित व्यक्तिपरक तक पहुँचने के लिए क्रियाओं की श्रृंखला ..... है।
(क) नीति (ख) प्रक्रिया (ग) उद्देश्य (घ) रणनीति
उत्तर (ख) प्रक्रिया

प्र.20. इस प्रकार, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी निर्णय लेने या किसी भी समस्या से निपटने का एक अनुकूलित तरीका कहा जाता है–
(क) नीति (ख) बजट (ग) रणनीति (घ) नियम
उत्तर (क) नीति

प्र.21. योजना बनाने का मूल क्या है?
(क) आयोजन (ख) पहले से सोचना (ग) रास्ते पर लाने वाला (घ) ये सभी
उत्तर (ख) पहले से सोचना

प्र.22. कौन-सी योजना विशेषता उन योजनाकारों से संबंधित है जो बौद्धिक होते हैं क्योंकि वे परिवेश का विश्लेषण करने और भविष्य की भविष्यवाणी करने और उन सभी की तुलना विभिन्न अन्य विकल्पों से करने का दावा करते हैं जो सर्वोत्तम का चयन करते हैं?
(क) योजना बनाना एक मानसिक व्यायाम है (ख) योजना दूरदर्शी है
(ग) नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है (घ) योजना में निर्णय लेना शामिल है
उत्तर (क) योजना बनाना एक मानसिक व्यायाम है

प्र.23. संगठनात्मक माहौल में बदलाव पर ध्यान देने से कोई आश्चर्य नहीं होता है। विषय से संबंधित योजना के महत्त्व को संबोधित करें–
(क) योजना बनाने से अनिश्चितताओं का जोखिम कम हो जाता है।
(ख) योजना दिशा प्रदान करती है।
(ग) योजना नवोन्वेषी विचार को बढ़ावा देती है।
(घ) योजना निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करती है।
उत्तर (क) योजना बनाने से अनिश्चितताओं का जोखिम कम हो जाता है।

प्र.24. कार्य के भविष्य के पाठ्यक्रम की योजना को नियंत्रित करने के लिए किस प्रतिबंध पर प्रकाश डाला गया है और निदेशक इसे बदलने के स्थान पर नहीं हो सकता है–
(क) रचनात्मकता को कम करता है।
(ख) योजना गतिशील वातावरण में काम नहीं कर सकती है।
(ग) कठोरता पैदा करता है।
(घ) बहुत समय लगेगा।
उत्तर (ग) कठोरता पैदा करता है।

प्र.25. नियोजन के किस स्तर पर सबसे व्यवहार्य योजना बन जाती है जिसे क्रियान्वित किया जा सकता है?
(क) परिसर का विकास करना (ख) कार्रवाई के वैकल्पिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना
(ग) एक विकल्प का चयन करना (घ) उद्देश्य स्थापित करना
उत्तर (ग) एक विकल्प का चयन करना

TOUCH n PASS

प्र.26. नियोजन को हम इस प्रकार संबोधित कर सकते हैं–
(क) प्रबंधक का प्राथमिक कार्य (ख) एक प्रबंधक का अंतिम कार्य
(ग) इनमें से कोई नहीं (घ) (क) और (ख) दोनों
उत्तर (क) प्रबंधक का प्राथमिक कार्य

प्र.27. किसी भी निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों की अगली कड़ी कहलाती है?
(क) रणनीति (ख) प्रक्रिया (ग) नीति (घ) उद्देश्य
उत्तर (ख) प्रक्रिया

प्र.28. निर्देशित गतिविधियों की ओर झुके हुए परिणामों को इस रूप में माना जाता है–
(क) उद्देश्य (ख) प्रोग्राम (ग) नीति (घ) रणनीति
उत्तर (क) उद्देश्य

प्र.29. योजना पर कार्य किया जा सकता है–
(क) पर्यवेक्षण स्तर (ख) उच्चे स्तर का (ग) मध्य (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.30. योजना के क्रियान्वयन के बाद–
(क) फॉलोअप किया गया है। (ख) नई योजना बनती है।
(ग) योजना समाप्त होती है। (घ) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर (क) फॉलोअप किया गया है।

प्र.31. एक स्थानीय योजना एक ..... है।
(क) दूसरे योजनाकार के लिए एक उदाहरण के रूप में खड़ा है।
(ख) उपयोग के बाद त्याग दिया गया।
(ग) आवर्ती योजनाएँ।
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।
उत्तर (ग) आवर्ती योजनाएँ।

प्र.32. उन विचलनों को कैसे नियंत्रित किया जाए जिनकी देखभाल की जा सकती है–
(क) बजट (ख) नीति (ग) प्रक्रिया (घ) रणनीति
उत्तर (क) बजट

प्र.33. नियोजन एक जमीनी मानक स्थापित करता है–
(क) को नियंत्रित करना (ख) रास्ते पर लाने वाला (ग) स्टाफ (घ) आयोजन
उत्तर (क) को नियंत्रित करना

प्र.34. कोई योजना तभी बना सकता है जब–
(क) दूरदर्शिता (ख) कल्पना (ग) ध्वनि निर्धारण (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.35. योजना किसी उद्मय के संपूर्ण कामकाज के लिए रणनीतियों पर आधारित होती है–
(क) प्रभाग योजना (ख) कंपनी की योजना (ग) विभाग योजना (घ) इकाई योजना
उत्तर (ख) कंपनी की योजना

TOUCH 'n PASS

UNIT-III

प्रदेशों का परिसीमन और प्रादेशिक योजना
Delimitations of Region and Regional Planning

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. प्रादेशीकरण का क्या अर्थ है?

What is the meaning of regionalisation?

उत्तर प्रादेशीकरण का साधारण अर्थ धरातल को विभिन्न वर्गों के प्रदेशों में बाँटकर उनका विश्लेषण, अध्ययन एवं वर्णन करना है। प्रादेशीकरण में धरातल की स्थानिक संरचना के प्रतिरूपों, जटिल अन्तर्सम्बन्ध और संलग्नताओं का अध्ययन किया जाता है। सामान्य रूप में किसी भी क्षेत्र का प्रादेशीकरण करने हेतु उस क्षेत्र की सूक्ष्मस्तर तक भौगोलिक जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके पश्चात कुछ प्रभावी तत्त्वों को छाँटकर क्षेत्रवार उन तत्त्वों की समांगता का सीमांकन करते हैं। इस तरह प्रादेशीकरण में किसी भी क्षेत्र को कई क्रम के प्रदेशों में विभाजित करने हेतु पर्याप्त संख्या में चरों को लिया जाता है।

प्र.2. व्यक्तिगत सर्वेक्षण विधि क्या है?

What is the personal survey method?

उत्तर वास्तव में प्रादेशीकरण पूरी तरह से क्षेत्र की खोज पर आधारित है। यह खोज या विभिन्न तत्त्वों का प्रत्यक्ष अवलोकन व्यक्तिगत अनुसंधानकर्त्ताओं से ही संभव है। हालाँकि व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी किसी क्षेत्र के सारे तत्त्वों का प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं कर सकता है, लेकिन वह धरातलीय विन्यास का प्राथमिक अवलोकन करके विभिन्न तत्त्वों की समांगता का सीमांकन कर सकता है।

प्र.3. क्षेत्रीय नियोजन परिसीमन क्या है?

What is the regional planning delimitation?

उत्तर क्षेत्रों के परिसीमन में स्थानीय इकाइयों को एक साथ समूहित करना शामिल है जिनकी कुछ स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों के अनुसार समान विशेषताएँ हैं और जो कुछ चुने हुए मानदंडों के आधार पर क्षेत्र के बाहर की इकाइयों से काफी भिन्न हैं।

प्र.4. परिसीमन प्रक्रिया क्या है?

What is delimitation process?

उत्तर परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है—किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। परिसीमन का काम एक उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है।

प्र.5. चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है?

Who does the delimitation of election's areas?

उत्तर संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के बाद संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात केन्द्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। यह परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है।

प्र.6. सीमा और परिसीमन में क्या अंतर है?

What is the difference between and limitation delimitation.

उत्तर सीमाएँ आपके अध्ययन की कमियों को दर्शाती हैं, जो आपके सामने आने वाली व्यावहारिक या सैद्धांतिक बाधाओं पर आधारित होती हैं। इसके विपरीत, परिसीमन आपके शोध उद्देश्यों और शोध प्रश्नों के फोकस और दायरे के संदर्भ में आपके द्वारा चुने गए विकल्पों को दर्शाता है।

TOUCH 'n PASS

प्र.7. कार्यक्षेत्र और परिसीमन का क्या उदाहरण है?
What is the example of delimitation and work area?

उत्तर एक शोधकर्त्ता प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के व्यवहार पैटर्न पर मोबाइल फोन के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। हालाँकि, शोधकर्त्ता के लिए विषय के हर पहलू को कवर करना संभव नहीं है। इसलिए इसका दायरा लक्षित आबादी के एक निश्चित वर्ग तक सीमित करना होगा।

प्र.8. भूगोल में परिसीमन क्या है?
What is the delimitation in the Geography?

उत्तर 1. परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में प्रदेशो की सीमाओं को चिह्नित किया जाता है।
2. परिसीमन, पृथ्वी पर विभिन्न प्रदेशो की पहचान करने की प्रक्रिया है।

परिसीमन के उदाहरण निम्नलिखित हैं—
1. आर्थिक परिसीमन [उदाहरण, विकसित क्षेत्र, अविकसित क्षेत्र, आदि]
2. राजनीतिक परिसीमन [उदाहरण, कम्युनिस्ट क्षेत्र, लोकतांत्रिक क्षेत्र, आदि]
3. भौगोलिक परिसीमन [उदाहरण, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, आदि]

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. क्रमबद्ध सर्वेक्षण का उल्लेख कीजिए।
Explain the systematic survey.

उत्तर

क्रमबद्ध सर्वेक्षण
(Systematic Survey)

जब किसी भी क्षेत्र को कई क्रम के प्रदेशों में बाँटना होता है, तो सूचनाओं का मानकीकरण किया जाता है, अर्थात् बहुत से निरीक्षणकर्त्ताओं को लगाकर आँकड़े एकत्रित करते हैं। पुन: व्यक्तिगत स्तर पर अनुभवजन्य सूचनाओं को निकालकर सारे प्रेक्षणों को मिलाकर समान्यीकरण करके क्षेत्रीय समांगता को सीमांकित करते हैं। इस तरह उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर मानचित्रण करके प्रादेशीकरण किया जा सकता है। इसमें भी तीन दशाएँ हो सकती हैं—

1. जब एक विशेषता के आधार पर क्षेत्रीय समांगता का सीमांकन करना होता है तो सर्वप्रथम उस अकेली विशेषता के क्षेत्रीय वितरण की पहचान की जाती है। प्रथम दशा में यह संभव है कि पूरे क्षेत्र में वह विशेषता एक साथ कई उपक्षेत्रों में मिलती है तो समांगता का सीमांकन आसानी से हो जाता है—
   (क) यदि वही विशेषता सम्पूर्ण क्षेत्र में अनियमित रूप में हो तो समांगता वाला प्रदेश बन ही नहीं सकता और
   (ख) जब वही विशेषता कुछ क्षेत्रों तक हो या कुछ अन्य क्षेत्रों तक हो, तो स्तर के अनुसार कई समांग प्रदेशों का निर्धारण हो सकता है।
2. जब दो विशेषताओं के साथ समांगता की पहचान करके प्रादेशीकरण करना हो तो मानचित्रण की कई दशाएँ बनती हैं। प्रथम स्तर पर जब दोनों विशेषताएँ बिखरे हुए क्षेत्रों में हों तो प्रादेशीकरण कठिन हो जाता है। यदि दोनों विशेषताएँ एक साथ एक ही क्षेत्रों में हों तो एक प्रदेश, अलग-अलग समूहीकृत हो तो दो प्रदेश बनते हैं। इस तरह कुल मिलाकर एक ही क्षेत्र में दो विशेषताओं के आधार पर चार प्रदेशों का सीमांकन किया जा सकता है।
3. जब दो से अधिक विशेषताओं के आधार पर प्रादेशीकरण करना हो तो प्रत्येक विशेषता का अलग-अलग मानचित्रण करके एक-दूसरे पर अध्यारोपित करके प्रादेशीकरण किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी कई दशाएँ हो सकती हैं अर्थात् प्रदेश की अनेक सीमाएँ हो सकती हैं।

प्रदेशों के सीमांकन का प्रयत्न अनेक तरह से किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों की सीमाएँ अक्षाशों एवं देशान्तरों पर आधारित हैं और आंशिक रूप से नदियों या पर्वतों अथवा झीलों का अनुकरण करती हैं। अधिकतर सीमाएँ सीधी रेखा की तरह हैं, जबकि पृथ्वी की सतह पर इस तरह का विभाजन कठिन होता है। ज्यामितीय सीमाओं के अलावा नदियाँ, पर्वत, श्रेणियाँ, जल विभाजकों की सीमाएँ अपने आप में स्पष्ट हैं। इसी तरह समुद्रों एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण भी करना पड़ता है।

प्रदेश का निर्धारण या सीमांकन या सीमा-निर्धारण या परिसीमन (Delimitation) किसी एक तत्त्व या कई तत्त्वों (Criteria) के आधार पर किया जाता है और माना जाता है कि निर्धारित प्रदेश में इनके वितरण में समरूपता (Uniformity) है, किन्तु सूक्ष्म

TOUCH 'n PASS

रूप से देखने से स्पष्ट होता है कि प्रदेश के केन्द्र (Core) में तत्त्व के मूल गुण (Original Properties) मिलते हैं, जो बाहरी सीमा (Boundary) की ओर जाने पर क्षीण होते जाते हैं। जैसे क्रोबर (Kroeber) के अनुसार— सांस्कृतिक प्रदेशों की सीमाएँ एक नृविज्ञानी (Anthropologist) के लिए बहुत महत्त्व की नहीं है, क्योंकि सीमा के सहारे दो संस्कृतियों की मिलावट मिलती है। नृजातीय अध्ययन का उत्तम स्थान प्रदेश का केन्द्र है। इसी तरह किसी वनस्पति प्रदेश के केन्द्र में उसकी मुख्य विशेषताएँ मिलेगी जो सीमा की तरफ जाने पर क्षीण होती जायेंगी और सीमा के पास दूसरे वनस्पति प्रदेश की प्रजातियों के साथ मिश्रित रूप से मिलेंगी जिसे इकोटोन (Ecotone) कहा जाता है।

कार्यात्मक प्रदेश मानवीय क्रियाकलापों (Activities) द्वारा निर्धारित होते हैं। इनमें कार्यों की समांगता (Homogeneity) मिलती है; जैसे—कृषि प्रदेश, जिसके निर्धारण का आधार मानव की कृषि क्रिया है। मानव-भूमि का यह क्रियात्मक सम्बन्ध ही कर्मोपलक्षी प्रदेश (Functional Region) के निर्धारण का आधार है। कृष्येत्तर क्षेत्रों (Non-agricultural Areas) जैसे औद्योगिक क्षेत्र या बर्फाच्छादित क्षेत्र को कृषि प्रदेश के तहत सम्मिलित नहीं किया जाता। कृषि-प्रदेश को फसलों (गेहूँ, जूट, गन्ना, मसाले, चाय इत्यादि) के आधार पर पुन: अनेक उपकृषि प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि जूट कृषि प्रदेश और चाय कृषि प्रदेश में कार्यात्मक भिन्नता (Functional Difference) मिलती है। जिससे प्रक्रम सम्बन्ध (Process Relationship) बदल जाता है; जैसे—जूट निम्न समतल भूमि पर तथा चाय पर्वतीय ढलानों पर पैदा किया जाता है। इस तरह कार्यों की समांगता वाले स्थानों जैसे गेहूँ उत्पादन क्षेत्रों को एक कार्यात्मक प्रदेश (Function Region) के तहत रखा जाता है। कार्यात्मक प्रदेशों का प्रादेशीकरण मानव क्रियाओं की समरूपता पर निर्भर करता है।

प्र.2. लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर टिप्पणी लिखिए।

Write the note on democratic decentralization.

उत्तर

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण : पंचायती राज संस्थान
(Democratic Decentralization: Panchayati Raj Institutions)

भारत गाँवों का देश है। गाँवों की उन्नति और प्रगति पर ही भारत की उन्नति और प्रगति निर्भर करती है। गाँधीजी ने ठीक ही कहा था कि "यदि गाँव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, वह भारत नहीं होगा, विश्व में उसका सन्देश समाप्त हो जाएगा।" भारत के संविधान-निर्माता भी इस तथ्य से भली-भाँति परिचित थे, अत: हमारी स्वाधीनता को साकार करने और उसे स्थायी बनाने के लिए ग्रामीण शासन व्यवस्था की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया। हमारे संविधान में यह निर्देश दिया गया है कि "राज्य ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए कदम उठाएगा और उन्हें इतनी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिससे कि वे (ग्राम-पंचायतें) स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें।"

देश में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और विकास कार्यक्रमों में जनता का सहयोग लेने के ध्येय से 1957 में प्रस्तुत **बलवन्तराय मेहता समिति** के प्रतिवेदन के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गयी। इनके स्वरूप (Form) में विभिन्न राज्यों में कुछ अन्तर था, मगर कतिपय विशेषताएँ एक-सी थीं। **पहला** पंचायती राज की तीन सीढ़ियाँ थीं—ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला-परिषद। **दूसरा**, पंचायती राज प्रणाली में स्थानीय लोगों को काम करने की स्वतंत्रता थी और देख-रेख ऊपर से होती थी। **तीसरा**, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भाँति यह शासकीय ढाँचे का अंग नहीं था। पंचायती राज की संस्थाएँ निर्वाचित (Elected) होती थीं और इसके कर्मचारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधीन काम करते थे। **चतुर्थ**, साधन जुटाने और जनसहयोग संगठित करने का भी इन संस्थाओं (Institutions) को पर्याप्त अधिकार था।

प्र.3. पंचायती राज संस्थाओं के गठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए।

Light on the organizing of Panchayati Raj institution and their works.

उत्तर

पंचायती राज संस्थाओं का गठन
(Organizing of Panchayati Raj Institutions)

1. **ग्राम पंचायतें** (Village Panchayats)—ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार (Local Government) के रूप में ग्राम पंचायतें कार्य करती हैं। इनका कार्य-क्षेत्र प्राय: एक Revenue Village होता है। इसके कार्यों में विभिन्न प्रकार के न्यायिक (Judicial), पुलिस, नागरिक और आर्थिक कार्य शामिल रहते हैं। कुछ राज्यों में मामूली झगड़े ग्राम पंचायतों द्वारा ही निपटा दिये जाते हैं। कुछ राज्यों में सड़कों, प्राइमरी स्कूलों और ग्राम दवाखानों का प्रबन्ध, पंचायत घरों एवं ग्रामीण जलाशयों का निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है और कुछ क्षेत्रों में पीने तथा सिंचाई के लिए पानी की पूर्ति के उत्तरदायित्वों को भी इनके कार्य-क्षेत्र में शामिल किया गया है। पंचायतों को कुछ कर (Land Rent) लगाने के

TOUCH 'n' PASS

अधिकार भी दिये गये हैं। इन करों में—(i) सामान्य समिति कर, (ii) भूमि लगान या भूमि के किराये पर कर, (iii) व्यवसाय कर, (iv) जानवरों और वाहनों पर कर, (v) सेवा कर (Service Tax), (vi) चुंगी, (vii) थियेटर कर, (viii) पथ कर (Road Tax) शामिल हैं। पंचायतों द्वारा कर केवल सम्बन्धित राज्य सरकार की स्वीकृति के आधार पर ही लगाये जा सकते हैं।

2. **समिति** (Samiti)—जिला परिषद् के क्षेत्र को कुछ उप-क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है और प्रत्येक उप-क्षेत्र का प्रशासन समिति द्वारा किया जाता है। समिति का क्षेत्र प्राय: सामुदायिक विकास ब्लाक के क्षेत्र के बराबर रहता है। समिति के मुख्य कार्यों में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से कृषि का विकास करना, बीज गोदामों की स्थापना, भूमि संरक्षण, पौधे संरक्षण में सहायता करना शामिल होता है। इन समितियों को मध्यम स्तरीय पंचायत (Intermediate Level Panchayats) या खण्ड सलाहकारी समिति (Block Advisory Committees) का नाम भी दिया गया है।
3. **जिला परिषद् या जिला पंचायत** (Zila Parishad or District Board or Zila Panchayat)—जिला परिषद मे जिले का पूरा ग्रामीण (Rural) क्षेत्र आता है। इन परिषदों को सौंपे गये कार्यों में सड़कों का निर्माण एवं उनकी देखभाल, वृक्षारोपण और उनकी सुरक्षा, मनुष्यों, पशुओं और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था, अस्पतालों, चिकित्सालयों और पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था, बाजरों एवं पार्कों का निर्माण तथा देखभाल, प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था आदि मुख्य हैं। विगत कुछ वर्षों में इनके कार्यों को पंचायतों द्वारा पूरा किये जाने और कुछ उत्तरदायित्वों (Responsibilities) को राज्य सरकारों द्वारा ले लिये जाने के कारण इन परिषदों का कार्य-क्षेत्र एवं महत्त्व कम होता जा रहा है। वित्त की दृष्टि से जिला परिषदों के कर-आगम अधिक सीमित होते हैं और उन्हें बहुत कुछ राज्य के अनुदानों पर निर्भर रहना पड़ता है।

प्र.4. पंचायती राज की आवश्यकता तथा महत्त्व का उल्लेख कीजिए।
Explain the significance and need of Panchayati Raj.

उत्तर

पंचायती राज की आवश्यकता तथा महत्त्व
(Significance and need of Panchayati Raj)

पंचायतें बहुत पुराने जमाने में भी विद्यमान थीं मगर वर्तमान पंचायती संस्थाएँ इस माने में भी नई हैं कि उनको काफी अधिकार, साधन और जिम्मेदारियाँ सौंपी गयी हैं। नाम पुराना है मगर संस्थाएँ नयी हैं। इनका महत्त्व और उपयोगिता निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है—

1. भारत में स्वस्थ प्रजातान्त्रिक परम्पराओं (Traditions) को स्थापित करने के लिए पंचायत व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। इसके माध्यम से शासन-सत्ता जनता के हाथ में चली जाती है। यह व्यवस्था ग्रामवासियों में प्रजातान्त्रिक (Democratic) संगठनों के प्रति रुचि स्थापित करती है।
2. ये संस्थाएँ भारत का भावी नेतृत्व तैयार करती हैं, विधायकों एवं मन्त्रियों को प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती हैं जिससे वे ग्रामीण भारत की समस्याओं से अवगत होते हैं। इस तरह ग्रामों में उचित नेतृत्व का निर्माण करने एवं विकास कार्यों में जनता की रुचि बढ़ाने में पंचायतों का प्रभावी योगदान रहता है।
3. पंचायती राज संस्थाएँ केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के भार से हल्का करती हैं। उनके द्वारा ही शासकीय शक्तियों एवं कार्यों का विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) किया जा सकता है। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया में शासकीय सत्ता गिनी-चुनी संस्थाओं में न रहकर गाँव की पंचायत के कार्यकर्त्ताओं के हाथों में पहुँच जाती है।
4. पंचायतों के कार्यकर्त्ता एवं पदाधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच कड़ी हैं। इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से प्रारम्भ किए हुए राष्ट्र निर्माण के क्रियाकलापों का चलना कठिन हो जाता है। इन लोगों के सहयोग के बिना सरकारी अधिकारियों का काम भी मुश्किल हो जाता है।
5. पंचायतें प्रजातन्त्र (Democracy) की प्रयोगशालाएँ हैं। ये नागरिक को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती हैं। साथ ही उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में मदद करती हैं।
6. हमारी जनता इन संस्थाओं के माध्यम से शासन के बहुत करीब पहुँच जाती है। जनता और शासन में एक-दूसरे की कठिनाइयाँ समझने की भावनाएँ पैदा होती हैं। इससे दोनों में परस्पर सहयोग (Mutual Cooperation) बढ़ता है जो ग्रामीण उत्थान के लिए परम आवश्यक है।

TOUCH 'n PASS

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. प्रदेशों के सीमांकन हेतु गुणात्मक विश्लेषण विधि की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

Explain in detail the method of Qualitative Analysis for delimition of regions.

उत्तर धरातल पर विभिन्न प्रकार के प्रदेश मिलते हैं, जिनका सीमांकन किसी-न-किसी आधार पर किया जाता है। प्रदेशों की एक-दूसरे से अलग-अलग पहचान उनके क्रोडों (Cores) तथा सीमाओं के रेखांकन द्वारा की जाती है। प्रदेशों को सीमांकित करना **प्रादेशिक परिसीमन या निर्धारण या सीमांकन या प्रदेशों का सीमांकन या प्रादेशिकरण** (Method of Regional Delimitation or Delimitation of the Region or Regionalisation) कहलाता है। ये परिसीमन मुख्य रूप से निम्न दो विधियों द्वारा किया जा सकता है—

(अ) गुणात्मक विश्लेषण द्वारा प्रादेशिक सीमांकन, (ब) मात्रात्मक विश्लेषण द्वारा प्रादेशिक सीमांकन।

(अ) गुणात्मक विश्लेषण द्वारा प्रादेशिक सीमांकन (Regional Delimitation by Qualitative Analysis)

गुणात्मक विधि का प्रयोग करने के लिए, सर्वप्रथम प्रदेशों के कुछ ऐसे सूचक (Indicators) तत्त्वों का चयन कर लिया जाता है, जिनके आधार पर प्रदेशों की सीमाएँ निश्चित की जाती हैं, उदाहरणार्थ, ट्रक-परिवहन के भाड़े का अनुमान, रेल टिकटों की संख्या, समाचार-पत्रों का परिसंचारण, टेलीफोन वार्ताएँ आदि। फिर उन सूचकों के क्षेत्रों के अलग-अलग मानचित्र (Map) बनाकर उन मानचित्रों को एक-दूसरे के ऊपर अध्यारोपित (Superimposed) कर दिया जाता है। ये पूर्ण रूप से एक-दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं या विभिन्न सूचक-क्षेत्रों की सीमाएँ एक-दूसरे के ऊपर फिट नहीं होती हैं। इसलिए सभी सूचक क्षेत्रों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अन्तर्वेशन (Interpolation) विधि द्वारा दो प्रदेशों की मध्य-सीमा रेखा (Median boundary) अंकित कर परिसीमन पूर्ण किया जाता है। ये तीन क्रमों में पूर्ण होता है—

(i) सूचक तत्त्वों, आधारों या तत्त्वों (Bases or Criteria) का चयन,
(ii) आधारों का विश्लेषण तथा सूचक क्षेत्रों का परिसीमन,
(iii) मानचित्र अध्यारोपण एवं प्रादेशिक परिसीमन।

गुणात्मक विश्लेषण की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं—

1. **अभिलक्षणों की सातत्यता के आधार पर** (On the basis of the Continuity or Criteria)—गुणों या लक्षणों की सातत्यता के आधार पर किसी भी प्रदेश का सीमांकन तीन तरह से होता है—
   (क) **असातत्यता का सीमांकन** (Delimitation of Discountinuity)—कुछ प्रदेश एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे काली मिट्टी (Black Soil) का क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से या लौह खनिज युक्त पहाड़ी की सीमा या मरुस्थल एवं हरित भूमि के बीच बनी सिंचाई नहर की सीमा। इनमें से वनस्पति या मिट्टियों की सीमाओं में रेखीय शुद्धता नहीं होती। संक्रमण की पेटी होती है, किन्तु नहर या किसी विशेष खनिज क्षेत्र की सीमाएँ स्पष्ट होती हैं। एकसमान (Uniform) प्रदेशों में जहाँ क्रोड की विशिष्टताएँ कमजोर होने लगती हैं, सीमांकन कर दिया जाता है। केन्द्राधारिता प्रदेशों में जिस सीमा पर दो केन्द्रों का आकर्षण बल बराबर हो जाता है, सीमा बना दी जाती है।
   (ख) **सातत्यता का सीमांकन** (Delimitation of Continuity)—यह सीमांकन असातत्यता के सीमांकन से अलग है। सातत्यता में विचलन (Deviation) की मात्रा या गहनता देखी जाती है। सामान्य रूप से समान रेखाएँ (Isolines) खींची जाती हैं, जो समान मान के स्थानों को मिलाती हैं।
   (ग) **असातत्यता के वितरण का सीमांकन** (Delimitation of Discountinuity Distribution)—इसके अन्तर्गत प्राय: जनसंख्या के वितरण की असंतति (Discountinuity) का सीमांकन होता है। सभी क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण एकसमान नहीं होता तथा कुछ क्षेत्र जन-विहीन भी होते हैं।
2. **प्राकृतिक एवं स्थानीय भिन्नताओं के आधार पर** (On the basis of Natural and Spatial Disparity)—इस विधि में भौतिक तत्त्वों जैसे उच्चावच, अपवाह तन्त्र (Drainage System), जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति आदि की असंगति को आधार मानकर किसी भी प्रदेश का वृहद् स्तर पर सीमांकन किया जाता है। उदाहरणार्थ-पर्वतीय प्रदेश, नदी बेसिन, काली मिट्टी का प्रदेश, भूमध्यसागरीय जलवायु (Mediterranean Climate) का प्रदेश, प्रेयरी घास के

TOUCH 'n PASS

मैदान, कृषि प्रदेश आदि। ये भौतिक तत्त्व किसी क्षेत्र विशेष को संलग्न क्षेत्रों से अलग कर देते हैं। इसके बाद वृहत् स्तरीय प्रदेशों को स्थानीय विशेषताओं के आधार पर लघु स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, जैसे—जलविहीन क्षेत्र, जलबहुल क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या का क्षेत्र, किसी कृषि प्रदेश को फसलों की उत्पादकता या बोयी गयी भूमि के आधार पर लघु कृषि प्रदेशों में बाँटा जा सकता है। इस तरह सीमाएँ विकसित होती रहती हैं।

3. **अध्यारोपण विधि** (Method of Superimposition)—इस विधि के द्वारा किसी भू-भाग को प्रदेशों में विभक्त करने के लिए किसी एक अभिलक्षण को आधार न मानकर विभिन्न अभिलक्षणों को आधार माना जाता है। अलग-अलग अभिलक्षणों के आधार पर अलग-अलग प्रदेशों का सीमांकन कर लिया जाता है, बाद में इन सभी प्रदेशों के मानचित्रों को एक-दूसरे के ऊपर रखकर (अध्यारोपित कर) एक क्रोड प्रदेश (Core Region) का सीमांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी भू-भाग के आर्थिक प्रदेश के निर्धारण के लिए उस भू-भाग में कृषि प्रदेश, खनिज प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश तथा जनसंख्या प्रदेश सीमांकित कर लिए जाते हैं। जिन्हें एक ही मापक पर अध्यारोपित कर आर्थिक प्रदेशों की सीमाएँ ज्ञात की जा सकती हैं।

इस विधि से भौतिक तत्त्वों एवं मनुष्यजन्य लक्षणों के आधार पर भी प्रदेशों का सीमांकन किया जा सकता है। प्राय: यह विधि क्रोड प्रदेश को उभारने में सहायक होती है।

इस मानचित्र अध्यारोपण (Super-imposed) की विधि को ग्रीन (Green) महोदय ने 1995 में संयुक्त राज्य अमेरिका के दो बड़े नगरों, न्यूयॉर्क तथा बोस्टन के क्षेत्रों के सीमांकन करने में प्रयोग किया था। उन्होंने परिवहन, संचार, कृषि, मनोरंजन, विनिर्माण, उद्योग, राजस्व, बैंक आदि सूचकों के अलग-अलग मानचित्र बनाकर दोनों नगर क्षेत्रों के बीच की औसत सीमा रेखा को अन्तर्वेशन (Interpolation) द्वारा निर्धारित किया। इस तरह के सीमांकन में कुछ अनिश्चितता अवश्य बनी रहती है। ग्रीन (Green) से पूर्व दो अर्थशास्त्रियों ने समाचार-पत्र संचारण के आधार पर कनेक्टीकट राज्य को बोस्टन के क्षेत्र में रख दिया था और राष्ट्रीय साधन समिति ने इस राज्य को मुख्यत: न्यूयॉर्क के क्षेत्र में रखा था। ग्रीन ने परिवहन (Transport), संचार (Communication), कृषि, मनोरंजन, निर्माण-उद्योग, राजस्व-बैंक आदि के सात सूचकों के अलग-अलग मानचित्र बनाकर, उनको एक-दूसरे पर अध्यारोपित किया और दोनों नगर-क्षेत्रों के बीच की मध्य सीमारेखा को अन्तर्वेशन (Interpolation) द्वारा खींच दिया। उससे यह स्पष्ट हो गया था कि कनेक्टीकट राज्य बोस्टन के बजाय, न्यूयॉर्क पर ही पूरी तरह निर्भर था।

यद्यपि मानचित्र-अध्यारोपण की विधि से प्रदेशों के क्रोड-क्षेत्रों (Core areas) को शीघ्रता से निश्चित किया जा सकता है, फिर भी इस विधि से सीमांकन में कुछ अनिश्चितता (Uncertainty) अवश्य रहती है। इसलिए प्रादेशिक सीमांकन के लिए अन्य विधियों के प्रयोग किए जा रहे हैं।

प्र.2. प्रदेशों के सीमांकन हेतु प्रमुख मात्रात्मक विधियों का वर्णन कीजिए।
Describe the regional delimitations by main quantitative analysis.

उत्तर

मात्रात्मक विश्लेषण द्वारा प्रादेशिक सीमांकन
(Regional Delimitation by Quantitative Analysis)

विभिन्न प्रकार के प्रदेशों को सीमांकित करने के लिए अनेक मात्रात्मक विधियों का विकास हो रहा है। मात्रात्मक विश्लेषण विधि के तहत विभिन्न गणितीय एवं सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग नगरीय, औद्योगिक, कृषि आदि प्रदेश के सीमाकंन में किया जाता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश भूगोलवेत्ता **पीटर हैगेट** (Peter Haggett) ने 1965 में अपनी पुस्तक '*Locational Analysis in Human Geography*' में कार्यात्मक या कर्मोपलक्षी या सकेन्द्रीय (Functional or Nodal) प्रदेशों के सीमांकन हेतु चार मात्रात्मक विधियों का वर्णन किया है। ये विधियाँ निम्नलिखित हैं—

1. थिसेन बहुभुज विधि, 2. दूरी न्यूनतमीकरण विधि, 3. विविक्तकर विश्लेषण विधि, 4. ग्राफ-सिद्धान्त विधि।

1. **बहुभुज सीमांकन तकनीक** (Polygon Delimitation Technique)—किसी क्षेत्र के प्रारम्भिक विकास में प्रत्येक परिवार या समूह आवश्यक मात्रा में वनों की सफाई कर कृषि करता है। कालांतर में जनसंख्या बढ़ने पर उसे कृष्य भूमि का विस्तार करना पड़ता है। जब विभिन्न परिवार या समूह लगातार वृद्धि करते हैं तथा कृषि का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि एकाधिक समूहों के कृष्य क्षेत्रों की सीमाएँ आपस में मिल जाती हैं तथा फिर सीमांकन आवश्यक हो जाता है। खेत पर मेड़ बनाई जाती है या अन्य सीमांकन के प्रतीक (Sign) स्थापित किए जाते हैं। यदि प्रारम्भिक सीमाएँ वृत्ताकार (Circular) थीं, तो वृत्तों की परिधि पर अतिव्यापन कम-से-कम करने के प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार

TOUCH 'n' PASS

क्रमश: बहुभुज की आकृति वाले प्रदेशों का सीमांकन अपने आप हो जाता है। इन सीमाओं की विशेषता (Speciality) यह होती हैं कि ये किन्हीं दो संलग्न फार्मों या केन्द्रों की सीमाओं से समकोण बनाती हैं तथा फॉर्म के केन्द्र के समीप होती हैं। पीटर हैगेट के अनुसार बहुभुत सीमांकन विधि के सोपान निम्नलिखित हैं—

(i) प्रत्येक केन्द्र से संलग्न केन्द्र को सीधी रेखा से जोड़ना।

(ii) ये अन्त केन्द्रीय रेखाएँ आपस में एक-दूसरे को काटती हैं तथा उनका मध्य बिन्दु निर्धारित होता है।

(iii) मध्य बिन्दु से इन रेखाओं पर लम्बवत् सीमाएँ खींची जाती हैं तथा विषम बहुभुजों का निर्माण होता है। प्रत्येक बहुभुज की सीमाएँ सम्बन्धित बहुभुज के केन्द्र के निकटतम होती हैं। इस विधि का प्रयोग केन्द्रस्थलों की सीमा निर्धारण में भी किया जाता है। इस विधि को वोरोनोई बहुभुज (Voronoi Polygon), थियेसिन बहुभुज (Thiesen Polygon) तथा डिरिक्लिट प्रदेश (Dirichlet Regions) भी कहते हैं।

थिसेन बहुभुज विधि (Thissen Polygon Method)—किसी भूभाग में आर्थिक विकास (Economic Development) की प्रारम्भिक अवस्था में उसके कृषि क्षेत्रों की प्रारम्भिक सीमाएँ प्राय: वृत्ताकार होती है, लेकिन बाद में आर्थिक विकास के बढ़ते जाने से इन कृषि प्रदेशों की सीमाएँ स्वयं ही बहुभुज का रूप ले लेती हैं। इस विधि का उपयोग साधारणतया केन्द्रीय स्थानों की सीमाओं के निर्धारण में किया जाता है।

थिसेन बहुभुज विधि का सर्वप्रथम उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के मौसम ब्यूरो द्वारा 'वर्षा क्षेत्रों की पहचान' करने के लिए किया गया था। वर्तमान समय में इस विधि का उपयोग कार्यात्मक क्षेत्र (Functional Region) की सीमाओं को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। इस विधि में थिसेन बहुभुजों (Thissen Polygons) का प्रयोग किया जाता है। बौगुए (Bogue) ने इस विधि का प्रयोग 1949 के संयुक्त राज्य अमेरिका के 67 महानगरीय केन्द्रों के सीमांकन के लिए भी किया था। इस विधि में बहुभुजों (polygons) की रचना हेतु निम्न चार क्रियाएँ की जाती हैं—

(i) किसी दिए गए केन्द्र से उसके प्रत्येक समीपवर्ती केन्द्र को जोड़ने वाली रेखाएँ खींच दी जाती है।

(ii) केन्द्रों को जोड़ने वाली उन रेखाओं को समद्विभाजित करके उनके मध्य बिन्दु ज्ञात कर लिए जाते हैं,

(iii) मध्य बिन्दु से उस रेखा पर लम्बवत् रेखा खींच दी जाती है, बहुभुज की एक भुजा होती है। इसी तरह अन्य मध्य-बिन्दुओं से रेखाएँ खींची जाती हैं।

(iv) सीमा रेखाओं के आर-पार स्थित काउण्टियों को उस केन्द्र की सीमा के अन्दर शामिल कर लिया जाता है जिसके अन्दर उस काउन्टी का आधे से अधिक क्षेत्र स्थित होता है।

थिसेन बहुभुज की यह विधि दो मान्यताओं/कल्पनाओं (Assumptions) पर निर्भर करती है—

(i) प्रथम मान्यता यह है कि बहुभुज की प्रतिच्छेदी (Intersecting) सीमा रेखाओं के अन्दर स्थित कोई क्षेत्र उस बहुभुज के अन्दर परिबद्ध केन्द्र के अधिक समीप होता है, बजाय किसी अन्य केन्द्र के।

(ii) दूसरी मान्यता यह है कि कोई महानगर (Metropolis) उस समस्त क्षेत्र पर प्रभावी होता है, जो ज्यामितीय प्रकार से उस केन्द्र से सबसे अधिक समीप होती है।

कोपेक (Kopec) ने 1963 में इन बहुभुजों की रचना की एक नई विधि बतलाई थी जिसमें समीपवर्ती बिन्दुओं से समान अर्द्धव्यास के वृत्तों के चाप (Arcs) खींचकर, उन चापों को परस्पर काटने वाले प्रतिच्छेदी बिन्दुओं (Intersected Points) के मध्य रेखाएँ खींच दी जाती हैं, ये रेखाएँ ही बहुभुजों की सीमा रेखाएँ होती हैं। इस विधि में विकर्णों (Diagonals) को खींचने की जरूरत नहीं होती और गलतियों की सम्भावना भी बहुत कम हो जाती है।

2. **दूरी न्यूनतमीकरण विधि** (Distance Minimization Method)—इस विधि के द्वारा किसी वस्तु को उसके विभिन्न स्रोतों से गन्तव्य स्थानों (Destination Places) तक पहुँचाने के लिए परिवहन लागत (Transport Cost) को न्यूनतम (Minimum) करना होता है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु को उसके विभिन्न स्रोतों से बहुत से गन्तव्य स्थानों तक पहुँचाने हेतु, या गन्तव्य स्थानों से स्रोतों तक ले जाने के लिए, परिवहन की लागत को न्यूनतम करना होता है।

इस विधि के अन्तर्गत **यीट्स** (Yeates) महोदय ने 1963 में एक कम्प्यूटर (IBM 709 Computer) की मदद से यह बात समझाई थी, कि परिवहन की समस्याओं को हल करने हेतु अभिकल्पित सक्रिय शोध (Operation Research) की एक विधि का प्रयोग करके अनेक मार्ग संगम केन्द्रों (Nodal centres) तक की दूरी को अनुकूलतम किया जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से, इसके द्वारा परिवहन की लागत न्यूनतम हो जाती है। यीट्स ने अपने प्रयोग को विस्कोन्सिन में

ग्रांग काउन्टी के तेरह हाई स्कूलों में जाने वाले 2,900 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण (Survey) करके किया था। स्कूल क्षेत्रों की अनुकूलतम सीमाओं को इस प्रकार निर्धारित किया गया था कि (i) स्कूलों की कुल दूरी न्यूनतम हो गई थीं, (ii) प्रत्येक स्कूल अपनी पूरी क्षमता तक भर गया था। इस समस्या को प्रकट करने का सूत्र निम्न है—

$$\sum_{i=1}^{n} = \sum_{j=1}^{m} dij,\ xij = \text{minimum}$$

इसमें $dij = i$ खण्ड से j हाई स्कूल तक की दूरी

$xij = i$ खण्ड के j हाई स्कूल में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या।

यीट्स के इस विश्लेषण का समर्थन कई अन्य स्थानों से हुआ है। ब्रिटेन के सोमर्सेट क्षेत्र में ग्रामीण विद्यार्थियों और स्कूलों की स्कूल-बस समस्या को हल करने में इस विधि का प्रयोग किया गया था, जिसमें पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई थी।

यीट्स महोदय का अनुसरण करते हुए गैरीसन (Garrison) ने औद्योगिक अवस्थिति के सन्दर्भ में पेट्रोलियम पदार्थों के वितरण की लागत को कम करने हेतु इस विधि का प्रयोग किया।

3. **विविक्तिर विश्लेषण विधि** (Discriminant Analysis Method)—भौगोलिक वितरणों के क्षेत्रों की सीमा निश्चित करने की इस विधि में वितरण की घटनाओं की दो विधाओं हु और η उनके चार समूह-प्रतिरूपों में रखते हैं। उन अधिक जटिल बहुपद (Polynomial) रेखाओं का, जो वितरण पर अध्यारोपित (Superimposed) किए जाने पर, क्षेत्रों को 5 और η में विभाजित करती हैं, परिकलन (Computation) किया जाता है। साधारण प्रथम श्रेणी की बहुपद रेखाएं सरल (Straight) रेखाएँ प्रतीत होती हैं, फिर जटिलता बढ़ती है, छठी श्रेणी की बहुपद रेखाएँ जटिल (Complex) होती है। जटिल रेखा ξ और η में वितरणों का शुद्ध वर्गीकरण कर देती है। इन दोनों के बीच माध्यमिक हल होते हैं, जिनकी द्वितीय श्रेणी बहुभुज रेखाएँ पर्याप्त शुद्ध होती हैं।

4. **ग्राफ सिद्धान्त विधि** (Graph Principle Method)—प्रादेशिक योजनाओं के निर्माण में परिवहन जालों (transport networks) व प्रादेशिक संरचना (regional structure) के विश्लेषण (Analysis) में ग्राफ सिद्धान्त का सफल प्रयोग किया गया है। इससे किसी क्षेत्र में स्थित नगरों के एक समुच्चय (Set of elements) में उनके साहचर्य की मात्रा ज्ञात करने पर उनका प्रादेशिक पदानुक्रम (Regional hierarchy) तय कर लिया जाता है।

ग्राफ के अन्दर नगरों को अन्तरथ बिन्दु (Terminal points) माना जाता है। नगर का क्रम (Order) उसके अन्दर आने वाले प्रवाह से (जैसे टेलीफोन वार्ताओं की संख्या से) मापा जाता है। नगरों के बीच पदानुक्रम सम्बन्धों को, अधिक ऊँचे क्रम के नगर की ओर से सबसे अधिक बाहर जाने वाले प्रवाह (Nodal flow) द्वारा निर्धारित किया जाता है।

नीस्टुएन (Nystuen) एवं एम. एफ. डेसी (M. F. Dacey) ने 1961 में ग्राफ सिद्धान्त का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के अन्दर और समीपवर्ती 40 नगरों के क्षेत्र सीमांकन हेतु किया था। उसमें लम्बी दूरी के टेलीफोन यातायात के आँकड़ों को 40 × 40 के मैट्रिक्स में रखकर, ग्राफ-सिद्धान्त द्वारा उस मैट्रिक्स का विश्लेषण किया गया था, उसके परिणामस्वरूप निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए—

(i) प्रादेशिक पदानुक्रम (Regional hierarchy) सीटिल नगर पर केन्द्रित था और नीडित पदानुक्रम (Nested hierarchy) याकिमा तथा स्पोकेन नगरों के चारों ओर थे,

(ii) एक पृथक् प्रणाली का केन्द्र पोर्टलैण्ड नगर था,

(iii) दो छोटी स्वतन्त्र प्रणालियाँ पेस्को तथा मोसेज-लेक नगरों पर केन्द्रित थीं।

ग्राफ-सिद्धान्त विधि के द्वारा प्रादेशिक-बन्धन के सापेक्ष के सामर्थ्य निश्चित हो जाती है और यह विधि प्रशासनिक एवं औद्योगिक-व्यापारिक दोनों प्रकार की आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रादेशिक सीमांकन के लिए विशेष उपयोगी है। ग्राफ सिद्धान्त प्रवाह विश्लेषण उपागम (Flow Analysis Approach) का परिवर्तित रूप है। यह कर्मोपलक्षी प्रदेशों के सीमांकन का बहुत ही सरल, क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ढंग है। प्रादेशीकरण करते समय जब कोई क्षेत्र अपने समीपवर्ती क्षेत्र

TOUCH 'n' PASS

से कितना मिलता-जुलता है, इस तथ्य को निश्चित करने के लिए क्षेत्रों के गुणों के आधार पर प्रदेशों के समूह (Clusters) बनाए जाते हैं। समीपस्थ क्षेत्रों की तुलना करने की दो विधियाँ हैं—

(अ) **प्रसरण विश्लेषण विधि** (Variance Analysis Method)—इस विधि का प्रयोग **जॉबलर** (Zobler) ने किया था जिसमें उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के समीपवर्ती चार राज्यों की उद्योगों में लगी जनसंख्या की तुलना करके प्रसरण विश्लेषण (Analysis) ज्ञात किया। किसी प्रदेश में स्थित राज्यों के अन्दर ही अन्दर जो उनकी परस्पर भिन्नता (Variance) या विसरण होता है, उसे प्रदेश का आन्तरिक विसरण (Within region Variation) कहते हैं। कई प्रदेशों के मध्य भिन्नता या विसरण को प्रदेशों के मध्य विसरण (Between region Variation) कहते हैं। दोनों प्रकार की प्रादेशिक भिन्नताओं को प्रसरण विश्लेषण (Analysis) द्वारा ही ज्ञात किया जाता है।

(ब) **सहसम्बन्ध व प्रादेशिक बन्धन** (Correlation and Regional Bonds)—सहसम्बन्ध का सामान्य अर्थ मात्रात्मक व गुणात्मक विशेषताओं का साहचर्य है। इसे सहसम्बन्ध गुणांकों (Correlation Coefficients) द्वारा मापा जाता है। **एम. जी. कैण्डल** (M.G. Kendall) तथा बकलैण्ड (Buckland) ने उसके लिए निम्नांकित सूत्र का प्रयोग किया है—

$$T = (\sum aij\, bij) \sqrt{(\sum_{aij^2} \sum_{bij^2})}$$

इसमें T = सामान्यीकृत सहसम्बन्ध गुणांक

$\Sigma = 1$ संख्या से n संख्या तक के i और j के समस्त मूल्यों का योग।

थॉम्पसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य के घातांक को ज्ञात करने में इस विधि का प्रयोग किया था। हैगुड (Hagood) ने बन्ध-मानों (Bond Values) द्वारा नाभिकीय (Nuclear) तथा सीमान्त (Marginal) राज्यों का प्रतिरूप स्पष्ट किया है।

उपर्युक्त विधियों के अतिरिक्त निम्नलिखित विधियों का प्रयोग भी प्रदेशों के सीमांकन में किया जाता है. जिसका विवरण निम्नलिखित है—

गुरुत्व विश्लेषण मॉडल (Gravity Analysis Model)—गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी मॉडल का प्रयोग भी प्रदेशों के सीमांकन में किया जाता है। इस मॉडल की उत्पत्ति **न्यूटन के गुरुत्व मॉडल** से विकसित हुई है। इसमें दो केन्द्रों के मध्य अन्योन्यक्रिया (Interaction) केन्द्रों की जनसंख्या के सीधे अनुपात में तथा केन्द्रों के मध्य की दूरी के सन्दर्भ में व्युत्क्रमानुपाती होती है। गुरुत्व विश्लेषण के लिए निम्नांकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है—

$$Tij = R\left[Pi \times \frac{Pj}{dij^2}\right]$$

यहाँ, $Tij = i$ और j नगरों के मध्य गुरुत्व

Pi, pj = दोनों केंद्रों की जनसंख्या

dij^2 = दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी का वर्ग

R = स्थिरांक (Constant) है।

इसी प्रकार का एक सूत्र **डब्ल्यू.जे. रैली** (W.J. Reilly) ने भी दिया है।

$$M_1 = K \times P_1 \times \frac{P_2}{d_2}$$

M_1 = सूचकांक

K = आनुपातिक स्थिरांक

P_1 = प्रथम केन्द्र की जनसंख्या

P_2 = दूसरे केन्द्र की जनसंख्या

d^2 = दोनों केन्द्रों के मध्य की दूरी का वर्ग।

स्पष्ट है कि प्रादेशीकरण के लिए जो विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं उनमें से प्रत्येक की कुछ-न-कुछ विशेषताएँ हैं। इनको अधिक उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रादेशीकरण से पूर्व अध्ययन क्षेत्र की भली प्रकार जानकारी प्राप्त कर ली जाये। ऐसा करने से समांगता (Homogeneity) का पता लगाना आसान हो जाता है। किसी क्षेत्र का प्रादेशीकरण अनेक चरों (Variables) के आधार पर भी किया जा सकता है जिसमें कम्प्यूटरों की सहायता भी ली जा सकती है।

TOUCH 'n PASS

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. निम्नलिखित में से कौन-सा लक्षणों की सातत्यता के आधार पर किसी भी प्रदेश के सीमांकन की विधि है?
(क) सातत्यता का सीमांकन (ख) असातत्यता का सीमांकन
(ग) असातत्यता के वितरण का सीमांकन (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.2. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रादेशिक परिसीमन हेतु गुणात्मक विश्लेषण की विधि है?
(क) अभिलक्षणों की सातत्यता के आधार पर (ख) प्राकृतिक एवं स्थानीय भिन्नताओं के आधार पर
(ग) अध्यारोपण विधि (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.3. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रादेशिक परिसीमन हेतु मात्रात्मक विश्लेषण की विधि नहीं है?
(क) थिसेन बहुभुज विधि (ख) दूरी न्यूनतमीकरण विधि (ग) अध्यारोपण विधि (घ) ग्राफ-सिद्धान्त विधि
उत्तर (ग) अध्यारोपण विधि

प्र.4. निम्नलिखित में से '*Locational Analysis in human geography*' पुस्तक के लेखक कौन हैं?
(क) जे० रैली (ख) जॉबलर (ग) पीटर हैगेट (घ) कोपेक
उत्तर (ग) पीटर हैगेट

प्र.5. संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों के सीमांकन हेतु ग्राफ सिद्धान्त का प्रयोग किसने किया?
(क) एम०एफ० डेसी (ख) नीस्टुएन (ग) (क) एवं (ख) दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ग) (क) एवं (ख) दोनों

प्र.6. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का सुझाव दिया–
(क) राजमन्नार समिति ने (ख) बलवन्तराय मेहता समिति ने
(ग) अशोक मेहता समिति ने (घ) चन्दा समिति ने
उत्तर (ख) बलवन्तराय मेहता समिति ने

प्र.7. बलवन्तराय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया?
(क) ग्राम सभा को (ख) पंचायत को (ग) पंचायती समिति को (घ) जिला परिषद् को
उत्तर (ग) पंचायती समिति को

प्र.8. पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे–
(क) महात्मा गाँधी (ख) सिद्धराज ढड्डा (ग) राजीव गाँधी (घ) ये सभी
उत्तर (ग) राजीव गाँधी

प्र.9. 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस भाँति के चुनाव का प्रावधान किया गया है?
(क) प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान (ख) अप्रत्यक्ष
(ग) गुप्त मतदान (घ) खुला मतदान
उत्तर (क) प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान

प्र.10. ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है–
(क) ग्राम पंचायतें (ख) जिला पंचायतें (ग) ब्लॉक समितियाँ (घ) ये सभी
उत्तर (क) ग्राम पंचायतें

प्र.11. लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगर क्षेत्र को कहा जाता है–
(क) टाउन एरिया (ख) नगर पालिका (ग) नगर निगम (घ) छावनी बोर्ड
उत्तर (ग) नगर निगम

TOUCH 'n' PASS

UNIT-IV

प्रादेशिक योजना की विचारधाराएँ और मॉडल
Theories and Models for Regional Planning

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. सन्तुलित क्षेत्रीय विकास का क्या अर्थ है?
What is the meaning of balanced regional development?

उत्तर विश्व के कुछ ही राष्ट्र ऐसे हैं जिसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अत्यधिक है तथा जो विकास की उच्चस्तरीय अवस्थाओं में प्रविष्ट हो चुके हैं। वहीं देशों का बहुत बड़ा समूह ऐसा है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बहुत कम है और जो विकास की निम्नस्तरीय अवस्थाओं को भी पार नहीं कर पा रहे हैं। अतिविकसित (Very Developed) देशों एवं अल्प-विकसित (Under developed) देशों में यह अन्तर निरन्तर विद्यमान ही नहीं है, बल्कि इस अन्तर में वृद्धि भी होती जा रही है। यही क्षेत्रीय असन्तुलन (Regional Inbalance) है। क्षेत्रीय विकास दो रूपों में मिलता है—(i) विभिन्न देशों का सन्तुलित विकास करना, (ii) एक ही राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों का सन्तुलित विकास करना।

प्र.2. क्षेत्रीय सन्तुलन को परिभाषित कीजिए।
Define regional balance.

उत्तर क्षेत्रीय सन्तुलन से हमारा तात्पर्य किसी देश में विभिन्न भौगोलिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान विकास से है अर्थात् विकास प्रक्रिया का संचालन इस प्रकार किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास को गतिशील रखने के साथ-साथ पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास की गति को अधिक तीव्र रखा जाए जिससे पिछड़े क्षेत्र विकसित क्षेत्रों के समान विकास का स्तर प्राप्त कर सकें। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि विकास प्रक्रिया में विकसित क्षेत्रों के और विकास को उस समय तक गतिहीन रखा जाए जब तक कि अन्य क्षेत्र इनके समान विकास स्तर प्राप्त न कर ले। विकसित क्षेत्रों के विकास की गति को तीव्र रखकर इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। वर्तमान युग में लगभग सभी विकासशील राष्ट्र असन्तुलित क्षेत्रीय विकास के दोष से पीड़ित हैं और इन देशों की विकास प्रक्रिया का संचालन इस प्रकार किया गया है।

प्र.3. खण्डीय सन्तुलन से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by sectoral balance?

उत्तर खण्डीय सन्तुलन के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों (कृषि, खनिज, उद्योग, यातायात, संचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, आदि) में सन्तुलन स्थापित किया जाता है। विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों में पारस्परिक सन्तुलन स्थापित किए बिना विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान नहीं की जा सकती है। एक उद्योग अथवा व्यवसाय के उत्पादों अथवा सेवाओं का उपयोग अन्य उद्योग एवं व्यवसायों में आदाओं (inputs) के रूप में किया जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के समस्त खण्ड एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं और एक खण्ड का प्रभाव दूसरे खण्ड पर पड़ता है। अत: जब तक अर्थव्यवस्था के सभी खण्डों का विकास सन्तुलित रूप से नहीं किया जाता है, एक खण्ड की क्रियाएँ दूसरे खण्ड की क्रियाओं को या तो अवरुद्ध (Hindered) करती हैं अथवा दोहराती (Repeat) हैं जिससे साधनों का अपव्यय (Wastage) होता है। अधिकतर विकासशील राष्ट्रों में विकास की गति धीमी होने के कारणों में मुख्य है खण्डीय सन्तुलन।

प्र.4. क्षेत्रीय असन्तुलित विकास के उदय होने के प्रमुख कारण लिखिए।
Write the main reasons for the emergence of regional imbalance in development.

उत्तर क्षेत्रीय असन्तुलित विकास के उदय होने के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं—

1. उपरिढ़ाँचे की सुविधाओं की उपलब्धता में विषमता होती है।
2. पिछड़े क्षेत्रों में जनमानस की विकासपरक अभिव्यक्ति प्राय: गौण रहती है।

TOUCH 'n PASS

3. पिछड़े क्षेत्र कृषि प्रधान होते हैं और नगरीय क्षेत्रों की सुविधाओं से वंचित होते हैं।
4. पिछड़े क्षेत्रों में निजी निवेश की प्रेरणा नहीं होती।
5. पिछड़े क्षेत्रों की गरीबी आर्थिक क्रियाएँ आरम्भ करने में बाधक होती हैं।

प्र.5. आय वितरण सन्तुलन क्या है?
What is the income distribution balance?

उत्तर विकास नियोजन के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि हो जाती है, परन्तु आय के पुनर्वितरण द्वारा समानता उदय नहीं हो पाती है। आय एवं अवसर की समानता उत्पन्न किए बिना विकास की प्रक्रिया का लाभ सम्पन्न वर्गों को ही अधिक मिलता है जिससे विषमताओं में और वृद्धि होती है। आय के विषम वितरण से समाज में सम्पन्न एवं विपन्न जनसमुदाय के वर्ग स्थापित होते हैं और सामाजिक असन्तुलन (Social Inbalance) का उदय होता है। विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक प्रगति के साथ-साथ विषमताएँ एवं सामाजिक असन्तुलन भी बढ़ता जाता है और व्यापक निर्धनता निरन्तर बनी रहती है।

प्र.6. मिर्डल के मॉडल का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए।
Give the critical appraisal of Myrdal's Model.

उत्तर मिर्डल के मॉडल ने बहुत सुन्दर ढंग से उन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों को मिला दिया है जो विश्व के अल्प-विकसित देशों को उस संचयी प्रक्रिया में रखने का प्रयास करती हैं, जहाँ दरिद्रता स्वयं अपना कारण बन जाती है। यह सत्य है कि अल्प-विकसित देशों में प्रबल अतिनिर्यात प्रभाव प्रसरण प्रभावों को मन्द कर देते हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं तथा प्रादेशिक व विश्व असमानताओं को प्रेरित करती हैं। बाजार व्यवस्था में नियन्त्रण की कमी के कारण अल्प-विकसित देशों के निर्यात नहीं बढ़े हैं। इससे विकसित देशों के आयातों एवं निर्यातों में बड़ा अन्तर आ गया है, जिसने उनके आर्थिक विकास को महँगा तथा लम्बा बना दिया है। अनुभव ने भी मिर्डल के मॉडल की पुष्टि की है।

प्र.7. आर्थिक विकास की अवस्थाओं की आलोचनाएँ लिखिए।
Write the criticisms of stages of economic growth.

उत्तर रोस्टोव के मॉडल की मुख्य आलोचनाएँ निम्न हैं—

1. देश के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक नहीं होता है कि वह परम्परागत अवस्था से ही गुजरे।
2. पूर्व स्थिति की अवस्था में यह आवश्यक नहीं है कि वह आत्मस्फूर्ति (Take-off) से पूर्व ही आएं।
3. भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ एक-दूसरी की पर्याप्त सीमा तक अतिव्यापी (overlapping) रही हैं।
4. आत्मस्फूर्ति सम्बन्धी आलोचनाएँ की गई हैं जैसे कि—
   (i) आत्मस्फूर्ति की तिथियाँ सन्देहयुक्त रहती हैं।
   (ii) असफलताओं (Failures) की सम्भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है।

प्र.8. अल्प-विकसित देश एवं रोस्टोव के मॉडल का महत्त्व बताइए।
State the importance of Rostow's model and under-developed countries.

उत्तर अल्प-विकसित देशों के औद्योगीकरण हेतु आत्मस्फूर्ति का सिद्धान्त बहुत ही उपयुक्त है। राष्ट्रीय आय के 10% के ऊपर पूँजी-निर्माण तथा एक या अधिक क्षेत्रों का विकास प्राय: अल्प-विकसित देशों के औद्योगीकरण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इन देशों में तीसरी शर्त अधिक महत्त्वपूर्ण है जिसमें मौद्रिक एवं राजनीतिक संस्थाएँ तथा कुशलताएँ एक निम्न स्तर पर होती हैं, जिसके कारण वे आधुनिक क्षेत्र में तीव्रगति से विकास नहीं कर पाती हैं।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. विकास ध्रुव सिद्धान्त में जे०आर० बाउडेविले द्वारा संशोधन का उल्लेख कीजिए।
Explain the modification by J.R. Boundeville in growth pole theory.

उत्तर

विकास ध्रुव सिद्धान्त में जे. आर. बाउडेविले द्वारा संशोधन
(Modification by J.R. Boundeville in Growth Pole Theory)

फ्रेंकोइस पेरॉक्स ने सन् 1950 ई. में विकास की संकल्पना 'एक अमूर्त या अदृश्य आर्थिक क्षेत्र' में आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु या नाभिक के रूप में की थी जिसमें एक अन्य फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे. आर. बाउडेविले ने सन् 1966 ई. में संशोधन करते हुए इसकी व्याख्या 'एक मूर्त या दृश्य भौगोलिक क्षेत्र' में विकास केन्द्र के रूप में प्रस्तुत की। इस प्रकार बाउडेविले ने अपने सिद्धान्त

का आधार 'भौगोलिक क्षेत्र' (Geographic area or region) को बनाया और 'विकास ध्रुव' के स्थान पर 'विकास केन्द्र' शब्दावली का प्रयोग किया। विकास ध्रुव सिद्धान्त को बाउडेविले के कारण ही विशिष्ट प्रादेशिक एवं औद्योगिक महत्त्व प्राप्त हुआ। बाउडेविले आर्थिक स्थान की प्रादेशिक विशेषता पर बल देते हैं।

बाउडेविले के अनुसार 'विकास केन्द्र' शहरों की तरह जन्म लेता है जहाँ विभिन्न जटिल एवं प्रगतिकारक (Propulsive) उद्योग स्थित रहते हैं। अत: यह कहा जा सकता है कि बॉउडेविले ने पेरॉक्स के सिद्धान्त को मानते हुए क्रियात्मक एवं स्थानिक ध्रुवों के बीच की दूरी (Distance) को कम करने का प्रयास किया है। बॉउडेविले ने 'विकास केन्द्र' को इस प्रकार परिभाषित किया है—'विकास केन्द्र एक नगरीय क्षेत्र में स्थित वृद्धिमान उद्योगों के समूह हैं, जो इसके सम्पूर्ण प्रभाव क्षेत्र में आर्थिक विकास को पुन: प्रेरित करता है।' वह प्रदेश या औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ ये प्रभावशाली उद्योग स्थापित होते हैं वह उस प्रदेश का पुंज या ध्रुव बन जाता है और इस प्रकार एकत्रीकरण/समूहीकरण (Agglomeration) की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

बॉउडेविले ने पेरॉक्स के विकास ध्रुव सिद्धान्त का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया कि विकास ध्रुव को स्थापित किया जाता है तो आर्थिक विकास के साथ क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि हो सकती है, अतएव बाउडेविले ने भौगोलिक दृष्टिकोण से आर्थिक एवं सामाजिक विकास (Social Development) पर आधारित मॉडल के द्वारा क्षेत्रीय विषमता के प्रभाव को कम करने का सुझाव व्यक्त किया। बाउडेविले के अनुसार विकास ध्रुव वह है, जो किसी प्रेरक उद्योग को जन्म दे और वह केन्द्र से होता हुआ ग्रामीण अर्थतंत्र तक पहुँच जाए। बाउडेविले ने यह तर्क दिया कि चूँकि प्रेरक उद्योग किसी-न-किसी केन्द्र पर ही स्थापित होगा, अतएव जहाँ ऐसा प्रेरक उद्योग स्थापित होगा वह बिन्दु विकास ध्रुव (Growth Pole) बन जाएगा तथा ऐसे अन्य केन्द्र जो अग्रगामी एवं पश्चगामी शृंखला (Forward and Backward Linkages) में प्रेरक उद्योग से जुड़े उद्योगों के स्थल होंगे, अन्य विकास केन्द्र के रूप में विकसित होंगे। इस प्रकार विकास केन्द्रों के माध्यम से सम्पूर्ण देश में औद्योगिक विकेन्द्रीकरण होगा। इस प्रकार सम्पूर्ण देश का आर्थिक विकास होगा और प्रादेशिक विषमता कम होगी।

बाउडेविले ने भौगोलिक स्थान में एक बड़े निरन्तर विस्तृत प्रदेश की कल्पना करके उस प्रदेश में तीन प्रकार के प्रदेशों-समांग, ध्रुवीकृत तथा नियोजन (Homogenous, Polarised and Planning) का अनुमान किया। पहला प्रदेश किसी वस्तु के समान वितरण पर निर्धारित किया जाता है, दूसरा प्रदेश विभिन्न तत्त्वों की अन्तर्निभरता के गुण और मानवीय क्रियाओं के एकत्रीकरण से जाना जा सकता है तथा तीसरा प्रदेश नीति निर्णायक प्राधिकरण द्वारा विकास लक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

पेरॉक्स एवं बॉउडेविले ने वृद्धि ध्रुव की जनसंख्या के बारे में कोई विचार नहीं रखा, तथापि भारतीय विद्वानों (आर. पी. मिश्रा, के. वी. सुन्दरम, प्रकाश राव आदि) ने वृद्धि ध्रुव की जनसंख्या 5 से 25 लाख तक बतायी है। प्रत्येक विकास ध्रुव 20 मिलियन (2 करोड़) ग्रामीण जनसंख्या की सेवा करता है तथा यह देश के एक वृहद् प्रदेश का हृदय स्थल होता है, जहाँ विशेषीकृत द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियायें होती हैं, जो अन्य केन्द्रों पर नहीं होती। ये ध्रुव अपने केन्द्रों तथा बिन्दुओं को वित्तीय, तकनीकी, अनुसंधान तथा औद्योगिक सुविधाएँ प्रदान करते हैं। कलकत्ता उत्तर-पूर्वी भारत, दिल्ली उत्तर-पश्चिमी भारत, मुम्बई पश्चिमी भारत तथा मद्रास दक्षिणी भारत के विकास ध्रुव हैं। आर. पी. मिश्र ने भारत के इन 4 महानगरों को विकास ध्रुव (Growth Pole) बताया तथा मध्य नगरों जैसे मैसूर, जयपुर, भोपाल, मेरठ इत्यादि को विकास केन्द्र (Growth Centre) बताया तथा बाजार केन्द्रों (Market Towns) को विकास बिन्दुओं (Growth Points) के रूप में विकसित पाया।

प्र.2. विभिन्न देशों के सन्तुलित विकास के कारणों का उल्लेख कीजिए।

Explain the causes of unbalanced growth of different countries.

उत्तर

विभिन्न देशों के सन्तुलित विकास के कारण
(Causes of Unbalanced Growth of Different Countries)

आधुनिक युग में विकास के स्तर में विभिन्न राष्ट्रों में अत्यधिक विभिन्नता विद्यमान है। यह विभिन्नता प्रति व्यक्ति आय से परिलक्षित होती है। प्रति व्यक्ति औसत आय देश के उत्पादन एवं जनसंख्या से सन्दर्भित होती है।

विभिन्न देशों के सन्तुलित विकास के कारण निम्नलिखित हैं—

1. **निर्धनता का दुश्चक्र** (Vicious Circle of Poverty)—अल्प-विकसित राष्ट्रों की व्यापक निर्धनता एक ऐसा ऋणात्मक घटक है, जो विभिन्न अन्य ऋणात्मक घटकों को जन्म देता है। दूसरी ओर विकसित राष्ट्रों में सम्पन्नता का चक्र ऊर्ध्वमुखी होता है जिससे विकास में सहायता पहुँचाने वाले बहुत-से घटक उदय एवं सुदृढ़ होते रहते हैं।
2. **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रतिकूल शर्तें** (Unfavourable terms of International Trade)—अल्प-विकसित राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने निर्यात का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है और उन्हें अपने आयात के लिए अधिक

मूल्य चुकाना पड़ता है। इनके निर्यात में विभिन्नता की कमी, पूर्ति एवं माँग का बेलोच होना आदि प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत, आयात सशर्त होते हैं जिनका लाभ सहायता देने वाले देशों को होता है।

3. **प्राकृतिक साधनों का उपयुक्त अवशोषण न किया जाना** (Unexploitation of available natural resources)—अल्प-विकसित राष्ट्रों में प्राकृतिक साधनों का पर्याप्त विदोहन (Sufficient Exploration) नहीं किया जा सका है और जिन साधनों का विदोहन किया भी गया है उन पर विदेशियों का प्रभुत्व है जिससे देश की अर्थव्यवस्था इससे लाभान्वित नहीं होती है।
4. **जनसंख्या का परिमाण, संरचना एवं गुण विकास के अनुकूल न होना** (Unfavourable quantum, composition and quality of population for growth)—अल्प-विकसित देशों में जनसंख्या की वृद्धि की गति तेज रहती है और जन-साधारण का जीवनकाल छोटा होता है जिससे उत्पादक श्रम शक्ति का जनसंख्या में अनुपात कम रहता है। परम्परागत जीवन, व्यापक अशिक्षा एवं सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण श्रम में कुशलता ग्रहण करने की क्षमता कम होती है जिससे उत्पादन की क्रियाएँ अवरुद्ध होती हैं।
5. **राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता** (Political and economic unstability)—विकसित राष्ट्रों की तुलना में अल्प-विकसित राष्ट्रों में राजनीतिक उथल-पुथल अत्यधिक होती है। सुदृढ़ शासन की अनुपस्थिति में विकास के अनुकूल नीतियों का निर्धारण और कुशल संचालन सम्भव नहीं हो पाता है। इससे साधनों का अपव्यय (Wastage) होता है।
6. **औद्योगीकरण की मन्द गति** (Slow growth of industrialisation)—असन्तुलित विकास का एक प्रमुख कारण औद्योगीकरण की गति का अन्तर भी है। अल्पविकसित राष्ट्र प्राय: कृषि प्रधान होते हैं। कृषि व्यवसाय में विकास की गति मन्द (Slow) रहती है, क्योंकि यह प्रकृति पर निर्भर करती है। वहीं औद्योगीकरण की प्रगति की दर मानवीय प्रयासों द्वारा उत्पादक साधनों पर निर्भर करती है। यही कारण है कि औद्योगिक राष्ट्रों में विकास की गति कृषि प्रधान राष्ट्रों की तुलना में अधिक रहती है।
7. **आय का वितरण विकास में सहायक नहीं** (Distribution of Income is not helpful in development)—अल्पविकसित राष्ट्रों में आय का वितरण विकसित राष्ट्रों की तुलना में अधिक विषम होता है। इन राष्ट्रों में आय का बहुत बड़ा भाग जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों को प्राप्त होता है, जो जोखिम नहीं उठाते हैं। वहीं विकसित राष्ट्रों में आय का वितरण साहसियों के पक्ष में होता है जिससे उत्पादक विनियोजन में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।

प्र.3. मिर्डल मॉडल की प्रादेशिक असमानताएँ बताइए।
Explain the regional disparity of Myrdal's Model.

उत्तर

प्रादेशिक असमानताएँ
(Regional Disparity)

देश में प्रादेशिक असमानता का कारण आर्थिक भिन्नता है। यह पूँजीवादी (Capitalist) अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित रहती है तथा लाभ के उद्देश्य से चलाई जाती है। वे क्षेत्र विकसित हो जाते हैं जो कि लाभ के उद्देश्य से चलाए जाते हैं और अन्य क्षेत्र अल्प-विकसित रह जाते हैं। बाजार शक्तियों (Market Powers) की स्वतन्त्र शक्ति प्रादेशिक असमानताओं (Disparities) को बढ़ाती है। यह प्रादेशिक असमानताएँ उस समय उभर आती हैं जबकि कुछ स्थानों पर कीमत में वृद्धि हो जाती है और वे प्रदेश गतिहीन बने रहते हैं। प्रो. मिर्डल का कहना है कि "यदि बात बाजार शक्तियों पर ही छोड़ दी जाए और उन्हें किन्हीं नीति हस्तक्षेपों से अवरुद्ध न किया जाए तो समस्त आर्थिक सक्रियताएँ विकासशील अर्थव्यवस्था को औसत से अधिक प्रतिफल (Return) प्रदान करेंगी।" इसके विपरीत विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा व संस्कृति कुछ स्थानों पर एकत्रित हो जाएगी और देश के दूसरे भाग को न्यूनाधिक पश्चग-जल (backwater) में छोड़ देंगी। इस प्रकार प्रादेशिक असमानताएँ तब उभरती हैं, जब कुछ स्थान अन्य प्रदेशों की कीमत पर वृद्धि करते हैं और वे प्रदेश गतिहीन रहते हैं।

पूँजी से भी प्रादेशिक असमानताएँ बढ़ जाती हैं। विकसित प्रदेश में बढ़ी हुई माँग विनियोग को प्रेरित करती है जिससे माँग में और वृद्धि होकर विनियोग में वृद्धि हो जाती है। यदि बैंकिंग व्यवस्था को नियमित नहीं किया गया तो दरिद्र क्षेत्रों से बचतों को निकाल कर धनी एवं प्रगतिशील (Progressive) प्रदेशों में पहुँचाने का साधन बन जाती है जिससे पूँजी के प्रतिफल ऊँचे और सुरक्षित हो जाते हैं। मिर्डल पिछड़े हुए प्रदेशों पर देशान्तर, पूँजीगतियों व व्यापार के अतिनिर्यात प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने अपनी थीसिस में यह बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार श्रम का देशान्तर, पूँजीगतियों एवं व्यापार के अतिनिर्यात प्रभाव पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास में बाधा (Obstacle) डालते हैं। साथ ही समस्त अर्थव्यवस्था के विकास को धीमा करते हैं। जब एक क्षेत्र का विकास

अन्य पिछड़े हुए क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होने लगता है तो विकसित क्षेत्र में संचयी प्रसार की शृंखला चालू होने से अन्य क्षेत्रों पर अतिनिर्यात प्रभाव कार्यशील हो जाते हैं जिससे विकास अन्तर शुरू होते हैं।

प्र.4. मिर्डल के चक्रीय/संचयी कार्यकरण के मॉडल का उल्लेख कीजिए एवं इसकी अन्तर्राष्ट्रीय असमानताएँ लिखिए।
Mention Myrdal's Model of Circular/Cumulative Causation and write its international inequalities.

उत्तर

मिर्डल का चक्रीय/संचयी कार्यकरण का मॉडल
(Myrdal's Model of Circular/Cumulative Causation)

प्रो. मिर्डल (Myrdal) का मत है कि आर्थिक विकास का परिणाम चक्रीय कार्यकरण प्रक्रिया है। इससे धनिक को अधिक लाभ प्राप्त होता है और जो लोग पिछड़ जाते हैं, उनके प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। प्रो. गुन्नार मिर्डल ने विकासात्मक समस्याओं का अवलोकन विभिन्न देशों में पाई जाने वाली क्षेत्रीय असमानताओं और अन्तर्राष्ट्रीय असमानताओं के सन्दर्भ में किया है। अर्द्ध-विकसित देश के अन्दर ही विभिन्न क्षेत्रों में आय, कच्चे माल की उपलब्धि की प्रवृत्ति प्राय: पाई जाती है। कुछ देशों में साम्राज्यवाद (Imperialism) के कारण भी इसमें वृद्धि हुई है।

प्रो. गुन्नार मिर्डल ने 'प्रसरण प्रभाव' एवं 'अति निर्यात प्रभाव' में अन्तर प्रस्तुत किया है। पहला प्रभाव विस्तार और समृद्धि के बढ़ने से सम्बन्धित है एवं दूसरा आय और अन्य आर्थिक लाभों के क्षेत्र में विभिन्नताओं के बढ़ने को दर्शाता है। जब भी एक क्षेत्र विशेष में विकास होता है तब दूसरे क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव 'प्रसार' या 'अति निर्यात प्रभावों' पर दोनों ही प्रकार का पड़ता है, किन्तु 'प्रसरण प्रभाव' अधिक व्यापक और प्रभावशाली होते हैं। यही कारण है कि प्रो. मिर्डल ने 'साधनों के मूल्यों की समानता द्वारा आर्थिक एकीकरण' को विकास की प्राथमिक आवश्यकता बताया है। यदि श्रम उद्योग-धन्धों में कृषि की अपेक्षा अधिक आय प्राप्त कर सकता है तो साधनों का पुन: वितरण आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार घरेलू अर्थव्यवस्था में अनेक असन्तुलन उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ पाई जाती हैं, उसी प्रकार विश्व अर्थव्यवस्था में भी अनेक असन्तुलन उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ पाई जाती हैं। इन क्षेत्रीय असमानताओं, इत्यादि का क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर निवारण आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय असमानताएँ—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से अल्प-विकसित देशों में प्रबल अतिनिर्यात प्रभाव हो सकते हैं। **मिर्डल** का मत है कि 'व्यापार धनी तथा प्रगतिशील प्रदेशों के पक्ष में आधारभूत पक्षपात लेकर और कम विकसित देशों के प्रतिकूल परिचालन करता है।' यदि दो देशों में से एक औद्योगिक हो और दूसरा अल्प-विकसित हो और औद्योगिक एवं अल्प-विकसित देशों के मध्य अबाधित व्यापार हो, तो वह औद्योगिक देश को बल देगा और अल्प-विकसित देश को गरीब बना देगा। अमीर देश उत्पादों को सस्ती दर पर लाकर अल्प-विकसित देशों के लघु उद्योगों को पीछे धकेल देता है जिससे पिछड़े देश प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादक मात्र बनकर रह जाते हैं। चूँकि निर्यात व्यापार में प्राथमिक वस्तुओं की माँग लोच (Elasticity) रहित होती है अत: उन्हें मूल्यों में काफी उतार-चढ़ाव के कारण हानि सहनी पड़ती है तथा निर्यातों से अधिक लाभ अर्जित नहीं कर पाते हैं। इसमें भुगतान शेष की कठिनाइयाँ भी आती हैं। पूँजी प्राप्तियाँ भी अन्तर्राष्ट्रीय असमानताओं की रोकथाम करने में असफल रही हैं। अत: जो अबाधित व्यापार उन्नत देशों में प्रगति लाते हैं, उन्हीं ने अल्प-विकसित देशों में प्रबल अतिनिर्यात प्रभाव उत्पन्न किए हैं। अत: अल्प-विकसित देशों के बीच जो दुर्बल प्रसरण प्रभाव विद्यमान हैं, वे इन देशों के अपने ही भीतर के उन दुर्बल प्रसरण प्रभावों की झलक मात्र हैं, जो कि इनके विकास के निम्न स्तर के कारण उत्पन्न हुए रहते हैं।

पूँजी-गतियाँ भी अन्तर्राष्ट्रीय असमानताओं की रोकथाम करने में असफल रही हैं, क्योंकि विकसित देश स्वयं ही निवेशकर्त्ताओं (Investors) को वस्तुएँ, लाभ तथा सुरक्षा प्रदान करते हैं जिससे पूँजी अल्प-विकसित देशों से दूर रहती है।

प्र.5. असन्तुलित विकास पद्धति के गुणों व दोषों का उल्लेख कीजिए।
Explain the merits and demerits of unbalanced growth method.

उत्तर

असन्तुलित विकास पद्धति के गुण व दोष
(Merits and Demerits of Unbalanced Growth Method)

असन्तुलित विकास पद्धति के गुण व दोषों को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है—

असन्तुलित विकास पद्धति के गुण—हर्शमैन द्वारा प्रतिपादित असन्तुलित वृद्धि का सिद्धान्त अल्प-विकसित देशों के लिए शीघ्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने का एक साहसिक प्रयास है। यह यथार्थिक है और विकास योजना के लगभग सभी पक्षों पर विचार करता है। असन्तुलित विकास पद्धति के मुख्य गुणों को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है—

1. **औद्योगिक विकास**—यदि सामाजिक उपरिपूँजी के रूप में विनियोग किया जाता है तो परिवहन, आदि की सुविधाओं के कारण देश में नवीन उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है तथा देश औद्योगिक प्रगति करता है।

2. **कम समय में अधिक विकास**—असन्तुलित विकास में प्रारम्भिक अवस्था में बड़े उद्योगों पर जोर दिया जाता है जिससे अन्य उद्योगों को स्वयं सहायता मिल जाती है, फलस्वरूप कम-से-कम समय में अधिक से अधिक विकास सम्भव हो जाता है।
3. **उपभोग-प्रधान उद्योगों की नींव**—असन्तुलित विकास में विशाल एवं आधारभूत (Fundamental) उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया जाता है जिससे देश में स्वत: ही उपभोग प्रधान उद्योगों की स्थापना के लिए नींव स्थापित हो जाती है जो आगे चलकर विकसित हो जाते हैं।

असन्तुलित विकास पद्धति के दोष—असन्तुलित विकास पद्धति के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं—

1. **उत्पादन वृद्धि होने में देरी**—असन्तुलित विकास में विशाल उद्योगों के विकास पर ही जोर दिया जाता है, जिससे देश के अन्य उद्योगों का विकास देरी से होता है और उत्पादन में वृद्धि होने में बहुत देर लग जाती है जिससे अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास होने में बहुत समय लग जाता है।
2. **मुद्रा-स्फीति का भय**—असन्तुलित विकास की पद्धति से कुछ उद्योगों में भारी मात्रा में विनियोग (Investment) किया जाता है, जिससे प्राय: अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में मुद्रा-स्फीति (Inflation) का भय बना रहता है क्योंकि पूँजी के अभाव में विदेशी पूँजी या मुद्रा का सहारा लिया जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है और विकास में रुकावटें उत्पन्न करता है।

प्र.6. असन्तुलित विकास की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
Critically explain of unbalanced growth.

उत्तर

असन्तुलित विकास की आलोचना
(Criticism of Unbalanced Growth)

असन्तुलित विकास, विकास की आदर्श विधि नहीं है, जिसके आधार पर देश का विकास किया जा सके। इसकी प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

1. **समाजवादी अर्थव्यवस्था में कम महत्त्व**—असन्तुलित विकास का समाजवादी अर्थव्यवस्था में बहुत कम महत्त्व है, क्योंकि इसमें देश के विकास के कार्यक्रमों का निर्णय प्राय: राज्य द्वारा किया जाता है एवं स्वतन्त्र क्रियाओं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।
2. **अनिश्चितता में वृद्धि**—सन्तुलित विकास अनिश्चितता में वृद्धि लाता है, क्योंकि यह विदेशी व्यापार एवं विदेशी पूँजी पर अधिक निर्भर करता है, जो प्राय: राजनीतिक दबावों से चलने के कारण अनिश्चितता उत्पन्न करती है।
3. **राजकीय नियोजन का अभाव**—असन्तुलित विकास में राज्य के कार्यक्षेत्र को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया। इसमें राजकीय नियोजन का अभाव रहता है और स्वतन्त्र बाजार प्रेरणाएँ ही नियोजन के लिए पर्याप्त नहीं मानी जातीं। वास्तव में, असन्तुलित विकास के लिए भी राजकीय नियोजन आवश्यक है, जबकि उसका अभाव इसमें पाया जाता है।
4. **अवरोधों के उल्लेख का विकास**—असन्तुलित विकास में उन अवरोधों का भी वर्णन नहीं किया गया जो सुस्त पड़े रहते हैं। इस प्रकार समस्त क्षेत्रों का पूर्ण उल्लेख नहीं किया गया है।
5. **असन्तुलित विकास करना व्यर्थ**—कुछ अर्थशास्त्रियों का कथन है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में असन्तुलन की स्थिति का पाया जाना स्वाभाविक है और उसके लिए देश में असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न करना आवश्यक नहीं है। वास्तव में, माँग व पूर्ति सूची में बेलोच होने से असन्तुलन स्वयमेव ही उत्पन्न हो जाता है।
6. **अपव्यय में वृद्धि**—सन्तुलित विकास में कुछ ही क्षेत्रों का अत्यधिक विकास किया जाता है जिससे उसमें आधिक्य (Surplus) क्षमता होने से अपव्यय (Wastage) में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि विनियोग क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास होने के कारण क्षेत्र के साधन निष्क्रिय (Inactive) पड़े रहते हैं, जिनका पूर्ण उपभोग सम्भव नहीं होता जब तक कि अन्य क्षेत्र इस क्षेत्र के बराबर विकसित न कर लिए जाएँ।
7. **अवैज्ञानिक सिद्धान्त**—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की दृष्टि से असन्तुलित विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया जिससे यह सिद्धान्त वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं बन पाया है।
8. **स्फीतिक दबावों की उत्पत्ति**—असन्तुलित विकास सिद्धान्त से देश में स्फीतिक दबावों की उत्पत्ति होने का भय बना रहता है।

TOUCH 'n' PASS

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. फ्रेंकोइस पेरॉक्स के विकास ध्रुव सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

Description of growth pole theory of Francois Perroux.

उत्तर

विकास/वृद्धि ध्रुव सिद्धान्त
(Growth Pole Theory)

औद्योगिक क्रान्ति से लेकर वर्तमान काल तक मानव के समक्ष सर्वाधिक ज्वलंत समस्या आर्थिक विकास की गति तीव्र करने की है। यह समस्या विकासशील देशों में अधिक गम्भीर है, क्योंकि इनके पास पूँजी एवं संसाधन दोनों ही सीमित हैं। इसी कारण विश्व में प्राय: सभी देश विकास की गति को तीव्र करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तर तक प्रयासरत हैं। 1950 के दशक के बाद आर्थिक विकास के साथ बढ़ती हुई क्षेत्रीय असमानताओं (Regional Disparity) को दूर करने के लिए क्षेत्रीय आयामों से जुड़ी अनेक संकल्पनाओं का आविर्भाव हुआ जिसमें फ्रेंकोइस पेरॉक्स का विकास ध्रुव सिद्धान्त (1950), गुन्नार मिर्डल का संचयी परिणामी सिद्धान्त, (1957), ए. ओ. हर्शमैन का असंतुलित वृद्धि सिद्धान्त (1958), जे. फ्रीडमैन का केन्द्र-परिधि मॉडल (1966) आदि प्रमुख हैं।

आर्थिक एवं प्रादेशिक विकास सम्बन्धी 'विकास ध्रुव सिद्धान्त' (Growth pole theory) का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांस के प्रादेशिक अर्थशास्त्री फ्रेंकोइस पेरॉक्स (Francois Perroux 1903-1987) द्वारा सन् 1950 ई. में किया गया था। यह सिद्धान्त 1950 ई. में ही अर्थशास्त्र की त्रैमासिक पत्रिका 'ऑक्सफोर्ड जनरल्स' में 'Economic Space : Theory and Application' नाम से 'ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस' द्वारा प्रकाशित की गयी थी। पेरॉक्स के 'विकास ध्रुव सिद्धान्त' को एक अन्य फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री जे. आर. बाउडेविले (J. R. Boudeville) ने सन् 1966 ई. में संशोधित किया एवं अपनी पुस्तक *'Problems of Regional Economic Planning'* में इसे 'विकास केन्द्र सिद्धान्त' के नाम से प्रकाशित किया। इसके बाद बटलर (Buttler) ने अपनी पुस्तक *'Growth Pole Theory and Economic Development'* में आर्थिक विकास के सन्दर्भ में इसकी उपयोगिता का वर्णन किया।

फ्रेंकोइस पेरॉक्स का विकास ध्रुव सिद्धान्त
(Growth Pole Theory of Francois Perroux)

फ्रांसीसी अर्थशास्त्री पेरॉक्स द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद फ्रांस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं से बहुत अधिक प्रभावित थे। जिस समय वे अपने विकास ध्रुव की संकल्पना के विषय में लिख रहे थे; फ्रांस मार्शल योजना के अन्तर्गत पुनर्निर्माण की अवस्था से गुजर रहा था। उस समय नगरीय केन्द्र आर्थिक विकास के आरम्भिक केन्द्र थे जिनका विकास प्रौद्योगिकी और नवाचार (Innovation) पर आधारित उद्योगों पर आधारित था जो मुख्य रूप से अपने चतुर्दिक स्थित प्राथमिक संसाधनों यथा-लौह-अयस्क, कोयला, कृषि उत्पादों आदि पर आधारित थे। नगरीय केन्द्र पर उद्योगों के संकेन्द्रण (Centralisation) नगर से बाहर स्थित परिक्षेत्र की अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर रहे थे।

पेरॉक्स एक प्रादेशिक अर्थशास्त्री (Regional Economist) थे जो आर्थिक विकास की प्राय: सभी प्रक्रियाओं के निरीक्षण एवं अनुभव के आधार पर आर्थिक विषमता से सम्बन्धित जटिल समस्याओं के समाधान के लिए किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु 'नवाचार एवं वृहत् स्तर के फर्मों (Innovations and Large-Scale Firms) की भूमिका' के बारे में **शुम्पीटर** (Schumpeter) **के सिद्धान्त**, गत्यात्मक एवं प्रथम मूल उद्योग, अग्रगामी एवं पश्चगामी शृंखला एवं ध्रुवीकरण के सिद्धान्त के आधार पर विकास ध्रुव की संकल्पना का प्रतिपादन किया।

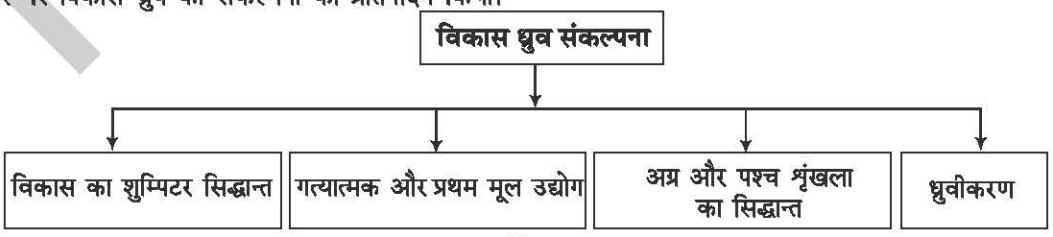

चित्र

पेरॉक्स ने स्पष्ट किया कि किसी प्रदेश का आर्थिक विकास एकाएक उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि यह मन्द गति से होने वाली एक सतत् प्रक्रिया है। तकनीकी युग से पहले आर्थिक विकास संतुलित रूप से समूचे प्रदेश में होता था, जबकि आज तकनीकी प्रधान

तीव्र आर्थिक विकास प्रदेश के कुछे बिन्दुओं या स्थानों पर केन्द्रित हो रहा है। आर्थिक वृद्धि के कुछेक बिन्दुओं/नगरों या क्षेत्रों में ही केन्द्रीकृत हो जाने एवं अवशेष विशाल भू-भाग के अविकसित उपान्त (Periphery) रह जाने की समस्या का निराकरण हेतु विकास ध्रुव को स्थापित करना आवश्यक हो जाता है।

आर्थिक विकास सर्वव्यापी नहीं होता है, बल्कि किसी एक केन्द्र से प्रारम्भ होता है। इस केन्द्र पर किसी उद्योग विशेष अथवा उद्योगों के समूह एवं आर्थिक संस्थानों का संकेन्द्रण (Centralisation) होने लगता है, जो वृद्धि ध्रुव या विकास ध्रुव (Growth) कहलाता है। यहाँ वृद्धि एवं विकास समानार्थी हो जाते हैं, क्योंकि इसी केन्द्र पर मात्रात्मक (Quantitative) एवं गुणात्मक (Qualitative) दोनों परिवर्तन होते हैं।

विकास ध्रुव को परिभाषित करते हुए पेरॉक्स ने लिखा है कि, 'वे सभी केन्द्र जहाँ से अपकेन्द्रीय शक्तियाँ (Centrifugal forces) उत्पन्न होती हैं एवं जिसके लिए अभिकेन्द्रीय शक्तियाँ (Centripetal Forces) आकर्षित होती हैं विकास ध्रुव कहलाता है। ऐसा प्रत्येक केन्द्र आकर्षण एवं प्रतिकर्षण (Attraction and Repulsion) का केन्द्र होने के कारण इसका अपना प्रभाव क्षेत्र होता है जो अन्य सभी केन्द्रों के क्षेत्रों के साथ व्यवस्थित होता है।' इस प्रकार विकास ध्रुव को एक नगरीय स्थिति माना जाता है, जहाँ आर्थिक क्रिया नगरीय परिधीय क्षेत्र में विकास तथा उच्चतर जीवन की गुणवत्ता को प्रज्वलित करती है। विकास ध्रुव पर संकेन्द्रित होने वाली आर्थिक क्रियाओं के प्रभाव से केन्द्र के बाहर एक प्रभाव क्षेत्र का विकास होता है।

1. **विकास ध्रुव सिद्धान्त की मान्यताएँ** (Assumptions of the Growth Pole Theory)—
   (i) पेरॉक्स ने विकास ध्रुव की संकल्पना 'एक अमूर्त आर्थिक क्षेत्र' (An Abstract Economic space) में आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु या नाभिक के रूप में की थी। इसमें कई केन्द्र या ध्रुव सम्मिलित रहते हैं जिनसे अपकेन्द्रीय बल या शक्तियाँ बाहर की ओर फैलती हैं एवं अभिकेन्द्रीय बल उसकी ओर आकर्षित होता है। प्रत्येक केन्द्र में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के रूप में उनके निजी क्षेत्र होते हैं, जो अन्य केन्द्रों के क्षेत्र में भी निहित हो सकते हैं।
   (ii) पेरॉक्स महोदय ने सामाजिक तत्त्वों पर ध्यान नहीं दिया तथा वृद्धि ध्रुवों के बनाने में उद्योगों की भूमिका ही प्रमुख मानते हैं।
   (iii) पेरॉक्स के अनुसार विकास ध्रुव की उत्पत्ति एवं विकास के लिए प्रभुत्व (Dominance) पक्ष का होना अति महत्त्वपूर्ण है। कोई वृहत् फर्म या उद्योग जिसकी अन्य फर्मों या उद्योगों के साथ उच्च श्रेणी की अन्त:क्रिया (Interaction) होती है और जो उस अन्त:क्रिया में प्रभुत्व रखती है उसे पेरॉक्स ने 'उत्प्रेरक' (Propulsive) की संज्ञा दी है। किसी उत्प्रेरक फर्म या उद्योग के विकास की प्रक्रिया को ध्रुवीकरण (Polarization) के नाम से जाना जाता है।
   (iv) पेरॉक्स की मान्यता के अनुसार वृद्धि-ध्रुवों या केन्द्रों पर कुछ ऐसे प्राथमिक उद्योग या आर्थिक क्रियाएँ होती हैं, जो बाद में नवीनीकरण और वृद्धि जनक के रूप में कार्य करते हैं। ये उद्योग नई तकनीकों तथा वृद्धि जनक विशेषताओं से पूर्ण होते हैं।
   (v) पेरॉक्स के अनुसार विकास ध्रुव के प्रभाव क्षेत्र में स्थापित छोटे-बड़े उद्योगों में अग्रगामी व पश्चगामी सम्बन्ध होने के कारण एक साथ कई उद्योगों का विकास होता है। साथ ही ये विकास का सृजन भी करते हैं।
2. **विकास ध्रुव सिद्धान्त की व्याख्या** (Explanation of the Growth Pole Theory)—पेरॉक्स ने एक 'अमूर्त या अदृश्य आर्थिक क्षेत्र' में आर्थिक विकास के नाभिक (Center) के रूप में विकास ध्रुव की संकल्पना प्रस्तुत की अर्थात् उनकी संकल्पना आर्थिक स्थान (Economic Space) से सम्बन्धित है, भौगोलिक स्थान (Geographic Space) से नहीं। उनका विकास ध्रुव सिद्धान्त दो बिन्दुओं पर आधारित है। **प्रथम** शुम्पीटर (Schumpeter) का औद्योगिक विकास सिद्धान्त तथा **द्वितीय** अन्तर-औद्योगिक सम्बन्ध व औद्योगिक अन्त:क्रिया (Interaction)। शुम्पीटर महोदय ने नवाचार एवं वृहदस्तरीय फर्म (Innovations and Large-Scale Firms) का विचार प्रतिपादित किया तथा स्पष्ट किया कि विकास कुछ नवाचार की सहायता से उद्यमियों द्वारा किया जाता है। वे बड़ी स्तर की फर्म तथा उद्योग किसी स्थान पर स्थापित करते हैं। ये उद्योग अपने पड़ोस से कच्चा माल (Raw Material) लेकर तथा तैयार माल देकर प्रभावित करते हैं। इस प्रकार विभिन्न असतत् केन्द्रों (Discontinous Spurts) का जन्म होता है। वास्तव में वे आर्थिक विकास के तथ्यपरक तथा संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया से सम्बद्ध थे। उन्होंने इस तथ्य की व्याख्या करने का प्रयास किया था कि 'किस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया, संतुलित विकास की स्थिर अवधारणा से भिन्न होती है।

   पेरॉक्स ने अपने सिद्धान्त में दो विचार दिए **प्रथम** गत्यात्मक नोदक-फर्म (Dynamic Propulsive Firm) जो सापेक्षता बड़ी होती है, नवाचार कर सकती है तथा तीव्र गति से वृद्धि करती है तथा **द्वितीय** अग्रणीय नोदक-फर्म

TOUCH 'n' PASS

(Leadning Propulsive Firm) जिसमें तकनीकी एवं प्रबन्धन का स्तर ऊँचा होता है, इसके उत्पाद की खपत अधिक होती है, अन्तर-औद्योगिक सम्बन्ध तीव्र होता है। **अन्तर-औद्योगिक सम्बन्ध** दो प्रकार का होता है-प्रथम अग्रगामी शृंखला (Forward Linkage) जिमसें अपने उद्योग में नवाचार वाले क्षेत्र के साथ सम्बन्ध, जैसे लौह-इस्पात उद्योग में अच्छे किस्म का इस्पात तैयार करने की इकाई के साथ सम्बन्ध का अध्ययन किया जाता है तथा द्वितीयक पश्चगामी शृंखला (Backward Linkage) जिसमें उद्योग के लिए कच्चा माल या उत्पाद माल तैयार करने वाले उद्योगों के साथ सम्बद्ध जैसे लौह-उद्योग का लौह-अयस्क खनन उद्योग से सम्बन्ध का अध्ययन होता है इस अग्रगामी एवं पश्चगामी सम्बन्ध से औद्योगिक उत्पादन की लागत घटती है जिससे उद्योग बढता है।

कच्चा लोहा ⟹ लौह-इस्पात ⟹ रेल पटरी, गाड़िया, कील आदि

चित्र : अन्तर-औद्योगिक सम्बन्ध

पेरॉक्स ने स्पष्ट किया कि "वृद्धि सर्वत्र एक साथ नहीं दिखती, बल्कि यह कुछ बिन्दुओं या विकास ध्रुवों पर विभिन्न गहनता के शुरू होकर अनेक चैनलों के माध्यम से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में फैलती है।" इन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक-आर्थिक विकास मानवीय क्रियाओं के स्थानिक संगठन द्वारा उत्पन्न होता है। इसलिए हमेशा असमान होता है। इन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक क्षेत्र (Economic Space) में एक केन्द्र होता है जिसे ध्रुव (Pole) की संज्ञा दी जाती है। आर्थिक विकास तभी अग्रसर होता है जब कोई उद्योग (Propeller Industry) देश में स्थापित हो। इस उद्योग के बढ़ने से, उससे अग्रगामी एवं पश्चगामी शृंखला (Forward and Backward Linkages) में आबद्ध अन्य विविध उद्योग भी सक्रिय हो जाते हैं जिससे सम्पूर्ण अर्थतन्त्र विकसित होता है। विकास ध्रुवों पर तेजी से विकास होता है और इससे प्रादेशिक असमानताएँ (Regional Disparities) कम होती हैं।

चित्र : वृद्धि बिन्दु, वृद्धि केन्द्र और वृद्धि ध्रुव : अग्रगामी और पश्चगामी शृंखला

विकास ध्रुवों में विकास को अन्य स्थानों तक पहुँचाने की क्षमता होती है। ये निकटवर्ती क्षेत्रों का संपोषणीय विकास करते हैं और समस्त क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्पष्ट है कि यह सिद्धान्त अर्थतन्त्र के संगठनात्मक पक्ष पर ध्यान देता है न कि प्रादेशिक विषमता पर। इस प्रकार विकास ध्रुव से सम्बन्धित आर्थिक विकास प्रारम्भ होता है और धीरे-धीरे उसका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाता है। इन्हीं प्रेरक उद्योगों के माध्यम से द्वितीय एवं तृतीय क्रम के केन्द्रों की एक शृंखला बन जाती है जिनके माध्यम से क्षेत्र के विभिन्न भागों में उनका प्रसार होता है। इस प्रकार विकास ध्रुव अर्थतंत्र का एक गत्यात्मक केन्द्र होता है। यह कभी भी स्थिर नहीं रहता। उदाहरणस्वरूप भारत के औद्योगिक विकास में सर्वप्रथम लोह-इस्पात उद्योग प्रेरक रहा, उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग आया, तदुपरान्त क्रमशः मोटर, मशीन तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने विकास ध्रुव का स्थान लिया। सम्प्रति भारत का वर्तमान विकास ध्रुव संचार केन्द्र प्रतीत होने लगा है।

विकास ध्रुव में अभिकेन्द्रीय बल (Centripetal Force) और अपकेन्द्रीय बल (Centrifugal Force) कार्य करते हैं। अभिकेन्द्रीय बल के द्वारा बाह्य सेवाएँ व संसाधन केन्द्र की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि अपकेन्द्रीय बल द्वारा केन्द्र से बाहर की ओर सेवाओं का प्रसार होता है। इस प्रकार विकास ध्रुव से सेवाओं का वितरण एवं प्रसार अन्य क्षेत्रों में निरन्तर होता रहता है। यह विकास की गति को तीव्र से तीव्रतर करने का प्रयास करता है। जब किसी नयी प्रौद्योगिकी (Technology) का विकास होता है तो नवाचार के रूप में इसे सबसे पहले विकास ध्रुव ग्रहण करते हैं। उसके बाद उनका प्रसार विकास बिन्दुओं से होता हुआ ग्रामीण सेवा केन्द्रों तक पहुँचता है। किन्तु जब तक इसका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में होता है तब तक कोई नया विकास ध्रुव बन जाता है। इस प्रकार विकास ध्रुव परिवर्तित होता रहता है। इसका प्रभाव केन्द्रीय भाग (क्रोड) से लेकर परिधि क्षेत्र तक तथा विकास केन्द्रों तक शृंखलाबद्ध रूप से क्रमशः ह्रासोन्मुख होता है। बीच-बीच में कुछ अप्रभावित क्षेत्र भी बच जाते हैं जिनका विकास नहीं हो पाता।

TOUCH 'n' PASS

3. **विकास ध्रुव पर मूल एवं सम्बद्ध उद्योगों का विकास** (Growth of Key and Linked Industries at Growth Pole)—पेरॉक्स के विकास ध्रुव सिद्धान्त के अनुसार विकास ध्रुव पर प्राय: मूल उद्योग (Key industries) स्थापित होते हैं जिनके प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव से उनके चारों तरफ सम्बद्ध उद्योगों (linked industires) का विकास होता है। मूल अथवा आरधारभूत उद्योग कई प्रकार के हो सकते हैं जिनमें लौह-इस्पात उद्योग, मोटर वाहन उद्योग, वैमानिकी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, कृषि-आधारित उद्योग, पेट्रोकैमिकल उद्योग आदि प्रमुख हैं। मूल उद्योग का प्रभाव उपभोक्ताओं पर दो तरह से पड़ता है-प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रभाव के अन्तर्गत क्रेता वस्तुएँ एवं सेवाएँ सम्मिलित होती हैं जो इसे आपूर्तिकर्त्ता (Supplier) उद्योगों से प्राप्त होती हैं अथवा जो वस्तुओं एवं सेवाओं को अपने उपभोक्ताओं (निचले सम्बद्ध उद्योगों) को प्रदान करता है। मूल उद्योग के अप्रत्यक्ष प्रभाव के अन्तर्गत उन लोगों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की माँगों को शामिल किया जा सकता है जो मूल अथवा सम्बद्ध उद्योगों में संलग्न होते हैं और फुटकर व्यापार जैसी आर्थिक क्रियाओं के विकास और विस्तार में सहयोग करते हैं।

मूल उद्योग के विकास एवं विस्तार के फलस्वरूप निवेश, उत्पादन, रोजगार, नवीन प्रौद्योगिकी (New Technology) के साथ ही नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का भी विस्तार होता है। प्रादेशिक विकास की इस प्रक्रिया में परिवहन मार्गों का विस्तार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विकास ध्रुव पर एकत्रीकरण के लाभ की उपलब्धता के कारण उसके समीपवर्ती क्षेत्रों का प्रादेशिक विकास प्राय: असंतुलित रहता है। बाद की अवस्था में द्वितीयक/गौण विकास ध्रुव की भी उत्पत्ति हो सकती है, विशेषकर तब जब गौण औद्योगिक क्षेत्र का अपनी स्वयं के सम्बद्ध उद्योगों के साथ उदय होता है जिससे प्रादेशिक आर्थिक विविधता (Economic Variation) उत्पन्न होती है।

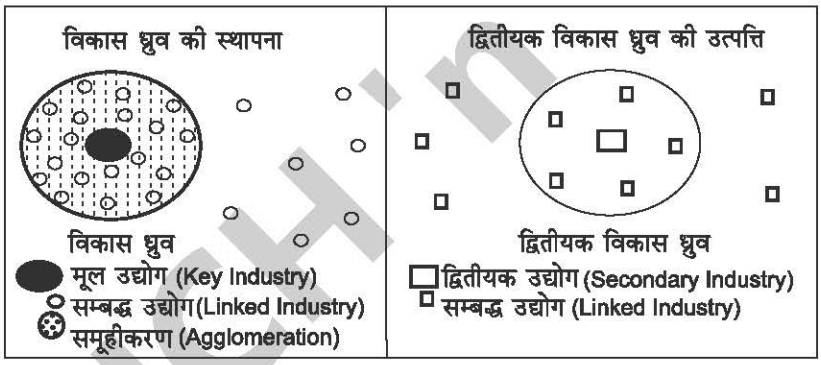

चित्र (1) चित्र (2)

चित्र

चित्र (1) प्रदर्शित करता है कि प्रारम्भ में किसी अकेले मूल उद्योग की स्थापना होती है जिसे विकास ध्रुव कहते हैं तथा मूल उद्योग पर आश्रित उद्योग मूल उद्योग या विकास ध्रुव के समीप संकेन्द्रित होने लगते हैं। रोजगार की उपलब्धता के कारण बाहरी क्षेत्रों से मूल उद्योग या विकास ध्रुव की ओर जनसंख्या का स्थानान्तरण (Transfer) होने लगता है और इस प्रकार मूल उद्योग के समीप औद्योगिक इकाइयों तथा जनसंख्या का एकत्रीकरण होने लगता है।

उपर्युक्त चित्र (2) में द्वितीयक विकास ध्रुव की उत्पत्ति को प्रकट किया गया है। मूल उद्योग की स्थापना के पश्चात् धीरे-धीरे अन्य विकास केन्द्रों का भी उद्‌भव होने लगता है जिसे द्वितीयक/गौण विकास ध्रुव कहा जाता है। द्वितीयक विकास ध्रुवों पर जब आधारभूत उद्योगों की स्थापना एवं विकास होने लगता है तब द्वितीयक विकास ध्रुव का विस्तार मूल विकास ध्रुव के समान होने लगता है।

प्र.2. विकास ध्रुव सिद्धान्त की सीमाओं एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए।

Describe the limitations and impacts of the growth pole theory.

उत्तर

विकास ध्रुव सिद्धान्त की सीमाएँ एवं प्रभाव
(Limitations and Impacts of the Growth Pole Theory)

1. विकास/वृद्धि ध्रुव सिद्धान्त का फ्रांस में उस समय उद्‌भव हुआ जब वहाँ आर्थिक विकास मन्द था तथा औद्योगिक विकास से असन्तुलन बढ़ रहा था। अत: तत्कालीन आवश्यकतानुसार औद्योगीकरण तथा नगरीकरण पर विशेष बल देकर किसी

प्रदेश को विकसित करने की बात कही गयी। परन्तु वर्तमान समय में नगरीकरण और औद्योगीकरण विकास की गति के साथ गम्भीर समस्या भी बन गये हैं। स्वस्थ औद्योगीकरण की चर्चा भी चल रही है जिसमें वातावरण को शुद्ध एवं प्रदूषण रहित बनाया जा सके और वातावरण पारिस्थितिकी में सन्तुलन भी रखा जा सके। इसलिए विकास ध्रुव सिद्धान्त में अन्य कमियों के साथ वातावरण गुणवत्ता की भी कमी है जो सम्प्रति विचारणीय है।

2. वृद्धि ध्रुव की संकल्पना पश्चिमी आर्थिक तंत्र के विचारों पर आधारित है जहाँ सामाजिक परिवर्तन पहले से ही शुरू हो गया था। इन देशों में औद्योगिक विकास के लिए निम्नतम प्रयास की आवश्यकता है। इसके विपरीत अधिकांश विकासशील देशों में अभी औद्योगीकरण की नींव डाली जा रही है। जिन देशों में औद्योगीकरण हुआ भी है तो गतिमान संस्थागत और आर्थिक संरचना के अभाव में उसका प्रभाव सीमित रह गया है।
3. प्रादेशिक विकास पर विकास ध्रुव के प्रभाव के अनेक उदाहरण औद्योगीकृत-नगरीकृत विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि में पाये जा सकते हैं, किन्तु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और कृषि प्रधान क्षेत्रों का समुचित आर्थिक विकास, विकास ध्रुव के माध्यम से नहीं किया जा सकता है।
4. वृद्धि ध्रुवों की संकल्पना को आर्थिक तथा प्रादेशिक विकास का आधार बनाने के लिए अथक प्रयास किया गया है। परन्तु अभी तक पूर्ण विकसित एवं सर्वमान्य नीति सामने नहीं आ पायी है। जिन देशों में अभी औद्योगीकरण प्रारम्भ नहीं हो पाया है वहाँ वृद्धि ध्रुवों को एक यंत्र के रूप में अपनाया जा रहा है।
5. विकास ध्रुव के प्रभाव का एक ज्वलंत उदाहरण कैलिफोर्निया (संयुक्त राज्य अमेरिका) की सिलिकान घाटी का लिया जा सकता है। यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी का उत्थान 1990 के दशक में बहुत तेजी से हुआ जिसका आर्थिक उत्प्रेरक कैलिफोर्निया या संयुक्त राज्य तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इसके प्रभाव की अनुभूति एशिया के कई देशों में रोजगार में वृद्धि और सामाजिक विकास के रूप में की गयी।
6. ऐतिहासिक रूप से पेराक्स के विकास ध्रुव सिद्धान्त का प्रयोग जब विकासशील देशों पर करने का प्रयास किया गया तब यह अधिकतर मामलों में अव्यावहारिक सिद्ध हुआ, क्योंकि किसी पिछड़े क्षेत्र में विकास ध्रुव का चयन करके उसके द्वारा उस सम्पूर्ण क्षेत्र में विकास को नहीं भरा जा सकता है। कुछ अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत प्रादेशिक उपागम ग्रामीण और नगरीय दोनों के आर्थिक विकास में अधिक उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं।
7. सीमावर्ती प्रदेशों में जनसंख्या बसाव बहुत कम मिलता है। इस तरह की समस्या ब्राजील में अधिक मिलती है। ऐसे प्रदेशों के विकास हेतु वृद्धि ध्रुव सिद्धान्त उपयोगी हैं। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील में ब्राजीलिया प्रोजेक्ट ऐसे ही परियोजना है। उपयुक्त ध्रुवों पर विकसित क्षेत्र या आन्तरिक क्षेत्र से श्रमिक, तकनीक और अन्य सुविधाओं का निर्यात करना होगा। यह कहना भी उचित है कि ऐसा विकास भारी उद्योगों और शक्ति-संसाधन के विकास पर निर्भर करता है। इनके सहायतार्थ अवस्थापना का विकास करके नगरों का निर्माण किया जाता है। इस सन्दर्भ में सामाजिक तथा संस्थागत नियोजन में वहाँ की वर्तमान समस्याओं पर ही ध्यान न देकर प्रदेश की सभी संभावित आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। यहाँ विकास का मुख्य उद्‌देश्य औद्योगिक संश्लिष्ट के उद्‌भव द्वारा आर्थिक विकास प्रारम्भ करना है जो प्रदेश के आन्तरिक भाग में संसाधनों के प्रवाह के माध्यम से विभिन्न तत्त्वों का समाकलन करता है और बाह्य भाग में वृद्धि जनक प्रक्रिया शुरू करता है।
8. किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु अवस्थापना अति आवश्यक है। अवस्थापना में नगरों का पदानुक्रमीय क्रम आवश्यक होता है। बिखराव की सभी क्रियाएँ राष्ट्रीय स्तर के महानगरों, प्रादेशिक स्तर के नगरों और उनसे स्थानीय स्तर के कस्बों के माध्यम से फैलती हैं, परन्तु वृद्धि ध्रुव सिद्धान्त में पदानुक्रमीय क्रम पर कोई विशेष विचार प्रस्तुत नहीं किया गया है। विकास ध्रुव क्रिस्ट्रालर के केन्द्रीय स्थल (Central place) से अलग हैं। विकास ध्रुव किसी ध्रुव की उत्पत्ति और उसके विकास तथा समूचे क्षेत्र पर उसके प्रभाव की व्याख्या करते हैं, जबकि केन्द्रीय स्थल (Central place) किसी समांग प्रदेश में विशिष्ट भौगोलिक स्थानों पर ध्रुवीय केन्द्र होते हैं जो आपस में अन्तर्सम्बन्धित रहते हैं और प्रादेशिक केन्द्र के गुरुत्वाकर्षण से आबद्ध होते हैं। क्रिस्टालर के उपयुक्त विचार में क्रिस्टालर के केन्द्र, सेवा केन्द्र (Service Centre) होते हैं जिनकी केन्द्रीयता आकार, दूरी तथा सेवा क्रियाओं पर आधारित होती है न कि उनमें विनिर्माण क्रियाओं पर। इसके विपरीत विकास ध्रुवों के अन्तर्गत विनिर्माण क्रियाएँ मुख्य हैं।
9. विकासशील देशों में आर्थिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन बढ़ता जा रहा है। जहाँ एक तरफ विकास ध्रुव आकार तथा गुणवत्ता में बढ़ रहे हैं, वहाँ आर्थिक क्रियाओं, अध:संरचना, पूँजी तथा कुशल-अकुशल श्रमिकों का संकेन्द्रण हो रहा है,

TOUCH 'n PASS

प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक पिछड़ापन एवं बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय तथा तकनीकी सुविधाएँ घट रही हैं। जिससे आर्थिक-सामाजिक संरचना में असंतुलन बढ़ रहा है और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों में प्रादेशिक चेतना (Regional Conciousness) बढ़ रही है जो प्रदेशवाद (Regionalism) तथा अलगाववाद (Spearatism) को जन्म देती है और जो राष्ट्रीय एकता में बाधक सिद्ध होती है। अतएव प्रादेशिक नियोजन में विकास ध्रुवों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिससे ये पिछड़े क्षेत्रों की कीमत पर न बढ़ें अपितु ये पिछड़े क्षेत्रों के विकास में अपनी भूमिका निभाएँ।

10. विकास ध्रुवों का विकास कुछ अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इनका चयन मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। साधारणतया दो निकटवर्ती वृद्धि ध्रुवों के क्षेत्र एक-दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं जिससे उनके निर्धारण में कठिनाई आती है। वृद्धि ध्रुवों की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं है। प्रत्येक वृद्धि ध्रुव सामाजिक-आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय समस्याओं को जन्म देता है। राजनीति पर आधारित वृद्धि ध्रुवों की स्थापना सम्पोषणीय नहीं होती। यह अनिवार्य नहीं कि वृद्धि ध्रुव एवं वृद्धि केन्द्र प्रादेशिक विषमताओं को दूर करने और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने में सदा सहायक हो। भिलाई और राऊरकेला का प्रभाव आस-पास के क्षेत्रों पर कम ही पड़ा है।
11. आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परन्तु घने बसे प्रदेशों में 'विकास ध्रुव' की संकल्पना की उपयोगिता संदिग्ध है, क्योंकि संसाधनों और नगरीकरण की कमी के कारण ये अधिक विकसित नहीं किये जा सकते। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार और तेलंगाना प्रदेश ऐसे उदाहरण हैं। उपर्युक्त प्रदेश सघन जनसंख्या वाले हैं। यहाँ की कृषि भी निर्वाहक प्रकार की है। इन प्रदेशों में नगर प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं।
12. सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, परन्तु संसाधन सम्पन्न सघन क्षेत्रों के विकास हेतु विकास ध्रुव सिद्धान्त अधिक सफल नहीं है। उदाहरणार्थ भारत में उद्योग को क्रोड मानकर विशाखापत्तनम में शिपयार्ड, भिलाई एवं राऊरकेला में आधुनिक इस्पात कारखाना यह सोचकर स्थापित किए गए कि इनको अभिकेन्द्र मानकर सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े प्रदेश में प्रादेशिक विकास शुरू होगा, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों (Natural Resources) का भौतिक विकास तो हुआ, परन्तु यथार्थ आर्थिक विकास नहीं हो सका। ऐसा भी पाया गया कि इन केन्द्रों के 10 (दस) किलोमीटर के बाह लोग अब भी वैसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसा इन केन्द्रों की स्थापना के पहले करते थे। नगरीय विकास का प्रादुर्भाव भी उचित रूप से नहीं हुआ। यहाँ के मुख्य उद्योगों का सम्बन्ध कुछ ही दूर स्थित वस्तु-निर्माण केन्द्रों से है जिसके कारण बैकवाश प्रभाव (Backwash Effect) भी सृजित नहीं हो पाया। वृद्धि-ध्रुव सिद्धान्त की उपयोगिता यातायात जाल की अपूर्णता और लोगों के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के कारण कम हो जाती है। पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थापना के अभाव के कारण वृद्धि जनक विकास निखर नहीं पाता है।
13. भारतीय आर्थिक-सामाजिक सन्दर्भ में वृद्धि ध्रुव के कार्य तीन चरणों में अपेक्षित हैं। प्रथमत: वृद्धि ध्रुव सेवा केन्द्रों का कार्य करेंगे और स्थानीय स्तर पर दैनिक आवश्यकताओं एवं सेवाओं की पूर्ति करेंगे या केन्द्रस्थलों का कार्य करेंगे। द्वितीय चरण में वृद्धि ध्रुव क्षेत्र के नवीनीकरण तथा वृद्धि में सहायक होंगे। इन केन्द्रों पर वस्तु-निर्माण एवं अन्य आर्थिक क्रियाएँ उपलब्ध रहेंगी जो राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक माँग की पूर्ति करेंगी। साथ ही उपर्युक्त क्रियायें कृषि कार्य के अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्रदान करायेंगी। अत: वृद्धि ध्रुवों का काम सिर्फ विभिन्न वस्तु-निर्माण उद्योगों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करना ही नहीं है वरन् क्षेत्र में औद्योगिक विकास की दशाएँ उत्पन्न करना भी है। तृतीय चरण में वृद्धि ध्रुव सामाजिक अन्तर्क्रिया का काम भी करेगें। यहाँ से सूचनाओं (Information) का प्रसार भी होगा। इन केन्द्रों के विस्तार सेवायें, शैक्षणिक सेवायें और बाजार की सुविधायें भी उपलब्ध होनी चाहिए जिससे सामाजिक क्रियाओं का पूर्णत: प्रसार सम्भव हो सके।
14. विकास ध्रुव सिद्धान्त के आधार पर ही भारत में स्वतन्त्रता के बाद लौह-इस्पात व उर्वरक उद्योगों को विकास ध्रुव के केन्द्र के रूप में स्थापित (जमशेदपुर, दुर्गापुर, धनबाद, बोकारो, नेवेली, सिंदरी आदि) किया गया, लेकिन उद्योगों को स्थापित किए जाने से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन तो मिला वहीं अपकेन्द्रीय बल के अपेक्षा अभिकेन्द्रीय बल का प्रभाव अधिक होने के कारण आर्थिक क्रियाओं के केन्द्रीकरण से क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि हुई। इस प्रदेश का अधिक सम्बन्ध अन्य नगरों की अपेक्षा कलकत्ता औद्योगिक प्रदेश से जुड़ गया है। प्रारम्भ में यह अनुभव हुआ कि ये केन्द्र कलकत्ता के चारों ओर काउन्टर चुम्बक (Counter Magnet) की तरह कार्य करेंगे और बिहार के विकास में सहायता करेंगे, किन्तु

TOUCH 'n' PASS

उद्देश्य के अनुरूप यहाँ भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। इस प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में जो भारी प्राथमिक उद्योग स्थापित किये गये उनका प्रादेशिक स्तर पर विकास नहीं हुआ जिससे नीचे जाने का प्रभाव (Trickle Down Effect) भी उत्पन्न नहीं हो सका।

15. पेराक्स के विकास ध्रुव सिद्धान्त के आधार पर अनेक महत्त्वपूर्ण विकास मॉडल तैयार किये गये हैं जिनका प्रयोग विकासशील विश्व के विभिन्न भागों में विकास हेतु योजना तैयार करने हेतु किया गया है। विकास ध्रुव सिद्धान्त के आधार पर ही प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री ए. ओ. हर्शमैन ने 1958 ई. 'रिसाव सिद्धान्त' (Trickle Down Theory) का प्रतिपादन किया है और स्पष्ट किया कि उद्यमी विकास ध्रुवों के आस-पास संकेन्द्रित (Concentrated) होते हैं साथ ही विकास ध्रुवों (Poles) या नगरीय क्रियाओं का प्रभाव चारों ओर स्थित स्थित पिछड़े क्षेत्रों पर पड़ता है।

विकास ध्रुव सिद्धान्त के आधार पर ही अमेरिकी नियोजक एवं अर्थशास्त्री जे. फ्रीडमैन ने विकास ध्रुव की संकल्पना को अलग रूप में प्रयोग करते हुए 1966 में अपने 'केन्द्र-परिधि मॉडल' (Cor-Periphery Model) का प्रतिपादन किया। उन्होंने विकास ध्रुव को ऐसे विकास केन्द्र के रूप में स्वीकार किया जहाँ उद्योग सहित सभी महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का संकेन्द्रण (Concentration) होता है और बाह्य क्षेत्र या परिधि को केन्द्र पर पूँजीभूत आर्थिक क्रियाओं पर आश्रित होना पड़ता है। इस प्रकार विकास ध्रुव की संकल्पना का उपयोग करते हुए अन्यान्य नगर नियोजकों, प्रादेशिक नियोजकों, आर्थिक भूगोलविदों आदि ने प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य से अलग-अलग मॉडल प्रस्तुत किये हैं।

प्र.3. रोस्टोव की आर्थिक विकास की अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए।
Describe the Rostow's stages of economic growth in detail.

उत्तर

रोस्टोव की आर्थिक विकास की अवस्थाएँ
(Rostow's Stages of Economic Growth)

रोस्टोव का मॉडल (Rostow's Model)

कुछ अर्थशास्त्रियों ने अवस्था प्रणाली द्वारा आर्थिक वृद्धि को मापने का यत्न किया है, जिसके कारण विकास प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विवेचन किया गया है। अर्थशास्त्रियों के इस वर्ग में लिस्ट, हिडलब्राण्ड, ग्रास, मार्क्स व रोस्टोव, आदि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आते हैं।

रोस्टोव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को पाँच अवस्थाओं (Five Stages) में विभाजित किया है—

1. परम्परागत समाज (Traditional Society),
2. आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था,
3. आत्मस्फूर्ति की अवस्था,
4. परिपक्वता की ओर (Towards Maturity) ,
5. अत्यधिक उपभोग की अवस्था (Stage of Excessive Consumption)।

1. **परम्परागत समाज** (The Traditional Society)—**रोस्टोव** के अनुसार, "परम्परागत समाज वह अवस्था है जिसके ढाँचे का विकास न्यूटन-पूर्व विज्ञान पर आधारित सीमित उत्पादन-फलनों के भीतर होता है, और जिसमें भौतिक जगत के प्रति न्यूटन-पूर्व मनोवृत्तियाँ रहती हैं।" ऐसे समाज का सामाजिक ढाँचा उत्तराधिकारवादी होता था, जिसमें परिवार तथा जाति सम्बन्ध प्रमुख भूमिका निभाते थे। राजनीतिक शक्ति सामान्यत: भूमिगत रईसों के हाथों में केन्द्रित रहती थी। 75 प्रतिशत से अधिक कार्यकारी जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी। स्वाभाविक रूप से, कृषि ही राज्य एवं शासकों की आय का मुख्य स्रोत और अपव्यय का साधन था।

परम्परागत समाज की विशेषताएँ—परम्परागत समाज में व्यापार की मात्रा और उसका क्षेत्र, बराबर राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों और केन्द्रीय शासन सत्ता की क्षमता पर आश्रित रहा है। जनसंख्या और उसके रहन-सहन का स्तर केवल फसलों पर ही नहीं बल्कि युद्ध एवं बीमारियों के प्रभावों पर भी निर्भर करता है। इस व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उत्पादन होते रहे, किन्तु उत्पादकता का स्तर आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के उपयोग की कमी के कारण नीचा रहा है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 'परम्परागत समाज' में हम न्यूटन पूर्व के सम्पूर्ण विश्व को सम्मिलित करते हैं। जैसे चीन में राजवंश, मध्यपूर्व की सभ्यता, मेडीटेरेनियन एवं मध्य यूरोप का विश्व। इसमें हम न्यूटन के बाद के ऐसे समाज को भी सम्मिलित करते हैं जिस पर मनुष्य की नई क्षमताओं (Capacity) का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आर्थिक परिस्थितियों को अपने लाभ के अनुसार प्रयोग में ला सकने में असमर्थ रहे।

TOUCH 'n PASS

2. **आत्म-स्फूर्ति के पूर्व की अवस्था** (Pre-conditions for Take-off)—इस अवस्था में सतत वृद्धि की पूर्व-स्थितियों का निर्माण होता है। सतत वृद्धि के लिए पूर्व स्थितियाँ ब्रिटेन एवं पश्चिमी यूरोप में 15वीं शताब्दी के अन्त और 16वीं शताब्दी के प्रारम्भ से उत्पन्न हुई थीं, उस समय मध्य युग का अन्त एवं आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व-स्थितियों को प्रोत्साहन देने वाली चार शक्तियाँ थीं—(i) नव राजतन्त्र, (ii) ईसाई धर्मान्दोलन, (iii) नव जागरण, (iv) नव जगत। इन शक्तियों ने धर्म के स्थान पर तर्क को जन्म दिया और सामन्तवाद का अन्त हुआ। इसने नवीन आविष्कारों को जन्म दिया।

रोस्टोव के अनुसार सतत औद्योगीकरण के लिए पूर्व-स्थितियाँ तीन उद्योगेतर क्षेत्रों में परिवर्तनों की अपेक्षा रखती हैं—
(i) सामाजिक उपरि-व्यय (Overhead social expenses) का निर्माण,
(ii) कृषि में तकनीकी क्रान्ति (Revolution in Technology of Agriculture),
(iii) आयातों का विस्तार करना (Enhancement of Exports)।

औपनिवेशिक शक्ति द्वारा अपनाई गई सामाजिक उपरिव्यय पूँजी को अवरुद्ध करने की नीति ने रूढ़िगत समाज को परम्परागत (Traditional) मार्ग पर चलने में सहायता दी। आधुनिक शिक्षा ने लोगों के विचार, ज्ञान और मनोवृत्ति में धीरे-धीरे सुधार किया तथा राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई भावना का विरोध होने लगा और आधुनिक उद्योग की वस्तुओं की ही माँग होने लगी।

रोस्टोव के अनुसार, सतत औद्योगीकरण के लिए पूर्व-स्थितियाँ, तीन गैर-उद्योग क्षेत्रों में आमूल परिवर्तनों की अपेक्षा रखती है—
(1) सामाजिक उपरिव्यय पूँजी का निर्माण जैसे परिवहन।
(2) कृषि में प्रौद्योगिकीय क्रान्ति और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कृषि उत्पादकता में वृद्धि होना।
(3) आयातों के विस्तार हेतु प्राकृतिक साधनों के कुशल उत्पादन और क्रय-विक्रय द्वारा वित्त प्रबन्ध करना।

3. **आत्म-स्फूर्ति की अवस्था** (The Take-off Stage)—रोस्टोव का मत है कि एक समाज के जीवन में आत्मस्फूर्ति एक बड़ा जलाशय है और जब विकास अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है तो आधुनिकीकरण की शक्तियाँ संस्थाओं के विरुद्ध संघर्ष करने लगती हैं और समाज के ढाँचे में चक्रवृद्धि ब्याज का निर्माण हो जाता है। आत्मस्फूर्ति एक औद्योगिक क्रान्ति है, जो उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तनों के साथ जुड़ी रहती है। आत्मस्फूर्ति की समयावधि छोटी मानी गई है, जो लगभग दो दशाब्दियों तक रहती है। रोस्टोव ने उनके लिए निम्नलिखित आत्मस्फूर्ति की तिथियाँ दी हैं—

देश	आत्मस्फूर्ति (वर्ष)	देश	आत्मस्फूर्ति (वर्ष)
भारत एवं चीन	1952	स्वीडन	1868-1890
तुर्की	1973	जर्मनी	1850-1873
अर्जेण्टाइना	1935	अमेरिका	1843-1860
कनाडा	1896-1914	बेल्जियम	1833-1860
रूस	1890-1913	फ्रांस	1830-1860
जापान	1878-1900	ब्रिटेन	1783-1803

आत्मस्फूर्ति की शर्तें—आत्मस्फूर्ति की निम्नलिखित सम्बद्ध लेकिन आवश्यक शर्तें हैं—
(i) विनियोग दर को राष्ट्रीय आय के 5% या उससे कम को बढ़ाकर 10% से अधिक करना।
(ii) वृद्धि की ऊँची दर वाले एक या अधिक क्षेत्रों का विकास।
(iii) राजनीतिक, सामाजिक एवं संस्थागत ढाँचे का विस्तार करना।

प्राय: समाज को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह आत्मस्फूर्ति के दौरान नवीनीकृत क्षेत्रों के लिए आधुनिक तकनीक के ढंगों का विस्तार करने पर अपने प्रयत्नों का केन्द्रीकरण करे। आत्मस्फूर्ति की स्थिति को संलग्न चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

[संलग्न चित्र में O बचत वक्र है; K_0Y_0 एवं K_1Y_1 पूँजी उत्पादन अनुपात है इसमें $OK_0/OY_0 = OK_1/OY_1$ और TY_0/Y_0Y_1 सीमान्त पूँजी उत्पादन अनुपात है।]

TOUCH 'n' PASS

अर्थव्यवस्था में आत्मस्फूर्ति आने एवं वृद्धि का यह ढाँचा जारी रहने पर अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बन जाती है। इस प्रकार आत्मस्फूर्ति का सूत्रपात किसी तीव्र प्रोत्साहन द्वारा होता है जैसे कि किसी प्रमुख क्षेत्र का निवास या राजनीतिक क्रान्ति से जो उत्पादन प्रक्रियाओं में बहिर्गामी परिवर्तन लाती है और शुद्ध निवेश के अनुपात में वृद्धि लाकर उसे राष्ट्रीय आय के 10% से अधिक दर पर ले जाती है और जो जनसंख्या वृद्धि (Population Increase) से आगे बढ़ जाता है।

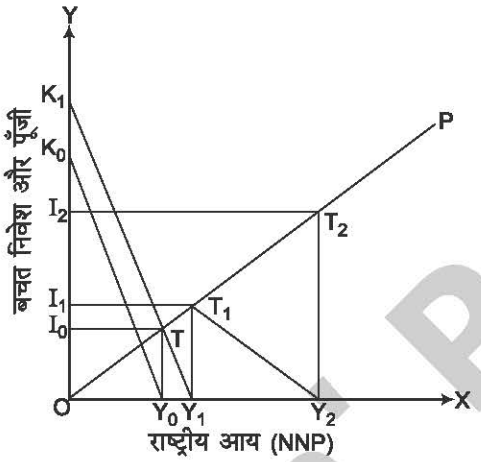

चित्र

आत्मस्फूर्ति की अवस्था के प्रमुख क्षेत्र (Leading Sectors in Take-off)—एक अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण क्षेत्र को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—

(i) **प्राथमिक विकास क्षेत्र**—इस क्षेत्र में नव-प्रवर्तनों अथवा नए लाभदायक विदोहन (Exploration) की सम्भावनाओं को शामिल करते हैं जो उच्च विकास दर प्रदान करती है और अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों को गतिमान बनाती है।

(ii) **सहायक विकास क्षेत्र**—यह ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर 'प्राथमिक विकास क्षेत्र' (Primary Development Area) में विकास होने के कारण अथवा प्राथमिक विकास के एक आवश्यक अंग के रूप में, विकास तीव्रगति से होता है। उदाहरणार्थ, रेलवे के विकास के फलस्वरूप कोयला, लोहा एवं इन्जीनियरिंग उद्योगों का विकास होना।

(iii) **व्युत्पन्न विकास क्षेत्र**—यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ विकास कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, औद्योगिक उत्पादन अथवा अन्य सभी आगे बढ़ते हुए विभागों के सन्दर्भ में यथोचित तीव्रता के साथ आगे बढ़ता है। उदाहणार्थ, जनसंख्या के सन्दर्भ में भोज्य पदार्थ, परिवार निर्माण के सन्दर्भ में गृह-निर्माण, आदि।

विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में प्राथमिक एवं सहायक क्षेत्रों में गति, लगातार उत्पादनों में परिवर्तनों के फलस्वरूप व्युत्पादित होती है, लेकिन व्युत्पन्न विकास क्षेत्र का सम्बन्ध माँग में परिवर्तनों से होता है। अतएव कहा जा सकता है कि आत्मस्फूर्ति विकास के लिए कोई निश्चित निर्धारित विभाग नहीं है और कोई भी विभाग, विकास के लिए अकेले जादू का कार्य नहीं कर सकता। सभी विभागों का आपसी और सामूहिक सहयोग आवश्यक है, चाहे कपड़े एवं जूट की मिलें हों, रेल व सड़कें हों, कोयला व लोहे का कारखाना हो, चाहे कच्चे माल का उत्पादन, परन्तु निम्न चार बातें आवश्यक हैं—

(i) **विस्तृत व प्रभावशाली माँग**—ऐसे उत्पादों की विस्तृत व प्रभावशाली माँग हो जो विकास की दर में तेजी से वृद्धि करने में आधार का काम करते हों। यह तभी सम्भव है जब आय का उत्पादक विनियोग किया जाए, पूँजी बाहर से आए, विनियोग की उत्पादकता बढ़े, उपभोक्ताओं की वास्तविक आय बढ़े।

(ii) **नई उत्पादन प्रणाली**—उपर्युक्त-क्षेत्रों में नई उत्पादन प्रणालियाँ लागू की जाएँ और उनकी क्षमता भी बढ़ाई जाए।

(iii) **पूँजी का संचय**—आत्मस्फूर्ति के उपरोक्त क्षेत्रों में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि समाज इस योग्य हो कि इस कार्य के लिए प्रारम्भ में आवश्यक पूँजी को गतिमान कर सके। यह भी आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में भाग लेने वाले पर्याप्त मात्रा में बचत का पुनर्विनियोग कर सकें।

TOUCH n PASS

(iv) **उत्पादन श्रृंखला**—प्रमुख क्षेत्र ऐसे हों कि उनमें विस्तार के फलस्वरूप दूसरे क्षेत्रों में विस्तार (Entension) हो और नए उत्पादनों के लिए बल मिले।

4. **परिपक्वता की ओर** (The Drive to Maturity)—**रोस्टोव** की परिभाषा के अनुसार, "परिपक्वता अवस्था (Mature Stage) वह अवधि है, जिसमें कोई समाज अपने अधिकांश साधनों पर आधुनिक तकनीकी के परिक्षेत्र का प्रभावपूर्ण व्यवहार करता है।" यह आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन होती है जो चार दशाब्दियों से भी अधिक समय तक रहती है। इसमें पुरानी तकनीकों का स्थान नवीन उत्पादन तकनीकें ले लेती हैं। शुद्ध विनियोग की दर राष्ट्रीय आय (National Income) के 10 प्रतिशत से अधिक रहती है। जब कोई देश तकनीकी (Technological) परिपक्वता की अवस्था में होता है तो तीन परिवर्तन होते हैं—

(i) **कार्यकारी शक्ति में परिवर्तन** (Change in Working Force)—श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी, दृष्टिकोण, संरचना और कुशलता में परिवर्तन आ जाते हैं। यह प्राय: देखा जाता है कि आत्मस्फूर्ति के पहले, श्रम शक्ति के लगभग 75 प्रतिशत लोग कृषि में कार्यरत हैं। आत्मस्फूर्ति काल में यह प्रतिशत घटकर 40 प्रतिशत आ जाते हैं और परिपक्वता के आने तक वह अंक 20 प्रतिशत तक आ जाता है।

उस अवस्था (Stage) में न केवल नगरीय जनसंख्या में ही वृद्धि होती है बल्कि कार्यालयों, दक्ष एवं समदक्ष श्रमिकों और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि होती है। श्रमिकों में जागरूकता (Awareness) आ जाती है और वे अपने अधिकार, अपनी सुविधाओं और सुरक्षाओं के लिए जागरूक हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के श्रम अधिनियमों (Labour Acts) का निर्माण होता है।

(ii) **साहसी की प्रकृति में परिवर्तन** (Change in Character of Entrepreneurship)—नेतृत्व की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। योग्य एवं दक्ष व्यावसायिक प्रबन्धकों की संख्या में वृद्धि होती हैं।

(iii) **नवीन आवश्यकताओं में परिवर्तन** (Change in New Wants)—सम्पूर्ण समाज आश्चर्यजनक औद्योगिक परिवर्तनों से कुछ हैरान-सा हो जाता है और तब कुछ विशेष प्रकार के सामंजस्य स्थापित किए जाते हैं।

अतएव इस अवस्था के अन्तर्गत निरन्तर विकास (Sustained Growth) प्रारम्भ हो जाता है। सभी आर्थिक क्रियाओं में आधुनिक तकनीक लागू हो जाती है। कुल राष्ट्रीय आय के 10 से 20 प्रतिशत तक बराबर विनियोग होने लगता है और उत्पादन में कुल वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि से तेज होती है। सम्बन्धित देश अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेता है। सभी उद्योग आधुनिक प्रकार के हो जाते हैं। जिन वस्तुओं का आयात होता था वे अब घर पर ही बनने लगती हैं। आयात की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। देश में नई प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हो जाती है।

5. **अत्यधिक उपभोग की अवस्था** (Stage of High Mass Consumption)—इस अवस्था में समाज का ध्यान पूर्ति की अपेक्षा माँग पर, उपभोग पर और कल्याण की समस्याओं पर अधिक बढ़ जाता है। निम्न तीन शक्तियाँ परिपक्वोत्तर अवस्था में कल्याण में वृद्धि करती हैं—

(i) शक्ति एवं प्रभाव बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय नीति का अनुसरण करना।

(ii) राष्ट्रीय आय के अपेक्षाकृत अधिक उचित वितरण द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।

(iii) नवीन व्यापार केन्द्र और प्रमुख क्षेत्रों का निर्माण करना।

इनसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं—

1. **बाहरी प्रभाव एवं शक्ति प्राप्ति का प्रयत्न**—प्राय: देखा जाता है कि जो राष्ट्र तकनीकी परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं वे प्रतिरक्षा एवं मिलिट्री पर व्यय अधिक करने लगते हैं और दूसरों पर अधिकार जमाने और अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपनी सीमा से बाहर भी नजर दौड़ाने लगते हैं।
2. **कल्याणकारी राष्ट्र**—इसमें राज्य प्रगतिशील (Progressive) कर प्रणाली एवं अन्य उपायों द्वारा वितरण अधिक उपयोगी एवं व्यावहारिक बनाने का प्रयास करता है। वैयक्तिक उपभोक्तावाद (Individual Consumerism) दबा दिया जाता है और समाज को अधिक-से-अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
3. **उपभोग में वृद्धि**—उपभोग की प्रकृति बदल जाती है और यह केवल अच्छे खाने, व अच्छे कपड़े तक सीमित नहीं रह जाती है बल्कि विशाल मात्रा में उपभोग की टिकाऊ वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग होने लगता है।

TOUCH 'n PASS

टिकाऊ वस्तुओं के अधिक उपभोग, निरन्तर पूर्ण रोजगार तथा सुरक्षा के कारण समाज में जनसंख्या वृद्धि की दर और बढ़ जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से, संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वप्रथम 1920 में, उसके बाद बर्तानिया 1920 में, जापान एवं पश्चिमी यूरोप 1950 में और रूस स्टालिन की मृत्यु के बाद अधिक उपभोग (Consumption) की अवस्था (Stage) में पहुँचे थे।

प्र.4. हर्शमैन के असन्तुलित वृद्धि सिद्धान्त का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

Describe the Hirschman's unbalanced growth theory in detail.

उत्तर

हर्शमैन का असन्तुलित वृद्धि सिद्धान्त
(Hirschman's Unbalanced Growth Theory)

अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास की पद्धति के सम्बन्ध में विभिन्न लेखकों द्वारा भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए गए हैं। लेखकों का एक वर्ग सन्तुलित विकास (Balance Development) का पक्षधर है जिसमें आर्थर लुईस, नर्कसे, सीटोवॉस्की, मेयर व बाल्डविन, एलन यंग और रोजेन्स्टीन-रोडान आदि आते हैं, जबकि दूसरा वर्ग **असन्तुलित आर्थिक विकास** को महत्त्व प्रदान करता है, जिसमें मार्क्स फ्लेमिंग, पॉल स्ट्रीटन, एलबर्ट हर्शमैन, हेन्स सिंगार आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

सन्तुलित विकास अथवा वृद्धि से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों एवं उद्योगों का एक-साथ विकास करना है जिससे विभिन्न क्षेत्रों की उपज के लिए तैयार बाजार मिल सके और असन्तुलन की स्थिति न उत्पन्न हो सके। असन्तुलित वृद्धि की धारणा सन्तुलित वृद्धि की धारणा के विपरीत हैं।

असन्तुलित विकास/वृद्धि का अर्थ (Meaning of Unbalanced Growth)

असन्तुलित वृद्धि का सिद्धान्त सन्तुलित वृद्धि की धारणा के बिल्कुल विपरीत है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश (Investment) न करके केवल कुछ क्षेत्रों में ही सर्वप्रथम निवेश किया जाना चाहिए, क्योंकि अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था में साधन व पूँजी इतने नहीं होते कि समस्त क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जा सके। अत: कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निवेश करके उससे विकास की गति तीव्र हो जाती है और अन्य क्षेत्रों का विकास किया जाता है। धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था असन्तुलित वृद्धि से सन्तुलित वृद्धि (Balance Growth) की ओर बढ़ती है।

प्रो. हर्शमैन का असन्तुलित विकास सिद्धान्त (Unbalanced Growth Principle of Prof. Hirschman)— प्रो. हर्शमैन ने पूर्व-निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जान-बूझकर (Intentionally) अर्थव्यवस्था के असन्तुलित वृद्धि को ही आर्थिक विकास का उत्तम ढंग माना है। **हर्शमैन, सिंगर** (Singer) एवं **नर्कसे** (Nurkse) के विचार से सहमत होते हुए 'बड़े धक्के' की आवश्यकता और परिपूरकता के विचार पर जोर देते हैं। हर्शमैन के अनुसार, विशाल पूँजी का विनियोग समस्त उद्योगों में एक साथ न करके कुछ ही उद्योगों व क्षेत्रों में प्रारम्भ करना चाहिए। उनके अनुसार आज के विकसित राष्ट्रों का आर्थिक विकास सन्तुलित विकास द्वारा न होकर असन्तुलित विकास द्वारा ही हुआ है। इस सन्दर्भ में अमेरिका का उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

हर्शमैन की व्यूह-नीति (Hirschman's Strategy)—प्रो. हर्शमैन ने असन्तुलित वृद्धि के सिद्धान्त का प्रवर्तन किया है। उनका मत है कि अल्पविकसित देशों में आर्थिक वृद्धि लाने का श्रेष्ठतम मार्ग यह है कि किसी पूर्व आकल्पित व्यूह-नीति के अनुसार जान-बूझकर असन्तुलन लाया जाए जो स्वयं आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। इस प्रकार प्रारम्भ में असन्तुलित विकास को महत्त्व दिया जाता है जिससे बाद में प्रोत्साहित होकर सन्तुलन की क्रिया प्रारम्भ हो जाएगी। हर्शमैन का मत है कि 'प्रगति इसी ढंग से होती आयी है क्योंकि अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों से अनुगामी क्षेत्रों को, एक उद्योग से दूसरे उद्योग को एवं एक फर्म से दूसरी फर्म को विकास का संचार होता रहा है।' उन्होंने यह भी कहा है कि "विकास असन्तुलनों की एक शृंखला है, जो असन्तुलनों को समाप्त करने के स्थान पर जीवित रखता है, जिससे लाभ एवं हानियाँ प्रतियोगी अर्थव्यवस्था के लक्षण माने जाते हैं। यदि अर्थव्यवस्था को आगे विकसित करना है तो विकास नीति का कार्य तनाव, गैर-अनुपात एवं असन्तुलनों को बनाए रखता है।" यदि सन्तुलित विकास के लिए अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के साधनों का विकास कर दिया जाए तो इससे राष्ट्रों को धीरे-धीरे लाभ होगा। जिन राष्ट्रों में कुल, अग्रगामी एवं अधोगामी कड़ियाँ (total, forward and backward linkage) अधिकतम हों, वहाँ असन्तुलित विकास बहुत प्रभावशाली होगा, परन्तु अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में इन कड़ियों का अभाव पाया जाता है। अत: ऐसे राष्ट्रों को प्रारम्भ में आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, परन्तु जब अर्थव्यवस्था का विकास एक निश्चित सीमा पर पहुँच जाए तो आयात के प्रतिस्थापित उद्योगों को देश में संरक्षण व कर छूट देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। व्यवहार में विकसित नीति के दो लक्ष्य होने चाहिए—(i) बाह्य मितव्ययिताओं को अधिक प्राप्त करने वाली विनियोजनों की ऊपरी सीढ़ियों की रोकथाम करना, एवं (ii) अधिकमितव्ययिताओं का निर्माण करने वाली अपसारी सीढ़ियों को बढ़ावा देना। इस प्रकार देश के सम्पूर्ण विकास के लिए असन्तुलन की नीति को अपनाना ही श्रेयस्कर रहेगा। उपरिपूँजी बाह्य मितव्ययिताओं (Frugality) का निर्माण करती है, जबकि

TOUCH 'n' PASS

प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाएँ मितव्ययिताओं को प्राप्त करती हैं। हर्शमैन ने विनियोग के क्रम को निर्धारित करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया—(i) सामाजिक उपरिपूँजी (Social Overhead Capital, SOC), (ii) प्रत्यक्ष उत्पादकता क्रियाएँ (Directly Productive Activities, DPA)।

सामाजिक उपरिपूँजी (SOC) से असन्तुलन स्थापित करना—सामाजिक उपरिपूँजी में वे क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं जिन पर अन्य औद्योगिक क्रियाएँ निर्भर रहती हैं, जैसे शक्ति, सिंचाई, विद्युत, परिवहन के साधन, आदि। प्रत्यक्ष उत्पादकता क्रियाओं से अन्तिम उत्पादन में वृद्धि होती है। अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में सामाजिक उपरिपूँजी एवं प्रत्यक्ष उत्पादकता क्रियाओं को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इससे अलाभकारी प्रभाव पड़ेंगे। इसी कारण यदि पहले सामाजिक उपरिपूँजी को बढ़ाया जाता है तो बाद में प्रत्यक्ष उत्पादकता क्रियाओं को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। सामाजिक पूँजी में वृद्धि होने से उत्पादन क्षमता में स्वयमेव ही वृद्धि हो जाती है, क्योंकि देश में परिवहन, शक्ति एवं सिंचाई के साधनों में वृद्धि हो जाती है। यदि इसमें सरकार का सहयोग रहता है तो उससे प्रत्यक्ष उत्पादकता क्रियाएँ भी प्रभावित होंगी और उत्पादन लागत गिरकर उद्योगपतियों को अधिक लाभ होता है। यह लाभ प्राय: उत्पत्ति वृद्धि नियम के क्रियाशील होने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में सामाजिक उपरिपूंजी का पूर्ण उपयोग करने के बाद, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं का विकास स्वत: ही रुक जाता है, परन्तु इससे आय में वृद्धि होने लगती है और सामाजिक उपरिपूँजी को दोबारा प्रोत्साहन मिलता है। सामाजिक उपरिपूँजी में भारी निवेश बाद में प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाओं में निजी प्रवेश को प्रोत्साहित करेगा। यह निवेश कृषि, उद्योग व व्यापार की अप्रत्यक्ष रूप में सहायता करता है, क्योंकि यह उनकी लागतों को कम कर देता है। इसके विपरीत, यदि प्रत्यक्ष उत्पादकता क्रियाओं का विस्तार पहले किया जाता है तो बाद में सरकार द्वारा देश में सामाजिक उपरिपूँजी में विनियोग करना चाहिए जिससे उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन मिल सके।

सामाजिक उपरिव्यय की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है—'इसमें वे समस्त आधारभूत सेवाएँ सम्मिलित की जाती हैं जिनके बिना प्राथमिक, द्वितीयक उत्पादन क्रियाएँ नहीं चल पातीं।' यदि देश में निजी उपक्रम द्वारा उत्पादकता क्रियाओं में विनियोग किया जाता है, अर्थात् नवीन उद्योगों की स्थापना की जाती है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार को सामाजिक उपरिपूँजी में भी विनियोग करना चाहिए जिससे उद्योगों को आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। यही **हर्शमैन** के अनुसार असन्तुलित विकास का सिद्धान्त है जिसे अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास में उपयोग किया जाना चाहिए।

उपरिपूँजी बाह्य मितव्ययिताओं का निर्माण करती है, जबकि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएँ (DPA) मितव्ययिताओं (Frugality) को प्राप्त करती हैं। सामाजिक उपरिपूंजी (SOC) में बड़ा निवेश बाद में प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं (DPA) में निजी निवेश प्रोत्साहित करेगा। सन्तुलित विकास द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो सकता। अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास में असन्तुलित विकास की नीति को ही अपनाना श्रेयष्कर होता है। इस प्रकार एक आदर्श स्थिति प्राप्त की जा सकती है जब एक असन्तुलन से विकास की गति मिलती है जो प्रतिफल में समान असन्तुलन को जन्म देती है और यही क्रिया अनन्तकाल तक चलती रहती है। यदि असन्तुलित विकास में ऐसी कड़ी को स्थापित किया जा सके, तो आर्थिक नीति के निर्माता पुराने अनुभवों (sidelines) से क्रियाओं को देख सकते हैं।

प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं (DPA) से अर्थव्यवस्था को असन्तुलित बनाना (Unbalancing the economy with DPA)—प्रत्यक्ष आर्थिक क्रियाओं से तात्पर्य निर्माणी उद्योगों के विस्तार से है। इसके माध्यम से भी असन्तुलन स्थापित किया जा सकता है। कोई सरकार SOC में निवेश करने के स्थान पर DPA में निवेश कर सकती है। यदि DPA निवेश पहले किए जाएँ, तो SOC सुविधाओं के अभाव के कारण उत्पादन लागतें बढ़ सकती हैं। राजनीतिक दबाव भी सामाजिक उपरिव्यय को उत्तेजित कर सकते हैं। लाभ प्रत्याशाओं और राजनीतिक दबावों से निवेश का अनुक्रम उत्पन्न होता है। लाभ प्रत्याशाएँ SOC से DPA में तथा राजनीतिक दबाव DPA से SOC में निवेश का अनुक्रम चलाते हैं। इन दोनों में पहले कौन-सा अनुक्रम अपनाया जाए, हर्शमैन उसे अधिमान देते हैं, जो प्रबलत: आत्मप्रणोदी (vigorously self-propelling) हो। इसे चित्र द्वारा समझाया गया है। चित्र में DPA निवेश को अनुलम्ब अक्ष पर तथा SOC को क्षैतिज अक्ष पर प्रदर्शित किया गया है।

वक्र aa_1, bb_1 तथा cc_1 समोत्पाद वक्र हैं जो DPA तथा SOC के उन विभिन्न संयोगों अर्थात् मात्राओं को व्यक्त करते हैं जिनके प्रत्येक बिन्दु पर राष्ट्रीय आय की मात्रा समान होती है। साथ ही दाहिनी ओर का वक्र अपेक्षाकृत ऊँचे आय के स्तर को बतलाता है। मूल बिन्दु M से खींची गई 45° की रेखा तीनों समोत्पाद वक्रों के अनुकूलतम बिन्दुओं को मिलाती है और साथ ही यह रेखा SOC तथा DPA की सन्तुलित वृद्धि को भी दर्शाती है।

हर्शमैन की विकास प्रक्रिया नीति के सम्बन्ध में दो मान्यताएँ हैं—(i) SOC एवं DPA का एक साथ विस्तार नहीं किया जा सकता (ii) विस्तार की वह रूपरेखा अपनाई जानी चाहिए जो प्रेरित निर्णयकरण (induced-decision-making) को अधिकतम कर दे।

यदि कोई देश प्रथम क्रम अर्थात् 'SOC की अतिरिक्त क्षमता के मार्ग' से विकास की नीति अपनाता है तो ऐसी दशा में अर्थव्यवस्था AA_1BB_2C रेखा-मार्ग का अनुसरण करेगी। यदि SOC को A से A_1 तक बढ़ाया जाता है तब इससे प्रेरित DPA निवेश B_1 तक लगातार बढ़ता रहेगा जब तक कि B बिन्दु पर पुन: सन्तुलन नहीं स्थापित हो जाता। इस बिन्दु पर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था (Economy) उत्पादन के पहले से अधिक ऊँचे स्तर पर होगी। अब यदि सरकार इस बढ़े हुए राष्ट्रीय उत्पादन से प्रेरित होकर SOC को और अधिक बढ़ाकर B से B_2 पर लाती है तो इससे DPA भी बढ़कर C बिन्दु पर पहुँच जाएगा।

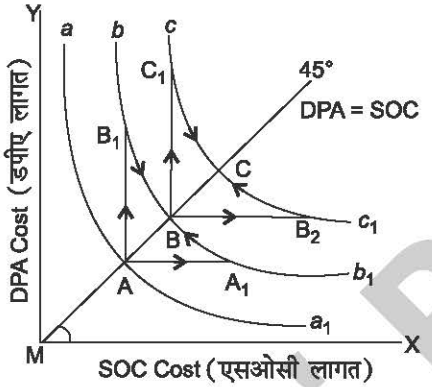

चित्र

इसके विपरीत (Adverse) यदि **'SOC की न्यूनता'** वाले विकास मार्ग को अपनाया जाए तो अर्थव्यवस्था रेखा AB_1BC_1C मार्ग से आगे बढ़ती है। जब DPA की मात्रा में B_1 तक वृद्धि की जाती है तो SOC को बिन्दु A_1 तक और फिर B बिन्दु तक जाना पड़ता है। इसी प्रकार जब DPA को आगे C_1 बिन्दु तक बढ़ाया जाता है तो सन्तुलन के लिए यह आवश्यक है कि SOC भी B_2 मार्ग से बढ़कर बिन्दु C पर आ जाए।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि निवेश (Investment) का प्रथम विकल्प अर्थात् अतिरिक्त SOC क्षमता के मार्ग से विकास का मार्ग दूसरे विकल्प की अपेक्षा अधिक निर्विघ्न, सपाट और आत्म चालित (अथवा आत्म प्रणोदी) है। **हर्शमैन** के शब्दों में, "न्यूनता के मार्ग से विकास की व्यूह रचना अव्यवस्थित एवं विवशताकारी, अनुक्रम का प्रतीक है जबकि SOC की अतिरिक्त क्षमता के मार्ग से विकास मूलत: अनुज्ञापक (permissive) है।"

हर्शमैन के अनुसार अब समस्या यह उत्पन्न होती है कि अर्थव्यवस्था में असन्तुलन का वह ढँग ढूँढ़ा जाए जो अधिकतम प्रभावशाली (Maximum Effective) भी सिद्ध हो सके। किसी भी निवेश परियोजना के अगामी अनुबन्धन प्रभाव (Forward Linkage Effects-FLE) तथा प्रतिगामी अनुबन्धन प्रभाव (Backward Linkage Effects-BLE) दोनों हो सकते हैं। FLE उत्पादन की 'आगामी अवस्थाओं' में निवेश को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि BLE निवेश की पिछली अथवा 'प्रारम्भिक अवस्थाओं' में निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। हर्शमैन का कथन है कि पहले उन उद्योगों अथवा परियोजनाओं का पता लगाया जाना चाहिए जिनका कुल अनुबन्धन प्रभाव (Total Linkage Effect-TLE) अधिकतम हो।

TLE वाली परियोजनाएँ समय-समय पर और देश-देश में बदलती रहती हैं तथा उनकी आगत-निर्गत सारणियों (Input-output Tables) के अनुभव-जन्य अध्ययन से ही उनका पता लगाया जा सकता है। हर्शमैन के अनुसार लौह तथा इस्पात उद्योग का TLE सबसे अधिक होता है यही कारण है कि अल्पविकसित देशों में प्राय: लौह एवं इस्पात उद्योग को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक देश में लौह एवं इस्पात उद्योग से ही विकास प्रारम्भ किया जाए। इसका कारण यह है कि अल्प-विकसित देशों में परस्पर-निर्भरता और अनुबन्धन का प्राय: अभाव पाया जाता है। उदाहरण के लिए, कृषि, जिसमें प्राथमिक उत्पादन भी शामिल है और खनन उद्योग में FLE तथा BLE दोनों निर्बल होते हैं। इसलिए हर्शमैन इस बात का समर्थन करता है कि 'अन्तिम उद्योग पहले' (Last Industries First) स्थापित किए जाने चाहिए, क्योंकि उनमें अधोगामी अनुबन्धन अधिक होने के कारण वे अन्य उद्योगों की स्थापना को बल प्रदान करते हैं।

हर्शमैन ने अपनी आर्थिक विकास की व्यूह रचना को निष्कर्ष रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। आर्थिक विकास विशिष्ट रूप में अनियमित वृद्धि का मार्ग अपनाता है; दबावों, प्रोत्साहनों एवं बाध्यताओं के कारण संतुलन पुन: स्थापित हो जाता है; आर्थिक विकास का मार्ग कुछ-कुछ बेढंगा, अड़चनों, कुशलताओं, सुविधाओं, सेवाओं और वस्तुओं के अभावों से बिखरा होगा; औद्योगिक विकास अधिकांशतया अधोगामी-अनुबंधन के माध्यम से होगा, अर्थात् अन्तिम रूपान्तरण से माध्यमिक तथा आधारभूत उद्योग की ओर चलेगा।

TOUCH 'n' PASS

प्र.5. केन्द्र-परिधि सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
Describe the Core-Periphery Theory.

उत्तर

केन्द्र-परिधि सिद्धान्त
(Core-Periphery Theory)

केन्द्र-परिधि सिद्धान्त (Core-Periphery Theory) की व्याख्या करने से पूर्व केन्द्र (Core) एवं परिधि (Periphery) के अर्थ को समझ लेना महत्त्वपूर्ण है, जो निम्नलिखित है—

(अ) केन्द्र/केन्द्रीय/क्रोड (Core) क्षेत्र (Central/Core Area)

वह क्षेत्र जहाँ औद्योगिक उत्पादन, खनन केन्द्र (Mining Centre), नगरीय केन्द्र, बैंकिंग, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, जहाजरानी इत्यादि प्रक्रियाओं की शुरुआत होती है और आगे चलकर वह कला, विज्ञान, साहित्य तथा उच्च संस्कृति के केन्द्र के रूप में विकसित (Developed) होता है, केन्द्रीय (Core) क्षेत्र कहलाता है। वे सभी प्रक्रियाएँ देश के कुछ निश्चित स्थानों एवं प्रदेशों में ही एकत्रित/केन्द्रीकृत (Concentrated) होती हैं।

केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र (Central Business District) किसी नगर का वाणिज्यिक हृदय स्थल कहलाता है। इस क्षेत्र में फुटकर व्यापार क्षेत्र एवं थोक व्यापार क्षेत्र का विस्तार, भूमि की उच्च कीमत, ऊँचे-ऊँचे भवन, दिन में अत्यन्त भीड़-भाड़ एवं पैदल चलने वालों की अधिक संख्या, उच्च भूमि उपयोग गहनता, उन्नत श्रेणी के क्रिया-कलाप तथा न्यून आवासीय क्षेत्र पाये जाते हैं। **ई. डब्ल्यू बर्गेस** (E. W. Burgess) ने केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र (CBD) को केन्द्रीय (Core) भाग के रूप में माना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हृदय स्थल (Heart Land) की संकल्पना को **एलेन प्रेड** (Allan Pred) ने केन्द्रीय (Core) भाग के रूप में देखा है। यहाँ का हृदय स्थल कृषि संसाधन एवं खनिज आर्थिक तंत्र के कारण उत्पन्न हुआ बताया जाता है। औद्योगीकरण के कारण जो विकास उत्पन्न होता है उसका प्रभाव सभी क्षेत्रों पर बराबर नहीं पड़ता बल्कि वह कुछ क्षेत्रों पर ही केन्द्रीकृत (Concentrated) हो जाता है जबकि अन्य क्षेत्र इससे वंचित रह जाते हैं। औद्योगीकरण (Industrialisation) शुरू होने के साथ जैसे ही केन्द्रीकरण होने लगता है, वह अन्य सहायक क्रियाओं को तीव्र गति से आकर्षित करता है फलत: केन्द्रीकरण की गति और तीव्र हो जाती है। ऐसे केन्द्रीकृत क्षेत्र को ही केन्द्रीय (Core) भाग कहा जाता है। इस केन्द्रीय भाग के बाहर क्रियाओं का एकत्रीकरण नहीं हो पाता है। एडवर्ड एल. उलमैन (E. L. Ullman) ने विकास से सृजित केन्द्रीय भाग की पहचान संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में किया है। पहला केन्द्रीय क्षेत्र पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका के 7.7% क्षेत्र, 43% जनसंख्या, 52% आय तथा 70% वस्तु निर्माण में लगे लोगों को समाहित करता है। इस केन्द्रीय भाग को औद्योगिक पेटी (Industrial Belt) का नाम दिया गया।

डॉ. महेन्द्र बहादुर सिंह ने वस्तु निर्माण में लगे लोगों (Manufacturing Employment) के आधार पर उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख केन्द्रीय भाग (Major Cores) तथा 7 गौण केन्द्रीय भाग (Minor Cores) को दर्शाया है। कानपुर, आगरा तथा मेरठ प्रमुख केन्द्रीय भाग के रूप में उभरे हैं।

ब्रसी महोदव (Bracey, H.E.) ने चुनी गई 15 सेवाओं के आधार पर नगर को तीन भागों में बाँटा है। जहाँ सेवाओं का स्कोर (Score) अधिकतम 15 होगा वह गहन क्षेत्र (Intensive Area) या केन्द्रीय (Core) भाग कहलायेगा। मध्यम स्कोर वाले क्षेत्र को विस्तृत क्षेत्र (Extensive Area) तथा निम्न स्कोर वाले क्षेत्र को उपान्त (Periphery) कहा जाता है।

वर्तमान समय में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ (multi-nationals) केन्द्रीय भाग में मुख्य प्लांट तथा परिधि क्षेत्र में सहायक उत्पादन प्लाटों को स्थापित करती हैं। संचार के साधनों के माध्यम से केन्द्रीय भाग एवं परिधि क्षेत्र में स्थानीकरण सम्बन्ध पाया जाता है। नियन्त्रण केन्द्रीय भाग में निहित रहता है। परिधि क्षेत्र कम्पनी की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता तथा बिक्री का अवसर बढ़ाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्रोड-परिधि क्षेत्र व्याप्त है। प्रौद्योगिकी विसरण (Technology Diffusion) की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल, जापान, पश्चिमी यूरोपीय देश (फ्रान्स, जर्मनी एवं ग्रेट ब्रिटेन) एवं रूस केन्द्रीय भाग के रूप में देखे जा सकते हैं, क्योंकि शेष देश इन्हीं से प्रौद्योगिकी ग्रहण करते हैं तथा वे परिधि क्षेत्र के रूप में लिये जा सकते हैं।

(ब) परिधि/ उपान्त/उपनगर/घेरा/केन्द्र के चतुर्दिक बाहरी हिस्सा (Periphery)

किसी केन्द्र के चतुर्दिक वह हिस्सा जो विकास से वंचित रहता है, परिधि क्षेत्र कहलाता है। केन्द्रीय भाग के चारों तरफ बाह्य क्षेत्र में आवासीय विरलता मिलती है। इसमें व्यापार एवं हल्के वस्तु निर्माण उद्योग आवासीय क्षेत्र से मिले रहते हैं। यह संक्रमण की पेटी कहलाती है। इस पेटी के बाद कार्यशील लोगों के गृहों की पेटी, बेहतर निवासों की पेटी एवं अभिगमनकर्त्ताओं (Commuters) की पेटी होती है जिसको उपान्त के रूप में लिया जा सकता है। उपान्त शब्द का प्रयोग नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य स्थित

TOUCH 'n PASS

संक्रमण क्षेत्र के लिए किया जाता है। संक्रमण पेटी और उपान्त क्षेत्र दोनों ही परिधि क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। पृष्ठ प्रदेश (Hinter Land) की संकल्पना को प्रेड (1996) ने परिधि क्षेत्र के रूप में देखा है। केन्द्रीय (Core) भाग के अतिरिक्त शेष समीपवर्ती क्षेत्र उसके परिधि क्षेत्र (Periphery) के रूप में विकसित हो जाता है।

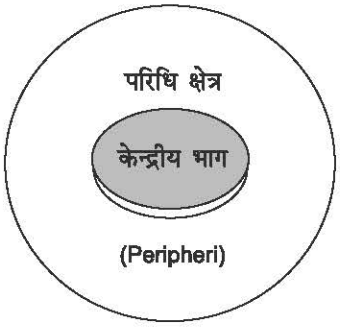

चित्र : केन्द्रीय भाग और परिधि क्षेत्र

केन्द्रीय भाग की अपेक्षा परिधि क्षेत्र तथा उपान्तों (Fringe) में विकास की सम्भावनाएँ बहुत कम होती हैं, क्योंकि ये केन्द्रीय भाग एवं उनके प्रभाव से काफी दूर स्थित होते हैं। इन क्षेत्रों में औद्योगिक पेटी की अनुपस्थिति में यदि कोई विशिष्ट आकर्षण (खनिज उपलब्धता के कारण, इमारती लकड़ी के कारण, पर्यटन स्थलों के कारण, इत्यादि) मौजूद हों तो इनका विकास सम्भव हो सकता है। केन्द्रीय-परिधि क्षेत्र सिद्धान्त यह बताता है कि अनेक आर्थिक एवं गैर आर्थिक बल निचले संक्रमण क्षेत्रों की अपेक्षा (Downward Transitional Areas) केन्द्रीय भाग (Core) तथा ऊपरी संक्रमण क्षेत्र (Upward Transitional Areas) को सहायता पहुँचाते हैं। ऊपरी संक्रमण क्षेत्र केन्द्रीय भाग (Core) के नजदीक होता है एवं संसाधन के प्रयोग को गहन बनाने में सक्षम होता है। इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि जनसंख्या का सर्वाधिक स्थानान्तरण (Transfer) इसी में पाया जाता है। केन्द्रीय भाग में बढ़ती माँग (Rising Demand) के प्रत्युत्तर में ही इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की सम्भावना बनती है। निचले संक्रमण क्षेत्र पुराने एवं लम्बे समय तक निवासित क्षेत्र होते हैं जहाँ का आर्थिक तन्त्र लगभग ग्रामीण एवं स्थिर होता है। इस कारण इस क्षेत्र से जनसंख्या का स्थानान्तरण दूसरे क्षेत्रों में होता है।

किसी देश में आर्थिक वृद्धि के कुछेक नगरों या क्षेत्रों (Core) में ही केन्द्रीकृत हो जाने एवं अवशेष विशाल भू-भाग के अविकसित उपान्त (Periphery) रह जाने की समस्या का निराकरण करने हेतु 1960 में कई सारे सिद्धान्त विकसित हुए उसमें 'फ्रीडमैन का केन्द्रीय भाग एवं परिधि क्षेत्र' सिद्धान्त/मॉडल एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है।

फ्रीडमैन का केन्द्र-परिधि मॉडल
(Friedman's Core-Periphery Model)

प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री **जॉन एन. फ्रीडमैन** (John N. Friedman) ने 1966 ई. ने अपनी पुस्तक '*Regional Development Policy : A Case Study of Venezuela*' में प्रादेशिक/क्षेत्रीय विकास (*Regional Development*) की व्याख्या हेतु अपना केन्द्र-परिधि मॉडल प्रस्तुत किया। फ्रीडमैन के अनुसार किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ के विकसित केन्द्र (Core) और अविकसित परिधि (Periphery) के परस्पर सम्बन्धों (Mutual Relations) पर निर्भर करता है। फ्रीडमैन के अनुसार, कुछ क्षेत्र कुछ अनुकूल कारणों से तेजी से विकसित हुए और विकास के केन्द्र (Core) बन गये, इन केन्द्रों की परिधि (Periphery) अविकसित क्षेत्र रह गयी। प्रादेशिक विकास हेतु जितना महत्त्व आर्थिक आधार का है उतना ही महत्त्व विभिन्न क्रियाओं के अन्तर्सम्बन्धों (Linkage) का है। फ्रीडमैन जिन अन्तर्सम्बन्धों की बात करते हैं वे प्रादेशिक ध्रुवीकरण (Regional Polarisation) अन्तर्क्रिया (Interaction) और आधुनिकीरण (Modernisation) के मध्य सम्पादित होता है। फ्रीडमैन के अनुसार, किसी भी क्षेत्र में एक खण्ड केन्द्रीय भाग (Core) का और दूसरा खण्ड परिधि क्षेत्र (Periphery) का होता है।

जॉन फ्रीडमैन के अनुसार, केन्द्रीय भाग आर्थिक वृद्धि की उच्च सम्भाव्यता (High potential) से युक्त क्षेत्र होते हैं। एक या अधिक नगरों का समूह (Cluster) अपने चतुर्दिक क्षेत्रों के साथ केन्द्रीय भाग का सृजन करता है। केन्द्रीय भाग (नगरीय औद्योगिक केन्द्र) अपने लाभ हेतु परिधि क्षेत्र का हर समय दोहन करता रहता है। समय के साथ-साथ परिधि निर्धन होती जाती है और इसमें सेवाओं एवं जन सुविधाओं की भी कमी आती जाती है। पदार्थों का परिधि से केन्द्र की ओर आना प्रारम्भ हो जाता है

TOUCH 'n PASS

जिससे परिधि के आर्थिक विकास को और अधिक धक्का लगता है और वहाँ के लाग भी वहाँ निवेश करने से कतराने लगते हैं। इसमें विकासीय स्तर में असमानता (Disparity) की खाई और भी गहरी होती चली जाती है।

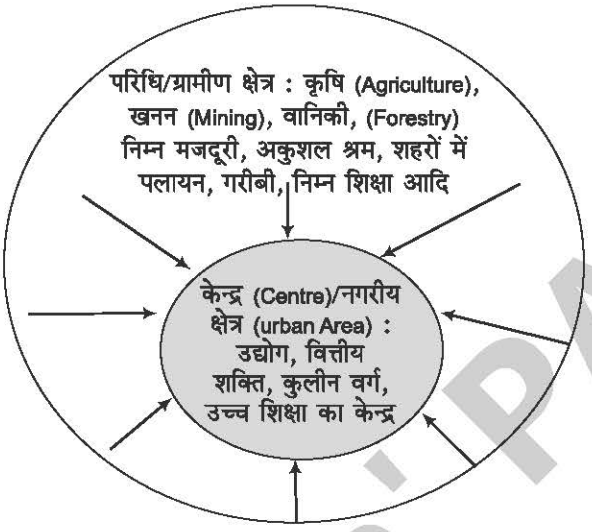

चित्र

केन्द्रीय भाग अपने परिधि क्षेत्र पर निर्णायक प्रभाव डालता है और केन्द्रीय भाग अपने प्रभुत्व (Dominance) को निम्न प्रभाव द्वारा मजबूत करता है।

1. परिधि क्षेत्र से प्राकृतिक, मानवीय एवं पूँजी संसाधन के केन्द्रीय भाग की तरफ शुद्ध स्थानान्तरण के कारण परिधि क्षेत्र कमजोर होते जाते हैं। अतएव केन्द्रीय भाग का प्रभुत्व प्रभाव (Dominance Effect) बना रहता है।
2. सम्भाव्य सम्पर्क एवं अन्तर्क्रिया (Potential Contact and Interactions) केन्द्रीय भाग में तीव्र होती है जिससे केन्द्रीय भाग का **सूचना प्रभाव** (Information Effect) परिधि क्षेत्र पर बना रहता है।
3. नवाचारों की सफलता के कारण केन्द्रीय भाग का परिधि क्षेत्र पर **मानसिक प्रभाव** (Psychological Effect) भी पड़ता है।
4. अन्वेषणों को सफल बनाने की प्रक्रिया के कारण केन्द्रीय भाग में सामाजिक मूल्यों (Social Values) और व्यवहार में परिवर्तन पाया जाता है। फलस्वरूप केन्द्रीय भाग का **आधुनिकीकरण प्रभाव** (Modernisation Effect) परिधि क्षेत्र पर मिलता है।
5. एक अन्वेषण कई अन्वेषणों को जन्म देता है। अतएव केन्द्रीय भाग का **अन्तर्सम्बन्ध प्रभाव** (Linkage effect) परिधि क्षेत्र पर दृष्टिगोचर होता है।
6. अन्वेषण से जुड़े विशिष्टीकरण (Specialisation) एवं निरन्तर बढ़ते आर्थिक तन्त्र मापक (Growing Economics of Scale) की प्रक्रिया के कारण परिधि क्षेत्र पर **उत्पादन प्रभाव** (Production Effect) भी पाया जाता है।

फ्रीडमैन का मानना था कि आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति, प्रौद्योगिकीय प्रगति और उच्च उत्पादकता का उच्च संकेन्द्रण, केन्द्र (Core) पर पाया जाता है जो एक नगरीय केन्द्र (Urban Centre) के रूप में स्थित होता है जबकि परिधि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के रूप में पायी जाती है। इस प्रकार केन्द्र (Core) नगरीय क्षेत्र का और परिधि उसके चतुर्दिक स्थित ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। केन्द्र पर उद्योगों, सरकार, कुलीन वर्ग, वित्तीय शक्ति और विकसित शैक्षिक पद्धति आदि का संकेन्द्रण (Concentration) पाया जाता है। इसके विपरीत परिधि क्षेत्र में ग्रामीण भूदृश्य, कृषि, खनन, वनोद्योग आदि प्राथमिक क्रियाएँ, क्षीण आर्थिक शक्ति, अकुशल श्रम, निम्न मजदूरी आदि सम्मिलित होती हैं। यही कारण है कि जनसंख्या का प्रवास प्राय: परिधि से केन्द्र की ओर होता है। इस प्रकार केन्द्र प्रभुत्वशाली होता है जबकि परिधि उस पर निर्भर होती है। यह निर्भरता केन्द्र और परिधि के बीच विनिमय सम्बन्धों के द्वारा निर्मित होती है।

TOUCH 'n' PASS

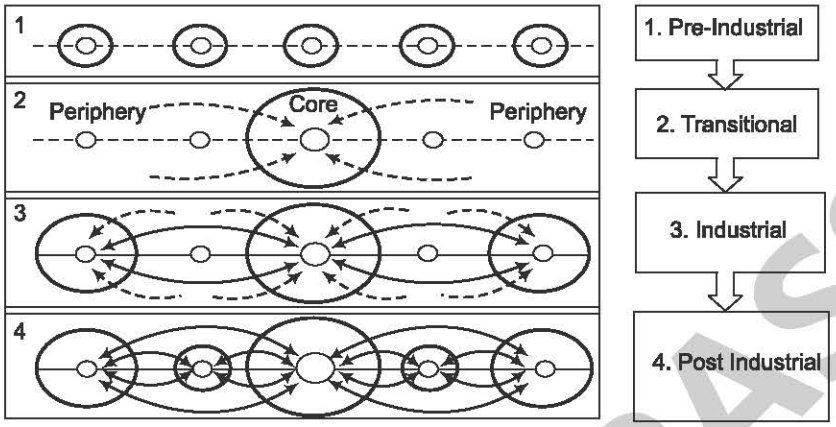

फ्रीडमैन के अनुसार परिधि से केन्द्र की ओर जनसंख्या का प्रवास

फ्रीडमैन ने 1966 में अपनी पुस्तक *'Regional Development Policy : A Case Study of Venezuela'* में प्रादेशिक विकास नीति का विश्लेषण करते हुए एक नगर तन्त्र में विकास की केन्द्र-परिधि अवस्थाओं/चरणों की व्याख्या की है। परम्परागत केन्द्र-परिधि विकास मॉडल के द्वारा प्रादेशिक नगर तन्त्र को चार प्रमुख अवस्थाओं में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। ये अवस्थाएँ प्राय: प्रादेशिक परिवहन तन्त्र की अनुगामी होती हैं जिनका विकास परिवहन तन्त्र के विकास के साथ-साथ होता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. *'Problems of Regional Economic Planning'* नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
(क) फ्रेंकोइस पेरॉक्स (ख) जे०आर० बाउडेविल
(ग) गुन्नार मिर्डल (घ) ए०ओ० हर्शमैन
उत्तर (ख) जे०आर० बाउडेविल

प्र.2. फ्रेंकोइस पेराक्स ने विकास ध्रुव संकल्पना का प्रतिपादन किसके सिद्धान्त को आधार मानकर किया था?
(क) शुम्पिटर (ख) गुन्नार मिर्डल (ग) हर्शमैन (घ) बटलर
उत्तर (क) शुम्पिटर

प्र.3. फ्रेंकोइस पेराक्स ने विकास ध्रुव संकल्पना का प्रतिपादन कब किया था?
(क) 1920 ई० (ख) 1930 ई० (ग) 1940 ई० (घ) 1950 ई०
उत्तर (घ) 1950 ई०

प्र.4. *'Growth Pole Theory and Economic Development'* नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
(क) हर्शमैन (ख) पेराक्स (ग) बाउडेविल (घ) बटलर
उत्तर (घ) बटलर

प्र.5. 'रिसाव सिद्धान्त' (*Trickle Down Theory*) का प्रतिपादन किसने किया है?
(क) गुन्नार मिर्डल (ख) जे० फ्रीडमैन
(ग) आर०पी० मिश्रा (घ) ए०ओ० हर्शमैन
उत्तर (घ) ए०ओ० हर्शमैन

प्र.6. चक्रीय कार्यकरण सिद्धान्त के प्रतिपादक थे–
(क) गुन्नार मिर्डल (ख) रैगनर नर्क्स
(ग) हर्शमैन (घ) आर्थर लुईस
उत्तर (क) गुन्नार मिर्डल

TOUCH n PASS

प्र.7. प्रो० मिर्डल के अनुसार, ''चक्रीय कार्यकरण प्रक्रिया'' होती है–
(क) आर्थिक विकास का परिणाम (ख) गैर–आर्थिक विकास का परिणाम
(ग) आर्थिक तथा गैर–आर्थिक विकास का परिणाम (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ग) आर्थिक तथा गैर–आर्थिक विकास का परिणाम

प्र.8. जब अर्थव्यवस्था के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निवेश किया जाता है तो उसे कहा जाता है–
(क) संतुलित विकास (ख) असंतुलित विकास (ग) संरचनात्मक विकास (घ) आधारभूत विकास
उत्तर (क) संतुलित विकास

प्र.9. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
(क) अल्पविकसित देशों में व्यापक निर्धनता विकास के ऋणात्मक घटकों को जन्म देता है।
(ख) विकसित देशों में सम्पन्नता का चक्र ऊर्ध्वमुखी होता है।
(ग) (क) तथा (ख) दोनों
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर (ग) (क) तथा (ख) दोनों

प्र.10. प्रो० रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था है–
(क) परम्परागत समाज (ख) बर्बर समाज
(ग) सभ्य समाज (घ) आधुनिक समाज
उत्तर (क) परम्परागत समाज

प्र.11. आत्म स्फूर्ति की धारणा का प्रतिपादन किसने किया?
(क) रोस्टोव (ख) मिर्डल (ग) मार्क्स (घ) ऐलिस
उत्तर (क) रोस्टोव

प्र.12. आत्म-स्फूर्ति की अवस्था के सन्दर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सही है?
(क) बचत तथा विनियोग की मात्रा बढ़ने लगती है। (ख) नए उद्योगों का विकास होता है।
(ग) उत्पादन की नई तकनीक का विकास होता है। (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.13. ''यह स्पष्ट है कि आत्म स्फूर्ति अवस्था के लिए समाज में एक ऐसे वर्ग का अस्तित्व और सफल कार्य आवश्यक है, जो जोखिम लेने को तैयार हो।'' यह कथन किसका है?
(क) रोस्टोव का (ख) कुजनेट्स का (ग) शुम्पीटर का (घ) लुईस का
उत्तर (क) रोस्टोव का

प्र.14. रोस्टोव की पुस्तक *'The stages of Economic Growth'* सन् 1960 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में विकास की कितनी अवस्थाएँ बताई गयी हैं?
(क) चार (ख) पाँच (ग) छः (घ) सात
उत्तर (ख) पाँच

प्र.15. रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास की अन्तिम अवस्था है–
(क) आत्म-स्फूर्ति की अवस्था (ख) परिपक्वता की ओर
(ग) अत्यधिक उपभोग की अवस्था (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ग) अत्यधिक उपभोग की अवस्था

प्र.16. जब अर्थव्यवस्था के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निवेश किया जाता है तो उसे कहा जाता है–
(क) असन्तुलित विकास (ख) सन्तुलित विकास
(ग) संरचनात्मक विकास (घ) धारणीय विकास
उत्तर (क) असन्तुलित विकास

TOUCH 'n' PASS

प्र.17. निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री सन्तुलित विकास का समर्थक नहीं था?
(क) नर्क्से (ख) रोडान (ग) हर्शमैन (घ) आर्थर लुईस
उत्तर (ग) हर्शमैन

प्र.18. 'असन्तुलित विकास' की विचारधारा के प्रतिपादक थे–
(क) हर्शमैन (ख) सैम्युलसन (ग) हैंडरसन (घ) रॉबिन्सन
उत्तर (क) हर्शमैन

प्र.19. हर्शमैन के अनुसार असन्तुलित विकास में ऐसे क्षेत्रों को छाँटना चाहिए, जिनमें निवेश से अधिकतम निम्न घटक प्राप्त हो सकें–
(क) सहलग्नता (ख) लाभ (ग) उत्पादन (घ) राष्ट्रीय आय
उत्तर (क) सहलग्नता

प्र.20. सन्तुलित विकास प्रक्रिया की आलोचना में हर्शमैन का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्री थे–
(क) पॉल स्ट्रीटन (ख) फ्लेमिंग (ग) सिंगर (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.21. प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन एन० फ्रीडमैन किस देश के निवासी थे?
(क) संयुक्त राज्य अमेरिका (ख) सोवियत रूस
(ग) ब्रिटेन (घ) जर्मनी
उत्तर (क) संयुक्त राज्य अमेरिका

प्र.22. एडवर्ड एल० उलमैन ने विकास से सृजित केन्द्रीय भाग की पहचान किन देशों में की?
(क) सोवियत रूस (ख) ब्रिटेन एवं जर्मनी
(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा (घ) चीन
उत्तर (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा

प्र.23. डॉ० महेन्द्र बहादुर सिंह ने वस्तु निर्माण में लगे लोगों के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने मुख्य एवं गौण भागों में विभाजित किया है?
(क) 3 प्रमुख केन्द्रीय भाग तथा 7 गौण केन्द्रीय भाग
(ख) 4 प्रमुख केन्द्रीय भाग तथा 7 गौण केन्द्रीय भाग
(ग) 5 प्रमुख केन्द्रीय भाग तथा 7 गौण केन्द्रीय भाग
(घ) 3 प्रमुख केन्द्रीय भाग तथा 9 गौण केन्द्रीय भाग
उत्तर (क) 3 प्रमुख केन्द्रीय भाग तथा 7 गौण केन्द्रीय भाग

प्र.24. ब्रेसी (Bracey, H.E.) महोदय ने कितनी चुनी गयी सेवाओं के आधार पर नगरों का विभाजन किया?
(क) 5 सेवाओं (ख) 10 सेवाओं (ग) 15 सेवाओं (घ) 20 सेवाओं
उत्तर (ग) 15 सेवाओं

प्र.25. फ्रीडमैन ने एक नगर तंत्र में विकास की कितनी अवस्थाओं/चरणों का वर्णन किया है?
(क) तीन चरण (ख) चार चरण
(ग) पाँच चरण (घ) छः चरण
उत्तर (ख) चार चरण

❑

TOUCH 'n PASS

UNIT-V

सतत् आर्थिक विकास
Sustainable Development

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है?
What is meant by economic development?

उत्तर विकास एक जटिल, व्यापक सापेक्ष संकल्पना है जिसकी सर्वस्वीकृत परिभाषा देना सहज (Easy) नहीं है। अर्थशास्त्रियों ने समय-समय पर भिन्न-भिन्न आधारों को दृष्टिगत रखते हुए विकास को समझाने एवं परिभाषित करने का प्रयास किया है। विकास की प्रक्रिया (Process) को आर्थिक एवं गैर-आर्थिक तत्त्व महत्त्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। विकास जिसे प्राय: आर्थिक विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसकी परिभाषा ऐसे दी जा सकती है—'आर्थिक विकास वह सतत प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है, आर्थिक विषमता में कमी आती है, जन सामान्य के जीवन स्तर एवं कल्याण में बढ़ोतरी होती है।'

प्र.2. विकसित अर्थव्यवस्थाओं को परिभाषित कीजिए।
Define developed economies.

उत्तर ऐसी अर्थव्यवस्थाएँ जो आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं एवं विकास के उच्चतर स्तर को प्राप्त किए रहती हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाएँ (Economies) कहलाती हैं। स्थाई आर्थिक वृद्धि एवं सुरक्षा (Sustained Economic Growth and Security) वाली अर्थव्यवस्थाएँ विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती हैं।

आशय यह है, उन्नत तकनीकी अवसंरचना वाली अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था बन जाती है। इन देशों में आर्थिक विकास के सभी अभिसूचक-ऊँचा सकल घरेलू उत्पाद, ऊँची प्रति व्यक्ति आय, ऊँचा औद्योगीकरण, सबल अवसंरचना एवं उन्नत रहन-सहन स्तर आवश्यक रूप से विद्यमान रहते हैं।

अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रांस, जापान, आस्ट्रेलिया विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण वाले देश हैं।

प्र.3. विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ लिखिए।
Write the characteristics of developed economy.

उत्तर 1. औद्योगिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में प्रभुत्व (Dominancy)।
2. सबल सेवा क्षेत्र।
3. बड़े आकार का उत्पादन-उत्पादन क्षेत्र में पूर्ण उत्पादकता विदोहन।
4. श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उत्पादन क्रिया का अभिन्न (Part and Parcel) अंग।
5. पूँजी की प्रधानता।
6. लाभ-अर्जन उद्देश्य प्रमख।
7. ऊँचा मानव विकास सूचकांक जिसमें देश का ऊँचा शिक्षा, साक्षरता एवं स्वास्थ्य का स्तर सुनिश्चित (Ensure) होता है।

प्र.4. सतत आर्थिक विकास का अर्थ क्या है?
What is meant by sustainable development.

उत्तर सतत आर्थिक विकास, एक राष्ट्रीय पहल है जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं की विशिष्ट परिसंपत्तियों पर बनाई गई है ताकि उनकी व्यक्तिगत चुनौतियों (Challenges) का सामना किया जा सके और उन्हें वास्तविक रूप से वास्तविक लाभ प्रदान किया जा सके।

TOUCH 'n PASS

प्र.5. सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is chief objective of sustainable development?

उत्तर सतत् विकास लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य विश्व से गरीबी को पूर्णत: समाप्त करना तथा सभी समाजों में सामाजिक न्याय एवं पूर्ण समानता स्थापित करना है। भारत को भी गंभीरता से इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करना चाहिये।

प्र.6. सतत् विकास क्या है?
What is the sustainable development?

उत्तर 'पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग' (1983) के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट (1987) के अनुसार—'आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत् विकास है।'

प्र.7. SDGs क्या है?
What is SDGs?

उत्तर MDGs (Millennium Development Goals) की अवधि 2015 में खत्म हो गई। पर्यावरण सुरक्षा के साथ मानव विकास हेतु।

प्र.8. MDGs के क्या उद्देश्य हैं?
What are the objectives of MPGs?

उत्तर MDGs के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

1. ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में फ्रेम को स्वीकार किया गया था।
2. लेकिन लक्ष्यों की 1990 के स्तर पर गणना (Enumeration) की गई।
3. ये 2015 तक के लिये थे।
4. इसके अंतर्गत 8 गोल तथा 18 टारगेट्स रखे गए थे।

प्र.9. UNDP की भूमिका लिखिए।
Write the role of UNDP.

उत्तर 1. SDG1 जनवरी, 2016 से प्रभाव में आ गए तथा यूएनडीपी की निगरानी और संरक्षण में ये अगले 15 सालों तक प्रभावी रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख SDG, लक्ष्य प्राप्ति कार्य करने वाली संस्था यूएनडीपी विश्व के 170 देशों में इन लक्ष्यों की प्राप्ति पर नजर रखेगी।

2. यूएनडीपी का प्रमुख लक्ष्य इन देशों में गरीबी को खत्म करना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन, पर्यावरण परिवर्तन और आपदा परिवर्तन पर कार्य तथा आर्थिक समानता प्राप्ति आदि पर ज्यादातर केंद्रित रहेगा।
3. SDGs, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सभी लोगों को आपसी सहयोग से काम करना होगा।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. अल्पविकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषाएँ लिखिए।
Write the meaning and definitions of under developed or developing economies.

उत्तर

अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ
(Under Developed or Developing Economies)

विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, विश्व में ऐसे भी देश हैं जहाँ नागरिकों को भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता है। पहनने के कपड़े सीमित मात्रा में ही मिल पाते हैं। उनका जीवन-स्तर बहुत नीचा है। वहाँ बेरोजगारी व अशिक्षा भारी मात्रा में पायी जाती है। ऐसे देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, आदि आते हैं। यह सभी देश अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहे जाते हैं।

वे अर्थव्यवस्थाएँ जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं विकसित अर्थव्यवस्थाएँ (Developed Economies) कही जाती हैं। इन्हें उत्तर (The North) के नाम से भी जाना जाता है। इसके विपरीत, वे अर्थव्यवस्थाएँ जो आर्थिक दृष्टि से निर्धन हैं अल्प-विकसित

TOUCH 'n' PASS

(Under-developed) कही जाती हैं उन्हें निर्धन (Poor), पिछड़ी हुई (Backward), विकासशील (Developing) या कम विकसित (Less-developed) के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हीं को तीसरा संसार (Third World) या दक्षिण (The South) भी कहा जाता है।

अल्प-विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था से आशय
(Meaning of Under Developed or Developing Economies)

अल्प-विकसित राष्ट्रों या अर्थव्यवस्थाओं की परिभाषाओं को तीन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता—(I) अल्प-विकसितता के कारणों पर आधारित परिभाषाएँ, (II) निर्धनता के आधार पर परिभाषाएँ, (III) विकास के आधार पर परिभाषाएँ।

(I) अल्प-विकसितता के कारणों पर आधारित परिभाषाएँ
(Definitions based on the Causes of Under Development)

1. **प्रो. केयर्नक्रॉस** के मत में, 'अल्प-विकसित देश विश्व की अर्थव्यवस्था की गन्दी बस्तियाँ हैं।' इससे अभिप्राय यह है कि अल्प-विकसित देशों में आय एवं रहन-सहन का स्तर निम्न होता है।
2. **प्रो. रेगनर नर्क्स** के शब्दों में, 'अल्प-विकसित देश वे हैं जहाँ जनसंख्या तथा प्राकृतिक साधनों को देखते हुए विकसित देशों की तुलना में पूँजी का अभाव है।'
3. **भारतीय योजना आयोग** की दृष्टि में, 'एक अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था वह है जिसमें मानवीय शक्ति का अल्प उपयोग या अनुपयोग एक ओर व प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग न होने की स्थिति दूसरी ओर साथ-साथ पायी जाती हैं।'

(II) निर्धनता के आधार पर परिभाषाएँ
(Definitions on the basis of Porerty)

1. **प्रो. ब्रिन्सटिन** के अनुसार, 'एक अल्प-विकसित देश वह है जिसमें प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है तथा जिसमें उत्पादन कुशलता बहुत धीरे-धीरे बढ़ रही है।'
2. **प्रो. सैम्युलसन** के मत में, 'एक अल्प-विकसित देश वह है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन व सामान्यतया पश्चिमी यूरोप के देशों की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है।'
3. संयुक्त राष्ट्र की समिति के अनुसार, 'अल्प-विकसित देश वे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया व पश्चिमी यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में कम है।'

(III) विकास के आधार पर परिभाषाएँ
(Definitions ohn the basis of Development)

प्रोफेसर जैकब वाइनर (Jacob Viner) के अनुसार, 'अल्प-विकसित देश वह है जिसमें अधिक पूँजी अथवा अधिक श्रम अथवा अधिक प्राकृतिक साधनों अथवा इन सभी के प्रयोग से वर्तमान जनसंख्या के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने की काफी सम्भावनाएँ हैं।'

उपरोक्त सभी परिभाषाओं में अल्प-विकसित देश या अर्थव्यवस्था की एक-एक विशेषता की बात कही गयी है। अर्द्ध-विकसित शब्द का प्रयोग सापेक्षिक रूप में होता है। अत: अल्प-विकसित व्यवस्था को कई मापों से मापा जा सकता है; जैसे (1) प्रति व्यक्ति आय, (2) प्रति व्यक्ति बचत व पूँजी, (3) औद्योगिक विकास की दर, (4) प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता, (5) जनसंख्या का घनत्व, (6) प्रत्याशित आयु, (7) विकास दर, (8) निर्यात अनुपात।

प्र.2. विकसित एवं अल्प-विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अन्तर बताइए।
Give the difference between developed and under-developed economies.

उत्तर

विकसित एवं अल्प-विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अन्तर
(Difference between Developed and Under-Developed Economies)

अन्तर का आधार	विकसित अर्थव्यवस्था	अल्प-विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था
कृषि प्रधानता	इसमें कृषि की प्रधानता नहीं होती है।	इसमें कृषि की प्रधानता होती है।
प्राकृतिक साधन	प्राकृतिक साधनों का भरपूर उपयोग होता है।	इसमें प्राकृतिक साधनों का अल्प उपयोग होता है।

TOUCH n PASS

प्रति व्यक्ति आय	इसमें प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है।	इसमें प्रति व्यक्ति आय कम होती है।
पूँजी-निर्माण	इसमें पूँजी-निर्माण की दर ऊँची होती है।	इसमें पूँजी-निर्माण की दर निम्न होती है।
सम्पत्ति व आय का वितरण	इसमें सम्पत्ति व आय का वितरण समान-सा होता है।	इसमें सम्पत्ति व आय का वितरण असमान होता है।
उद्योग	इसमें उद्योगों की प्रधानता होती है।	इसमें उद्योगों का अभाव होता है।
बेरोजगारी	इसमें बेरोजगारी नहीं या कम होती है।	इसमें बेरोजगारी अधिक होती है।
बैंकिंग सुविधाएँ	इसमें बैंकिंग सुविधाएँ पर्याप्त होती हैं।	इसमें बैंकिंग सुविधाओं का अभाव होता है।
जन्म एवं मृत्यु-दरें	इसमें जन्म-दर व मृत्यु-दर नीची होती हैं।	इसमें इनकी दरें ऊँची होती हैं।
ग्रामीण जनसंख्या	इसमें ग्रामीण जनसंख्या कम होती है।	इसमें ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है।
जनसंख्या घनत्व	इसमें जनसंख्या का घनत्व कम होता है।	इसमें जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है।
प्रत्याशित आयु	इसमें प्रत्याशित आयु अधिक होती है।	इसमें प्रत्याशित आयु कम होती है।
उत्पादन विधि	इसमें उत्पादन विधि नवीनतम होती है।	इसमें उत्पादन विधि पुरानी होती है।
तकनीकी शिक्षा	इसमें तकनीकी शिक्षा उच्च शिखर पर होती है।	इसमें तकनीकी शिक्षा का अभाव पाया जाता है।
संचार सुविधाएँ	इसमें संचार सुविधाएँ उन्नत दशा में होती हैं।	इसमें संचार सुविधाएँ पिछड़ी दशा में होती हैं।
साक्षरता	इसमें साक्षरता शत-प्रतिशत होती है।	इसमें साक्षरता कम पायी जाती है।
जातिवाद	इसमें जातिवाद नहीं होता है।	इसमें जातिवाद चरम सीमा पर होता है।
अधिकारों का ज्ञान	इसमें अधिकारों के प्रति ज्ञान काफी होता है।	इसमें यह ज्ञान कम होता है।
सुरक्षा	इन देशों के पास सुरक्षा के आधुनिकतम साधन होते हैं।	इसमें पर यह साधन कम मात्रा में होते हैं।
प्रशासनिक कुशलता	इसमें अधिक होती है।	इसमें कम मात्रा में होती है।
वित्तीय संगठन	सुदृढ़ वित्तीय संगठन होता है।	दोषपूर्ण वित्तीय संगठन होता है।

प्र.3. अल्पविकसित देशों की अन्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
Explain the other characteristics of under developed countries.

उत्तर

अन्य विशेषताएँ
(Other Characteristics)

1. **दोषपूर्ण वित्तीय संगठन**—अल्प-विकसित देशों में वित्तीय संगठन दोषपूर्ण होता है। इन देशों में परोक्ष कर (Indirect taxes) अधिक लगाये जाते हैं। मुद्रा बाजार असंगठित होता है। बैंकिंग व्यवस्था प्रभावशाली नहीं होती है। सरकारी आय के साधन भी सीमित होते हैं।
2. **स्थिर व्यावसायिक ढाँचा**—इन देशों में व्यावसायिक ढाँचा स्थिर (Stagment) रहता है। इसका अर्थ यह है कि इन देशों में व्यावसायिक ढाँचा एक जैसा रहता है, उसमें बदलाव नहीं होते हैं।
3. **जीवन की गुणवत्ता**—विकासशील देशों में जीवन की गुणवत्ता एवं रहन-सहन का स्तर अत्यधिक निम्न रहता है। इन देशों में लोगों को स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ वायु एवं स्वच्छ वातावरण के साथ-साथ कैलोरी युक्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं सामाजिक सुरक्षा भी समुचित रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती है।
4. **मानव विकास सूचकांक**—संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित एवं विकासशील देशों के सन्दर्भ में जो मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) तैयार किए गए हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि विकासशील देशों में मानव विकास सूचकांक का स्तर बहुत निम्न है, जबकि विकसित देशों के सन्दर्भ में यह सूचकांक उच्च स्तरीय है।

प्र.4. सतत विकास के क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए।
Explain the scope of sustainable development.

उत्तर

सतत विकास का क्षेत्र
(Scope of Sustainable Development)

सतत विकास महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह राष्ट्रीय बजट को बचाता है, लोगों की आवश्यकता को पूरा करता है, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के बीच समन्वय (Cordination) में सहायता करता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का

संरक्षण करता है। सतत विकास का लक्ष्य कल की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना आज की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसका अर्थ है कि हम संसाधनों के वर्तमान स्तर का उपयोग जारी नहीं रख सकते, क्योंकि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

कार्बन उत्सर्जन को स्थिर करना और कम करना पर्यावरणीय सीमाओं (Environmental Limits) के भीतर रहने की कुंजी है। सतत विकास की श्रेणियों का विश्वास है कि सही आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सीमाओं के भीतर काम करने से वास्तव में सतत स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण होगा, जो भविष्य के लिए उपयुक्त है। सतत विकास का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, क्योंकि यह सामाजिक आर्थिक, पर्यावरणीय और संस्थागत आयामों जैसे क्षेत्रों से संबंधित है।

सामाजिक आयाम (Social Dimension)—सतत विकास के सामाजिक आयामों में 'शून्य भूख', 'अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण', 'उत्तम शिक्षा', 'जनसंख्या नियंत्रण' और 'जेन्डर समानता' (Zero Hunger, Good Health and Well-being, Quality Education, Population Control, and Gender Equality) पर जोर देने के साथ एक मजबूत, स्वास्थ्य और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करना सम्मिलित है।

आर्थिक आयाम (Economic Dimension)—सतत विकास के आर्थिक आयामों में 'गरीबी नहीं', 'स्थायी अर्थव्यवस्था', 'रोजगार के अवसर, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, सभ्य काम और आर्थिक विकास', 'प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन', 'जिम्मेदार खपत और उत्पादन' (No Poverty, Sustainable Economy', Employment Opportunities, Decent Work and Economic Growth, Managing Natural Resources, and Responsible Consumption and Production) पर जोर देने के साथ जनता की आर्थिक भलाई सम्मिलित है।

पर्यावरणीय आयाम (Environmental Dimension)—सतत विकास के पर्यावरणीय आयामों में अनुकूल पर्यावरण को बढ़ावा देने के साथ 'स्वच्छ जल और स्वच्छता', 'सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा', 'उद्योग, परिवहन और ऊर्जा से उत्सर्जन को कम करना' (Clean Water and Sanitation, Affordable and Clean Energy', Reducing Emissions from Industry, Transport and Energy) (ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने जो ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण में योगदान देते हैं) पर जोर दिया गया है। 'नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना' (जैसे सौर या सूर्य, पवन और जल ऊर्जा), 'जलवायु कार्रवाई' और 'प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण (Climate Action and Preservation of Natural Resources), जबकि प्राकृतिक आवासों के जीवन रूपों का (जल के नीचे जीवन और पृथ्वी पर जीवन) का सम्मान करना और उनकी रक्षा करना सम्मिलित है।

संस्थागत आयाम (Institutional Dimension)—सतत विकास के संस्थागत आयामों में 'उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा', 'मजबूत वित्तीय संसाधन', 'शांति, न्याय और मजबूत संस्थान', 'सतत शहर और समुदाय', 'सतत विकास लक्ष्यों के लिए भागीदारी/साझेदारी (एस डी जी)' और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' (Industry, Innovation and Infrastructure, Sound Financial Resources, Peace, Justice and Strong Institutions, Sustainable Cities and Communities, Partnerships for the Sustainable Development Goals and International Cooperation) शामिल हैं।

प्र.5. संयुक्त राष्ट्र के एस०डी०जी० (SDGs) के लक्ष्यों को लिखिए।
Write the aims of SDGs of UN.

उत्तर

संयुक्त राष्ट्र के एस०डी०जी० (SDGs) (सतत विकास लक्ष्य)
(SDGs Aim of UN)

संयुक्त राष्ट्र ने 2015 और 2030 के बीच वैश्विक विकास का मार्गदर्शन करने के लिए 17 अलग-अलग लेकिन परस्पर संबंधित लक्ष्यों का एक समूह बनाया। प्रत्येक उद्देश्य में कार्यों का लक्ष्य होता है—कुल मिलाकर 169 लक्ष्य हैं, जिनमे कुल 232 उपसंकेतक हैं। एस डी जी को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने हेतु कार्रवाई की माँग करता है, ताकि लोग 2030 तक शांति और समृद्धि का आनंद ले सकें।

सतत विकास लक्ष्य (एस डी जी) निम्न हैं—

1. कोई गरीबी नहीं,
2. शून्य भूख,
3. अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण,
4. उत्तम शिक्षा,

TOUCH 'n' PASS

5. जेन्डर समानता,
6. स्वच्छ जल और स्वच्छता,
7. सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा,
8. उचित कार्य और आर्थिक विकास,
9. उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचे,
10. असमानता को कम करना,
11. सतत शहर और समुदाय,
12. जिम्मेदार उपभोग का उत्पादन,
13. जलवायु कार्यवाही,
14. जल के नीचे जीवन,
15. भूमि पर जीवन,
16. शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएँ,
17. लक्ष्य के लिए साझेदारी।

6 जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को महासभा द्वारा अपनाया गया था। प्रस्ताव में संकेतकों के साथ प्रत्येक लक्ष्य के लिए विशेष कार्य की पहचान (Identification) की जाती है, जो प्रत्येक कार्य के प्रति विकास के मापक के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। एस डी जी (SDG) को प्राप्त करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और नागरिकों की साझेदारी की आवश्यकता है, ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हम भावी पीढ़ी की लिए बेहतर ग्रह (Planet) छोड़ सकेंगे।

एस डी जी कई निकट मुद्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे जेन्डर समानता (Gender Equality), शिक्षा और संस्कृति (Education and Culture) सभी एस डी जी को तय करती है। सतत विकास प्राप्त करने के लिए, 3 क्षेत्रों को एक साथ आने की आवश्यकता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय क्षेत्र सभी गंभीर रूप से महत्त्वपूर्ण हैं और एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। प्रगति के लिए सभी तीन क्षेत्रों में बहु-विषयक और बहुज्ञानी विषयक (Multidisciplinary and Transdisciplinary) अनुसंधान की आवश्यकता होगी। यह कठिनता से सिद्ध होता है, जब प्रमुख सरकारें इसका समर्थन करने में विफल रहती हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार समुदाय के बहुत दूर पीछे तक पहुँचने के लक्ष्य हैं। हालांकि डेटा या जानकारी को कमजोर समूहों जैसे कि बच्चों, बुजुर्गों, विकलांग व्यक्तियों, स्वदेशी लोगों, प्रवासियों (Immigrants) और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति के लिए समायोजित (Adjusted) करना चाहिए।

प्र.6. सतत विकास के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।

Describe the important principles of sustainable development.

उत्तर

सतत विकास के महत्त्वपूर्ण सिद्धांत और विशेषताएँ
(Importan Principles and Characteristics of Sustainable Development)

सिद्धांत—सतत विकास के कुछ सिद्धांत, जो महत्त्वपूर्ण है, वे इस प्रकार हैं—

पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण (Conservation of Ecosystem)—सतत विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी संसाधनों का संरक्षण करना है: इसका लक्ष्य पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) को सतत बनाना है। इस उद्देश्य और लक्ष्य के लिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र सहित पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण आवश्यक है।

समाज का सतत विकास (Sustainable Development of Society)—जनसंख्या वृद्धि से वस्तुओं और सेवाओं की माँग बढ़ जाती है। समाज की सततता स्वस्थ निवास, संतुलित आहार, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। समाज में लोगों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा महत्त्वपूर्ण है।

जैव विविधता का संरक्षण (Conservation of Biodiversity)—विश्व में सभी जीवित प्राणियों के संरक्षण को सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है। जीवों की रक्षा के लिए लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना सीखना चाहिए। सितंबर 2020 में वैश्विक जैव विविधता दृष्टिकोण और विश्व वनजीवन कोष (World Wildlife Fund- WWF) और वर्तमान ग्रह सूची (Living Planet Index), दोनों ने सितंबर 2020 में जैव विविधता की हानि के विश्लेषण (Analysis) को रोकने और पृथ्वी ग्रह पारिस्थितिकी को मानव गतिविधि के परिणामों का खतरा होने से पूर्व पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बहाल करने के लिए कठोर और तत्काल कार्यवाही की माँग की।

जनसंख्या नियंत्रण (Population Control)—जनसंख्या वृद्धि से वस्तुओं और सेवाओं की माँग बढ़ जाती है और यदि कार्य अपरिवर्तित रहते हैं, तो इसका अर्थ पर्यावरणीय क्षति में वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या लगभग 1.7 प्रतिशत वार्षिक लगभग एक सौ मिलियन 1 वर्ष में बढ़ रही है। यह तेजी से जनसंख्या वृद्धि गरीबी और पर्यावरण निम्नीकरण के पारस्परिक रूप से मजबूत प्रभावों को बढ़ाती है। फिर भी पर्यावरणीय निम्नीकरण भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ा सकता है। दासगुप्ता (Dasgupta, 1990) का विचार है कि बच्चों को न केवल पैसा और भोजन कमाने के लिए और सेवानिवृत्ति और बीमा उद्देश्यों के लिए, बल्कि कार्यबल बढ़ाने के लिए भी पैदा किया जाता है। इसलिए, सतत विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण और प्रबंधन आवश्यक है।

TOUCH 'n' PASS

मानव संसाधन का संरक्षण (Conservation of Human Resources)—सतत विकास के लिए मानव संसाधन संरक्षण एक बड़ी क्षमता है। इसलिए मानव संसाधन का विकास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रशिक्षण प्रदान करके किया जाता है। सतत विकास के सिद्धांत को अपनाने में मानव संसाधन का योगदान होता है। पृथ्वी की देखभाल पर ज्ञान और कौशल विकसित किया जाना चाहिए। वैसे भी मानव संसाधन (Human Resource) का संरक्षण एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है।

नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना (Encouraging Citizens' Participation)—सतत विकास प्रक्रिया एक पूर्ण अर्थ प्राप्त करेगी यदि नागरिक सतत विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन (Implication) में पूरी तरह से भाग लेते हैं। कोविड-19 महामारी ने यह प्रकाश डाला है कि कैसे पर्यावरणीय संतुलन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम अधिक लचीले अर्थशास्त्र और समुदायों के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। कोविड-19 ने कठोर और दर्दनाक अनुस्मारक प्रदान किया है कि सतत विकास की अवधारणा इतनी महत्त्वपूर्ण क्यों है।

अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना (Promotion of International Coordination and Cooperation)—जैविक विविधता की रक्षा के लिए अधिक कार्यनीतिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के मामलों का समाधान सामान्य सिद्धांतों व प्रोत्साहन और बातचीत द्वारा समर्थित स्वतंत्र देशों के बीच सहयोग के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जैविक संसाधनों (Biological Resources) के लिए समान अंतर्राष्ट्रीय चिंता के कारण, विकासशील देशों को वित्त पोषण और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक मजबूत केस है। 31 जुलाई 2020 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री (भारत) द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) राष्ट्रों के बीच सर्वोत्तम कार्यों को साझा करने की माँग की गई।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. विकासशील या अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

Describe the characteristics of developing or under developed economy.

उत्तर

विकासशील या अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ
(Characteristics of Developing or Under Developed Economy)

एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को निम्न छः भागों में बाँटा जा सकता है—

(I) आर्थिक विशेषताएँ (Economic Characteristics)

1. **कृषि प्रधानता**—अल्प-विकसित देशों की प्रमुख विशेषता उसकी अधिकांश जनता का कृषि एवं सम्बद्ध व्यवसायों में लगे रहना है। कृषिगत आय (Agricultural Income) ही इन देशों में आजीविका (Livelihood) का मुख्य साधन होती है। यही कारण है कि अल्प-विकसित देशों की राष्ट्रीय आय, निर्यात व्यापार और उद्योग कृषि पर ही आधारित होते हैं।
2. **प्राकृतिक साधनों का अल्प उपयोग**—अल्प-विकसित देशों में प्राकृतिक साधनों के प्रचुर मात्रा (Abundantly) में उपलब्ध होने के बाद भी उनका पूर्ण विदोहन (Exploration) उचित उपरी ढ़ाँचे (Infrastructure) की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो पाता।
3. **प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर**—इन देशों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न होता है। भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021 में 2,257 अमेरिकी डॉलर थी, जबकि भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति आय अमेरिका में 62,670 डॉलर, जापान में 44,900 डॉलर तथा यू. के. में 37,740 डॉलर है। 2022 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2389 अमेरिकी डॉलर रही।
4. **पूँजी-निर्माण का निम्न स्तर**—इन देशों में पूँजी-निर्माण का स्तर निम्न होता है। अल्प-विकसित देशों में घरेलू निवेश की दर राष्ट्रीय आय की 5 से 10 प्रतिशत तक होती है, जबकि विकसित देशों में यह 20 से 25 प्रतिशत तक की होती है।
5. **अल्प-रोजगार व बेरोजगारी**—इन अल्प-विकसित देशों में अल्प-रोजगार के साथ-साथ बेरोजगारी भी विद्यमान होती है। इन देशों में मौसमी रोजगार अधिक पाया जाता है।
6. **औद्योगिक पिछड़ापन**—अल्प-विकसित देश औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। यहाँ आधारभूत उद्योगों का अभाव होता है। यहाँ उपभोग आधारित उद्योगों का विकास होता है जिसके कारण औद्योगिक निवेश नहीं हो पाता।

7. **सम्पत्ति एवं आय वितरण में असमानता**—अल्प-विकसित देशों में राष्ट्रीय सम्पत्ति एवं आय का बहुत बड़ा भाग कुछ ही व्यक्तियों के अधिकार में होता है, जबकि जनसंख्या के बड़े भाग को सम्पत्ति एवं आय का छोटा-सा हिस्सा मिल पाता है।
8. **बैंकिंग सुविधाओं का अभाव**—अल्पविकसित देशों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बैंकिंग सुविधाएँ बहुत ही कम होती हैं। परिणामस्वरूप देश में पर्याप्त बचत का एकत्रीकरण एवं विकासोन्मुख प्रयोग नहीं हो पाता।
9. **आर्थिक दुश्चक्र**—अल्प-विकसित देशों में आर्थिक दुश्चक्रों की प्रधानता रहती है। वहाँ पूँजी की कमी से उत्पादन कम होता है। इससे वास्तविक आय कम होती है। अत: वस्तुओं की माँग कम रहती है। इन सबका परिणाम यह होता है कि उत्पादकीय प्रेरणाएँ कम बनी रहती हैं। इस प्रकार यह कुचक्र चलता रहता है और इससे अर्थव्यवस्था निरन्तर प्रभावित होती रहती है।
10. **विदेशी व्यापार में अस्थिरता**—अल्प-विकसित देशों के द्वारा कच्चे माल का निर्यात व पक्के माल का आयात किया जाता है। कच्चे माल की वस्तुओं के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय (Intenational) बाजार में कम होता है। इसके फलस्वरूप निर्यात आय आयात व्यय से बहुत कम प्राप्त होती है।

(II) जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताएँ
(Populated Related Characteristics)

1. **ऊँची जन्म व मृत्यु-दरें**—अल्प-विकसित देशों में विकसित देशों की तुलना में जन्म-दर व मृत्यु-दर अपेक्षाकृत ऊँची रहती है। अल्प-विकसित देशों में ऊँची जन्म-दर के कारण हैं-सामाजिक धारणा एवं विश्वास, पारिवारिक मान्यता, बाल-विवाह, विवाह की अनिवार्यता, भाग्यवादिता, मनोरंजन सुविधाओं का अभाव, निम्न आय व निम्न जीवन-स्तर, निरोधक सुविधाओं का अभाव, आदि। इसी प्रकार यहाँ ऊँची मृत्यु-दर के कारण हैं—अकाल व महामारी, लोक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, स्त्री-शिक्षा का अभाव, पौष्टिक (Nutrient) आहार का अभाव, आदि।
2. **ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता**—अल्पविकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। भारत की (2022-23 में) 65% प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में व शेष शहरों में रहती है।
3. **जनसंख्या का आधिक्य**—अल्प-विकसित देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जबकि विकसित देशों में उतना नहीं होता है। साथ ही अल्प-विकसित देशों में जनसंख्या तीव्र गति (Rapidly) से बढ़ती है। अत: यहाँ जनसंख्या का आकार व घनत्व अधिक होता है।
4. **आश्रितों की अधिकता**-अल्प-विकसित देशों में एक परिवार में आश्रितों की मात्रा अधिक होती है। इसका अर्थ यह है कि इन देशों में कमाने वाले कम होते हैं, जबकि खाने वाले अधिक। इसका कारण यह है कि यहाँ बच्चों व बूढ़ों की संख्या विकसित देशों की तुलना में अधिक होती है।
5. **अकुशल जनशक्ति की अधिकता**—अल्प-विकसित देशों में अकुशल जनशक्ति (Unskilled manpower) की अधिकता रहती है। इसके कारण शिक्षा व प्रशिक्षण का अभाव, प्रति व्यक्ति निम्न आय, संयुक्त परिवार प्रणाली, रूढ़िवादिता (Conservatism), भाग्यवादिता, आत्मसन्तोष की भावना, आदि हैं।

(III) तकनीकी विशेषताएँ
(Technical Characteristics)

1. **पुरानी उत्पादन विधि**-अल्प-विकसित देशों में वही पुरानी उत्पादन विधि ही पायी जाती है जिसे उन्नत देश छोड़ चुके होते हैं। उदाहरण के लिए, अल्प-विकसित देशों में कृषि उत्पादन पुराने तरीके से ही होता है, जबकि उन्नत देश ट्रैक्टर व आधुनिक मशीनों का प्रयोग करते हैं।
2. **तकनीकी शिक्षा का अभाव**—अल्प-विकसित देशों में तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव होता है तथा उनके द्वारा अनुसन्धान और शोध कार्यों पर बहुत कम व्यय किया जाता है। इसके कारण अशिक्षा, श्रम की गतिशीलता का अभाव, परम्परावादी दृष्टिकोण (Traditional Outlook) तथा औद्योगीकरण की कमी है।
3. **अपर्याप्त संचार एवं आवागमन सुविधाएँ**—अल्प-विकसित देशों में संचार एवं आवागमन के साधन अपर्याप्त (unsufficient) होते हैं जिससे व्यापार सीमित मात्रा में ही होता है तथा श्रमिकों में गतिशीलता (Movability) की कमी पायी जाती है।

TOUCH 'n PASS

4. **कुशल श्रमिकों का अभाव**–श्रमिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए अल्प–विकसित देशों में प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव (Scaracity) रहता है। इससे देश में कुशल श्रमिक कम मात्रा में ही मिल पाते हैं।

(IV) सामाजिक विशेषताएँ (Social Characteristics)

1. **साक्षरता की कमी**—अल्प–विकसित देशों में साक्षरता की कमी पायी जाती है। दूसरे शब्दों में, इन देशों में व्यापक निरक्षरता होती है जिसका प्रतिशत 70 या इससे भी ऊपर होता है। विकसित देशों में निरक्षरता का प्रतिशत 5 से भी कम होता है। इस निरक्षरता के कारण ही यहाँ के निवासी रूढ़िवादी, अन्धविश्वासी एवं भाग्यवादी होते हैं, जो नवीन परिवर्तनों का धर्म के नाम पर विरोध करते हैं।
2. **जातिवाद**—इन देशों में वर्ग–भेद व जातिवाद की भावना व्याप्त होती है जिससे यहाँ के व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति भिन्न–भिन्न होती है तथा प्रत्येक जाति की अपनी परम्पराएँ एवं रीति–रिवाज होते हैं।
3. **रीति–रिवाजों की प्रधानता**—अल्पविकसित देशों में रीति–रिवाजों की प्रधानता होती है और समय–समय पर उन्हीं रिवाजों (Traditions) के अनुसार कार्य करता है जिसका परिणाम यह होता है कि अपव्यय (Extravagance) को बढ़ावा मिलता है जिससे निवासी निर्धन व ऋणग्रस्त बने रहते हैं।

(V) राजनीतिक विशेषताएँ (Political Characteristics)

1. **अधिकारों के प्रति जागरूक न होना**—अल्प–विकसित देशों में जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती है। अत: उसमें अधिकारों के प्रति जागरूकता (Awareness) नहीं पायी जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ के लोग अपनी दरिद्रता को ईश्वरीय देन मानते हैं।
2. **दुर्बल राष्ट्र**—अल्प–विकसित देश विकसित देशों के मुकाबले में दुर्बल होते हैं और ऐसे देशों पर सदा ही विदेशी राष्ट्रों का आधिपत्य (Supremacy) किसी–न–किसी रूप में बना रहता है।
3. **आधुनिक सेना का अभाव**—ऐसे देशों के पास आधुनिक अस्त्रों से लैस सेना का अभाव होता है।
4. **प्रशासनिक अकुशलता**—इन राष्ट्रों में प्रशासनिक कुशलता एवं ईमानदारी का अभाव होता है। राजनीतिक नेता भी इस सम्बन्ध में कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। अत: यहाँ कालाबाजारी, भ्रष्टाचार व बेईमानी भयंकर रूप में पायी जाती है।

प्र.2. सतत विकास का अर्थ एवं स्वरूपों का वर्णन कीजिए।
Describe the meaning and forms of sustainable development.

उत्तर

सतत विकास का अर्थ (Meaning of Sustainable Development)

1970 के दशक के आरंभ में सतत विकास शब्द संभवत: बारबरा वार्ड लेडी जैक्सन (Barbara Ward-Lady Jackson) द्वारा अंकित किया गया था, जो पर्यावरण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (International Institute for Environment and Development) की संस्थापक (Founder) थी। सतत विकास व्यापक रूप से लोगों, उनकी आर्थिक और सामाजिक भलाई और एक दूसरे के साथ अपने रिश्तो में समानता के विषय में है, उस संदर्भ में, जहाँ पर्यावरण–समाज के असंतुलन से आर्थिक और सामाजिक सततता को खतरा हो सकता है।

सतत विकास की अवधारणा की विरासत का शीर्षक 'हमारा सामूहिक भविष्य के लिए पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिर्पोट (Report of the World Commission on Environment and Development entitled Our Common Future) को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो इसे विकास के रूप में परिभाषित करते हुए कहता है कि 'भविष्य की पीढ़ियों की योग्यता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना आवश्यक है'। इस प्रकार, यह मानव की पीढ़ियों के भीतर न्याय संगतता और अंतर पीढ़ीगत न्याय संगतता की अनिवार्यता (Inevitability) को भी पूरा करने का प्रयास करता है। सतत विकास वह विकास है, जो वर्तमान और भावी पीढ़ी के कल्याण की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह सततता के मुद्दों और विशेष रूप से संरचनात्मक परिवर्तनों (Structural Changes) पर ध्यान केंद्रित करते हुए लंबी अवधि में विकास के साथ संबंधित

है, जो राज्यों के गुणात्मक रूप से अलग-अलग विशेषताओं या विचार के अंतर्गत प्रणाली के व्यवहार के परिणामस्वरूप परिवर्तित होता है।

पर्यावरणीय हानि के वैश्विक और स्थानीय प्रभावों को देखते हुए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सतत विकास, विकास योजना और संसाधन प्रबंधन में एक 'पसंदीदा शब्द' बन गया है। हालाँकि इस अवधारणा की व्याख्या अभी भी अस्पष्ट है। ब्रेटलैंड रिपोर्ट (Brundtland Report) के अनुसार, सतत विकास का विचार पर्यावरण संरक्षण से कहीं आगे तक पहुँचता है, क्योंकि इसका अर्थ है परिवर्तन की प्रक्रिया, जिसमें संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास का उन्मुखीकरण और संस्थागत परिवर्तन भविष्य में साथ ही साथ वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ तर्कयुक्त बनाए जाते हैं। यह सामंजस्य की निश्चित स्थिति नहीं है, बल्कि परिवर्तन की एक संतुलित और अनुकूल प्रक्रिया है।

सततता के लिए 'आर्थिक विकास के बीच संतुलन'—अर्थव्यवस्था में सभी मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित है, जो कल्याण में सकारात्मक योगदान प्रदान करते हैं और पारिस्थितिक सततता सभी मात्रात्मक और गुणात्मक पर्यावरणीय कार्यनीतियाँ हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कार्य करती है और अंतत: कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। दोनों आर्थिक और पर्यावरणीय प्रणालियों को जीवित रहने के लिए निश्चित न्यूनतम शुरुआत की आवश्यकता होती है।

'संक्षेप में, सतत विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जिसमें संसाधनों का दोहन, (Exploration of Resoures) निवेश की दिशा, तकनीकी विकास का उन्मुखीकरण, और संस्थागत परिवर्तन (Institutional Changes), सभी सामंजस्य में है और मानव की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं (Aspirations) को पूरा करने के लिए वर्तमान और भविष्य की क्षमता दोनों को बढ़ाते हैं'।

ब्रंटलैंड कमीशन की परिभाषा के अर्थ—'भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने' की विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Report, 1992) द्वारा दृढता से समर्थन किया गया है।

सतत विकास की अवधारणा पारंपरिक दृष्टिकोण (Traditional Outlook) को अस्वीकार करती है, जो आर्थिक विकास को आवश्यकता, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को विलास का साधन मानता है। पार्थ दासगुप्ता और कार्ल-गोरान मेलर (Partha Dasgupta and Karl-Goran Maler, 1990) लिखते हैं कि 'पर्यावरणीय संसाधन गरीब देशों के लिए छोटे महत्त्व के है वे आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह के संसाधन विलासिता की वस्तुएँ हैं और वे सार्वजनिक चेतना में ही बड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं, जब आय उच्च होती है.....पर्यावरणीय संसाधन केवल समृद्ध देशों की अतिव्यस्तता है। ये अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हैं, जो गरीब देशों में गरीबों की वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं।

हालाँकि, पिछले एक दशक में, पर्यावरणीय क्षय के वैश्विक प्रभावों पर आंशिक पर्यावरणीय विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परिवर्तन किया गया है—खतरनाक घटनाएँ जैसे बाढ़, अम्लीय वर्षा, मिट्टी स्थलन और मरुस्थलीकरण, ओजोन रिक्तिकरण, समुद्र प्रदूषण और संसाधन निष्कर्षण (Flooding, Acid Rain, Soil Erosion and Desertification, Destruction of the Ozone Layer, Ocean Pollution, and Resource Extraction) विनाश के अन्य चीजों के बीच परिलक्षित होती है। इस प्रकार, संसाधन संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण, कभी सोची हुई विलासिता की वस्तुएँ हैं, जो अब जीवन रक्षक प्राकृतिक प्रणालियों की रक्षा और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए आवश्यक रूप में पहचाने जाते हैं। नेता अब निरंतर समझ रहे हैं कि सामाजिक-आर्थिक विकास सतत होने चाहिए, जो न केवल वर्तमान जरूरतों को बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम हों।

इस संदर्भ में, प्रश्न ये हैं कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों की भलाई का आकलन कैसे किया जाए। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ना चाहिए कि वे स्वयं को हम से बुरी स्थिति मे न पाएँ। यह मुद्दा और अधिक जटिल हो जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे न केवल हमारे कृषि रहित खेत, नष्ट हुए पहाड़, प्रदूषित पानी और हवा, घास के मैदान, और रिक्त ओजोन को पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे श्रम के रूप में शिक्षा, कौशल और ज्ञान व भौतिक पूँजी का फल भी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, वे प्राकृतिक संसाधनों में मिट्टी की उर्वरता में सुधार और पुन:वितरण में निवेश से लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आशीष कोठारी (Ashish Kothari, 1993) का कथन है कि वर्तमान में परिभाषित 'सतत विकास की परिभाषा आंतर-पीढ़ीगत आंतर-जीवी असमानता (Intragenerational Inter-species Inequity) की सततता को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती है, और इसलिए खुशी, समानता, न्याय और शांति के विशाल मानवीय लक्ष्यों के दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है'।

सतत विकास का स्वरूप (Forms of Sustainable Development)

इस बात पर विचार करते हुए कि हम अपने बच्चों और पोते-पोतियों के लिए विरासत में क्या छोड़ते हैं और क्या करते हैं, हमें भौतिक और मानव पूँजी की पूरी-श्रृंखला और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सोचना चाहिए, जो उनके कल्याण का निर्धारण करेगी। सतत विकास के सिद्धांत को अपनाने के लिए सोच में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता होगी। निर्णय-निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा में संसाधनों की कमी और प्रदूषण की सही लागतों को प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि वे आय-उत्पादक के कम होते संसाधनों की अब अल्पकालिक लाभों की अपेक्षा भावी पीढियों को प्रभावित करता हैं। डेटा को वर्तमान आवश्यकताओं के साथ भविष्य की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, न कि उन्हें कम करना चाहिए, जो अल्पकालिक प्रभावों के पक्ष में निर्णय लेते हैं।

सिरिकेसी-वौर्टेप (Ciricacy-Wantrup, 1952) ने मानवीय गतिविधियों को सीमित करके पर्यावरण के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के अधिक शोषण से बचने के कारण संरक्षण के लिए सुरक्षित न्यूनतम मानकों के उपयोग पर जोर दिया, जो इसे पर्यावरण निम्नकरण को विराम देने या रद्द करने के लिए असंवैधानिक बनाते हैं। इस प्रकार, सतत विकास के विचार के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय, दोनों प्रणालियों के लिए स्थानीय सीमा स्तरों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, ब्राजील जैसे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि विकास के लिए वनों की कटाई आवश्यक हो सकती है, लेकिन यह वैश्विक पारिस्थितिक सततता के लिए घातक और हानिकारक सिद्ध हो सकती है, जब एक देश तेजी से जनसंख्या वृद्धि या आकस्मिक शहरीकरण का अनुभव करता है, तब सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जी एन पी (Gross National Product) वृद्धि, प्रमुख विकास समस्याएँ छिपा सकती हैं। वही कठिनाई उत्पन्न होती हैं, जहाँ विश्व किसी देश या क्षेत्र से कच्चे संसाधनों की माँग करता है, जो वैश्विक जरूरतों को पूरा करते हैं। संक्षेप में, जब तक हम सततता को परिभाषित करने के लिए तैयार होते हैं जिसमें उत्तर में खाद्य नीतियों से बाहरी खतरों और दक्षिण में जनसंख्यकीय दबाव से आंतरिक खतरों दोनों का अध्ययन शामिल हो, तब तक यह भ्रम बना रहेगा।

इसी प्रकार, भारत में भूमि दबाव (Land Pressure) की बढ़ती समस्याओं से निपटने के लिए—

1. जनसंख्या वृद्धि दर की जाँच करना और नियंत्रित करना;
2. संतुलित पशुधन विकास को सुनिश्चित करना;
3. भूमि हस्तांतरण पर नियंत्रण करना आवश्यक है।

दूसरी ओर, जब विश्व आयोग यह कहता है कि: 'सतत विकास के लिए आवश्यक है कि वायु, जल और अन्य प्राकृतिक तत्त्वों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव कम से कम पड़े, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र अखंडता को बनाए रखा जा सके', सफलता को आकना कोई आसान कार्य नहीं है।

इन कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए, विश्व आयोग (World Commission) ने उल्लेख किया कि सतत विकास में सफलता के उपायों को संदर्भ और सामाजिक चुनौतियों को पूरा करने की आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए। सततता के पहलू पर्यावरणीय प्रशासकों से यह माँग करता है कि सततता के लक्ष्य हों—

1. जैवमंडल के कार्य के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र और संबंधित पारिस्थितिकी प्रतिक्रियाओं को बनाए रखना;
2. वनस्पतियों और जीवो की सभी प्रजातियों के उनके प्राकृतिक आवासों में अतिजीवन और संरक्षण को सुनिश्चित करके जैविक विविधता को बनाए रखना;
3. जीवित प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र के दोहन में सर्वोत्तम सतत उपज के सिद्धांत का पालन करना;
4. महत्त्वपूर्ण पर्यावरण प्रदूषण या नुकसान को रोकना या कम करना;
5. पर्याप्त पर्यावरणीय संरक्षण मानकों की स्थापना करना;
6. प्रमुख कानून नीतियों, परियोजनाओं, और प्रौद्योगिकियों को, सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण मूल्यांकन (Evaluation) आरंभ करना है, जो सतत विकास में योगदान देती है।
7. प्रदूषण के हानिकारक या संभावित रूप से हानिकारक निवारण के सभी मामलों में देरी किए बिना सभी प्रसांगिक जानकारी सार्वजनिक करना, विशेष रूप से रेडियोधर्मी निवारण (Radioactive Release) की।

रियो शिखर सम्मेलन (Rio Summit) में यह माना जाता था कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सततता की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है। विश्व बैंक के पर्यावरण विभाग ने अब एक नई परिभाषा तैयार की है। यह दो भागों में है—

1. **आउटपुट गाइड** (Output Guide)—औद्योगति के बिना स्थानीय वातावरण की समावेश क्षमता के भीतर अपशिष्ट उत्सर्जन होना चाहिए।
2. **इनपुट गाइड** (Input Guide)—नवीकरणीय संसाधनों की पैदावर दरें प्राकृतिक सुधार क्षमता के भीतर होनी चाहिए, गैर-नवीकरणीय संसाधनों की कमी दर उस दर के समान होनी चाहिए, जिस पर नवीकरणीय विकल्प विकसित किए गए हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्याएँ हैं–
(क) पूँजी का अभाव (ख) निर्धनता (ग) बेरोजगारी (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.2. निम्नलिखित में से कौन अल्पविकसित देश की विशेषता नहीं है?
(क) आय एवं सम्पत्ति का समान वितरण (ख) प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर
(ग) औद्योगिक पिछड़ापन (घ) अकुशल जनशक्ति की अधिकता
उत्तर (क) आय एवं सम्पत्ति का समान वितरण

प्र.3. निम्नलिखित में से कौन-सा देश अल्पविकसित है?
(क) संयुक्त राज्य अमेरिका (ख) भारत (ग) इंग्लैण्ड (घ) जापान
उत्तर (ख) भारत

प्र.4. आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है–
(क) अल्पविकसित अर्थव्यवस्था (ख) विकासमान अर्थव्यवस्था
(ग) तृतीय विश्व (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.5. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
(क) अल्प-विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है।
(ख) अल्प-विकसित देशों में आर्थिक दुष्चक्रों की प्रधानता रहती है।
(ग) विकसित देशों में प्रत्याशित आयु अधिक होती है।
(घ) अल्प-विकसित देशों में वित्तीय संगठन दोषपूर्ण होता है।
उत्तर (क) अल्प-विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है।

प्र.6. अल्पविकास का अर्थ–
(क) श्रम की अधिकता से है। (ख) पूँजी की न्यूनता से है।
(ग) शिक्षा या ज्ञान के अभाव से है। (घ) एक या अनेक उत्पादन के घटकों की न्यूनता से है।
उत्तर (घ) एक या अनेक उत्पादन के घटकों की न्यूनता से है।

प्र.7. कोई भी दूषित घटक जो मिट्टी में रिसता है, निस्पंदन करता है और भूमिगत जलाशय में स्थानांतरित हो जाता है, उसे कहा जाता है
(क) जल प्रदूषण (ख) ध्वनि प्रदूषण (ग) भूमि संदूषण (घ) वायु प्रदूषण
उत्तर (ग) भूमि संदूषण

प्र.8. दक्षिण अफ्रीका का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्यात कौन सा संसाधन है?
(क) ताँबा (ख) डायमंड (ग) चाँदी (घ) सोना
उत्तर (घ) सोना

प्र.9. यदि सतत विकास की तीन नींवों में से केवल दो का ही सामना हो तो कौन सा विकल्प सत्य है?
(क) व्यवहार्य = आर्थिक + पारिस्थितिक स्थिरता (ख) सहने योग्य = सामाजिक + पारिस्थितिक स्थिरता
(ग) समतामूलक सामाजिक + आर्थिक स्थिरता (घ) पूर्ववर्ती कोई नहीं
उत्तर (घ) पूर्ववर्ती कोई नहीं

प्र.10. स्थिरता की अवधारणा पहली बार किस वर्ष सामने आई?
(क) 1992 (ख) 1978 (ग) 1980 (घ) 1987
उत्तर (ग) 1980

TOUCH 'n' PASS

प्र.11. वर्ष में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थिरता पर एक समिति (CSD) का गठन किया–
(क) 1995 (ख) 1994 (ग) 1993 (घ) 1992

उत्तर (घ) 1992

प्र.12. खनन के बाद छोड़े गए विशाल छिद्रों का उपयोग किया जाता है–
(क) अपशिष्ट जल भंडारण (ख) घरेलू अपशिष्ट जल भंडारण
(ग) अपशिष्ट निपटान (घ) कूड़ा संचयन

उत्तर (ग) अपशिष्ट निपटान

प्र.13. पारा, साथ ही सीसा, जहरीले पदार्थ हैं जो इसमें योगदान करते हैं–
(क) शोर जोखिम (ख) खराब वायु गुणवत्ता (ग) जल प्रदूषण (घ) मिट्टी का प्रदूषण

उत्तर (घ) मिट्टी का प्रदूषण

प्र.14. भूदृश्य-चित्रण का वैकल्पिक नाम है–
(क) घटाना (ख) पुनर्स्थापना (ग) ऊपरी मिट्टी हटाना (घ) पुनर्स्थापन

उत्तर (ख) पुनर्स्थापना

प्र.15. जब किसी खनिज का मूल्य मजबूत रहता है, तो कंपनी उसकी तलाश करती है–
(क) नये राष्ट्र (ख) नये खनिक (ग) नये क्षेत्र (घ) नई जमाए

उत्तर (घ) नई जमाए

प्र.16. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सतत विकास मापदंडों में शामिल नहीं है?
(क) लैंगिक असमानता और विविधता (ख) अंतरपीढ़ीगत और अंत:पीढ़ीगत समानता
(ग) प्रतिवर्ष बढ़ रहा है (घ) इनमे से कोई भी नहीं

उत्तर (घ) इनमे से कोई भी नहीं

प्र.17. सतत विकास की परिभाषा क्या है?
(क) वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को खतरे में डाले बिना वर्तमान माँगों को पूरा करता है।
(ख) प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए खनिज संपदा का संरक्षण करें और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का पता लगाएँ।
(ग) यह भूमि और भवन परियोजनाओं को इस तरह से बनाने की प्रक्रिया है कि उन्हें ईंधन-कुशल आत्मनिर्भरता पैटर्न का उत्पादन करने में सक्षम बनाकर उनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हो।
(घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (घ) उपरोक्त सभी

प्र.18. यदि हम सतत विकास की तीन नींवों में से केवल दो को ही पूरा करते हैं, तो पूर्ववर्ती में से कौन सा सही है?
(क) सामाजिक + वित्तीय दीर्घायु = निष्पक्षता (ख) सहने योग्य = आर्थिक + पारिस्थितिक स्थिरता
(ग) व्यवहार्य = सामाजिक + पारिस्थितिक स्थिरता (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.19. स्थिरता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
I. यह एक ऐसी प्रक्रिया या स्थिति का वर्णन करता है जो अनंत काल तक चल सकती है।
II. प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि पृथ्वी की वहन और उत्पादक क्षमताओं के अत्यधिक दोहन के कारण पारिस्थितिक ऋण न हो।
III. संपूर्ण प्राकृतिक पूँजी आधार को उसके मौजूदा स्तर से ऊपर रखना दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण है।

कोड—
(क) केवल I (ख) केवल II (ग) केवल II और III (घ) I, II और III

उत्तर (घ) I, II और III

TOUCH 'n PASS

प्र.20. उपरोक्त में से कौन-सा/से एक सतत विकास लक्ष्य है/नहीं है?

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन बनाये रखें।

(ख) कम से कम 123 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की गतिशील स्थिरता बनाए रखें, साथ ही कृषि विकास रणनीति भी।

(ग) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी और कृषि अतिरिक्त मूल्य) की प्रति इकाई पानी के उपयोग को कम करके एक गतिशील जल संसाधन संतुलन बनाए रखें।

(घ) पर्यावरण में इतने महत्त्वपूर्ण, यद्यपि हमेशा विनाशकारी नहीं, परिवर्तन का नेतृत्व करना।

उत्तर (घ) पर्यावरण में इतने महत्त्वपूर्ण, यद्यपि हमेशा विनाशकारी नहीं, परिवर्तन का नेतृत्व करना।

प्र.21. सभी मुख्य स्थिरता उद्देश्य क्या हैं?

I. गरीबी और भुखमरी उन्मूलन।

II. उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल मानक, विशेष रूप से पानी की गुणवत्ता और स्वच्छता के मामले में।

III. लैंगिक समानता।

IV. दीर्घकालिक आर्थिक विकास जो रोजगार को बढ़ावा देता है और समुदायों को मजबूत करता है।

कोड—

(क) I, II और III (ख) I, III और IV (ग) I और III (घ) I, II, III और IV

उत्तर (घ) I, II, III और IV

प्र.22. 'सतत विकास' वाक्यांश पहली बार कब सामने आया?

(क) 1987 (ख) 1980 (ग) 1978 (घ) 1992

उत्तर (ख) 1980

प्र.23. दिसंबर में, महासभा ने पर्यावरण स्थिरता पर संयुक्त राष्ट्र परिषद (CSD) का निर्माण किया–

(क) 1992 (ख) 1993 (ग) 1994 (घ) 1995

उत्तर (क) 1992

प्र.24. निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र आयोग एजेंडा 21 के साथ-साथ पर्यावरणीय मुद्दों पर रियो समझौते की प्रगति की निगरानी का प्रभारी है?

(क) संयुक्त राष्ट्र का निरस्त्रीकरण आयोग

(ख) संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग) बी. संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग

(ग) संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय स्थिरता समिति (सीएसडी)

(घ) संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार न्यायाधिकरण

उत्तर (ग) संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय स्थिरता समिति (सीएसडी)

प्र.25. सतत शासकीय विकास पर निम्नलिखित कथनों की जाँच करें।

I. सतत विकास के विचार को समझने में सहायता करना।

II. इसके साथ आने वाले मुद्दों की पहचान करें।

III. सक्रिय नीति पहलों के कार्यान्वयन में सहायता करना।

कोड—

(क) I और II दोनों (ख) II और III दोनों (ग) I और IV दोनों (घ) I, II और III

उत्तर (घ) I, II और III

प्र.26. निम्नलिखित में से कौन-सा सतत विकास चर में से एक नहीं है?

(क) वहन क्षमता (ख) अंतर और अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी

(ग) लिंग असमानता और विविधता (घ) इनमे से कोई भी नहीं

उत्तर (घ) इनमे से कोई भी नहीं

TOUCH 'n' PASS

प्र.27. 21वीं सदी में सतत विकास की धारणा पर अधिक जोर दिया गया है–
(क) आर्थिक प्रगति (ख) सामाजिक प्रगति (ग) पर्यावरण की सुरक्षा (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.28. स्थिरता विज्ञान ..... और सतत विकास जैसी अवधारणाओं का अनुप्रयोग है।
(क) पर्यावरण विज्ञान (ख) सामान्यत: विज्ञान (ग) सामाजिक विज्ञान (घ) जियोसाइंस
उत्तर (क) पर्यावरण विज्ञान

प्र.29. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सामाजिक प्रगति के महत्त्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित हैं–
(क) अनुदेश (ख) सार्वजनिक स्वास्थ्य (ग) जीवन स्तर (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.30. सतत विकास के लिए स्कूली शिक्षा का युग संयुक्त राष्ट्र (यूएन) से है–
(क) 2002-11 (ख) 2003-12 (ग) 2004-13 (घ) 2005-14
उत्तर (घ) 2005-14

प्र.31. संयुक्त राष्ट्र ने कुल सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) स्थापित किए–
(क) 15 (ख) 16 (ग) 17 (घ) 18
उत्तर (ग) 17

प्र.32. सतत विकास (एसडीजी) के लिए 2030 एजेंडा स्वीकार करता है कि सभी सरकारों को नीचे सूचीबद्ध महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई को बढ़ावा देना चाहिए।
(क) लोग, ग्रह, समृद्धि, शांति और सहयोग
(ख) लोग, दुनिया, धन, वनस्पति और योजना
(ग) लोग, ग्रह, धन, पौधे और सहयोग
(घ) लोग, पर्यावरण, समृद्धि, शांति और दूरदर्शिता
उत्तर (क) लोग, ग्रह, समृद्धि, शांति और सहयोग

प्र.33. सतत विकास को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय–
(क) प्राकृतिक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज (ख) पर्यावरण अर्थव्यवस्था और निष्पक्षता
(ग) सभ्यता, पारिस्थितिकी और पर्यावरण (घ) पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण
उत्तर (क) प्राकृतिक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज

प्र.34. जब संसाधन निष्कर्षण का उपयोग प्रकृति की पुन: पूर्ति की क्षमता के बराबर होता है, तो स्थिरता प्राप्त होती है–
(क) दीर्घकालिक नहीं (ख) अर्थव्यवस्था स्थिर स्थिति में
(ग) यह पर्यावरण के अनुकूल है (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) अर्थव्यवस्था स्थिर स्थिति में

प्र.35. आत्मनिर्भर प्रणालियों को डिजाइन करना दीर्घकालिक प्रगति की दिशा में एक व्यवहार्य मार्ग है–
(क) प्रतिवर्ती और लचीला (ख) प्रतिवर्ती और लचीला
(ग) प्रतिवर्ती और अनम्य (घ) अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनशील
उत्तर (ख) प्रतिवर्ती और लचीला

प्र.36. टिकाऊ खेती के घटक इस प्रकार हैं–
(क) पर्माकल्चर (ख) एग्रोफोरेस्टरी (ग) मिश्रित खेती (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VI

दक्षता-क्षमता डिबेट
Efficiency-Equity Debate

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. धारणीय अथवा टिकाऊ विकास की पाँच शर्तें लिखिए।
Write the five stipulations of sustainable development.

उत्तर 1. ऐसी सामाजिक प्रणाली, जिसमें गैर-सामंजस्यपूर्ण विकास से उठने वाले तनावों को सुलझाने की व्यवस्था हो।
2. ऐसी उत्पादन प्रणाली, जो विकास कि पारिस्थितिकीय आधार को सुरक्षित रखना अपना कर्त्तव्य मानती हो।
3. ऐसी प्रौद्योगिकी प्रणाली, जो निरन्तर नए सुझाव खोज सके।
4. ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली, जो व्यापार एवं वित्त के टिकाऊ तौर-तरीकों को बढ़ावा दे।
5. ऐसी प्रशासनिक प्रणाली जो लचीली हो और जिसमें अपनी भूलों को सुधारने की क्षमता हो।

प्र.2. दक्षता और इक्विटी प्रश्नोत्तरी में क्या अंतर है?
What is the difference between efficiency and equityquiz?

उत्तर दक्षता और समता में क्या अंतर है? सरकारी नीति निर्माताओं को अक्सर दक्षता और समानता के बीच व्यापार-विरोध का सामना क्यों करना पड़ता है? उत्पादक दक्षता तब होती है जब कम से कम संसाधनों का उपयोग करके g+s का उत्पादन किया जाता है। समानता व्यक्तियों और समाजों के बीच आर्थिक लाभों का उचित वितरण है।

प्र.3. दक्षता क्या है उदाहरण सहित समझाइए?
What is efficiency explain it with example?

उत्तर दक्षता का मतलब क्या है? दक्षता (Efficiency) का सामान्य अर्थ यह है कि किसी कार्य या उद्देश्य को पूरा करने में लगाया गया समय या श्रम या ऊर्जा कितनी अच्छी तरह काम में आती है। दक्षता एक मापने योग्य राशि है। ऊर्जा के रूपान्तरण की स्थिति में आउटपुट ऊर्जा और इनपुट उर्जा के अनुपात को दक्षता कहते हैं।

प्र.4. आर्थिक दक्षता की परिभाषा दीजिए।
Give a definition of efficiency.

उत्तर आर्थिक दक्षता तब होती है जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी सामान और कारकों को उनके सबसे मूल्यवान उपयोगों के लिए वितरित या आवंटित किया जाता है और अपशिष्ट को समाप्त या कम किया जाता है। एक प्रणाली को आर्थिक रूप से कुशल माना जाता है यदि उत्पादन के कारकों का उपयोग उनकी क्षमता के स्तर पर या उसके निकट किया जाता है।

प्र.5. आर्थिक दक्षता क्यों महत्त्वपूर्ण है?
Why is efficiency important?

उत्तर आर्थिक दक्षता महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यवसायों को अपनी लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने की अनुमति देती है। उपभोक्ताओं के लिए, आर्थिक दक्षता से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हो जाती हैं। सरकार के लिए, अधिक कुशल फर्में और उत्पादकता और आर्थिक गतिविधि के उच्च स्तर आर्थिक विकास को बढ़ाते हैं।

प्र.6. धारणीय विकास का क्या महत्त्व है?
What is the importance of sustainable development?

उत्तर 1. **प्रदूषण से बचाव**—धारणीय विकास द्वारा लोगों के स्वास्थ्य तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। इन्हें धारणीय विकास द्वारा ही प्रदूषण से बचाया जा सकता है।

TOUCH n PASS

2. **पर्यावरण संरक्षण**—धारणीय विकास द्वारा ही पर्यावरण संरक्षण सम्भव होता है। इससे आर्थिक विकास कायम रखने की सम्भावना बढ़ जाती है।

प्र.7. धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखिए?
What do you understand by sustainable development, write its features.

उत्तर धारणीय विकास—पर्यावरण को नुकसान पहुँचाये बिना वर्तमान पीढ़ी का विकास सुनिश्चित करना तथा भावी पीढ़ी की गुणवत्ता पूर्ण जीवन के लिए पर्याप्त रुप से प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखना धारणीय विकास कहलाता है।

प्र.8. विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं, विकास को धारणीय बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?
What do you understand by development of sustainability? What can be done to make development sustainable?

उत्तर विकास के टिकाऊ होने का मतलब है कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना विकास होना चाहिए, वर्तमान विकास में भावी पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। सतत विकास निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है– संसाधनों के वैज्ञानिक एवं उचित उपयोग से।

प्र.9. भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्त्रोत कौन-सा है?
Which is the best source of electricity in India by the outlook of sustainable development?

उत्तर सही उत्तर जलविद्युत है। जलविद्युत भारत में सतत विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन करने का सबसे अच्छा स्त्रोत है।

खण्ड-ब (लघु उत्तरीय) प्रश्न

प्र.1. धारणीय (सतत) विकास का क्या आशय है?
What is the meaning of sustainable development.

उत्तर

धारणीय (सतत) विकास का आशय
(Meaning of Sustainable Development)

मानव की प्रगति एवं विकास का आधार उसके द्वारा प्रकृति अथवा पर्यावरण का उपयोग है। मानव विकास की प्रारम्भिक अवस्था में सीमित जनसंख्या तथा सीमित आवश्यकताओं के कारण प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के उपरान्त भी उसका पर्यावरण से सामंजस्य बना रहा, किन्तु बढ़ती जनसंख्या तथा तकनीकी प्रगति के साथ-साथ प्रकृति के शोषण की दर बढ़ती गई। आर्थिक विकास की दौड़ में पर्यावरण (Environment) पर दबाव बढ़ता गया.। पर्यावरण पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार करके किया गया विकास स्वयं मानव के लिए ही आत्मघाती सिद्ध हुआ। पर्यावरण प्रदूषण, संसाधनों का संकट आदि इसके दुष्परिणाम हैं। निरन्तर विकास मानव की स्वाभाविक प्रकृति है तथा पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण विकास को रोका नहीं जा सकता है, तो पर्यावरण ह्रास के कारण समस्त जीव जगत पर बढ़ते संकट की अनदेखी भी नहीं की जा सकती है। अत: पर्यावरण को बचाते हुए सतत विकास की अवधारणा विकसित हुई। इसे प्रतिपालनीय विकास की अवधारणा भी कहा जाता है।

पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आयोग के ब्रंटलैण्ड प्रतिवेदन (Brundtland Report) में दी गई स्थिर अथवा टिकाऊं अथवा धारणीय विकास की परिभाषा इस प्रकार है—'धारणीय अथवा टिकाऊ विकास वह है, जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता को क्षति पहुँचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे।' इस तरह टिकाऊ विकास एक सर्वग्राह्य अवधारणा है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों का समावेश है।

विकास में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को सम्मिलित करके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी किया जा सकता है तथा पारिस्थितिकी संकट से बचा भी जा सकता है। सन्तुलित विकास, समन्वित विकास तथा सतत विकास इसके विभिन्न पक्ष हैं। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है, जो पर्यावरण को हानि पहुँचाए बिना जीवन की गुणवत्ता जारी रख सके। विकास को मात्र आर्थिक उत्पादन से न जोड़कर उसके सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय पक्षों पर भी ध्यान देना चाहिए। पारिस्थितिक तन्त्र (Ecosystem) के अनुरूप विकास हेतु पर्यावरण को कम-से-कम हानि पहुँचाने वाली प्रौद्योगिकी का विकास, जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का नियोजित (Planned) व नियमित उपभोग, संसाधन

TOUCH 'n PASS

संरक्षण (Resource conservation) आदि उपायों पर अमल करना होगा। चूँकि हमारा अस्तित्त्व पर्यावरण के साथ जुड़ा है अत: पर्यावरण को बचाते हुए सतत विकास की अवधारणा को विकसित करना समयानुकूल होगा।

अर्थशास्त्री रॉबर्ट सोलो (Robert Solow) के अनुसार, 'धारणीयता का कर्त्तव्य यह है कि भावी पीढ़ी को कोई विशेष वस्तु ही वसीयत में न दी जाये वरन् उनके लिये उन साधनों को जुटा दिया जाये, जो कम-से-कम उस अच्छे जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है, जो हमारा अपना है और उनकी अगली पीढ़ी को भी उसी रूप में देखा जाये।'

मानव विकास रिपोर्ट, 2011 में यह उल्लेख किया गया है कि धारणीय विकास की अधिकांश परिभाषायें इस बात पर जोर देती हैं कि भविष्य में लोगों के लिये उपलब्ध सम्भावनायें वर्तमान की तुलना में अलग नहीं होनी चाहिये, लेकिन प्राय: इसमें धारणीय मानव विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता। वे प्राय: चयन, स्वतन्त्रता और क्षमता के विस्तार का उल्लेख नहीं करते, जो मानव विकास के आन्तरिक घटक (Internal Component) हैं। मानव विकास स्वतन्त्रता और क्षमताओं का विस्तार है, जो व्यक्तियों को ऐसे जीवन के लिये चाहिये, जिसे वे मूल्यवान मानते हैं। स्वतन्त्रता और क्षमतायें जो हमें अर्थपूर्ण जीवन बिताने योग्य बनाती है, आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक महत्त्वपूर्ण होती हैं।

धारणीय विकास का मानवीय दृष्टिकोण (Outlook) इस बात पर जोर देता है कि व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वे जब जन्म ले तो निरंकुशता (Despotism) से प्रभावित न हों। इसके साथ ही समान जीवन स्तर की क्षमता ही न हो वरन् समान अवसर (Equal) भी मिलें। आज की पीढ़ी-भावी पीढ़ी से यह नहीं कह सकती कि वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने की अधिक क्षमता के बदले उन्हें प्रदूषित वायु में साँस लेनी होगी। यह भावी पीढ़ी को अधिक वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर स्वच्छ वायु के अधिकार से वंचित कर देगी।

मानव विकास दृष्टिकोण की केन्द्रीय चिन्ता सर्वाधिक असुविधापूर्ण या प्रतिकूल समूहों को संरक्षण देना है। सर्वाधिक असुविधापूर्ण पीढ़ी वह नहीं है, जो औसतन खराब स्थिति में है। इसमें वे भी शामिल हैं, जो हमारी क्रियाओं के परिणामस्वरूप विपरीत जोखिमों से सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

प्र.2. टिकाऊ विकास के लक्ष्य एवं कूटनीति का उल्लेख कीजिए।
Describe the objectives and diplomacy of sustainable development.

उत्तर

टिकाऊ विकास के लक्ष्य
(Objectives of Sustainable Development)

ब्रेटलैण्ड आयोग के अनुसार टिकाऊ विकास या धारणीय विकास के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं—

(1) वृद्धि को पुनरुज्जीवित करना, (2) वृद्धि के स्वरूप को बेहतर बनाना, (3) रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल और स्वच्छता जैसी मूलभूत (Fundamental) आवश्यकताओं की पूर्ति, (4) जनसंख्या को इतना ही रखना कि उसका पोषण (Nutrition) स्थायी तौर पर हो सके, (5) संसाधन स्रोतों का संरक्षण एवं परिवर्द्धन करना, (6) प्रौद्योगिकी को नई दिशा देना तथा खतरों के लिए उपाय करना, (7) नीतिगत निर्णयों में पर्यावरण एवं अर्थशास्त्र का समन्वय करना।

संक्षेप में, पारिस्थितिक विकास ही टिकाऊ विकास का आरम्भ बिन्दु है। विकास के इस आयाम का पक्ष संसाधनों की निरन्तर प्राप्ति एवं पुनर्चक्रण से सम्बन्धित है, जिससे संसाधन की उपलब्धता भविष्य में भी बनी रहे। वास्तव में विकास की परिकल्पना वर्तमान उपभोग स्तर को बनाए रखने तथा भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने से सम्बन्धित है। इस तरह, संविकास पारिस्थितिक तन्त्र के सम्वर्द्धन एवं अनुसंरक्षण को प्रोत्साहित करता है साथ ही, तकनीकी प्रत्यावर्तन इसके मूल में है, जिससे मानव तकनीकी प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप, संसाधनों के साथ सन्तुलित गत्यात्मक (Movable) सम्बन्ध स्थापित कर सके। अतएव धारणीय अथवा सततीय विकास का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को बदतर बनाए बिना पर्यावरणीय, मानवीय एवं भौतिक पूँजी भण्डार को सुरक्षित रखते हुए इसमें वृद्धि करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

धारणीय विकास की कूटनीति (Strategy of Sustainable Development)

धारणीय विकास की कूटनीति निम्नलिखित सिद्धान्तों पर अवलम्बित है—

1. मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना।
2. सामाजिक उन्नति जो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पहचानती है।
3. जीवन को सभी रूपों का आदर, सम्मान और देखभाल करना।
4. जैव विविधता (Biodiversity) का संरक्षण करना।

5. प्राकृतिक संसाधनों का विवेक के अनुसार उपयोग करना।
6. पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में बदलाव लाना।
7. आर्थिक विकास एवं रोजगार के उच्च एवं स्थिर स्तर को बनाए रखना।
8. प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास (Depreciation) में कमी लाना।
9. समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना।

प्र.3. हम धारणीय विकास कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उल्लेख कीजिए।
How can we attain sustainable development? Describe it.

उत्तर

धारणीय विकास
(Sustainable Development)

धारणीय विकास की सभी परिभाषाएँ, समस्त विश्व को एक मान कर चलने की आवश्यकता के बारे में बताती हैं। आप पहले ही जान चुके हैं कि धारणीय विकास की अवधारणा एक दीर्घकालीन अवधारणा है जो भावी पीढ़ियों के विकास को भी समान महत्त्व देती है। धारणीय विकास इस बात पर भी बल देता है कि विश्व के किसी एक भाग में की गई कार्यवाही और उपायों का विश्व के अन्य भागों में रहने वाले लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। विकास के धारणीय होने के लिये हमें न केवल अपने समाज अथवा गाँव अथवा देश बल्कि सारे विश्व के बारे में सोचना चाहिये। उदाहरण के लिये यदि उत्तरी अमरीका में फैक्ट्रियों से धुआँ निकलता है तो उत्तरी अमरीका से वह वायु प्रदूषण एशिया में वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इसी प्रकार, बंगला देश में कीटनाशकों का छिड़काव पश्चिमी बंगाल के समुद्र तट से भी मछलियों के स्टाक को हानि पहुँचा सकता है।

इसलिये धारणीय विकास के उपाय उन नीतियों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं जिन्हें समस्त विश्व में ग्रहण किया जाना चाहिये। इनमें से कुछ नीतियों को व्यक्तिगत देशों की सरकारों के स्तर पर लागू किया जाता है जबकि अन्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल (Combination) की आवश्यकता होती है।

उन विधियों के कुछ उदाहरण जिनके द्वारा हम धारणीय विकास में योगदान दे सकते हैं, नीचे दिये गये हैं—

1. **संसाधन**—गैर-नवीकरणीय संसाधनों के स्थानापन्न ढूँढ़ना तथा नवीकरणीय संसाधनों का युक्ति-संगत (Retionalize) प्रयोग करना। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति, ज्वार ऊर्जा तथा जैविक ईंधन (गोबर गैस) का प्रयोग अब व्यापक तौर पर ऊर्जा के स्रोतों जैसे कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैस, जिनका तीव्रगति से क्षय (Decay) हो रहा है, के स्थान पर हो रहा है। भारत के अनेक गाँवों में सौर ऊर्जा के उपकरणों जैसे सौर-कुकर, सौर-लालटेन तथा सौर-हीटर के उपयोग को सरकार द्वारा बढ़ावा तथा प्रोत्साहित किया जा रहा है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में बिजली का उत्पादन करने के लिये पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है।
2. **पुनर्चक्रीकरण**—दोबारा प्रयोग करना, पुन: संसाधित करना। कागज बनाने के लिये हमें लकड़ी के गूदे की आवश्यकता होती है जो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। इसलिये प्रयोग किये कागज के पुनर्चक्रीकरण द्वारा हम पेड़ों को काटने से बचाने में योगदान दे सकते हैं। जल एक दुर्लभ संसाधन है तब भी हम जल का न्यायोचित प्रयोग नहीं करते। हम वर्षा जल को इकट्ठा करके वर्षा जल का पुन: प्रयोग कर सकते हैं।
3. **कम करके**—कम प्रयोग करना अथवा अल्प व्यय करना। हमारा उपभोग हमारी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने तक सीमित होना चाहिये। स्थानीय बाजार तक जाने के लिये वाहन के प्रयोग के स्थान पर हम पैदल जा सकते हैं अथवा लिफ्ट द्वारा ऊपर जाने के स्थान पर सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। जिनकी हमें आवश्यकता न हो उन पंखों तथा रोशनी के उपकरणों को बंद कर सकते हैं।

प्र.4. भारत में धारणीय विकास विषयक प्रयास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on sustainable development efforts in India.

उत्तर

भारत में धारणीय विकास विषयक प्रयास
(Sustainable Development Efforts in India)

SNA विधि में देश के राष्ट्रीय लेखे में प्राकृतिक संसाधनों के योगदान को समाहित नहीं किया जाता किंतु हरित लेखांकन विधि इस त्रुटि को दूर कर सकती है। घरेलू उत्पाद के पर्या समंजित अनुमान ऐसी विकास नीतियाँ अपनाने में सहायक रहते हैं जो आर्थिक संवृद्धि के क्रम में अतिशय प्राकृतिक संसाधन विदोहन से बचते हुए आय के स्तर की धारणीयता का संवर्धन करती है।

Touch 'n' PASS

GDP और पर्या समंजित GDP के अंतर संसाधन क्षय और पतन का परिमाण स्पष्ट करते हुए उपयुक्त नीतियाँ अपनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं। भारत ने प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (NRA) में अध्ययन कार्य प्रारंभ कर दिये हैं ताकि अंतत: देश में हरित GDP का आंकलन किया जा सके। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) ऐसी विधि पर कार्य कर रहा है जिससे विभिन्न राज्यों में भूमि, जल, वायु और भूमिगत संपदाओं में निहित प्राकृतिक संसाधनों को व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय लेखांकन में स्थान दिया जा सके। हरित भारतीय राज्य न्यास (GIST) द्वारा हाल ही में सभी राज्यों के वार्षिक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़ों का ऊपर से नीचे की ओर समंजन करने वाले आर्थिक प्रतिमान निर्धारित करने के प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। उक्त अध्ययन का लक्ष्य 'वास्तविक मूल्य वृद्धि' का आकलन है और आशा है कि यह राष्ट्रीय एवं राज्य संपदा के अभी तक अछूत रहे गए आयामों तथा उत्पादन की इस प्रकार समीक्षा करने के संगतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मूल्यांकन मानकों का निर्धारण कर पायेगी जो नीति विश्लेषण (Analysis) में उपयोगी रहेंगे।

फिर भी अभी तक भारत में प्राकृतिक संसाधनों का राष्ट्रीय आय में लेखा करने के प्रयास धारणीय विकास की उपयुक्त नीतियाँ बनाने के लिए वांछित स्तर तक नहीं पहुँच पाए हैं। इसके लिए पर्या संसाधनों के मूल्यांकन (Evaluation) की बेहतर तकनीकों की पहचान लिए शोध-अन्वेषण को तीव्र करना होगा। इस संदर्भ में अधिक गंभीरता लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी आवश्यक है। पर्या लेखांकन पर भी आर्थिक लेखांकन जितना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ उन सूचकों का निर्माण उपयोगी होगा जो प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन विशेष के ह्रास का मूल्यांकन सुझा सके।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. धारणीय विकास के संकेतकों का वर्णन कीजिए।

Describe the indicators of sustainable development.

उत्तर

धारणीय विकास के संकेतक
(Indicators of Sustainable Development)

धारणीय विकास की धारणा बहुआयामी (Dimensional) पर्यावरण प्रबन्धन को इंगित (Indicate) करती है। विकास की इस अवधारणा में स्थानीय पर्यावरण एवं उससे सम्बन्धित प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय हित में प्रयोग इस तरह किया जाए कि प्रकृति की गुणवत्ता का ह्रास न हो साथ ही विकास के कार्यों में किसी तरह की बाधा भी न आये। इस तरह धारणीय अथवा टिकाऊ या सतत विकास के अन्तर्गत पर्यावरण एवं समाज के हितों के अनुकूल विकास के कार्यक्रमों को योजनाबद्ध रूप में निर्मित कर क्रियान्वित किया जाता है। धारणीय विकास के मुख्य संकेतक निम्नलिखित हैं—

धारणीय कृषि विकास—धारणीय कृषि विकास में रासायनिक उर्वरकों एवं खतरनाक कीटनाशकों (Germicide) के स्थान पर जैव उर्वरकों एवं जैव कीटनाशकों का प्रयोग कर कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति को भविष्य में भी बनाए रखना सम्भव होगा और मृदा में जो खतरनाक रसायन प्रवेश कर उसे प्रदूषित करते हैं उससे मुक्ति मिलेगी।

धारणीय औद्योगिक विकास—धारणीय औद्योगिक विकास के अन्तर्गत उद्योगों को प्रदूषण फैलाने से मुक्त रखने का प्रयास किया जाता है। विकासशील देशों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया में वृहत् उद्योग, मध्यमस्तरीय उद्योग एवं लघु उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ऐसे उद्योगों की स्थापना प्राय: नगरों में एवं बस्तियों के आस-पास की जाती है जिससे नगरों एवं बस्तियों के लोग इन उद्योगों द्वारा फैलाए जाने प्रदूषणों का शिकार बनते हैं। इन उद्योगों में प्रदूषण के शमन से सम्बन्धित संयन्त्र नहीं लगाए जाते। धारणीय विकास के अन्तर्गत ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाती है जो उपभोक्ता एवं पूँजी वस्तुओं का निर्माण तो करें, परन्तु वस्तु की कीमत पर समाज को प्रदूषण का तोहफा न दें। इस दृष्टि से उद्योगों के स्थापना के साथ ही उनमें प्रदूषण उपशमन यन्त्र भी लगाया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को कानून बनाकर उसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए साथ ही बड़े और हानिकारक रसायन (Chemical) उत्पाद उद्योगों को बस्ती और शहरों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। इन उद्योगों के आस-पास वृक्षारोपण कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए वृक्ष प्रदूषण एवं शोर गुल को सोखकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं।

प्रदूषण मुक्त परिवहन—प्रदूषण मुक्त परिवहन धारणीय विकास का एक अन्य संकेतक है। अल्पविकसित देशों में परिवहन के साधन के रूप में स्कूटर, मोटर साइकिलों, कारों, बसों, ट्रकों एवं रेलों, वायुयान एवं जलपोतों का उपयोग होता है, जो हानिकारक धुएँ का उत्सर्जन कर वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को फैलाते हैं। अत: धारणीय विकास के अन्तर्गत परिवहन के ऐसे साधनों का विकास

किया जाना चाहिए जो साइलेन्सर युक्त हों तथा विषैली गैसों का उत्सर्जन (Emission) न करें। विकसित देशों में किए जा रहे ऐसे प्रयास को विकासशील देशों में भी अपनाया जाना चाहिए।

प्रदूषण मुक्त ऊर्जा उत्पादन—प्रदूषण मुक्त ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना भी सततीय विकास का एक सूचक है। ऊर्जा के परम्परागत स्रोत (Traditional Sources) कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ हैं। इन दोनों साधनों से विद्युत उत्पादन करने पर पर्यावरण के प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है। अत: ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रदूषण मुक्त पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए, साथ ही गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि) के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

जनसंख्या नियन्त्रण—अल्पविकसित देशों में अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि गरीबी एवं पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देने का कार्य करती है, अत: टिकाऊ धारणीय विकास के लिए जनसंख्या नियन्त्रण विकासशील देशों की अनिवार्य आवश्यकता है।

पर्यावरणीय धारणीयता—इस सन्दर्भ में मानव विकास रिपोर्ट 2011 में निम्न सूचकांकों (Indexes) का उल्लेख किया गया है—

1. धारणीयता की संयोजित (Composite) माप—(अ) समायोजित शुद्ध बचत, (ब) पारिस्थितिकी पदचिह्न (Ecological Footprint), (स) पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक।
2. प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति (अ) जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels), (ब) पुनरुत्पादनीय।
3. कार्बन-डाइ-आक्साइड उत्सर्जन (Emission of CO_2) (अ) प्रति व्यक्ति टन, (ब) औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि।
4. प्रदूषण—(अ) प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, (ब) शहरी प्रदूषण—माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर।
5. प्राकृतिक संसाधन अवक्षय एवं जीव-विविधता—(अ) प्राकृतिक संसाधन अवक्षय, (ब) शुद्ध पानी का प्रयोग, (स) वन क्षेत्र, (द) वन क्षेत्र में परिवर्तन, (य) संकट में पड़ी प्रजाति।

पर्यावरणीय खतरों से मानव विकास पर प्रभाव—इस सन्दर्भ में मानव विकास रिपोर्ट 2011 में निम्न सूचकांकों का उल्लेख किया गया है—

1. 5 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या (अ) विकास-रुद्धता से पीड़ित, (ब) क्षयकारक से पीड़ित।
2. प्राकृतिक विनाशों का प्रभाव—(अ) मृतकों की संख्या-प्रति दस लाख व्यक्तियों पर वार्षिक औसत, प्रभावित जनसंख्या प्रति दस लाख व्यक्तियों पर वार्षिक औसत।
3. प्रति दस लाख व्यक्तियों पर मृत्यु—(अ) जल प्रदूषण, (ब) आन्तरिक वायु प्रदूषण, (स) बाह्य वायु प्रदूषण, (द) मलेरिया, (य) डेंगू के कारण।
4. खराब भूमि में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत।

प्र.2. धारणीय विकास की नीतियों का वर्णन कीजिए।
Describe the policies for sustainable development.

उत्तर

धारणीय विकास की नीतियाँ
(Policies for Sustainable Development)

कृषि एवं औद्योगीकरण की प्रगति, नगरीकरण एवं जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ आधारभूत संरचना का विस्तार होने के फलस्वरूप पर्यावरणीय अपकर्षण बढ़ रहा है। पर्यावरणीय आकर्षण देश के निवासियों के स्वास्थ्य पर गम्भीर प्रभाव डाल रहा है। इससे आर्थिक उत्पादकता और अन्य सुविधाओं की हानि का खतरा उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण पर आर्थिक विकास के हानिकारक प्रभाव को आर्थिक एवं पर्यावरणीय नीतियों के विवेकपूर्ण चुनाव तथा पर्यावरणीय निवेशों द्वारा कम किया जा सकता है। नीतियों एवं निवेशों के बीच चुनाव का उद्देश्य आर्थिक विकास तथा धारणीय विकास में सामंजस्य (Combination) स्थापित करना है। इस सम्बन्ध कुछ नीति उपाय निम्नलिखित हैं—

1. **गरीबी दूर करना** (Reducing Poverty)—गरीबी दूर करने तथा रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करने वाले कार्यक्रम (Program) प्रारम्भ किए जाने चाहिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं बाल विकास कार्यक्रम, परिवार नियोजन सेवाओं और शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे गरीबी के कम होने के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि में भी कमी आए। पुन: शुद्ध पेय जल की आपूर्ति, स्वच्छता की सुविधाएँ, गंदी बस्तियों (Dirty settlements) के स्थान पर वैकल्पिक आवास जैसी नागरिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए किए जाने वाले निवेश से लोक कल्याण में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही पर्यावरण (Environment) में भी सुधार होगा।

TOUCH 'n' PASS

2. **सब्सिडी हटाना** (Removing Subsidies)—सरकार द्वारा शुद्ध वित्तीय लागत पर ही नहीं, बल्कि पर्यावरण अवनयन कम करने के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा संसाधन प्रयोग के लिए दी जाने वाली सब्सिडियों को समाप्त किया जाना चाहिए। विद्युत्, उर्वरक, कीटनाशक, डीजल, पेट्रोल, गैस, सिंचाई, पानी आदि के प्रयोग पर सब्सिडी देने से इन पर फिजूलखर्ची एवं पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। पूँजी गहन एवं अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले निजी और सार्वजनिक उद्योगों के लिए सब्सिडी देने से पर्यावरण अपकर्षण होता है। सब्सिडी को हटाने या घटाने से देश को आर्थिक एवं पर्यावरणीय दोनों लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
3. **नियामक नीतियाँ** (Regulatory Policies)—नियामक नीतियाँ भी पर्यावरणीय अपकर्षण को कम करने में सहायक होती हैं। नियामकों को कीमत, मात्रा और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय-निर्माण में उन्हें परिमाण या प्रदूषण की कीमत या संसाधन प्रयोग या तकनीकों में से चुनाव करना पड़ता है। नियामक अधिकारी को यह भी निर्णय लेना होता है कि पर्यावरणीय समस्या के लिए नीतियाँ प्रत्यक्ष हों अथवा अप्रत्यक्ष हों। वह तकनीकी मानकों (Technical Parametres) एवं नियामकों तथा जल, वायु तथा भूमि प्रदूषकों पर शुल्क निर्धारित करता है। नियामकों को सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के प्रदूषकों या संसाधन प्रयोगकर्त्ताओं के लिए पर्यावरणीय मानकों को लागू करने में भेदभाव (Discrimination) नहीं करना चाहिए।
4. **आर्थिक प्रोत्साहन** (Economic Incentives)—आर्थिक प्रोत्साहन कीमत, मात्रा एवं तकनीक से सम्बन्धित हो सकते हैं। प्रोत्साहन सदैव वायु, जल, भूमि के प्रयोग में प्रदूषकों की मात्रा हेतु संसाधन प्रयोगकर्त्ताओं के लिए परिवर्तनीय शुल्कों के रूप में होते हैं। यदि निर्धारित उत्सर्जन मानकों (emission standards) से कम प्रदूषण उत्पन्न किए जाते हैं, तब उन्हें छूट (Rebate) प्रदान की जाती है।
5. **सम्पत्ति अधिकारों को स्पष्ट करना एवं बढ़ाना** (Clarifying and Extending Property Rights)—संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग पर सम्पत्ति अधिकारों के अभाव में पर्यावरण का अवनयन होता है। इससे सामूहिक या सार्वजनिक भूमियों पर अति चराई, वन-कटाई एवं खनिजों आदि का अधिक शोषण (Exploitation) होता है। लोगों को मालिकाना अधिकार देने और काश्तकारी अधिकारों के स्पष्टीकरण करने से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान हो सकता है। ऐसे स्थानों पर जहाँ भूमि, वन, सिंचाई प्रणाली मत्स्य पालन (Fishery) आदि के सामूहिक प्रयोग को नियमित किया जाता है और समुदाय द्वारा इनके प्रयोग हेतु सुविचारित नियम बनाए जाते हैं, वहाँ मालिकाना अधिकारों का प्रशासनिक अभिलेखों में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
6. **बाजार आधारित पद्धतियाँ** (Market Based Approaches)—पर्यावरण संरक्षण हेतु नियामक उपायों के अलावा बाजार आधारित पद्धतियों को अपनाए जाने की महती आवश्यकता है। इनका उद्देश्य पर्यावरण पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग करने की लागत के विषय में उपभोक्ता एवं उद्योगों को जाग्रत करना है। ये लागतें (Costs) वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए चुकाई गई कीमतों में प्रतिबिम्बित (Reflected) होती हैं, जिससे उद्योग और अंततः उपभोक्ता वायु, जल आदि के प्रदूषण को कम करने के लिए उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं।
   बाजार आधारित उपकरणों (Market Based Instruments) की धारणा का प्रयोग विकसित तथा विकासशील दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं में प्रयोग की गई हैं। MBIs दो प्रकार के होते हैं—परिणाम आधारित तथा कीमत आधारित। ये पर्यावरणीय करों के रूप में होते हैं, जिसमें प्रदूषण शुल्क (उत्सर्जन कर/प्रदूषण कर), विक्रय परमिट, जमाकर्त्ता निधि प्रणाली, आगत कर, वस्तु शुल्क, विभेदक कर दरें और प्रयोगकर्त्ता प्रशासनिक शुल्क और वायु एवं जल संसाधनों के लिए प्रदूषण कम करने वाले उपकरण के लिए सब्सिडियाँ (Subsidies) शामिल हैं।
7. **व्यापार नीति** (Trade Policy)—पर्यावरण से सम्बन्धित व्यापार नीति के दो निहितार्थ हैं—प्रथम, घरेलू नीति सुधारों से सम्बन्धित तथा द्वितीय, विदेशी व्यापार नीति से सम्बन्धित। घरेलू व्यापार नीति नगरों से दूर कम प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना और प्रदूषणकारी उद्योगों में परिशोधन तकनीक अपनाकर पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं पर बल देती है।
   जहाँ तक विदेशी व्यापार तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच सम्बन्ध की बात है, यह विवादित है कि उदारीकृत व्यापार पर्यावरणीय अपकर्षण का कारण तो नहीं है। निष्कर्ष रूप में, यह कहा जा सकता है कि 'कुल मिलाकर, व्यापार

TOUCH 'n PASS

उदारीकरण से ऋणात्मक पर्यावरणीय बाह्यताएँ उत्पादित होने की सम्भावना है, परन्तु इससे कुछ पर्यावरणीय लाभ के होने की भी सम्भावना है।' इसका तात्पर्य यह नहीं है कि स्वतन्त्र व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए, बल्कि ऐसी लागत-प्रभावी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए, जो बाह्यताओं को अनुकूलतम कर सकें। स्वतन्त्र व्यापार से पर्यावरणीय अपकर्षण 'प्रदूषक भुगतान सिद्धान्त ' पर आधारित घरेलू नीति उपाय द्वारा कम किया जाना चाहिए। उचित यह होगा कि विदेशी कम्पनी पर स्पष्ट तकनीक स्थानांतरित करने के लिए तथा चालू उद्योगों के लिए पर्यावरण स्वच्छ करने में सहायता देने के लिए बल दिया जाए।

8. **सार्वजनिक सहभागिता** (Public Participation)—सार्वजनिक जागरूकता एवं सहभागिता पर्यावरणीय दशाओं को सुधारने में अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हो सकती है। पर्यावरण प्रबन्धन और पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रमों से सम्बन्धित औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा का संचालन पर्यावरणीय अवनयन को नियन्त्रित करने एवं पर्यावरण स्वच्छ रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरणार्थ, पर्यावरण-प्रतीक लेबल लगाने की योजना उपभोक्ताओं को पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं की पहचान करने में सहायता करती है।
   सार्वजनिक सहभागिता वनारोपण, वन्य जीवों के संरक्षण, पार्कों के प्रबन्धन, सफाई व्यवस्था में सुधार जल-निकासी तथा बाढ़ प्रबन्धन में बिना लागत के तथा उपयोगी सहायता भी प्रदान करती है। स्थानीय संगठनों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा पर्यावरणीय अपकर्षण के हानिकारक प्रभावों तथा पर्यावरण स्वच्छ रखने के लाभों के विषय में जनता को शिक्षित तथा जागरूक करने में बहुत उपयोगी भूमिका निभाई जा सकती है।
9. **विश्व पर्यावरणीय प्रयासों में सहभागिता** (Participation in Global Environmental Efforts)—पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा पर कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं समझौते हुए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक देश के लिए अपेक्षित है। इनमें ओजोन कम करने वाले रसायनों को समाप्त करने के सम्बन्ध में मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol) तथा बैसेल सम्मेलन (Basel Convention) एवं रियो घोषणा (Rio Declaration) आदि सम्मिलित हैं। जैव विविधता संरक्षण या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से सम्बन्धित समझौतों का पालन नहीं करने वाले देशों के विरुद्ध व्यापार अनुमोदनों का खतरा होता है। वास्तव में, अभी भी कई देश इसका पालन नहीं कर रहे हैं।

प्र.3. धारणीय विकास की सैद्धांतिक संरचना की व्याख्या विस्तार से कीजिए।
Describe in detail principled structure of sustainable development.

उत्तर

सैद्धांतिक संरचना (रूपरेखा)
(Principled Structure)

अर्थतंत्र को निरंतर उत्पादन के लिए संगठनबद्ध रखने का विचार नया नहीं है। वान्यिकी एक मत्स्य पालन में कभी से प्राप्ति के धारणीय स्तरों को लेकर चिन्ताएँ विद्यमान रही हैं अर्थात् लकड़ी की कटाई और मछलियों को पकड़ने की दरों और उनके जैव भंडार की प्राकृतिक वृद्धि दरों के संतुलन बनाए रखना उनका मुख्य सरोकार रहा है। यदि संदर्भित संसाधनों के गत्यात्मक संवृद्धि वक्र का अच्छा ज्ञान हो (अर्थात् इनमें वृद्धि और कमी के क्रम किस प्रकार चलते हैं) तो धारणीय व्यवहार को अपनाना संभव हो सकता है।

भले ही अनेक संसाधन वृक्षों एवं मछलियों की भाँति पुन: नवीकृत हो जाते हों फिर भी अर्थव्यवस्था केवल नवीकरणीय साधनों पर निर्भर नहीं रहती। अत: धारणीयता का एक अर्थ यह भी होगा कि गैर-नवीकरणीय संसाधनों के मौलिक भण्डार के दुर्लभ हो जाने से पूर्व ही उनके स्थानापन्नों (Subsitutes) का विकास कर लेना चाहिए। इसका यह भी अर्थ है कि संसाधन प्रयोग के पर्या प्रभावों को पृथ्वी की उस धारण क्षमता तक ही सीमित रखना चाहिए जो इन प्रभावों को आत्मसात् करने में समर्थ हों। इस संदर्भ में धारणीय विकास के विचार के बहु-विषयी आयामों पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

धारणीय विकास का बहु-विषयी स्वरूप

धारणीय विकास की संकल्पना मूलरूप से ही बहुविषयी है। इस अवधारणा की शब्दावली केवल पर्यासंसाधनों के ह्रास से संबंधित आर्थिक आशंकाओं से विकसित नहीं हुई वस्तुत: सोलो ने अंतरपीढ़ी समता या न्याय का प्रश्न भी इसी के साथ जोड़ दिया है। दूसरे शब्दों में, केवल अर्थशास्त्र तक सीमित दृष्टिकोण को धारणीय विकास के सभी सरोकारों के साथ संपूर्ण दृष्टि से न्याय करने में

TOUCH 'n' PASS

सक्षम नहीं पाया गया। इसी संदर्भ में पर्यावरण और उसके विभिन्न भू-भौतिक उप-तन्त्रों के व्यवहार को समझना अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गया है। अत: संसाधन उपभोग प्रक्रिया की संरचना की प्रकृति (आर्थिक संवृद्धि और विकास क्रम में) को समझ लेना आवश्यक है, ताकि धारणीय विकास के अनेक मापकों के विकास की प्रक्रिया को सटीक रूप से समझा जा सके। यह संरचनात्मक प्रकृति आर्थिक विकास में सहायक पर्यातंत्र के गैर-रैखिक, सुदृढ़ और अप्रत्यावर्ती आयामों के रूप में निरूपित होती है।

संरचनात्मक प्रत्यक्ष दर्शन

धारणीय विकास में निहित संरचनात्मक स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन इसके गैर-रैखिक, अप्रत्यावर्ती और लचीलेपन के आयामों में होता है।

गैर-रैखिकता—हमारे ग्रह पृथ्वी पर अधिकांश घटनाक्रम (चाहे जनसंख्या की वृद्धि हो या चक्रवृद्धि दर पर ब्याज की) गैर-रैखिक व्यवहार दर्शाते हैं। पर्या परिवर्तन न तो बहुत धीमा होता है और न ही यह निरंतर चलता रहता है। विशेषकर जीवशास्त्रीय संवृद्धि क्रम तो निरंतर चलता रहता है किंतु जब पतन या विनाश का समय होता है तो वह अकस्मात ही हो पाता है। गैर-रैखिकता का एक अन्य उदाहरण विषाक्त आदानों के ग्रहण और उनके जीवधारियों एवं जीवाणुओं पर प्रभाव है। यही नहीं, जब पर्यावरण के उतार-चढ़ाव होते हैं तो किसी जैविक प्रकार 'भेद-W' के स्वास्थ्य स्तर को ज्यामितिक औसत द्वारा ही दिखाया जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि X_i, प्रत्येक पर्या तंत्र N में स्वस्थता का स्तर है तो औसत स्वस्थता स्तर होगा—

$$W = N \sqrt{\overset{N}{\underset{i=1}{\Pi}} X_i \; .... i = 1 .... N}$$

पर्यातंत्रों में गैर-रैखिक व्यवहार की समझ उन तंत्रों को प्रभावित करने वाली विभिन्न नीतियों के गुणों और त्रुटियों को समझ पाने के लिए आवश्यक है। उदाहरणार्थ—(i) समय-समय पर होने वाले यादृच्छिक परिवर्तन नाटकीय व्युत्क्रमों को आरंभ कर पूरे तंत्र के विकास पथ को बदल सकते हैं; (ii) धीमे-धीमे चल रही प्रक्रियाएँ संकुलित रूप से स्थायी संबंधों के क्षेत्र को ध्वस्त कर तंत्र को एक नियंत्रक प्रक्रिया व्यवस्था से विचलित कर किसी अन्य में पहुँचा देती हैं। इसी तरह जब अम्लीय वर्षा के प्रभाव से एक वन्य पर्यातंत्र धीरे-धीरे ह्रासगत होता है तो सारा वन निश्चित रूप से धीमे-धीमे विनाश की ओर चला जाता है। यही नहीं, जीवाश्मीय ईंधन की खपत भले ही कुछ रैखिकता दर्शा रही हो इसका पर्या प्रदूषण पर प्रभाव प्राय: रैखिक नहीं रहता।

अप्रत्यावर्तनीयता—विभिन्न पर्यातंत्रों में संतुलन को प्रभावित करने वाली गतिविधियों का संचयी प्रभाव गैर- रैखिकताओं के साथ-साथ अप्रत्यावर्तनीयताओं (अर्थात् जैविक विविधता एवं प्रजातियों के विलोपन) को भी जन्म देता है। एक उदाहरण तो पर्यावरण की प्रदूषण को धारण एवं आत्मसात कर लेने की क्षमता ही है। इसमें गैर-रैखिकता एवं अप्रत्यावर्तनीयता समाहित हैं। भले ही, हरितगृह गैसें (GHGs) तकनीकी दृष्टि से समय व्यतीत होने पर प्रत्यावर्तनीयता दर्शाती हों किंतु इन गैसों की गहनता में कमी आने से पूर्व पर्यातंत्र को अप्रत्यावर्तनीय हानि पहुँच चुकी होती है।

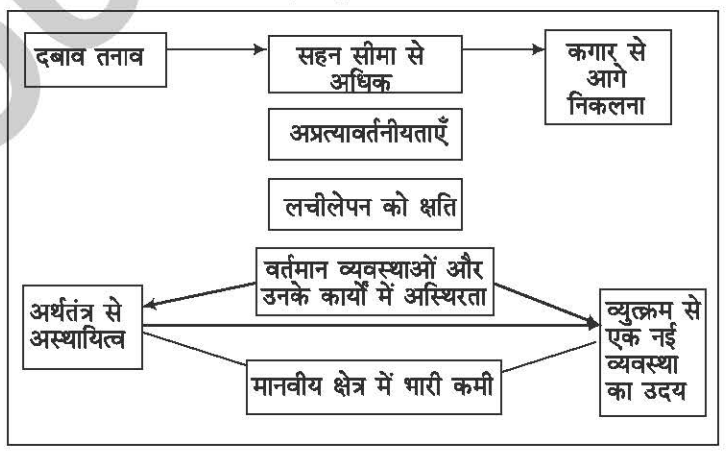

चित्र : लचीलेपन और मानवीय क्षेम की परस्पर निर्भरता

TOUCH-N-PASS

लचीलापन—यह किसी व्यवस्था की विसंगति सहन करने की क्षमता है—इसमें किसी सीमा तक अनुकूलन कर जाने का तत्त्व भी समाहित होता है। किंतु जब विसंगतियाँ या बाहरी प्रभावों की गहनता उस सहन सीमा से अधिक हो जाती हैं तो फिर यह लचीलापन समाप्त हो जाता है। यह सहन कर पाने की सीमाएँ विभिन्न प्रजातियों एवं जीवाणुओं में अलग-अलग होती हैं और इसी कारण इनके लिए किसी सांझे गुणांक का प्रयोग नहीं हो पाता। यह लचीलेपन की हानि ही संपूर्ण व्यवस्था को एक कगार तक ले जाती है वह (उससे) व्युत्क्रम—अर्थात् किसी अन्य संतुलन की ओर अग्रसर हो जाता है। सीधे-सीधे तो लचीलेपन का अर्थ किसी व्यवस्था या तंत्र की व्याघात सहन कर उन्हें आत्मसात् कर लेने की क्षमता है। 'पर्यातंत्र लचीलापन' द्वारा मापित (यह मान) पर्या-धारणीयता का एक उपयोगी सूचक बन जाता है। यदि मानवीय गतिविधियों को धारणीय बने रहना है तो पर्यावरण व्यवस्था में लचीलापन भी बना रहना चाहिए। 'पर्या लचीलेपन' की किसी भी क्षति का अर्थ है वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए सुलभ विकल्पों में अप्रत्यावर्तनीय बदलाव आ सकते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. धारणीय (टिकाऊ) विकास से अर्थ है–
(क) बिना पर्यावरण को हानि पहुँचाये जीवन की गुणवत्ता जारी रखना
(ख) प्राकृतिक साधनों का सर्वाधिक विदोहन करना
(ग) संसाधन संरक्षण पर कोई ध्यान न देना
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर (क) बिना पर्यावरण को हानि पहुँचाये जीवन की गुणवत्ता जारी रखना

प्र.2. ब्रंटलैण्ड प्रतिवेदन किस विषय पर है?
(क) जनसंख्या नियन्त्रण पर (ख) धारणीय/टिकाऊ विकास पर
(ग) उद्योगों पर (घ) खनन पर

उत्तर (ख) धारणीय/टिकाऊ विकास पर

प्र.3. धारणीय विकास के घटक हैं–
(क) धारणीय कृषि विकास (ख) औद्योगिक विकास
(ग) जनसंख्या वृद्धि (घ) परिवहन विकास

उत्तर (क) धारणीय कृषि विकास

प्र.4. सस्टेनेबल डिवेलपमेंट (सतत विकास) का सबसे अच्छा कारण क्या है?
(क) रिबूट (ख) रीयूज
(ग) रीसायकल (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.5. निम्नलिखित में से कौन-सा एक कार्यकलाप लघु विकास के लिए उत्तरदाई हो सकता है?
(क) कारपूल
(ख) बिजली बचाओ पानी बचाओ
(ग) वैज्ञानिक औद्योगिक उद्यम विकसित जिसमें प्राकृतिक दोहन कम हो/न हो
(घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (ग) वैज्ञानिक औद्योगिक उद्यम विकसित जिसमें प्राकृतिक दोहन कम हो/न हो

प्र.6. निम्नलिखित में से किस कारण से चॉकलेट के डाइसेक्शन पर रोक लगाई गई?
(क) पर्यावरण की खाद्य सामग्री डिस्टर्ब होने लगी थी
(ख) विश्ववासियों की जनसंख्या कम हो रही है इसे लेकर मास्को तक की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी
(ग) यह एक विशेष साध्य कार्य था
(घ) इसके स्थान पर आर्टिफिशियल स्टॉक प्रयोग किया जाने लगा

उत्तर (ख) विश्ववासियों की जनसंख्या कम हो रही है इसे लेकर मास्को तक की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी

TOUCH 'n' PASS

प्र.7. निम्नलिखित में से एक ऊर्जा का अक्षय स्त्रोत कौन-सा है?

(क) दार्शनिक द्वारा बिजली बनाना (ख) पवन चालकों का प्रयोग जाना
(ग) सूर्य की किरण से पानी को गर्म करना (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.8. निम्नलिखित में से कौन-सा एक अनोखा प्रकार का विकास है?

(क) फैक्ट्री की चिमनियों को हटाना (ख) टन पर कार्बन पार्टिकल विशेष लगा देना
(ग) फैक्ट्रियों को बंद कर देना (घ) ये सभी

उत्तर (ख) टन पर कार्बन पार्टिकल विशेष लगा देना

प्र.9. गंगा का जल विकास प्रक्रिया के साथ-साथ साफ होना चाहिए इसकी पुष्टि करने वाला वर्णन है?

(क) सामूहिक जल को संयंत्रों द्वारा पुनः आरंभ करके गंगा में प्रवाहित किया जाना चाहिए
(ख) उसमें डालने वाले नालों के जल को पहले प्लांट द्वारा साफ करने के बाद गंगा में रखना चाहिए
(ग) प्रोडक्शन प्लांट पर प्रतिबंध लगा दिया
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर (ख) उसमें डालने वाले नालों के जल को पहले प्लांट द्वारा साफ करने के बाद गंगा में रखना चाहिए

प्र.10. पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण की अति दोहन से सर्वाधिक क्षति क्या हुई है?

(क) उत्पाद को बढ़ावा मिलता है
(ख) जैव विविधता में कमी आई है
(ग) बायोलॉजिकल आवर्धन (जैविक आवर्धन) बढ़ा है
(घ) जन्म सातत्य कम हुई है

उत्तर (ख) जैव विविधता में कमी आई है

प्र.11. हमें प्राकृतिक निर्माण (प्राकृतिक संसाधनों) का मितव्ययिता से तथा विवेक से दोहन करना चाहिए क्योंकि–

(क) यह उपकरण सीमित है और समाप्त होने का खतरा है
(ख) हमारे पास वैकल्पिक उपकरण मौजूद हैं
(ग) सभी कार्य वैकल्पिक शिक्षक से हो रहे हैं
(घ) प्रदूषण का जन्म होता है

उत्तर (क) यह उपकरण सीमित है और समाप्त होने का खतरा है

प्र.12. सतत विकास की अवधारणा किसकी मांद है?

(क) ब्रेटलैंड आयोग (ख) सिम्थ आयोग (ग) विल्सन आयोग (घ) विल्हेम आयोग

उत्तर (क) ब्रेटलैंड आयोग

प्र.13. सतत विकास पर मानव पर्यावरण एवं स्टॉकहोम सम्मेलन भंडार हुआ–

(क) 1972 में (ख) 1980 में (ग) 1985 में (घ) 1987 में

उत्तर (क) 1972 में

प्र.14. गाँधी नहर (इंदिरा गांधी नहर) कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कारक कौन है?

(क) कृषि विकास (ख) परिवहन विकास
(ग) पारिस्थितिक विकास (घ) भूमि उपनिवेशन

उत्तर (ग) पारिस्थितिक विकास

प्र.15. पोषण विकास क्या है?

(क) आर्थिक विकास (ख) सामाजिक विकास (ग) पर्यावरण विकास (घ) ये सभी

उत्तर (क) आर्थिक विकास

TOUCH 'n PASS

प्र.16. सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया–

(क) 1985 में (ख) 1986 में (ग) 1987 में (घ) 1988 में

उत्तर (ग) 1987 में

प्र.17. सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है–

(क) उपयोगी के मुख्य उपयोग से (ख) संरक्षण से

(ग) साधन के औद्योगिक उपयोग से (घ) ऊर्जा उत्पादन के विकास से

उत्तर (ख) संरक्षण से

प्र.18. वह विकास एकॉस्क नवीन प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए जो–

(क) उत्पाद दे

(ख) प्रदूषण नगण्य करें

(ग) पर्यावरण को कम पहुँचाए

(घ) पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले और आगामी रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण को दंडित करने वाले

उत्तर (घ) पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले और आगामी रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण को दंडित करने वाले

प्र.19. सुस्थिर विकास का अर्थ है–

(क) तेजी से विकास (ख) औद्योगिक विकास

(ग) अच्छा विकास (घ) पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास

उत्तर (घ) पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास

प्र.20. उन्होंने विकास शब्द का प्रथम प्रयोग किया–

(क) कोकोयाक ने समय की घोषणा की (ख) स्टॉकहोम सम्मेलन में

(ग) पृथ्वी सम्मेलन द्वितीय (घ) पृथ्वी सम्मेलन प्रथम

उत्तर (क) कोकोयाक ने समय की घोषणा की

प्र.21. शून्य विकास रणनीति-1977 पुस्तक किसकी है?

(क) मिल्टन (ख) फ्रीमैन (ग) डेली (घ) नोगार्ड

उत्तर (ग) डेली

प्र.22. जैव विविधता सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है–

(क) वायुदाब (ख) जलवायु

(ग) उच्च वाचक (घ) मिट्टी

उत्तर (ख) जलवायु

प्र.23. बौद्ध धर्म रेखा सदाबहार वनों में सबसे अधिक पाई जाती है–

(क) जैव विविधता (ख) पर्यावरण विविधता

(ग) जातिगत विविधता (नस्लीय विविधता) (घ) तंत्र विविधता (सिस्टम विविधता)

उत्तर (ग) जातिगत विविधता (नस्लीय विविधता)

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VII

क्षेत्रीय विकास सूचक
Regional Development Indicators

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक विकास के प्राचीन मापदण्डों को बताइए।
State the ancient parameters of economic development.

उत्तर प्राचीन अर्थशास्त्रियों एवं विचारकों ने आर्थिक विकास के अलग-अलग मापदण्ड सुझाए हैं। वाणिकवादी अर्थशास्त्रियों ने किसी देश में उपलब्ध सोने-चाँदी की मात्रा और विदेशी व्यापार की मात्रा को आर्थिक विकास का सूचक माना। एडम स्मिथ तथा समकालीन अर्थशास्त्रियों में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का अधिक होना ही आर्थिक विकास माना है। कार्ल मार्क्स अधिकतम सामाजिक कल्याण के आधार पर समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना को ही आर्थिक विकास का मापदण्ड मानते हैं। जे. एस. गिल ने सहकारिता की स्थापना को ही आर्थिक विकास का मापदण्ड माना है।

प्र.2. किसी क्षेत्र के विकास का सूचक क्या है?
What is the indicator of development of any area?

उत्तर विकास के मुख्य सामाजिक संकेतकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दर और लैंगिक समानता शामिल हैं।

प्र.3. विकास सूचक का अर्थ क्या है?
What is the meaning of development indicator?

उत्तर मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) जीवन प्रत्याशा, शिक्षा (शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने पर स्कूली शिक्षा के पूरे वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष), और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है, जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के चार स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है।

प्र.4. क्षेत्रीय विकास से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by regional development?

उत्तर क्षेत्रीय विकास किसी देश के कुछ क्षेत्रों को विकसित करने के प्रयासों का लेबल है, विकास को आमतौर पर सामाजिक-आर्थिक अर्थ में समझा जाता है।

प्र.5. मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है?
What is the rank of India in Human development index 2023.

उत्तर श्रीलंका की रैंकिंग 73 और भारत 132 है। मानव विकास सूचकांक में नेपाल और पाकिस्तान को छोड़कर भारत बाकी पड़ोसी देशों से पीछे चला गया है। इस सूची में श्रीलंका 73वें स्थान पर है—चीन 79, भूटान 127, बांग्लादेश 129, नेपाल 143 और पाकिस्तान 161वें स्थान पर रहा।

प्र.6. भारत के किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है?
Which state of has the highest human index India?

उत्तर गोवा का मानव विकास सूचकांक भारत में सर्वोच्च है।

प्र.7. उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन-से है?
Which countries have high human development index?

उत्तर HDI में शीर्ष पाँच देश—रिपोर्ट के अनुसार, नॉर्वे मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है, इसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड का स्थान है।

TOUCH 'n PASS

प्र.8. मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दी थी?
Who gave the conception of Human Development Index?

उत्तर मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया।

प्र.9. पहला मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया था?
When did first Human Development Index issue?

उत्तर पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया।

प्र.10. मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है?
Who does issue Human development Index?

उत्तर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है।

प्र.11. मानव विकास सूचकांक में किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है?
Which indicators are used in Human Development Index?

उत्तर सूचकांक की गणना 3 प्रमुख संकेतक जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अंतर्गत की जाती है।

प्र.12. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme-UNDP) क्या है?
What is United nations Development Programme-UNDP?

उत्तर 1. UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है।
2. इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है।
3. UNDP गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है।
4. इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिये नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं एवं संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है।

प्र.13. मानव विकास सूचकांक में निचले स्थान पर कौन-से देश हैं?
Which countries have bottom place in Human Development Index?

उत्तर सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर क्रमशः नाइजर, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, चाड और बुरुंडी हैं।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मापदण्ड क्या है?
What is the PQLI?

उत्तर अर्थशास्त्रियों ने एक, दो अथवा अधिक संकेतकों के आधार पर मानव विकास के सम्मिश्र सूचकांकों के निर्माण के लिए मूल आवश्यकताओं के सामाजिक सूचकांकों को मापने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में मौरिस द्वारा विकसित जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक (Physical Quality of Life Index) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित मानव विकास सूचकांक (HDI) उल्लेखनीय हैं।

जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक (PQLI)—मौरिस ने 1979 में 23 विकसित एवं विकासशील देशों के जीवन की सम्मिश्र भौतिक गुणवत्ता (Composite Physical Quality of Life) का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने शिशु मृत्यु दर, एक वर्ष की आयु में जीवन सम्भाव्यता तथा 15 वर्ष की आयु में मूल शिक्षा जैसे तीन सूचक घटकों को, लोगों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने, के कार्य के मूल्यांकन (Evaluation) हेतु शामिल किया। इस सूचक से बहुत से सूचकों; जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पोषण तथा स्वच्छता आदि का पता चलता है। प्रत्येक सूचक के तीनों घटकों को शून्य से 100 तक के पैमाने पर रखा गया जिसमें शून्य को मन्दतम तथा 100 को सर्वोत्तम प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया गया है। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की गणना तीनों घटकों को समान भार प्रदान करते हुए औसत निकाल कर की जाती है और सूचक को भी शून्य से 100 के पैमाने पर रखा गया है। मौरिस के अनुसार तीनों सूचकों में से प्रत्येक सूचक परिणाम को मापता है न कि आगतों को जैसे—आय। प्रत्येक सूचक आवण्टन प्रभावों के प्रति संवेदनशील है अर्थात् इन सूचकों में वृद्धि अथवा सुधार से लोगों को उसी अनुपात में होने वाले लाभ का पता चलता है, परन्तु कोई भी सूचक विकास के किसी स्तर विशेष पर निर्भर नहीं होता। प्रत्येक सूचक की अन्तर्राष्ट्रीय तुलना की जा सकती है।

TOUCH n PASS

जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यद्यपि अल्पविकसित क्षेत्रों का पता लगाने और सामाजिक नीतियों की असफलता अथवा उपेक्षा के शिकार समाज के विभिन्न वर्गों की जानकारी प्राप्त करने में सहायक है फिर भी यह कहा जा सकता है कि यह (PQLI) मूल आवश्यकताओं को केवल एक सीमा तक ही माप सकता है। यह GNP का परिपूरक है न कि विस्थापक। इसके अतिरिक्त यह सामाजिक और आर्थिक संगठन के बदलते हुए ढाँचे को भी नहीं दर्शाता। इस तरह, यह आर्थिक विकास को नहीं मापता। यह कुल कल्याण को भी नहीं मापता। फिर भी यह जीवन की गुणवत्ता (Quality) को मापता है जो गरीबों के लिए बहुत जरूरी है।

प्र.2. लिंग सम्बन्धी विकास सूचकांक एवं क्रय शक्ति समता विधि का उल्लेख कीजिए।
Describe the gender related development index and purchasing power parity method.

उत्तर

लिंग-सम्बन्धित विकास सूचकांक
(Gender Related Development Index—GDI)

लिंग सम्बन्धित विकास सूचकांक पुरुषों एवं स्त्रियों में असमानता को दर्शाता है, जबकि मानव विकास सूचकांक औसत उपलब्धि की माप है। लिंग-सम्बन्धित विकास सूचकांक में जिन तीनों बातों को सम्मिलित किया जाता है वे हैं—(i) स्त्रियों में जन्म पर जीवन प्रत्याशा, (ii) स्त्री वयस्क साक्षरता एवं कुल नामांकन अनुपात (iii) स्त्री प्रति व्यक्ति आय।

लिंग असमानता विद्यमान न होने की दशा में मानव विकास सूचकांक और लिंग-सम्बन्धित विकास सूचकांक समान होंगे। यदि लिंग असमानता विद्यमान है तो लिंग सम्बन्धित विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक से कम होगा। इन दोनों में जितना अधिक अन्तर होगा, उतनी ही अधिक लिंग-असमानता होगी। मानव विकास रिपोर्ट की सूचनाओं के अनुसार अधिक लिंग-असमानता वाले देश हैं : सऊदी अरब, ईरान, भारत, मिस्र तथा नाइजीरिया। जिन देशों में लगभग लिंग-समानता विद्यमान हैं वे हैं-नॉर्वे, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूसी फेडरेशन, मलेशिया, वेनेजुएला, फिलीपीन्स, श्रीलंका, चीन, वियतनाम, आदि।

क्रय शक्ति समता विधि (Purchasing Power Parity Method)—आर्थिक विकास के मापक के रूप में क्रय शक्ति समता (PPP) विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने 1993 में किया था। वर्तमान में विभिन्न देशों के जीवन-स्तर की तुलना करने के लिए विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग करता है। इस विधि के अन्तर्गत किसी राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद को उस देश में प्रचलित मुद्रा की (अमेरिकी डॉलर के सन्दर्भ में) क्रय शक्ति के आधार पर व्यक्त किया जाता है।

प्र.3. मानव निर्धनता सूचकांक क्या है?
What is the Human Poverty Index (HIP)?

उत्तर

मानव निर्धनता सूचकांक
(Human Poverty Index-HPI)

मानव विकास रिपोर्ट 1997 द्वारा मानव निर्धनता सूचकांक की अवधारणा का विकास किया गया जो मानव जीवन के तीन अनिवार्य अंगों में पृथक्करण अथवा वंचन (Deprivation) पर ध्यान संकेन्द्रित करता है, जो मानव विकास सूचकांक में दृष्टिगोचर होती हैं—दीर्घ जीवन, ज्ञान एवं एक अच्छा जीवन स्तर।

सबसे प्रथम पृथक्करण अथवा वंचन अपेक्षाकृत कम आयु में मृत्यु सम्बन्धी दुर्बलता है और इस सूचकांक में इसका संकेत 40 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत से प्राप्त होता है। दूसरा वंचन ज्ञान से सम्बन्धित है और इसका माप वयस्कों में गैर-साक्षरों के प्रतिशत से प्राप्त किया जाता है। तीसरा वंचन अच्छे जीवन-स्तर से सम्बन्धित है। यह तीन चरों से सम्बद्ध है—जन सामान्य का प्रतिशत जिसमें (क) स्वास्थ्य सेवाएँ, (ख) शुद्ध पेय जल की उपलब्धता, (ग) पाँच वर्ष से कम आयु वाले कुपोषित बच्चों का प्रतिशत।

मानव विकास रिपोर्ट, 2010 में HPI के स्थान पर एक नया माप बहु आयामी अपनाया गया है। इस तरह, मानव निर्धनता सूचकांक में बच्चों के कुपोषण की विद्यमानता का प्रयोग किया गया है जिसकी माप अपेक्षाकृत आसान है और जिसके आँकड़े भी सरलता से उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और सुरक्षित पेय जल की पहुँच को भी सम्मिलित किया गया है। इन तीनों चरों को जोड़कर मानव निर्धनता की पर्याप्त एवं सही तस्वीर बनाना युक्ति संगत (Rationalize) माना गया।

कुछ चुने हुए ओ. ई. सी. डी. देशों के लिए एक अलग मानव निर्धनता सूचकांक का प्रयोग किया गया है। इनमें सम्मिलित किए गए चार प्रमुख चर हैं—

TOUCH 'n PASS

1. जन्म पर 60 वर्ष की आयु तक न जीवित रहने की सम्भावना।
2. कार्यात्मक साक्षरता (Functional Literacy) के अभाव वाले वयस्कों का प्रतिशत।
3. 11 डॉलर प्रतिदिन (क्रय शक्ति समता 1994) की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत।
4. दीर्घकालीन बेरोजगारी दर (12 महीने या इससे अधिक)।

मानव निर्धनता सूचकांक इन चारों चरों का औसत है।

स्पष्टतया आय-निर्धनता रेखा की अपेक्षा मानव निर्धनता सूचकांक एक अधिक व्यापक माप है, क्योंकि आय निर्धनता रेखा एक ही चर पर आधारित है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक विकास के आधुनिक मापदण्ड का वर्णन कीजिए।

Describe the modern parameter of economic development.

उत्तर

आधुनिक मापदण्ड
(Modern Parameter)

प्राचीन अर्थशास्त्रियों की ही भाँति आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी आर्थिक विकास का कोई निश्चित मापदण्ड नहीं बताया है। फिर भी आधुनिक विकासवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा आर्थिक विकास के निम्नलिखित मापदण्ड प्रस्तुत किए जाते हैं—

1. **वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि मापदण्ड**—इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं—प्रो. मायर एवं बाल्डविन, कुजनेट्स, यंगसन तथा मीड। इन विकासवादी अर्थशास्त्रियों ने किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को उस देश के आर्थिक विकास का सूचक बताया है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरन्तर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तो यह कहा जाएगा कि वह देश आर्थिक विकास कर रहा है। यह विचारधारा एक महत्त्वपूर्ण मापदण्ड के रूप में स्वीकार की जाती है।

   इस कथन को निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र में क्षैतिज अक्ष पर समय को तथा अनुलम्ब अक्ष पर समय के साथ राष्ट्रीय आय में परिवर्तन को प्रदर्शित किया गया है। रेखा Y_a देश M में राष्ट्रीय आय के स्तर को तथा Y_b देश N में राष्ट्रीय आय के स्तर को प्रकट करती है समय T तक देश M की राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश N की अपेक्षा अधिक है। परन्तु दीर्घकालीन विकास परियोजनाओं के प्रारम्भ होने से देश N की राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि होती है। जैसा कि निम्न चित्र में प्रदर्शित है, बिन्दु E के पश्चात $Y_b > Y_a$ हो जाता है। इस सन्दर्भ में मॉयर एवं बाल्डविन का कथन है कि 'आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है।'

   वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का मापदण्ड मानने में निम्नलिखित कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं—

   (i) वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती हैं; जैसे आँकड़ों को एकत्र करने की कठिनाई, वस्तुओं एवं सेवाओं के चयन की कठिनाई, दोहरी गणना की कठिनाई तथा मूल्यों के चुनाव की कठिनाई, आदि।

   (ii) इसमें जनसंख्या की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता। यदि वास्तविक राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़े तब आर्थिक विकास न होकर आर्थिक अवनति (Economic Degradation) होगी।

   (iii) आर्थिक विकास के इस मापदण्ड में समाज में व्याप्त आय के वितरण पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है जबकि आर्थिक विकास एवं आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने में आय के वितरण का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

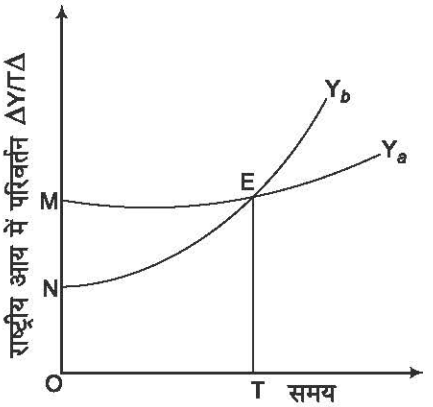

चित्र

TOUCH 'n' PASS

(iv) यदि आय में वृद्धि के बावजूद उपभोग में वृद्धि न हो तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक नहीं हो सकेगी, क्योंकि वास्तविक आय में असमान वितरण से आर्थिक संकेन्द्रण (Economic Centralisation) होता है और पूँजीपतियों के हाथों में ही अधिकांश सम्पत्ति संकेन्द्रित होने लगती है जिससे समाज के उपभोग स्तर (Consumption level) में वृद्धि नहीं हो पाती है।

(v) वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि सदैव आर्थिक विकास का द्योतक नहीं है। यदि वास्तविक राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन की वृद्धि प्राकृतिक साधनों के रिक्तिकरण (Depletion) अथवा श्रमिकों के शोषण का परिणाम हो तो इसे हम विकास नहीं कह सकते।

2. **प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मापदण्ड**—इस विचार के समर्थकों का मत है कि राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास का सही मापदण्ड नहीं है बल्कि देश में प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को उस देश के आर्थिक विकास के अभिसूचक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। किसी भी देश के सम्मुख प्रमुख समस्या होती है अपने देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और जीवन स्तर का प्रति व्यक्ति आय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। प्रो. पॉल बरन के अनुसार, 'आर्थिक वृद्धि की परिभाषा भौतिक वस्तुओं की एक निश्चित काल में प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि के रूप में की जानी चाहिए।' इस तरह प्रति व्यक्ति आय विचारधारा आर्थिक विकास मापने का एक अच्छा अभिसूचक है।

इस विचारधारा के समर्थकों का उद्देश्य इस विचारधारा पर बल देना है कि आर्थिक विकास के लिए वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर जनसंख्या में वृद्धि की दर से अधिक होनी चाहिए परन्तु यह विचारधारा उन प्रश्नों को गौण बना देती है जो समाज के ढाँचे, उसकी जनसंख्या के आकार एवं बनावट, उसकी संस्थाओं तथा साधन स्वरूपों और समाज के सदस्यों में उत्पादन के समान वितरण से सम्बन्ध रखते हैं।

इसके अतिरिक्त प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उपभोग के स्तर में वृद्धि की कोई गारण्टी नहीं देती। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के साथ प्रति उपभोग (Consumption) में कमी भी हो सकती है। ऐसा तब सम्भव है जब लोग अपनी बचत की दर में वृद्धि करने लगे अथवा राज्य बढ़ी हुई आय का प्रयोग सैन्य एवं अन्य गैर-विकास योजनाओं में करने लगें। ऐसी दशा में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होने पर भी लोगों के उपभोग एवं जीवन-स्तर में वृद्धि नहीं होगी। साथ ही प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होने, परन्तु न्यायोचित वितरण (Justifiable distribution) न होने से धनी व्यक्ति अधिक धनी और गरीब अधिक गरीब हो सकते हैं। आय के न्यायोचित वितरण के बिना सामाजिक आर्थिक कल्याण में वृद्धि होना सम्भव नहीं है।

3. **अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक संरचना का स्वरूप**—किसी देश की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य कार्यशील जनसंख्या का विभिन्न व्यवसायों में लगा होना है। आर्थिक विकास एवं जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण के बीच धनात्मक सह-सम्बन्ध होता है। प्रो. कोलिन क्लार्क ने समस्त कार्यशील जनसंख्या को तीन क्षेत्रों में बाँटा है। (अ) प्राथमिक क्षेत्र, (ब) द्वितीयक क्षेत्र, (स) तृतीयक क्षेत्र। अन्य शब्दों में कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या के अनुपात में कमी और द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता हैं। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र का अंशदान राष्ट्रीय आय में अधिक होता है और देश की अधिकांश कार्यशील जनता इस क्षेत्र में लगी रहती है।

4. **आर्थिक कल्याण वृद्धि मापदण्ड**—यह मापदण्ड राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के स्थान पर लोगों के आर्थिक कल्याण या जीवन स्तर में वृद्धि को आर्थिक विकास की कसौटी के रूप में स्वीकार करता है।

इस सम्बन्ध में ओकन एवं रिचर्डसन (B. Okun and R. W. Richardson) का कथन है कि यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने पर लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो जाए। जीवन-स्तर मुख्य रूप से उपभोग के स्तर पर निर्भर करता है इसलिए देश में बढ़ता हुआ उपभोग एवं जीवन-स्तर ही आर्थिक विकास का सूचक है। उन्हीं के शब्दों में आर्थिक विकास 'भौतिक समृद्धि में ऐसा अनवरत दीर्घकालीन सुधार है जो कि वस्तुओं एवं सेवाओं के बढ़ते हुए प्रवाह में प्रतिबिम्बित समझा जा सकता है।'

इस मानदण्ड में भी कुछ विसंगतियाँ हैं; जैसे अल्पविकसित (Under-developed) देशों में उपभोग प्रवृत्ति पहले से ही अधिक होती है और इन देशों में उपभोग को कम करने का प्रयास भी किया जाता है जिससे बचतों में वृद्धि करके पूँजी (Capital) निर्माण को बढ़ाया जा सके। इस तरह इन देशों में उपभोग को बढ़ावा देने का अर्थ होगा, देश को अविकसित

TOUCH 'n' PASS

अवस्था में बनाए रखना। दूसरा, उपभोग तथा जीवन-स्तर अत्यन्त भ्रामक (Illusive) शब्द हैं जिनकी निरपेक्ष माप सम्भव नहीं है। तीसरा, कल्याण के दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर केवल इस बात पर ही विचार नहीं किया जा सकता कि 'क्या और कितना उत्पादित (Produce) किया जा रहा है' बल्कि 'कैसे उत्पादित किया जा रहा है' यह भी देखना होगा। यह सम्भव है कि राष्ट्रीय-प्रदा बढ़ने के साथ-साथ वास्तविक और सामाजिक लागतों (Costs) (कष्ट, पीड़ा, त्याग, शोषण, नैतिक पतन आदि) में भी वृद्धि हो जाए जो अन्ततः सामाजिक कल्याण को सीमित कर दे।

5. **सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता सूचक मापदण्ड**—आर्थिक विकास के माप के रूप में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद से असन्तुष्ट अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को सामाजिक अथवा आधारभूत (मूलभूत) आवश्यकता सूचक के रूप में मापना प्रारम्भ किया है। इसका कारण यह रहा कि आर्थिक विकास की माप के सूचक GNP/GNP प्रति व्यक्ति वृद्धि की धारणा में गरीबी, बेरोजगारी तथा आय असमानताओं जैसी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस सम्बन्ध में डेविड मोरवेट्ज (David Morawetz) का तर्क है कि विकासशील देशों में 1950-75 के बीच GNP प्रति व्यक्ति में 3.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष औसत दर से वृद्धि हुई। परन्तु यह वृद्धि दर ऐसे देशों की गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानताओं की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रही। विश्व बैंक के पूर्व गवर्नर रॉबर्ट मैक्कनमारा ने भी फरवरी 1970 में विकासशील देशों में GNP वृद्धि दर की आर्थिक विकास के सूचक के रूप में विफलता को इन शब्दों में स्वीकार किया : 'प्रथम विकास दशक में, GNP में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के प्राथमिक (Primary) विकास उद्देश्य को प्राप्त किया गया था। यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। परन्तु GNP में सापेक्षतया ऊँची वृद्धि दर विकास में सन्तोषजनक प्रगति (Progress) लाने में असफल रही। विकासशील जगत में दशक के अन्त में, कुपोषण सामान्य है, शिशु मृत्यु दर ऊँची है, अशिक्षा व्याप्त है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, धन और आय का पुनर्वितरण अत्यन्त विषम है।' विकास के GNP/GNP प्रति व्यक्ति माप से असन्तुष्ट आर्थिक विचारकों ने 1970 के दशक से विकास प्रक्रिया की गुणवत्ता पर ध्यान देना प्रारम्भ किया, जिसके अनुसार वे तीन विभिन्न, परन्तु पूरक, रोजगार में वृद्धि करने, गरीबी दूर करने तथा आय और धन की विषमताओं को कम करने के लिए मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं (basic human needs) की कूटनीति पर बल देते हैं। इसके अनुसार, जनसाधारण को स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, खुराक, कपड़ा, आवास, रोजगार आदि के रूप में मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं और साथ ही सांस्कृतिक पहचान तथा जीवन और कार्य में उद्देश्य एवं सक्रिय भाग की भावना जैसी अभौतिक आवश्यकताएँ प्रदान करना है।

हिक्स और स्ट्रीटन (Norman L. Hicks and Paul P. Streeten) ने मूलभूत आवश्यकताओं के अन्तर्गत निम्नलिखित छः सामाजिक सूचकों को सम्मिलित किया है—

	मूल आवश्यकता	सूचक
1.	स्वास्थ्य	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा (Life expectancy at the time of birth)
2.	शिक्षा	प्राथमिक विद्यालयों में जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार दाखिले द्वारा साक्षरता की दर
3.	खाद्य	प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति
4.	जल आपूर्ति	शिशु मृत्यु दर (Child death rate) तथा पीने योग्य पानी तक कितने प्रतिशत जनसंख्या की पहुँच
5.	स्वच्छता	शिशु मृत्यु दर तथा स्वच्छता प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत
6.	आवास	कुछ नहीं

प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति के अतिरिक्त शेष अन्य सूचक निर्गत सूचक हैं। निःसन्देह नवजात शिशुओं की मृत्यु दर, स्वच्छता तथा स्वच्छ पेयजल सुविधाओं दोनों के अभाव की सूचक है, क्योंकि नवजात शिशु पानी से संक्रमित रोगों के शीघ्र शिकार हो जाते हैं। नवजात शिशु मृत्यु दर भोजन की पौष्टिकता से भी सम्बन्धित है। इस तरह, शिशु मृत्यु दर 6 में से 4 मूल आवश्यकताओं को मापती है।

आलोचना—सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता सूचकों से सम्बन्धित विकास का एक सामान्य सूचक बनाने के मार्ग में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं; यथा—(i) ऐसे सूचकांक में शामिल किए जाने वाली मदों की संख्या और किस्मों के बारे में अर्थशास्त्रियों के बीच मतैक्य नहीं है। उदाहरणार्थ—हैगन (Hagen) और संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक विकास के लिए अन्वेषण संस्था 11 से 18 मदों का प्रयोग करते हैं जिनमें से बहुत कम समान हैं, जबकि डी. मौरिस तुलनात्मक अध्ययन के लिए विश्व के 23 विकसित और विकासशील देशों से सम्बन्धित 'जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक' (Physical Quality of Life Index) बनाने के लिए केवल तीन मदों अर्थात् जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता दर को सम्मिलित करते हैं।

TOUCH 'n' PASS

इसके अतिरिक्त, (ii) विभिन्न मदों को भार देने की भी समस्या उत्पन्न होती है। (iii) सामाजिक, सूचकांक वर्तमान कल्याण से सम्बन्धित होते हैं न कि भविष्य के कल्याण से। (iv) अधिकतर सूचकांक आगतें हैं न कि निर्गत जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। (v) उनमें निर्णय पाए मूल्य जाते हैं। अत: मूल्य निर्णयों से बचने और सुगमता के लिए अर्थशास्त्री तथा यू. एन. ओ. के संगठन GNP प्रति व्यक्ति को आर्थिक विकास के माप के रूप में प्रयोग करते हैं।

प्र.2. मानव विकास सूचकांक एवं पर्यावरणीय सुधार मापदण्ड या अभिसूचक का वर्णन कीजिए।
Describe the Human Development Index and environmental improvement parameteror indicator.

उत्तर

मानव विकास सूचकांक
(Human Development Index—HDI)

संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (UNDP) के तत्त्वावधान में आर्थिक विकास के मापक के रूप में वर्ष 1990 से विश्व के सदस्य देशों के मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा इस आधारभूत परिकल्पना पर आधारित है कि 'किसी राष्ट्र के निवासी ही उस राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति होते हैं।' आर्थिक विकास का मूलभूत उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे लोग लम्बे समय तक स्वस्थ एवं सुखी जीवन का आनन्द उठा सकें।

मानव विकास की अवधारणा की विवेचना करते हुए यू.एन.डी.पी. (UNDP) की मानव विकास रिपोर्ट (1997) में इंगित किया गया है कि 'यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसामान्य के विकल्पों का विस्तार किया जाता है और इनके द्वारा उनके कल्याण के उच्च स्तर को प्राप्त किया जाता है। यही मानव विकास की धारणा का मूल है। ऐसे सिद्धान्त न तो सीमाबद्ध होते हैं और न ही स्थैतिक, परन्तु विकास के स्तर को दृष्टि में न रखते हुए जनसामान्य के पास तीन विकल्प हैं—एक लम्बा और स्वस्थ्य जीवन व्यतीत करना, ज्ञान प्राप्त करना और अच्छा जीवन-स्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों तक अपनी पहुँच बढ़ाना। कई और भी विकल्प हैं जिन्हें बहुत से लोग महत्त्वपूर्ण मानते हैं। इनमें उल्लेखनीय हैं-राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता से सृजनात्मक और उत्पादक बनने के अवसर और स्वाभिमान एवं गारण्टीयुक्त मानव अधिकारों का लाभ उठाना।' इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए मानव विकास रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, 'आय केवल एक विकल्प है और जो लोग प्राप्त करना चाहेंगे, चाहे यह महत्त्वपूर्ण है, परन्तु यह उनके समस्त जीवन का सार नहीं है। आय एक साधन है, जबकि मानव विकास एक लक्ष्य है।'

वर्ष 1990 में महबूब-उल-हक के मार्गदर्शन में विकास के सर्वमान्य माप के रूप में 'मानव विकास सूचक' (HDI) को विकसित किया गया। इसके पश्चात इसे और अधिक परिष्कृत करने के उद्देश्य से 'लिंग- सम्बन्धित विकास सूचकांक' (GDI) तथा मानव निर्धनता सूचकांक (HPI) (बहु आयामी निर्धनता सूचकांक) का विकास किया गया।

मानव विकास सूचकांक (HDI) में आर्थिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के विकल्पों को शामिल किया जाता है। HDI में प्रतिव्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) आर्थिक सूचक है, जबकि जीवन प्रत्याशा एवं शिक्षा की उपलब्धि सामाजिक सूचक है।

मानव विकास सूचकांक का आकलन—HDI मानव विकास का माप है। यह किसी देश की मानव विकास के संदर्भ में तीन मूलभूत आयामों के क्षेत्र में उपलब्धियों की माप करता है। ये तीन मूलभूत आयाम हैं—(i) लम्बा व स्वस्थ जीवन, (ii) ज्ञान की उपलब्धि (iii) एक अच्छा जीवन स्तर। इन तीन आयामों के लिए आकलित सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य लिया जाता है।

मानव विकास सूचकांक की गणना से पूर्व उपर्युक्त तीनों आयामों के लिए अलग-अलग सूचकांक तैयार किए जाते हैं। सूचकों (Indicators) को शून्य से एक के बीच सूचकांक के रूप में व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक सूचक के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य निश्चित किया जाता है।

सारणी : आयाम सूचकांकों के न्यूनतम व अधिकतम मूल्य

आयाम	सूचकांक	न्यूनतम	अधिकतम
स्वास्थ्य शिक्षा (ज्ञान)	जीवन प्रत्याशा (वर्ष) (Life Expectancy Year)	20	85
	स्कूल में व्यतीत किए जाने वाले संभावित वर्ष	0	18
	स्कूल में व्यतीत औसत वर्ष (Average Years spend in school)	0	15
जीवन स्तर	प्रति व्यक्ति आय (क्रय शक्ति समता अनुसार 2011 में अमेरिकी डॉलर के मूल्य में)	100	75,000

प्रत्येक आयाम निष्पादन को 0 और 1 के बीच मूल्य के रूप में निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है—

$$\text{आयाम सूचकांक} = \frac{\text{वास्तविक मूल्य} - \text{न्यूनतम मूल्य}}{\text{अधिकतम मूल्य} - \text{न्यूनतम मूल्य}}$$

मानव विकास सूचकांक इन तीनों आयाम सूचकांकों का साधारण औसत (ज्यामितीय माध्य) है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक (HDI) जीवन की प्रत्याशा सूचकांक, शैक्षिक सूचकांक तथा समायोजित वास्तविक प्रति व्यक्ति GDP सूचकांक का एक औसत (ज्यामितीय माध्य सूचकांक) है। इसकी गणना में प्रत्येक चर (मद) को शून्य से एक तक के पैमाने पर रखा जाता है। प्रत्येक देश इस पैमाने के किसी-न-किसी बिन्दु पर आता है।

प्रत्येक देश के मानव विकास सूचकांक (HDI) का मूल्य इस तथ्य की ओर संकेत (Indicate) करता है कि उस देश को अपने कुछ परिभाषित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कितना प्रयास (Effort) करना होगा। ये परिभाषित लक्ष्य हैं : 85 वर्ष के औसत जीवन की अवधि, सभी के लिए शिक्षा तथा उत्कृष्ट जीवन-स्तर।

सीमाएँ (Limitations)—मानव विकास सूचकांक (HDI) की भी अपनी सीमाएँ हैं—(i) केवल तीन सूचकांक ही मानव विकास के सूचकांक नहीं हैं। शिशु मृत्यु दर, पोषण (Nutrition) आदि अन्य सूचकांक भी महत्त्वपूर्ण हैं जिन्हें भी HDI के निर्माण में सम्मिलित किया जाना चाहिए। (ii) मानव विकास सूचकांक (HDI) निरपेक्ष मानव विकास को न मापकर सापेक्ष मानव विकास को मापता है। यदि सभी देश समान भारित (Weighted) दर से अपने मानव विकास सूचकांक (HDI) मूल्य को सुधार लें तो निम्न मानव विकास वाले देशों के सुधार का पता नहीं चल पाएगा। (iii) किसी देश का मानव विकास सूचकांक (HDI) वहाँ व्याप्त उच्च विषमता (Disparity) को दूर करने के लक्ष्य से विमुख हो सकता है।

पर्यावरण सुधार मापदण्ड या अभिसूचक
(Environmental Improvement Criteria or Indicators)

पर्यावरण तथा किसी देश की अर्थव्यवस्था के बीच प्रत्यक्ष, सहजीवी एवं गहन सम्बन्ध होता है। पर्यावरण अनेक जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बना है। जब ये समस्त घटक निश्चित अनुपात में होते हैं तो एक सुन्दर एवं स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मनुष्य की भोगकारी प्रवृत्ति से प्रेरित तीव्र आर्थिक विकास की लालसा ने इन घटकों (Component) के अनुपात को बिगाड़ दिया है। जिससे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को अपूरणीय क्षति पहुँच रही है। पर्यावरण की गुणवत्ता में होने वाले ह्रास (Depreciation) ने वायु, जल, ध्वनि एवं मृदा-प्रदूषण के रूप में अपना विकराल रूप दिखाना प्रारम्भ कर दिया है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में आर्थिक विकास के कारण भारी पर्यावरणीय ह्रास हुआ है। भारत में वर्तमान समय में लगभग 10 से 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर पर्यावरणीय क्षति का आकलन किया गया है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.5 से 6 प्रतिशत तक होता है।

आज विश्व के किसी भी देश के लिए आर्थिक विकास की प्रक्रिया एवं संसाधनों के विदोहन को बंद कर देना संभव नहीं है क्योंकि आर्थिक विकास से ही देश की प्रगति संभव है। फिर भी इस बात की आवश्यकता है कि ह्रासमान पारिस्थितिक तन्त्र (Ecosystem) को सुधारने एवं भविष्य में विकासात्मक नीतियों के निर्धारण एवं उनके सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिए पारिस्थितिक विकास की अवधारणा को आधार बनाया जाए।

आज किसी देश के आर्थिक संवृद्धि की अवधारणा को पर्यावरण की गुणवत्ता से जोड़कर देखा जाने लगा है। वर्तमान में आर्थिक विकास की माप सकल राष्ट्रीय उत्पाद/प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जैसे मात्रात्मक तत्त्वों से नहीं की जाती है बल्कि सामाजिक कल्याण, जीवन स्तर में वृद्धि एवं 'मानव विकास सूचक' के स्तर में वृद्धि को आर्थिक विकास का मापदण्ड माना जाता है। विगत कुछ वर्षों से यह धारणा बलवती होती जा रही है कि उच्च गुणवत्ता वाले जीवन के लिए पर्यावरण सुरक्षा/संरक्षण अति आवश्यक है। इसलिए किसी देश के आर्थिक विकास को पर्यावरण से सम्बद्ध किए जाने की आवश्यकता है। आज यह अनुभव किया जाने लगा है कि आर्थिक विकास एवं पर्यावरण एक-दूसरे पर निर्भर ही नहीं करते बल्कि एक-दूसरे के पूरक भी हैं। पर्यावरण अपघटन (Decompesition) से किसी देश की राष्ट्रीय आय में गिरावट आती है। अनुमान है कि पर्यावरण अपघटन से विश्व अर्थव्यवस्था की आय में 5% से 10% तक की कमी आती है। पर्यावरण संरक्षण के अभाव में विवेकपूर्ण एवं न्यायपूर्ण (Justifiable) विकास की कल्पना करना व्यर्थ होगा। अन्य शब्दों में, आर्थिक विकास एवं मानव के उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन के लिए पृथ्वी के संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक एवं वांछित है। इस दृष्टि से वर्तमान में सन्तुलित, समन्वित एवं सतत पारिस्थितिक विकास की कल्पना की गई है जिसके अन्तर्गत विकासात्मक योजनाओं के साथ पर्यावरणीय मुद्दों को समन्वित किया जाता है। इस तरह

TOUCH 'n' PASS

अर्थव्यवस्था को विकसित करने की जो भी परियोजनाएँ चलाई जाती हैं उसमें पर्यावरण के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने, सामाजिक कल्याण फलन को अधिकतम करने की नियोजित रणनीति (Planned Strategy) अपनाई जाती है।
जिस देश में पर्यावरण सुरक्षित/संरक्षित है तथा प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन पर्यावरण को हानि पहुँचाए बिना किया जाता है उस देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध एवं सम्पन्नता का प्रतीक समझी जाती है।
उपयुक्त मापदण्ड–आर्थिक वृद्धि अथवा विकास का उपयुक्त मापदण्ड क्या होना चाहिए? यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है। विभिन्न कालों एवं परिस्थितियों में विभिन्न माप स्वीकार किए गए हैं। प्रत्येक मापदण्ड के अपने–अपने गुण–दोष हैं। विकास का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से अल्पविकसित एवं विकासशील देशों की समस्याओं से सम्बद्ध है। इसलिए आर्थिक विकास की कसौटी हेतु प्रति व्यक्ति आय एवं कल्याण में होने वाली वृद्धि को स्वीकार किया जा सकता है। आर्थिक विकास के सूचकांक के रूप में वर्तमान में HDI का प्रयोग किया जाता है जिसमें आर्थिक चरों के साथ ही सामाजिक चरों का भी समावेश किया गया है। इसके अलावा HDI हमें विकास की प्रगति की ओर जाने के बारे में भी बताता है। पर्यावरण को हानि पहुँचाए बिना होने वाले सतत् विकास को भी आर्थिक विकास का संकेतक माना जाता है। अतएव अल्पविकसित अथवा विकासशील देशों के लिए HDI को आर्थिक विकास के सर्वोत्तम माप के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक विकास का आर्थिक अभिसूचक है–
(क) वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि (ख) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि
(ग) अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या के अनुपात में कमी
(घ) उपर्युक्त सभी
उत्तर (घ) उपर्युक्त सभी

प्र.2. निम्नलिखित में किसमें विकास के आर्थिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के विकल्पों को शामिल किया जाता है?
(क) जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक (ख) मानव विकास सूचकांक
(ग) अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक संरचना का स्वरूप (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) मानव विकास सूचकांक

प्र.3. निम्नलिखित में से कौन–सा मानव विकास सूचकांक से सम्बन्धित है?
(क) महबूब–उल–हल (ख) रॉबर्ट मैकनमारा (ग) रिचर्ड निक्सन (घ) डॉ० मनमोहन सिंह
उत्तर (क) महबूब–उल–हल

प्र.4. मानव विकास का आयाम है–
(क) लम्बा व स्वस्थ जीवन (ख) ज्ञान की उपलब्धि (ग) एक अच्छा जीवन स्तर (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.5. आयाम सूचकांकों से मानव विकास सूचकांक प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस माध्य का प्रयोग किया जाता है?
(क) समान्तर माध्य (ख) गुणात्मक माध्य (ग) हरात्मक माध्य (घ) बहुलक
उत्तर (ख) गुणात्मक माध्य

प्र.6. निम्नलिखित में से कौन–सा विकास का सबसे उचित वर्णन करता है?
(क) गुण में धनात्मक परिवर्तन (ख) गुण में ऋणात्मक परिवर्तन
(ग) आकार में परिवर्तन (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (क) गुण में धनात्मक परिवर्तन

प्र.7. मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है?
(क) रैटजेल (ख) डॉ. महबूब–उल–हक (ग) ग्रिफिथ टेलर (घ) इनमे से कोई नहीं
उत्तर (ख) डॉ. महबूब–उल–हक

प्र.8. निम्नलिखित में से कौन–सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है?
(क) नॉर्वे (ख) जापान (ग) अर्जेंटीना (घ) मिस्र
उत्तर (घ) मिस्र

TOUCH 'n PASS

प्र.9. 1990 में किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया?
(क) डॉ. मनमोहन सिंह (ख) डॉ. महबूब-उल-हक (ग) अमर्त्य सेन (घ) इनमे से कोई नहीं

उत्तर (ख) डॉ. महबूब-उल-हक

प्र.10. निम्नलिखित में से कौन-सा मानव विकास का स्तम्भ नहीं है?
(क) समता (ख) सतत पोषणीयता (ग) उत्पादकता (घ) भेदभाव

उत्तर (घ) भेदभाव

प्र.11. निम्नलिखित में से कौन-सा सशक्तिकरण का सही अर्थ है?
(क) शारीरिक रूप से बलवान
(ख) अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना
(ग) सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों का सशक्तिकरण करना
(घ) (ख) और (ग)

उत्तर (घ) (ख) और (ग)

प्र.12. मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किन प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम आधार तैयार करता है?
(क) स्वास्थ्य (ख) शिक्षा (ग) संसाधनों तक पहुँच (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.13. मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों का क्रम निम्नलिखित में से किस स्कोर पर आधारित होता है?
(क) 5 से 10 के बीच (ख) 10 से 20 के बीच (ग) 100 से 200 के बीच (घ) 0 से 1 के बीच

उत्तर (घ) 0 से 1 के बीच

प्र.14. स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(क) अधिक आयु (ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा
(ग) कम मृत्यु दर (घ) इनमे से कोई नहीं

उत्तर (ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा

प्र.15. मानव विकास उपागमों में निम्नलिखित में से कौन-सा उपागम नहीं है?
(क) आय उपागम (ख) क्षमता उपागम (ग) कल्याण उपागम (घ) व्यय उपागम

उत्तर (घ) व्यय उपागम

प्र.16. आय उपागमों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(क) आय का स्तर ऊँचा होगा पर मानव विकास का स्तर भी ऊँचा होगा
(ख) आय का स्तर ऊँचा होने पर मानव विकास का स्तर निम्न होगा
(ग) (क) तथा (ख) दोनों (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर (ख) आय का स्तर ऊँचा होने पर मानव विकास का स्तर निम्न होगा

प्र.17. मानव विकास प्रतिवेदन 2016 में भारत का स्थान क्या था?
(क) 120वाँ (ख) 122वाँ (ग) 131वाँ (घ) 124वाँ

उत्तर (ग) 131वाँ

प्र.18. विश्व में मानव विकास प्रतिवेदन 2015 के अनुसार सर्वोच्च 'उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश कौन सा था?
(क) जर्मनी (ख) पाकिस्तान (ग) जापान (घ) नॉर्वे

उत्तर (क) जर्मनी

प्र.19. मानव विकास का अर्थ होता है–
(क) आर्थिक सुधार (ख) सामाजिक सुधार (ग) गुणवत्ता में सुधार (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ग) गुणवत्ता में सुधार

TOUCH 'n' PASS

प्र.20. निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तम्भ नहीं है?
(क) समता (ख) सतत पोषणीयता
(ग) उत्पादकता (घ) व्यापारीकरण
उत्तर (घ) व्यापारीकरण

प्र.21. अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति का विचार करना ..... कहलाता है।
(क) आत्मविश्वास (ख) उत्पादकता
(ग) सशक्तिकरण (घ) संसाधनों तक पहुँच
उत्तर (ग) सशक्तिकरण

प्र.22. निम्नलिखित में से कौनसी विशेषता मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों में नहीं होती।
(क) राजनीतिक उपद्रव (ख) सामाजिक खण्डों में अधिक निवेश
(ग) सामाजिक अस्थिरता (घ) अकाल व बीमारियाँ
उत्तर (ख) सामाजिक खण्डों में अधिक निवेश

प्र.23. सार्थक जीवन केवल ..... होता है।
(क) दीर्घ नहीं (ख) दीर्घ (ग) लघु (घ) इनमे से कोई नहीं
उत्तर (क) दीर्घ नहीं

प्र.24. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन वृद्धि के संदर्भ में सत्य है?
(क) इसका चिह्न धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है।
(ख) इसका चिह्न केवल धनात्मक हो सकता है।
(ग) इसका चिह्न केवल ऋणात्मक हो सकता है। (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर (क) इसका चिह्न धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है।

प्र.25. निम्नलिखित में से कौन-सा उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है?
(क) कल्याण उपागम (ख) क्षमता उपागम (ग) आय उपागम (घ) इनमे से कोई नहीं
उत्तर (ग) आय उपागम

प्र.26. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा कौन-सा उपागम प्रस्तावित किया गया?
(क) आय उपागम (ख) कल्याण उपागम
(ग) आधारभूत आवश्यकता उपागम (घ) इनमे से कोई नहीं
उत्तर (ग) आधारभूत आवश्यकता उपागम

प्र.27. निम्नलिखित में से मानव विकास का मापन के लिए क्रम कौन तैयार करता है?
(क) HDI (ख) PDI (ग) MTI (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (क) HDI

प्र.28. निम्न में से कौन-सा वह देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है?
(क) भारत (ख) भूटान (ग) नेपाल (घ) चीन
उत्तर (ख) भूटान

प्र.29. मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश ..... से गुजर रहे हैं।
(क) राजनीतिक उपद्रव (ख) गृहयुद्ध
(ग) (क) तथा (ख) (घ) इनमे से कोई नहीं
उत्तर (ग) (क) तथा (ख)

TOUCH 'n' PASS

❑

UNIT-VIII

भारत में प्रादेशिक योजना की आवश्यकता
Need for Regional Planning in India

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. भारत में प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य लिखिए।
Write the objectives of regional planning in India.

उत्तर प्रादेशिक नियोजन का मूल उद्देश्य किसी प्रदेश के निवासियों की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास के लिए कार्य करना है। इसीलिए भारतीय नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य कहे जा सकते हैं—

1. कृषि एवं सम्बन्धित वस्तुओं का विकास–भूमि सुधार, मिट्टी संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, सिंचाई, उर्वरक, जंगलों का विकास इत्यादि।
2. आधारभूत एवं भारी उद्योगों को प्रमुखता देते हुए तीव्र औद्योगीकरण।
3. सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
4. देश में अपेक्षित जीवनस्तर (Expected Life standard) प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सामाजिक सेवाओं का विकास–शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि।
5. यातायात एवं संचार साधनों का विकास।
6. आय एवं सम्पत्ति में असमानता को कम करना और आर्थिक शक्ति का समान वितरण।
7. संपोषणीय विकास (Sustainable Growth)।
8. समावेशीय विकास (Inclusive Growth)।

प्र.2. आर्थिक नियोजन से क्या तात्पर्य है?
What is the meant by economic planning?

उत्तर वर्तमान युग में आर्थिक नियोजन प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक विकास की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। विश्व के सभी देशों में नियोजन को प्रगति के इंजन के रूप में स्वीकार किया गया है। आज प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अथवा अपनी आर्थिक सम्पन्नता को बनाए रखने के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लेता है। विकासशील एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राष्ट्रों के लिए विकास की क्रमबद्ध प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा उपलब्ध संसाधनों को गतिशील बनाने की दृष्टि से आर्थिक नियोजन बहुत ही आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

प्र.3. बहुस्तरीय नियोजन से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by multi level planning?

उत्तर बहुस्तरीय आयोजन, जैसा कि शब्द इंगित करता है, विभिन्न स्तरों पर नियोजन का एकीकरण है। बहुस्तरीय नियोजन में नियोजन के विभिन्न स्तर उच्च स्तरीय नियोजन के लिए आधार प्रदान करते हैं। ऐसी योजनाओं में नियोजन प्रक्रिया में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है।

प्र.4. भारत में नियोजन के कितने चरण हैं?
How many stages of planning are there in India?

उत्तर 1. योजना का निर्माण 2. योजना का निष्पादन या कार्यान्वयन 3. योजना का पर्यवेक्षण 4. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ)।

TOUCH 'n' PASS

प्र.5. योजना के प्रमुख उद्देश्य लिखिए।
Write the main objectives of the plan.

उत्तर भारत का योजना आयोग एक ऐसा उपकरण है जिसका लक्ष्य दीर्घावधि में राष्ट्र की आकांक्षाओं और सपनों को समझना है। इसके मुख्य उद्देश्यों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है—

(i) आर्थिक विकास
(ii) रोजगार में वृद्धि आत्मनिर्भरता
(iii) आर्थिक स्थिरता
(iv) समाज कल्याण
(v) क्षेत्रीय विकास
(vi) सर्वांगीण विकास
(vii) आर्थिक असमानताओं को कम करना
(viii) सामाजिक न्याय
(ix) जीवन स्तर में वृद्धि

प्र.6. संसाधन आयोजन क्या है?
What is the planning of resources?

उत्तर भारत में, संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) देश भर में मौजूदा संसाधनों की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए सर्वेक्षण और मानचित्रण
(ii) संसाधन विकास योजनाओं का मानचित्रण
(iii) यह सुनिश्चित करना कि पड़ोसी राज्यों के बीच कोई संघर्ष न हो
(iv) प्रत्येक डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए उसका महत्त्व, प्रकृति और गुणवत्ता
(v) किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले यह एक सरकारी प्रक्रिया है।

प्र.7. भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई?
When did economic planning start in India?

उत्तर राष्ट्रीय योजना आयोग के गठन के बाद, भारत ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करके नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत की। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना पर टिप्पणी कीजिए।
Give a note on the concept of regional planning.

उत्तर नियोजन के तहत प्राय: किसी कल्याणकारी राज्य द्वारा किसी देश या प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु बनाये गये कार्यक्रम तथा उनके क्रियान्वयन (Implement) को शामिल किया जाता है। अर्थात् नियोजन प्रादेशिक विकास की वह प्रणाली है जिसके द्वारा किसी देश या प्रदेश के संसाधनों का सर्वोत्तम (Optimum) उपयोग करते हुए उच्चतम सामाजिक-आर्थिक स्तर को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। नियोजन के तहत क्षेत्र के संपोषणीय (Sustainable) विकास के साथ-साथ प्रादेशिक असमानता (Regional Inequality) को भी कम करने का प्रयास किया जाता है। विकासशील देशों के पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए प्रादेशिक नियोजन एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, सार्थक एवं अपरिहार्य प्रणाली है। पैट्रिक गेडीस (Patrick Geddes) को 'प्रादेशिक नियोजन का पिता' (Father of Regional Planning) कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले अमेरिकी विद्वान बेन्टन मैकाय (Benton Mackaye) ने 1927 ई. में 'प्रादेशिक नियोजन' शब्द का प्रयोग किया था।
प्रादेशिक नियोजन एक बहु-आयामी विषय है। सिद्धान्त एवं व्यवहार दोनों में ही यह अन्तर्विषयक (Interdisciplinary) है। पैट्रिक गेडीस ने प्रादेशिक नियोजन को मानव समूह एवं उसके विभिन्न कार्यकलापों से सम्बन्धित माना है। बेन्टन मैकाय के अनुसार, प्रादेशिक नियोजन स्थानिक स्तर (Spatial level) तक ही सीमित है। प्रादेशिक नियोजन द्वारा पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों के अन्वेषण का प्रयास किया जाता है एवं उस प्रदेश के निवासियों की सभ्यता के प्रवाह को नियन्त्रित करने का प्रयास किया जाता है। जॉन एन. फ्रीडमैन (John N. Friedman) के अनुसार, प्रादेशिक नियोजन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों

TOUCH 'n' PASS

जुड़ा होना चाहिए। इन्होंने इसे अन्तर्विषयक विधि के रूप में तथा उच्च शिक्षा एवं तकनीक के सहारे मानवहितों को बढ़ाने वाला कहा है। लेविस ममफोर्ड (Lewis Mumford) ने प्रादेशिक नियोजन को किसी प्रदेश के क्रमबद्ध विकास एवं दूसरे प्रदेशों से सुदृढ़ सम्बन्धों के रूप में देखा है। इसलिए प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना वर्तमान आर्थिक तन्त्र के सन्दर्भ में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उपर्युक्त संकल्पना किसी प्रदेश के सम्पूर्ण विकास को अपने अन्दर समाहित किये हुए है। प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना अति लोचपूर्ण है।

प्र.2. प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना के तत्त्वों का उल्लेख कीजिए।
Describe the elements of regional plannings concept.

उत्तर प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना में निम्न तत्त्व अन्तर्निहित हैं—

1. प्रादेशिक नियोजन, समन्वित (Integrated) प्रादेशिक विकास का प्रयास करता है।
2. प्रादेशिक नियोजन, सन्तुलित प्रादेशिक विकास एवं आर्थिक क्रियाओं के प्रसार पर विशेष जोर (Emphasis) देता है तथा आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानता (Regional Disparity) को दूर करने का प्रयत्न करता है।
3. प्रादेशिक नियोजन, नियोजन प्रदेश को विभिन्न पदानुक्रमों में बाँटता है, तदनन्तर प्रदेश की समस्याओं का क्रम (Order) भी निर्धारित करता है कि कौन-सी समस्या का हल पहले ढूँढ़ना है।
4. प्रादेशिक नियोजन, 'क्षेत्रीय आर्थिक संश्लिष्ट' के निर्माण पर बल देता है जिससे क्षेत्र विशेष में किसी-न-किसी आर्थिक क्रिया-कलाप में विशेषीकरण (Specialization) उत्पन्न हो, जीवनयापन के आवश्यक पदार्थों जैसे खाद्य सामग्री में आत्म निर्भरता हो तथा अनावश्यक लम्बी दूरी का परिवहन समाप्त किया जा सके।
5. प्रादेशिक नियोजन के अन्तर्गत नियोजन इकाइयों के विभाजन के समय यह स्पष्ट रहे कि ये इकाइयाँ प्रशासनिक सीमा को ध्यान में रखकर बनायी जाएँ।
6. प्रादेशिक नियोजन, निवास्य क्षेत्र (Habital) के प्रत्यावर्तन (Transformation) की चेष्टा करता है जिससे मानव समुदाय का अपने वातावरण से सम्यक् सामन्जस्य स्थापित हो सके। नियोजन के दो प्रमुख क्रियाकलाप हैं जिसमें पहला विकास हेतु और दूसरा वातावरण सुधार हेतु कार्य करता है। ये दोनों क्रियाएँ परस्पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। जैसे यदि उद्योग एवं कृषि में प्रगति होती है तो अन्य क्रियाएँ निश्चित ही मन्द पड़ जाती हैं एवं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, अतएव प्रादेशिक नियोजन हेतु वातावरण सुधार पर ध्यान देना परमावश्यक है। अन्यथा सम्पूर्ण जैविक संसाधन नष्ट हो जायेंगे। पर्यावरण प्रदूषण पर रोक एवं नियन्त्रण भी इसी का अंग है।
7. प्रादेशिक नियोजन पूर्ण रूप से तभी सफल होगा जब राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास की गति से जुड़ा हो।
8. इसमें प्रदेश में मानव और प्राकृतिक संसाधनों की सीमाओं (limitation) को भी ध्यान में रखा जाता है।
9. प्रादेशिक नियोजन किसी प्रदेश विशेष के एकपक्षीय अथवा एकाकी विकास का समर्थन नहीं करता वरन यह प्रत्येक प्रदेश के अन्तर्गत सर्वांगीण तथा विभिन्न प्रदेशों के अन्तर्सम्बन्धित विकास पर जोर देता है।

प्र.3. प्रादेशिक नियोजन की विभिन्न परिभाषाएँ लिखिए।
Write the different definitions of regional planning.

उत्तर

प्रादेशिक नियोजन की परिभाषा
(Definition of Regional Planning)

किसी भी प्रदेश या क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु बनाये गये सरकारी कार्यक्रम को प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। यह एक क्षेत्रीय विषय है जिसके द्वारा किसी प्रदेश की सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन करके निदान हेतु सुझाव दिया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि इस नियोजन के बाद प्रदेश का सभी दिशाओं में सर्वांगीण विकास हो ही जाय। भारत के सम्पूर्ण राष्ट्रीय उत्पादन (G.N.P.) में तो अवश्य वृद्धि हो रही है, परन्तु भारत के सभी प्रदेशों एवं सभी व्यक्तियों की आय में समान वृद्धि नहीं हो रही है। विकासशील देशों में प्रादेशिक नियोजन ग्रामीण विकास से नजदीक से जुड़ा हुआ है। तीव्र नगरीकरण के बावजूद भी जनसंख्या का अधिक भाग ग्रामीण रहन-सहन अपनाये हुए है तथा कृषि से अपना जीविकोपार्जन करता है।

प्रादेशिक नियोजन में एक अहम कार्य भविष्य पर भी ध्यान देना होता है। प्रादेशिक नियोजन को प्रादेशिक विकास प्राप्ति हेतु एक साधन (Means) माना जाता है। प्रादेशिक नियोजन राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय विकास, वैज्ञानिक संसाधन उपयोग, संरक्षण एवं

TOUCH 'n' PASS

समान वितरण की एक महत्त्वपूर्ण संकल्पना तथा प्रमुख साधन है। प्रादेशिक नियोजन को स्पष्ट करते हुए सी. वी. नरसिंहम ने लिखा है कि 'प्रादेशिक नियोजन द्वारा एक उपयुक्त ढाँचे का निर्माण होता है, जिसमें राष्ट्रीय एवं स्थानीय महत्त्व की योजनाओं में एकीकरण होता है। इस प्रकार के पूर्ण प्रादेशिक महानगरीय विकास क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र तथा ग्रामीण पुनरुत्थान के नियोजन तथा उद्योग-धन्धों के स्थानीयकरण सम्बद्ध होते हैं।' अत: प्रादेशिक नियोजन में किसी प्रदेश में उपलब्ध स्थान एवं संसाधनों के दोहन के तरीकों का अध्ययन किया जाता है, जिनसे सम्पूर्ण प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके। प्रादेशिक नियोजन को कुछ प्रमुख विद्वानों ने परिभाषित किया है जिनका विवरण अग्रलिखित है—

1. **पैट्रिक गेडिस** (Patric Geddes) के अनुसार, 'प्रादेशिक नियोजन का क्रिया स्थल 'प्रदेश' है, जिसके अन्तर्गत 'स्थान' (भूगोल), 'लोग' (समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र) एवं 'कार्य' (अर्थशास्त्र) आते हैं।' प्रादेशिक नियोजक को इन तीनों का अपनी क्रिया द्वारा एक सजीव एकीकरण करना होता है।
   प्रादेशिक नियोजन न तो केवल आर्थिक नियोजन है न ही भौतिक नियोजन। इसका मर्म भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक तत्त्वों के समामेलन में निहित है। इसका अर्थ यह है कि किसी प्रदेश का नियोजन एकाकीपन में नहीं किया जा सकता बल्कि इसे पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखना आवशयक है।
2. **बेन्टन मैकाय** के अनुसार, 'प्रादेशिक नियोजन विभिन्न स्थानीय स्तरों पर राष्ट्रीय आर्थिकी एवं किसी क्षेत्र के सम्भाव्य विकास को क्रमश: सुदृढ़ एवं सुरक्षित करता है।' इसका उद्देश्य वर्तमान संसाधनों अर्थात् भूमि, मानव एवं उद्योग के विकास के लिए आत्मसहायता, आत्मविकास एवं स्थानीय साधनों से शुरुआत करना है।
3. **जॉन फ्रीडमैन** के अनुसार, 'प्रादेशिक नियोजन अधिनगरीय स्थान अर्थात् एक नगर की अपेक्षा अधिक बड़े क्षेत्र में मानवीय क्रिया-कलापों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित है, अथवा प्रादेशिक नियोजन अधिनगरीय स्थान के अन्तर्गत मानवीय क्रिया-कलापों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों के सूत्रीकरण की प्रक्रिया है।

प्र.4. प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
Explain the objectives of regional planning.

उत्तर

प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य
(Objectives of Regional Planning)

प्रत्येक देश की भूमि, संसाधन एवं पूँजी सीमित है। अत: प्रादेशिक नियोजन का उस सीमित संसाधन की खोज करके उच्च तकनीकी एवं प्रशिक्षण द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य (Objective) है। किसी देश का शिक्षित एवं स्वस्थ मनुष्य ही उसका सबसे बड़ा संसाधन होता है। जब लेनिन से पूछा गया कि आप अपने देश के विकास के लिए क्या करेंगे तो उन्होंने कहा शिक्षा प्रथम, शिक्षा द्वितीय एवं शिक्षा तृतीय अर्थात् शिक्षा का सर्वांगीण विकास करेंगे। बेन्टन मैकाय ने 1928 में यह कहा था कि प्रादेशिक नियोजन मुख्य उद्देश्य प्रत्येक प्रदेश में उच्च जीवन स्तर की स्थिति उपलब्ध कराना होता है। इसी प्रकार ममफोर्ड ने भी अपने प्रादेशिक नियोजन में मानव हितों को ही सर्वोपरि बताया है।

प्रादेशिक नियोजन में प्रदेशों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध प्रयास किये जाते हैं। अत: यह कहा जा सकता है कि मानव समाज का सर्वांगीण विकास (Overall development) ही इसका लक्ष्य है, जो क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों एवं मानवीय कार्यों को पुनर्व्यवस्थित रूप देने से प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रादेशिक नियोजन क्षेत्र विशेष के पर्यावरण के सन्दर्भ में संपोषणीय (Sustainable) विकास एवं उसमें समान वितरण की भावना लाने का प्रयास करता है। प्रादेशिक नियोजन किसी प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि उसके द्वारा प्रदेश में दूसरा विकल्प भी प्रस्तुत किया जाता है। यह नियोजन यह भी अध्ययन करता है कि कैसे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को प्रभावित करता है। प्रादेशिक विकास में असमानता को दूर करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इस असमानता को दूर करने हेतु इसकी विभिन्न प्रक्रियाओं में ऊर्ध्वाधर (Vertical) एवं क्षैतिज (Horizontal) समन्वयन आवश्यक है, क्योंकि इसी से स्थानीय स्तर पर भी जनसंख्या की सहभागिता (Particapation) सुनिश्चित होती है। इसके अन्तर्गत क्षेत्र विशेष की पारिस्थितिकी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के अनुसार इसके कई उद्देश्य एक-दूसरे के परिपूरक या अन्तर्सम्बन्धित हैं। ये निम्नलिखित हैं—

1. प्रदेश विशेष के उपलब्ध संसाधनों का सम्यक् उपयोग।
2. प्रादेशिक-आर्थिक संश्लिष्ट का निर्माण।
3. विभिन्न आर्थिक प्रखण्डों एवं अन्तर-प्रादेशिक स्तर पर समन्वयन।

TOUCH 'n PASS

4. भूवैन्यासिक संगठन की प्रक्रियात्मक गहनता में वृद्धि।
5. विकास प्रक्रिया में सभी सदस्यों की सहभागिता से सामाजिक न्याय की भावना में वृद्धि करना।
6. क्षेत्रीय आधार पर भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना।
7. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण (Natural environmental conservation)।
8. विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित (Integrated) विकास द्वारा प्रदेशिक एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना।

प्र.5. आर्थिक नियोजन की विभिन्न परिभाषाएँ दीजिए।
Give the different definitions of economic planning.

उत्तर

आर्थिक नियोजन की परिभाषा
(Definition of Economic Planning)

आर्थिक नियोजन एक व्यापक शब्द है जिसकी भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ दी हैं, इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

1. **भारतीय योजना आयोग** के अनुसार, 'आर्थिक नियोजन आवश्यक रूप से सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप साधनों को अधिकतम लाभ हेतु संगठित एवं उपयोग करने का एक मार्ग है।'
2. **गुन्नार मिर्डल** (Gurnnar Myrdal) के अनुसार, 'आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय सरकार की रीति-नीति से सम्बन्धित वह कार्यक्रम है जिसमें बाजार शक्तियों के कार्यकलापों में राज्य हस्तक्षेप की प्रणाली को सामाजिक प्रक्रिया के ऊपर ले जाने हेतु लागू किया जाता है।'
3. **लेविस लॉर्डबिन** (Lewis Lordwin) के शब्दों में, 'आर्थिक नियोजन आर्थिक संगठन की एक योजना है जिसमें सभी व्यक्तियों और अलग-अलग प्लाण्टों, उपक्रमों और उद्योगों को एक दिए हुए समय के अन्तर्गत जनसाधारण की आवश्यकताओं की अधिकतम सन्तुष्टि की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधन का उपयोग करने के उद्देश्य से, एकल प्रणाली की समन्वित इकाइयों के रूप में संचालित किया जाता है।'
4. **एस. ई. हैरिस** (S. E. Harris) के अनुसार, 'नियोजन से अभिप्राय आय तथा मूल्य के सन्दर्भ में, नियोजन अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के लिए, साधनों का आबण्टन मात्र है।'
5. **राष्ट्रीय नियोजन समिति** के मत में, 'आर्थिक नियोजन उपयोग, उत्पादन, विनियोग, व्यापार तथा राष्ट्रीय लाभांश के वितरण से सम्बन्धित स्वार्थरहित विशेषज्ञों का तकनीकी समन्वय है जो राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राप्त किया जाए।'

इस तरह, आर्थिक नियोजन के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि, आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है जिसमें एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियन्त्रण किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन एक पद्धति है, यह वांछित लक्ष्यों व उद्देश्यों को पूरा करने का एक साधन है। यह लक्ष्य, केन्द्रीय नियोजन अधिकारी (Central Planning Officer) एवं शक्ति द्वारा पूर्व निर्धारित तथा स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए, भले ही लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अथवा सैन्य और सुरक्षा से सम्बन्धित ही क्यों न हों।

प्र.6. आर्थिक नियोजन की विशेषताएँ अथवा लक्षणों का उल्लेख कीजिए।
Explain the characteristics of economic planning.

उत्तर

आर्थिक नियोजन की विशेषताएँ अथवा लक्षण
(Characteristics of Economic Planning)

आर्थिक नियोजन की विशेषताएँ और लक्षण निम्नलिखित हैं—

1. नियोजन आर्थिक संगठन एवं विकास की एक समन्वित (Integrated) प्रणाली है।
2. आर्थिक नियोजन एक निश्चित अवधि (Duration) के लिए होता है जिसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं।
3. आर्थिक नियोजन में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और निजी उद्योगों व संस्थाओं को भी राजकीय निर्देशों का पालन करना पड़ता है। कभी-कभी स्वयं राज्य भी नए-नए उद्योग व संस्थाएँ स्थापित कर देता है।

TOUCH 'n' PASS

4. आर्थिक नियोजन का उद्देश्य सामाजिक उत्थान करना है जिससे कि समाज का विकास हो, उसका रहन-सहन का स्तर ऊपर उठे, उसकी आय में वृद्धि हो तथा सामाजिक बुराइयों का अन्त हो।
5. आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषता निश्चित लक्ष्यों का निर्धारण है। यह लक्ष्य पहले से खूब सोच-विचारकर निर्धारित किए जाते हैं फिर उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विकास की प्राथमिकताएँ (Priorities) एवं उनका क्रम निर्धारित किया जाता है।
6. आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत नियोजन का कार्य एक केन्द्रीय नियोजन संस्था को सौंप दिया जाता है। यही संस्था या संगठन योजनाएँ बनाता है एवं उनमें समन्वय करता है तथा उनको कार्य रूप में परिणत (Implement) कराने की व्यवस्था करता है।
7. आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। इसमें एक के बाद एक योजनाएँ चलाई जाती हैं जिसमें आपस में दीर्घकालीन सम्बन्ध होता है।
8. आर्थिक नियोजन की एक विशेषता यह है कि इसमें साधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है।
9. आर्थिक नियोजन सरकारी रणनीति (Government Strategy) का एक भाग होता है। इसका अर्थ यह है कि इसको सरकारी कार्यक्रम के रूप में ही अपनाया जाता है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. प्रादेशिक नियोजन के विषय क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
Describe the scope of regional planning in detail.

उत्तर प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य सर्वांगीण (Overall) विकास है। इसको प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष पर्यावरण के सन्दर्भ में मानवीय क्रियाओं को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि उससे अधिकतम (Maximum) आर्थिक उत्पादन हो, उत्पादन प्रक्रिया में सबकी सहभागिता रहे और पर्यावरण सन्तुलन भी बना रहे, जिससे भविष्य में मानवीय क्रियाओं का संगठन लाभप्रद बना रहे।

इस प्रकार प्रादेशिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए मानवीय एवं प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग, संरक्षण और विकास करना है।

प्रादेशिक नियोजन का विषय क्षेत्र
(Scope of Regional Planning)

प्रादेशिक नियोजन का विषय क्षेत्र व्यापक है। वर्तमान समय में प्रादेशिक नियोजन एक विषय के रूप में पूर्ण रूप से विकसित है। जहाँ स्वतन्त्र विषय के रूप में नियोजन में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, गणित, राजनीति एवं बहुत सी तकनीकी विषय सम्मिलित हैं। वहीं भूगोल का सम्बन्ध इसके प्रादेशिक उपागम से रहा है। अतएव प्रादेशिक नियोजन क्षेत्र विशेष के सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित है। इसलिए इसके अध्ययन क्षेत्र में वे सभी तथ्य आ जाते हैं, जो प्रादेशिक नियोजन को प्रभावित करते हैं। प्रादेशिक नियोजन के विषय क्षेत्र को निम्न शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है—

1. **आर्थिक विकास के लिए प्रादेशिक नियोजन** (Regional Planning for Economic Development)—प्रादेशिक नियोजन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अध्ययन विषय आर्थिक विकास ही है। इसलिए इसके अन्तर्गत आर्थिक विकास के विभिन्न चरण, उनको प्रभावित करने वाले प्राकृतिक, मानवीय और तकनीकी कारकों का अध्ययन सम्मिलित है। आर्थिक विकास के अन्तर्गत कृषि, उद्योग एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं के उन्नयन पर विशेष बल दिया जाता है। इसके साथ ही आर्थिक विकास के विभिन्न प्रकार के मॉडल उनका प्रयोग आदि का प्रयोग इसके अन्तर्गत किया जाता है।
2. **प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन** (Planning of Natural Resources)—प्रादेशिक नियोजन प्रदेश विशेष के संसाधनों के सन्दर्भ में ही नियोजन करता है। इसलिए विभिन्न प्राकृतिक, मानवीय संसाधनों का विश्लेषण, उनके संरक्षण के उपाय, जनसंख्या और संसाधन का अन्तर्सम्बन्ध विभिन्न संसाधनों का उपयोग प्रतिरूप इसके अध्ययन के अन्तर्गत आते हैं।
3. **सामुदायिक नियोजन** (Community Planning)—इस अध्ययन के द्वारा स्थानीय स्तर पर समुदाय विकास हेतु नियोजन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अन्तर्गत सम्बन्धित प्रदेशों में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा वाले समुदायों की पहचान, प्राथमिकता का निर्धारण और समुदायों के विस्तृत सामाजिक-आर्थिक अध्ययन के पश्चात् उनके लिए

TOUCH 'n PASS

नियोजन प्रस्तावित किया जाता है। इस तरह समुदायों का अध्ययन इसका उल्लेखनीय पक्ष है। उदाहरण के लिए, आदिवासी, दलित, कृष्य एवं औद्योगिक समुदाय का नियोजन। सामुदायिक निवास की दशाओं एवं तत्सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन भी इसमें सम्मिलित किया जाता है।

4. **मानव संसाधन नियोजन** (Human Resources Planning)—किसी भी प्रदेश में पाये जाने वाले संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन मानव संसाधन नियोजन द्वारा ही सम्भव है। इसमें मानव संसाधन की समस्याओं का व्यापक अध्ययन किया जाता है तथा उनके सुधार हेतु उपाय बताये जाते हैं। मानव संसाधन का विस्तृत विश्लेषण, वृद्धि, प्रजातीय, यौन संरचना, व्यावसायिक संरचना, मानव संसाधन की प्रवृत्ति (Tendency of Human Resources) और उसकी सम्भाव्यता (Probability) का अध्ययन मानव संसाधन नियोजन में सम्मिलित है।
5. **नगरीय एवं महानगरीय नियोजन** (Urban and Metropolitan Planning)—नगरीय क्षेत्र महानगरीय प्रदेश के ही भाग हैं। विभिन्न क्षेत्रों के सन्दर्भ में प्राथमिक अर्थव्यवस्था के रूपान्तरण के कारण नगरों का विकास तीव्रगति से हो रहा है। सर्वप्रथम नगरीय क्षेत्र एवं महानगरीय प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। इसके बाद नगरों की विभिन्न समस्याओं का आकलन करके सामान्य समस्याओं को अलग कर लिया जाता है। उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर नगरीय क्षेत्र एवं महानगरीय प्रदेशों के नियोजन हेतु निश्चित अवधि के लिए सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं। नगरों की समस्याएँ, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से अलग होती हैं। नगरों में नगरीय परिवहन, आवासीय समस्या, जनसंख्या संकेन्द्रण की समस्या, प्रदूषण व स्वास्थ्य, नगरीय व्यवसाय एवं उद्योगों का विकेन्द्रीकरण तथा नगरीय प्रभाव प्रदेशों का अध्ययन नगरीय नियोजन के अन्तर्गत सम्मिलित है।
6. **ग्रामीण नियोजन** (Rural Planning)—ग्रामीण क्षेत्रों का कार्यात्मक (Functional) भूदृश्य नगरों से पूर्णतया भिन्न होता है। अत: ग्रामीण नियोजन पर सम्यक् ध्यान देना आवश्यक है। नगर-ग्राम सातत्य होते हुए भी नगर एवं ग्राम दोनों का अपना वैशिष्टय एवं व्यक्तित्त्व होता है। अधिक आर्थिक लाभ, संकेन्द्रित जन समूह, अत्यधिक माँग एवं विकास के ध्रुवीकरण की परछाई ग्राम्य क्षेत्रों पर पड़ने लगती है, तो नगरों की अवनति (Degradation) का समय आ जाता है, क्योंकि नगरों की जनसंख्या की भूख ग्राम ही मिटा सकते हैं। एक तरह से ध्रुवीकृत नगरीय विकास अपने विनाश (Destruction) के बीज बोता है। अत: आवश्यकता है कि ग्रामीण नियोजन को नगरीय नियोजन की भांति प्राथमिकता दी जाय।
7. **पर्यावरण नियोजन** (Environment Planning)—प्रदेश विशेष के सन्दर्भ में मानव और प्रकृति के अन्तर्सम्बन्धों के परिणामस्वरूप पर्यावरण ह्रास की समस्याएँ खड़ी हो रही हैं, इसलिए पारिस्थितिकीय सन्तुलन (Ecological Balance) विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का निवारण, मानवीय कार्यों का पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से पुनर्व्यवस्थापन, वातावरण गुणवत्ता आदि भी प्रादेशिक नियोजन के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते हैं।
8. **सामाजिक विकास हेतु प्रादेशिक नियोजन** (Regional Planning for Social Development)—देश में नियोजित विकास शुरू हुए लगभग 72 वर्ष बीत गये, परन्तु देश में कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में विचारणीय सफलता नहीं मिल पायी है। इतना ही नहीं, समाज के अन्दर कई ऐसे सामाजिक वर्ग मिलते हैं जहाँ विकास का प्रभाव नहीं पहुँच रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं ओड़िसा के कई हिस्से आज भी देश के बाकी हिस्सों से काफी पिछड़े (More Backward) हैं। देश में छठवीं योजना से ही इस खण्ड पर ध्यान दिया जा रहा है। आठवीं योजना की अवधि में सामाजिक खण्ड पर सर्वाधिक धन खर्च करने की संस्तुति (Recommendation) की गयी है। बारहवीं योजना में तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी हैं। हुए विकास (Inclusive Growth) पर बल दिया गया, लेकिन अभी तक यथोचित परिणाम प्राप्त नहीं हुए इस दिशा में प्रादेशिक नियोजन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अल्प विकसित प्रदेश एवं न्यून विकसित सामाजिक वर्ग को इसके माध्यम से समुचित गति प्रदान की जा सकती है।
9. **अवस्थापना के लिए प्रादेशिक नियोजन** (Regional Planning for Infrastructure)—अवस्थापना सुविधाओं को विकास की धुरी के रूप में माना जाता है। अवस्थापना सुविधाओं में परिवहन (सड़क, रेल और जहाज), पत्तन, संचार, ऊर्जा (ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ) तथा सिंचाई को प्रमुख स्थान दिया जाता है। भारत में परिवहन अवस्थापना की हालत सबसे खस्ता है। संचार के क्षेत्र में देश ने अप्रत्याशित विकास किया है, लेकिन ऊर्जा तथा सिंचाई खण्ड की स्थिति अभी भी दयनीय (Pitable) बनी हुई है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि जिन क्षेत्रों में अवस्थापना के साधनों

TOUCH 'n PASS

का अल्प विकास हुआ है वहाँ तीव्रता लाने की आवश्यकता है। प्रादेशिक नियोजन के विभिन्न उपागमों का अलग से या संयुक्त रूप से अवस्थापना विकास में प्रयोग हो रहा है, परन्तु अभी तक हम लक्ष्य से बहुत पीछे हैं।

इस प्रकार प्रादेशिक नियोजन की विषय-वस्तु को मेकेई (B. Mackaye) ने स्पष्ट करते हुए है कि 'प्रादेशिक नियोजन के अन्तर्गत मानवीय लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रकृति की योजनाओं को तलाशने का प्रयास किया जाता है। इसमें उद्योग को संस्कृति के दास के रूप में देखा जा सकता है तथा उसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अन्तर्गत सभ्यता के संचार करने में मार्गदर्शन करना होता है।'

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रादेशिक नियोजन क्षेत्र विशेष में व्याप्त पर्यावरण के सन्दर्भ में मानव समाज को इस प्रकार व्यवस्थापन करने का प्रयास है, जिससे वर्तमान और भविष्य के सन्दर्भ में भी मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ-ही-साथ क्षेत्र का भी संपोषणीय विकास होता रहे। इसलिए प्रादेशिक नियोजन के अन्तर्गत मानव समाज और पर्यावरण के सभी तथ्य अध्ययन के विषय बन सकते हैं।

प्र.2. भारत में प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए।
Describe the importance of regional planning in India.

उत्तर

भारत में प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता
(Importance of Regional Planning in India)

ब्रिटिशकाल में देश का अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था, फिर भी अनेक स्वतन्त्र रियासतें, राज्य अस्तित्त्व में थे। इसी तरह सीमान्त क्षेत्र में स्थित राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग थीं। 15 अगस्त, 1947 ई. में स्वतन्त्रता मिलने पर देश में एक बड़ा कार्य विभिन्न क्षेत्रों को कार्यात्मक रूप से एक शासन के अधीन लाना था। सरदार पटेल के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप सभी इकाइयाँ केन्द्र शासन के अन्तर्गत सम्मिलित हो गयीं। इसके साथ ही क्षेत्रीय आकांक्षा को बनाये रखने हेतु देश में संघीय व्यवस्था (Federal System) स्वीकृत की गई। विभिन्न सीमान्तीय इकाइयों को कार्यात्मक रूप से जोड़े रखने हेतु संघीय व्यवस्था भी एकीकृत (Unitary) या केन्द्रीकृत (Centralized) रूप में अपनायी गयी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया सोवियत रूस के मॉडल (Inter Economic Balance Model, 1926) पर आधारित पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से शुरू की गई। देश की भौगोलिक विशिष्टता को ध्यान में रखकर केन्द्रीकृत नियोजन पद्धति विकसित की गई। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सम्पूर्ण देश के सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण का प्रयास किया जाने लगा। भारत में 15 मार्च, 1950 को योजना आयोग (Planning Commission) का गठन किया गया था तथा 1 अप्रैल, 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। देश में बारह पंचवर्षीय योजनाएँ तथा कुछ वार्षिक योजनाएँ समाप्त हो चुकी हैं तथा 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति (NITI) आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान समय में भारत में आर्थिक विकास का दायित्व नीति आयोग के पास ही है।

स्वतन्त्रता के बाद देश के समक्ष अपनी आर्थिक व्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं सुदृढ़ बनाने की समस्या प्रकट हुई। अंग्रेजों ने देश के उन्हीं क्षेत्र में अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विकास किया जहाँ से वे कच्चा माल को ब्रिटेन भेज सके तथा तैयार माल को लाकर भारत में अधिक लाभ पर बेच सकें। भारत में चाय अथवा जूट उद्योग जो ब्रिटिश साम्राज्य की दृष्टि से अधिक उपादेय एवं लाभकारी थे, विकसित अवस्था में थे जबकि कृषि अथवा अन्य आधारभूत उद्योग (Core Industry), उपेक्षित एवं अविकसित अवस्था में थे। अर्थतन्त्र के इस द्विघात्मक (Dual) स्थिति की अभिव्यक्ति भूवैन्यासिक संगठन में हुई। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे पतन केन्द्र जो ब्रिटेन से औद्योगिक वस्तुओं जैसे वस्त्र एवं उपकरण आदि के आयात तथा भारत से चाय, जूट, कपास आदि के निर्यात के द्वार थे, इस प्रकार से अत्याधुनिक नगर केन्द्र के रूप में विकसित (Developed) हुए। इनके सम्पूरक क्षेत्रों में भी आर्थिक कार्य-कलाप अपेक्षाकृत समुन्नत थे, जबकि देश का विशाल अवशेष भाग परम्परागत निर्वाहक कृषि पर निर्भर, अत्यन्त पिछड़ा, दरिद्र बना रहा। अतएव इन क्षेत्रों से रोजगार की खोज में प्रशिक्षित-अशिक्षित सभी प्रकार के श्रमिक, पत्तन-केन्द्रों की ओर भागते थे। यह भूवैन्यासिक संगठन क्रोड़-उपान्त (Core-Periphery) की समस्या से ग्रस्त है अर्थात् इसमें कुछ गिने-चुने केन्द्रों (Core) में आधुनिक अर्थव्यवस्था मिलती है, जबकि अवशेष विशाल क्षेत्र (उपान्त) अत्यन्त पिछड़ी अर्थव्यवस्था के प्रतीक बने रहते हैं। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास आदि क्रोड़ के रूप में विकसित हो गये जबकि अवशेष विशाल भू-भाग इनके सापेक्ष उपान्त बने रहे।

देश के विभिन्न क्षेत्रों का पर्यावरण, संसाधन आधार, निवासित जनसंख्या की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताएँ तथा रीति-रिवाज (Traditions) अलग-अलग हैं। इसलिए कोई भी विकास नीति एक ही आकार-प्रकार की हर क्षेत्र के लिए सफल नहीं हो सकती है। अलग-अलग क्षेत्रों के पर्यावरण के अनुसार अलग-अलग विकास नीतियाँ ही प्रभावी हो सकती हैं। जैसे पूर्वोत्तर

भारत की जनजातीय संस्कृति के क्षेत्र के लिए वन संसाधन और बागाती कृषि पर आधारित ऐसे कार्यक्रम सफल हो सकते हैं, जो आर्थिक विकास के साथ-साथ उनकी संस्कृति, रीति-रिवाज तथा क्षेत्रीय आकांक्षा को भी बनाये रख सकें। इसी तरह मध्यवर्ती जनजातीय क्षेत्र में भी क्षेत्रीय वैशिष्टय के आधार पर विकास नीतियाँ सफल हो सकती हैं। हर क्षेत्र का एक परम्परागत अर्थतन्त्र होता है। उसी तंत्र में आधुनिक तकनीकी, संरचनागत प्रत्यावर्तन एवं संस्थागत रूपान्तरण (Conversion) करके वहाँ के लिए शाश्वत विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए भारत में सामान्य नियोजन के साथ-साथ विशिष्ट नियोजन के अन्तर्गत प्रादेशिक नियोजन को भी अपनाया गया। प्रादेशिक नियोजन में प्राथमिकता (Priority) के आधार पर चयनित क्षेत्रों का नियोजन किया गया है। इस नियोजन के अन्तर्गत विभिन्न प्राथमिकता के क्षेत्रों को उनकी संसाधन क्षमता, सम्भावना एवं पर्यावरण के अनुसार, नियोजित अर्थतन्त्र के अन्तर्गत लाना है। इसलिए वहाँ अभीष्ट विकास कार्यक्रम संपोषणीय (Sustainable) हो सकते हैं। भारत में सम्पूर्ण नियोजन तन्त्र ही बहुस्तरीय है अर्थात् राष्ट्रीय स्तर पर प्रजातान्त्रिक संघीय ढाँचे के अनुसार बजट निर्धारण, योजना निर्देशन तथा प्रशासन और मानीटरिंग की जाती है, जबकि राज्य स्तर पर योजना निर्माण और जनपद स्तरों की योजनाओं को स्वीकृत किया जाता है। सामान्य योजनाओं का कार्यान्ययन (Implementation) राज्य स्तर पर ही किया जाता है, लेकिन कार्यान्वयन तन्त्र जनपद स्तर पर ही रहता है। इसके साथ ही लघुस्तरीय योजनाएँ जनपद स्तर पर ही संचालित की जाती हैं, लेकिन इनमें से सबकी स्वीकृति राज्य (State) स्तर अथवा केन्द्रीय (Central) स्तर से ली जाती है। इस तरह भारतीय नियोजन को विकेन्द्रीकृत (Decentralized) भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें वित्तीय आवंटन (Allocation) और निर्णय प्रक्रिया एक चरणबद्ध (Stepwise) प्रक्रिया है। सन् 1990 ई. के बाद पंचायती राज के माध्यम से योजना निर्माण, निर्णय और कार्यान्वयन स्थानीय (Local) स्तर पर हो रहा है। इसी क्रम में प्रादेशिक विकास नीति का निर्धारण भी केन्द्रीय स्तर और राज्य स्तर के समन्वयन के आधार पर किया जाता है। भारत में प्रादेशिक नियोजन का प्रारम्भ प्रादेशिक असमानताओं को दूर करने के लिए किया गया है। प्रथम एवं द्वितीय योजना में ही इस पर व्यापक जोर (Emphasis) दिया गया, जब पिछड़े क्षेत्रों तक विकास प्रक्रिया का लाभ पहुँचाने हेतु विभिन्न विकास कार्यक्रमों से जोड़ा गया। केन्द्र सरकार के अधीन बड़े पैमाने के उद्योग और अन्य कार्य प्राथमिकता के आधार पर वहाँ स्थापित किये गये। इससे यह उम्मीद की गई थी कि पिछड़े क्षेत्र भी त्वरित गति से विकसित होकर विकसित क्षेत्रों के समकक्ष आ जायेंगे, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना तक यह अनुभव किया गया कि पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित आर्थिक कार्यों से विकास की प्रक्रिया का प्रसार नहीं हो पा रहा है और क्षेत्रीय लोगों की आकांक्षा भी पूरी नहीं हो पा रही है तो चौथी पंचवर्षीय योजना से पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग से योजनाएँ प्रस्तावित की गईं और उन्हीं के अनुसार विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जाता रहा। पाँचवीं योजना (Fith Plan) में गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को मुख्य प्राथमिकता (Main Priority) दी गयी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना जो कि भारत सरकार की अन्तिम योजना थी इसमें तीव्र अधिक समावेशी एवं सतत् वृद्धि को प्राथमिकता दी गयी। स्वन्त्रता के इन 72 वर्षों में देश उल्लेखनीय राष्ट्रीय विकास प्राप्त नहीं कर पाया है। अत: देश को इस दिशा में गहराई से सोचना पड़ेगा कि कौन-सा तरीका अपनाया जाय जिससे संसाधनों का दक्ष वितरण (Efficient Resource Allocation) हो सके।

देश में उपर्युक्त असमानता या अपर्याप्त विकास का कारण आधुनिकीकरण (Modernization), औद्योगीकरण एवं संस्थाकरण का कुछ स्थानों या जिलों में एकत्रित होना है तथा ग्रामीण क्षेत्रों की घोर उपेक्षा (Ignonrance) है। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि पर्याप्त औद्योगीकरण पहले से हुआ होता तो देश में ऐसी दुर्व्यवस्था नहीं उत्पन्न होती। इन सबके बावजूद देश के राष्ट्रीय विकास का स्तर ऊँचा न होने का कारण राष्ट्रीय योजना में जनता की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं तथा उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान न देना है। समन्वित विकास उपागम की घोर उपेक्षा रही। अत: प्रादेशिक नियोजन में सही रणनीतियों का विकास, उनका चयन एवं क्रियान्वयन महत्त्वपूर्ण है। अभी भी भारत की लगभग दो तिहाई (2011 की जनगणना अनुसार 68.84 प्रतिशत) (2023 में 65%) जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। अगर विकास की बात की जाए तो अधिकांश शहरी क्षेत्रों में हो रहा है एवं ग्रामीण क्षेत्र दिन-प्रतिदिन पिछड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए गाँवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। वर्तमान समय में देश में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार (Corruption) की है, किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु आबंटित धन का अधिकांश हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है जिससे हमारे आर्थिक विकास की गति धीमी होती जा रही है तथा आर्थिक असमानता भी बढ़ती चली जा रही है।

अन्त में यह कहना समीचीन होगा कि देश में विशिष्ट राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक प्रदेश पाये जाते हैं। इन प्रदेशों की संस्कृति और परम्पराएँ दूसरे प्रदेशों से अलग हैं। वे अपनी पहचान बनाये रखना चाहते हैं। उदाहरणस्वरूप, पंजाब, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, असम, छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्रों, गोरखालैण्ड इत्यादि की अलग संस्कृति है। देश में विकास हेतु बनाई गई कुछ परियोजनाएं इनकी संस्कृति हेतु खतरा बनी हुई हैं। इतना ही नहीं देश में उपर्युक्त वर्णित प्रदेशों की मिट्टी,

जलवायु, जनसंख्या गुणवत्ता तथा संसाधनों की मौजूदगी में काफी विभिन्नता पाई जाती है। अत: इतनी विभिन्नताओं को किसी तरह भी एक राष्ट्रीय योजना में निरूपित नहीं किया जा सकता अर्थात् प्रत्येक प्रदेश हेतु अलग से प्रादेशिक योजना की भूमिका अनिवार्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास में प्रादेशिक नियोजन की भूमिका उल्लेखनीय है या प्रादेशिक नियोजन एवं राष्ट्रीय विकास एक-दूसरे के पूरक हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन, आत्म-निर्भरता की प्राप्ति, निवेश एवं पूँजी निर्माण को बढ़ावा आय एवं सम्पत्ति की असमानता को कम करना, उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण (LPG) के दौर में गरीबों को सुरक्षा जाल प्रदान करना, तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास (Inclusive Growth) के पथ पर आगे बढ़ना आदि में सहयोग हेतु भारत में प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता है।

प्र.3. अल्प-विकसित देशों में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
Describe the need, importance and objectives of economic planning in under-developmed countries.

उत्तर अल्प-विकसित देशों में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता अथवा महत्त्व (Need or Importance of Economic Planning in Under-Developed Countries)

आर्थिक नियोजन विकसित एवं अल्प-विकसित दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं के विकास एवं समृद्धि के लिए आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण होता है। विकसित देशों में जहाँ नियोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को पूर्ण रोजगार के स्तर पर बनाए रखना है, वहीं अल्पविकसित देशों में इसका उद्देश्य स्थिरता (Stagence) के साथ विकास करना होता है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक नियोजन की तीव्र आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा, पूँजी की कमी, जनसंख्या की अधिकता, बाजार की अपूर्णताएँ, अविकसित मुद्रा एवं पूँजी बाजार, आय एवं उत्पादन में असमानताएँ, घोर गरीबी, नवीनता का विरोधी रूढ़िवादी (Consernative) समाज विद्यमान होता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए आर्थिक नियोजन आवश्यक है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य इन देशों में आय, बचत तथा निवेश के स्तर में वृद्धि करके पूँजी निर्माण की दर को बढ़ाना है। इन देशों में लगातार बढ़ती हुई श्रम शक्ति को लाभदायक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा उपलब्ध संसाधनों का समुचित विवेकपूर्ण (Discretionary) ढंग से विदोहन (Exploration) करना नियोजन के माध्यम से ही सम्भव है।

अल्पविकसित देशों में आर्थिक नियोजन के महत्त्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

1. **संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग**—अल्पविकसित देशों में सीमित साधन, अपूर्ण ज्ञान, पर्याप्त निरक्षरता, कुशल श्रमिकों की कमी, पूँजीगत एवं तकनीकी साधनों की कमी इत्यादि के कारण तीव्र गति से विकास एवं तकनीकी साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना सम्भव नहीं होता है। इससे देश के बहुत से संसाधन निष्क्रिय (Inactive) पड़े रहते हैं। आर्थिक नियोजन से इन साधनों का उचित उपयोग हो सकता है।
2. **आर्थिक कुचक्रों की समाप्ति**—अल्पविकसित देशों में कार्यकुशलता कम होती है, उत्पादन निम्न होता है तथा देश में निर्धनता व्याप्त होती है जिससे आर्थिक कुचक्र चलते रहते हैं। पूँजी का निर्माण धीमी गति से होता है। कुचक्रों को तोड़ने के लिए आर्थिक नियोजन आवश्यक होता है जिससे कि कार्यकुशलता (Skillness) में वृद्धि की जा सके, पूँजी-निर्माण की दर बढ़ाई जा सके तथा विनियोग की कुल मात्रा को प्रोत्साहित किया जा सके।
3. **शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव**—अर्धविकसित देशों में शिक्षा की कमी रहती है। वहाँ प्रशिक्षित व्यक्ति भी कम संख्या में ही मिलते हैं। आर्थिक नियोजन से शिक्षा का विस्तार होता है। प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे उद्योग, व्यापार, कृषि व अन्य क्षेत्रों के लिए सुयोग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति मिलने में सुविधा रहती है तथा उनका विकास तीव्र गति से होता है।
4. **पूँजी की कमी**—अर्धविकसित देशों में पूँजी-निर्माण की दर कम होती है अत: वहाँ पूँजी का अभाव बना रहता है। इन देशों में प्रतिव्यक्ति आय भी कम होती है। इस प्रकार विकास बहुत ही धीमी गति से होता है। आर्थिक नियोजन से उत्पादन बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तथा पूँजी-निर्माण की दर भी बढ़ती है जिससे पूँजी का अभाव कम होता है और देश का विकास तेजी से होता है।

TOUCH 'n PASS

5. **विभिन्न क्षेत्रों के विकास में समन्वय**—एक देश में विभिन्न क्षेत्र होते हैं। जैसे—वन, वृहत उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, लघु उद्योग, आदि। देश को समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाने के लिए इन सभी में समन्वय होना चाहिए। आर्थिक नियोजन इनमें समन्वय का कार्य करता है।
6. **बेरोजगारी की समस्या का समाधान**—भारत सहित अल्पविकसित देशों में पहले से ही व्याप्त बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अत: इस समस्या का समाधान करने के लिए आर्थिक नियोजन आवश्यक है।
7. **जनसंख्या की समस्या**—अर्धविकसित देशों में जनसंख्या बढ़ने की गति तीव्र रहती है जिसके कारण देश अपना आर्थिक विकास ठीक से नहीं कर पाते, अत: इस समस्या के समाधान के लिए भी नियोजन की आवश्यकता होती है।
8. **सम्पत्ति एवं साधनों का समान वितरण**—अल्पविकसित देशों में सम्पत्ति एवं अन्य साधनों का असमान वितरण रहता है जिससे इनका पूर्ण शोषण एवं देश का विकास नहीं हो पाता है। आर्थिक नियोजन का दृष्टिकोण समाजवादी होता है जिसमें सम्पत्ति एवं साधनों के समान वितरण की व्यवस्था की जाती है।
9. **आर्थिक संरचना का विकास**—किसी देश का सर्वांगीण विकास तभी सम्भव है जबकि इस देश में अन्य सुविधाएँ जैसे—बिजली, पानी, शक्ति एवं परिवहन, आदि भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, यह सुविधाएँ आर्थिक नियोजन के माध्यम से उपलब्ध की जा सकती हैं। इससे आर्थिक संरचना का विकास होता है।

भारत में नियोजन के उद्देश्य
(Objectives of Plannings in India)

अब तक के 675 वर्ष के नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार रहे हैं—

1. **आत्मनिर्भरता**—योजनाओं के प्रारम्भ से ही आत्मनिर्भरता (Self sufficiency) की बात कही गयी है, लेकिन तृतीय योजना ने इस पर विशेष बल दिया गया है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में तो विदेशी सहायता पर निर्भरता को न्यूनतम करने की बात कही गयी थी। आठवीं योजना में तकनीक, खाद्यान्न, सुरक्षा व साधनों की आत्मनिर्भरता का उद्देश्य रखा गया था जबकि नौवीं योजना से 12वीं योजना तक का उद्देश्य आत्मनिर्भरता के प्रयासों को मजबूत करना रहा है।
2. **राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि**—भारतीय नियोजन का दूसरा मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में तीव्र गति से वृद्धि करना रहा है जिससे कि जन-साधारण के जीवन-स्तर को ऊपर उठाया जा सके।
3. **समाजवादी समाज की स्थापना**—इन योजनाओं में समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर (Emphasis) दिया गया है। इसके लिए आर्थिक असमानताओं को कम करने तथा आम जनता को सामाजिक न्याय दिलाने का प्रयास किया गया है।
4. **रोजगार अवसरों की वृद्धि**—भारतीय नियोजन का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार सुविधाओं में वृद्धि का भी रहा है। प्रत्येक योजना में इस बात को शामिल किया गया है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कृषि, उद्योग, सेवाए, आदि का विस्तार किया गया है।
5. **अन्य उद्देश्य**—उपर्युक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त आर्थिक नियोजन के उद्देश्य भी रहे हैं; जैसे जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण, मूल्य स्थिरता, उद्योग एवं सेवाओं का विस्तार, खाद्य एवं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, आदि।
6. **कल्याणकारी राज्य की स्थापना**—भारतीय योजना का एक उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना रहा है, जिसके लिए आय एवं सम्पत्ति की असमानता को दूर करने की बात प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रत्येक योजना में कही जा रही है। पाँचवीं योजना से ही गरीबी (Poverty) दूर करने की बात कही गयी है। छठी योजना में भी इस उद्देश्य को पूरा करने के संकल्प को दोहराया गया, जबकि सातवीं तथा ग्यारहवीं योजना में पुन: गरीबी कम करने की बात पर जोर दिया गया।
7. **सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार**—भारत में आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जाए जिससे कि जिन क्षेत्रों में निजी उद्योगपति भारी विनियोग के कारण उद्योग स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जा सके तथा निजी क्षेत्र से प्रतियोगिता कर उनके शोषण की प्रवृत्ति को रोका जा सके। लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार कुछ ही क्षेत्रों के लिए सीमित कर दिया गया है।

TOUCH 'n' PASS

भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों की प्राप्ति
(Achieving the Objectives of Economic Planning in India)

भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता कहाँ तक प्राप्त हुई है यह प्रश्न विवादास्पद है। अर्थशास्त्रियों व राजनीतिज्ञों का मत है कि आर्थिक नियोजन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण सफल रहा है, जबकि कुछ इसको पूर्णतया असफल मानते हैं। हम मध्यम मार्ग अपनाकर यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णरूप से सफल न होकर आंशिक रूप से सफल रहा है। इसके लिए निम्न तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं—

1. **राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि**—भारत में 1950-51 में सकल राष्ट्रीय आय (चालू मूल्यों पर) ₹ 10,181 करोड़ थी, जो 2016-17 में बढ़कर ₹ 1,52,15,268 करोड़ तथा 2021-22 में ₹ 2,67,99,146 करोड़ हो गयी है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति निबल राष्ट्रीय आय (चालू मूल्यों पर) जो 1950-51 में ₹ 265 थी वहीं प्रति व्यक्ति आय (NNI) 2022 में 1.97 लाख हो गई। 2022-23 में निर्यात 447.46 बिलियन यू एस डॉलर होने का अनुमान है।
2. **आत्मनिर्भरता**—नियोजन के कारण ही आज हम आत्मनिर्भर होने की स्थिति में हैं। विदेशी सहायता भी हम कम ले रहे हैं और भविष्य में और भी कम लेने का अनुमान है। यह भी सम्भव है कि अगले वर्षों में बिना किसी विदेशी निर्भरता से ही अपना विकास कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय 2022-23 में 272.41 लाख करोड़ रूपये अनुमानित हैं।
3. **कल्याणकारी राज्य की स्थापना**—कल्याणकारी राज्य की स्थापना में भी हम अग्रसर हुए हैं। नियोजन काल में देश में शिक्षा का विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य, कल्याणकारी कार्यों में प्रगति हुई है। सामाजिक सेवाओं जैसे पिछड़ी जातियों के कल्याण, उचित मूल्य पर वस्तुओं का वितरण, परिवहन एवं संचार सेवाओं का विस्तार, आदि किया गया है।
4. **रोजगार सेवाओं में वृद्धि**—नियोजन काल में नये-नये उद्योगों की स्थापना एवं पुराने उद्योगों के विकास, परिवहन एवं संचार सेवाओं के विस्तार, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार, आदि के कारण रोजगार अवसरों में भारी वृद्धि हुई है।
5. **सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार**—नियोजन के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है। मार्च 2021 के अन्त में इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के 256 सार्वजनिक उपक्रमों में ₹ 30,38,492 करोड़ की पूँजी विनियोजित थी जिसमें उर्वरक, भारी एवं हल्की इंजीनियरिंग सामान, खनिज एवं धातु, उपभोक्ता माल, परिवहन, विपणन, आदि की सेवाएँ शामिल हैं।
6. **समाजवादी समाज की स्थापना**—आर्थिक नियोजन समाजवादी समाज की स्थापना करने में भी सहायता दे रहा है, यद्यपि अभी हम पूर्ण रूप से समाजवादी समाज की स्थापना नहीं कर पाये हैं।
7. **अन्य उद्देश्य**—आर्थिक नियोजन अन्य उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में आंशिक रूप से ही सफल रहा है। पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया है। उद्योगों का विकास हुआ है। कृषि उत्पादन बढ़ा है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण करने में भी सहायता मिली है। विदेशी व्यापार कुछ सन्तुलित हुआ है। परिवहन एवं संचार व्यवस्था का विस्तार हुआ है तथा आन्तरिक बचतें बढ़ी हैं।

प्र.4. भारत में पंचवर्षीय योजनाओं एवं बहु-स्तरीय नियोजन का सविस्तार विवरण दीजिए।
Give the description of five year plans and multi-level plan in India.

उत्तर

भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ एवं बहु-स्तरीय नियोजन
(Five year Plans and Multi-level Plans in India)

भारत में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद एक अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम विदोहन (Exploration) करना था। इस तरह, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से समाज में आर्थिक समानता के उद्देश्य से धन का पुनर्वितरण करना, लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करना, जनता के अधिकतम कल्याण में वृद्धि करना, देश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास कर सम्पूर्ण देश का संतुलित विकास करना, तीव्र विकास हेतु बेकार पड़े संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का प्रयास करना, देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) प्रदान करना, देश में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ देश की सुरक्षा पर ध्यान देना तथा बहु-स्तरीय नियोजन के माध्यम से राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य रहा है।

TOUCH 'n' PASS

भारत में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं एवं जन आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए योजनाएँ बनायी जाती हैं, जिसका संचालन केन्द्रीय नियोजन सत्ता (योजना आयोग) द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करते समय नियोजन के भौतिक तथा वित्तीय स्वरूप के मिश्रण को अपनाया गया है तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ देश के सर्वांगीण (Overall) एवं समावेशी (Inclusive) विकास का प्रयास किया गया है।

भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
(Five Year Plans of India)

भारत की प्रमुख पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1951 से प्रारंभ हुई थी, जबकि इस योजना का अंतिम प्रारूप दिसम्बर 1952 में प्रकाशित किया गया था। भारत में अब तक बारह पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। इस बीच तीन एक-एक वर्षीय योजनाएँ व एक वर्ष के अंतराल में भी नियोजन हुआ है।

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है—

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 1951 से 31 मार्च, 1956)
First Five Year Plan (April 1, 1951 to March 31, 1956)

प्रथम योजना की रूपरेखा में कहा गया था कि नियोजन का केन्द्रीय उद्देश्य जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना और उसके लिए एक अधिक समृद्धिशाली देश और विविधतापूर्वक जीवन के अवसर प्रदान करना है। इस मूल उद्देश्य के साथ ही पहली योजना में दो अन्य उद्देश्य भी निर्धारित किए गए—(1) दूसरे विश्वयुद्ध एवं देश-विभाजन के फलस्वरूप देश में जो समस्याएँ उत्पन्न हो गई थीं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो असन्तुलन आ गया था, उन्हें दूर करना (2) देश की अर्थव्यवस्था के आधार को सुदृढ़ करना और उसमें इस प्रकार के संस्थागत परिवर्तन लाना जिससे भविष्य में तेजी से अधिक विकास सम्भव हो सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल परिव्यय ₹ 1,960 करोड़ था। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 11% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि 17.5% रही। कृषि प्रधान योजना होने के कारण कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। वर्ष 1955-56 में खाद्यान्नों का उत्पादन 64.8 मिलियन टन था, जो लक्ष्य से 3 मिलियन टन अधिक था। यद्यपि इस योजना में औद्योगिक विकास पर कम ध्यान दिया गया, लेकिन फिर भी औद्योगिक उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई। इस योजना में भूमि सुधार, सामुदायिक विकास तथा सहकारी संगठनों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में संस्थागत (Institutional) परिवर्तनों की शुरुआत हुई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 1956 से 31 मार्च, 1961)
Second Five Year Plan (April 1, 1956 to March 31, 1961)

इस योजना के विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार करते समय समाजवादी समाज की स्थापना करने के दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया। इस योजना के उद्देश्य निम्न थे—

1. **जीवन स्तर को उन्नत बनाना**—योजना का प्रमुख उद्देश्य देश के लोगों का जीवन स्तर ऊँचा करना था, जिसके लिए पाँच वर्षों से राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि करने का लक्ष्य (Target) रखा गया था।
2. **तीव्र औद्योगीकरण**—द्वितीय योजना के उद्देश्यों में तीव्र औद्योगीकरण (Rapid Industrialisation) को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया और इस दृष्टि से आधारभूत एवं भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई।
3. **रोजगार में वृद्धि**—देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने की दृष्टि से एक उद्देश्य यह भी रखा गया कि देश में रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि की जाए।
4. आर्थिक विषमताओं में कमी-देश में आय तथा सम्पत्ति की विषमताओं में कमी करना, न्याय और समानता को बनाए रखा जा सके।

द्वितीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय की राशि ₹ 4,672 करोड़ थी। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि 20% रही। योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दिए जाने के कारण औद्योगिक उत्पादन का निर्देशांक सन् 1956 में 139 से बढ़कर 1961 में 194 हो गया। इस योजना में लौह एवं इस्पात उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन विशाल कारखाने—दुर्गापुर, (ब्रिटेन की सहायता से) भिलाई (सोवियत संघ की सहायता से) एवं राउरकेला (पश्चिमी जर्मनी की सहायता से) स्थापित किए गए। इस योजना में खाद्यान्नों का उत्पादन सन् 1955-56 में 64.8 मि. टन से बढ़कर सन् 1960-61 में 76 मिलयन टन हो गया।

TOUCH 'n PASS

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 1961 से 31 मार्च, 1966)
Third Five Year Plan (April 1, 1961 to March, 31, 1966)

तृतीय पंचवर्षीय योजना में आत्म-निर्भर और आत्म-वाहक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने पर जोर दिया गया। इस योजना में निर्धारित मुख्य उद्देश्य निम्न थे—

1. **राष्ट्रीय आय में वृद्धि**—राष्ट्रीय आय में 5% वार्षिक से अधिक की वृद्धि करना तथा विनियोग इस प्रकार करना कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि का क्रम अगली योजनाओं में भी चलता रहे।
4. **खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता**—कृषि क्षेत्र में यह उद्देश्य रखा गया कि खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता की प्राप्ति का प्रयास किया जाएगा और अन्य कृषि उत्पादनों में इतनी वृद्धि की जाएगी कि घरेलू उद्योगों और निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
5. **आधारभूत उद्योगों का विकास**—आधारभूत उद्योगों का इस प्रकार विकास करना कि भावी औद्योगीकरण की सभी आवश्यकताओं को देश के आन्तरिक साधनों द्वारा ही पूरा किया जा सके।
2. **मानवीय शक्ति का प्रयोग**—देश की मानवीय शक्ति (Human Power) का यथासम्भव पर्याप्त उपयोग करना तथा देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
3. **आर्थिक शक्ति के वितरण में समानता**—अवसर की समानता की अधिकाधिक स्थापना करना, आय तथा सम्पत्ति की असमानता में कमी लाना और आर्थिक शक्ति के वितरण में समानता लाना।

तृतीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल परिव्यय ₹ 8,577 करोड़ था। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 5% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वार्षिक वृद्धि योजना के प्रथम चार वर्षों में क्रमश: 2.5%, 1.7%, 4.9% और 7.6% हुई, किन्तु अन्तिम वर्ष (1965-66) में इसमें 3.9% की गिरावट आयी। औद्योगिक विकास का लक्ष्य 11% रखा गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 7.9% वार्षिक रही।

तीन वार्षिक योजनाएँ (1 अप्रैल, 1966 से 31 मार्च, 1969)
Three Annual Plans (April 1, 1966 to March 31, 1969)

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों में गम्भीर सूखा, मुद्रा के अवमूल्यन, मूल्यों में वृद्धि, वित्तीय, संसाधनों की समस्या तथा 1965 में भारत-पाक युद्ध के कारण चतुर्थ योजना को अन्तिम स्वरूप देने में देरी लग गयी और इस कारण तीन वार्षिक योजनाएँ संचालित की गईं। इस अवधि को कुछ अर्थशास्त्रियों ने 'योजना अवकाश' (Plan Holiday) का नाम भी दिया, क्योंकि इस अवधि में नियमित नियोजन नहीं अपनाया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1974)
Fourth Five Year Plant (April 1,1969 to March 31,1974)

चतुर्थ योजना के दो मुख्य लक्ष्य रखे गए थे—स्थिरता के साथ विकास (Growth with Stability) तथा 'आत्म-निर्भरता (Self sufficiency) की अधिकाधिक प्राप्ति'। इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से चतुर्थ योजना के विस्तृत उद्देश्य निम्न निर्धारित किए गए (1) आर्थिक विकास लगभग 51/2 प्रति वर्ष की दर से करना। (2) कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में आत्म-निर्भरता लाना। (3) जनसंख्या की वृद्धि रोकने तथा जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लागू करना। (4) मूल स्थायित्व को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा-स्फीतिकजनक तत्त्वों (Inflitory Elements) को रोकने तथा घाटे की वित्त व्यवस्था को दूर करना। (5) कपड़ा, चीनी, दवाइयां, तेल, कागज तथा अन्य समान, उपभोग की वस्तुओं, जिन पर उपभोक्ता अपनी राय का अधिकांश भाग व्यय करता है, के उत्पादन को प्रोत्साहन देना। (6) सामाजिक सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहित करना। (7) आर्थिक असमानताओं (Elonomic) को दूर करना। (8) पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल देना। (9) बेरोजगारी जैसी गम्भीर समस्या को हल करना (Disparity), (10) निर्यात में प्रति वर्ष 7% की बृद्धि करना।

चतुर्थ योजना में सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) का परिव्यय ₹ 15,779 करोड़ था। इस योजना में शुद्ध घरेलू आय में 5.7% प्रति वर्ष वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तविक औसत वृद्धि 3.2% ही रही। कृषि उत्पादन में प्रति वर्ष लगभग 5% वृद्धि का लक्ष्य रखा था, लेकिन वास्तविक उपलब्धि 2.57% रही। औद्योगिक उत्पादन में प्रतिवर्ष 8 से 10 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद की गई थी, लेकिन वास्तविक उपलब्धि काफी कम रही।

TOUCH 'n PASS

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च, 1979)
Fifth Five Year Plant (April 1, 1974 to March 31, 1979)

पाँचवीं योजना में दो मुख्य और आधारभूत लक्ष्य रखे गए थे—'गरीबी उन्मूलन' (Removal of Poverty) तथा 'आर्थिक आत्म-निर्भरता' (Economic Self-reliance)।

इस योजना में उद्देश्यों के रूप में निम्न बातें रखीं गयीं—

(1) आर्थिक विकास में 4.37% प्रति वर्ष की वृद्धि। (2) उत्पादन रोजगार की सम्भावनाओं में विस्तार। (3) न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, पीने के पानी की व्यवस्था, गाँवों में शिक्षा का प्रबन्ध, पौष्टिक आहार, भूमिहीन, श्रमिकों को मकान बनाने को जमीन, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, बिजली सुविधाओं में वृद्धि तथा गन्दी बस्तियों का सुधार और सफाई शामिल है। (4) समाज कल्याण (Social welfare) के अधिक व्यापक कार्यक्रम। (5) खेती, प्रमुख और बुनियादी उद्योगों तथा व्यापक उपभोग की चीजें बनाने वाले उद्योगों पर विशेष जोर। (6) खपत की अनिवार्य वस्तुओं की निश्चित पूर्ति करने की व्यवस्था। (7) निर्यात की तेजी से वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापना। (8) गैर-जरूरी उपभोग पर प्रभावशाली प्रबिन्ध। (9) मूल्यों, वेतनों तथा आयों में उचित सन्तुलन (10) सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए संस्थागत, वित्तीय एवं अन्य उपाय।

पाँचवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल परिव्यय ₹ 39,426 करोड़ हुआ। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 5.5% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

छठवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1985)
Sixth Five Year Plan (April 1, 1980 to March 31, 1985)

छठवीं योजना में 'गरीबी उन्मूलन' (Removal of Poverty) तथा रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान करने को मुख्य एवं आधारभूत लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया गया। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छठवीं योजना में निर्धारित किए गए उद्देश्य अग्र प्रकार थे—

1. **विकास दर में वृद्धि**—आर्थिक विकास की वृद्धि दर में महत्त्वपूर्ण वृद्धि करना और इसके लिए उत्पादकता में वृद्धि तथा संसाधनों के मितव्ययी प्रयोग को प्रोत्साहित करना।
2. **आधुनिकीकरण की सुदृढ़ता**—देश में आधुनिकीकरण (Modernization) की प्रवृत्तियों को सुदृढ़ करना, जिससे आर्थिक एवं तकनीकी आत्म-निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
3. **निर्धनता एवं बेरोजगारी में कमी**—देश में निर्धनता एवं बेरोजगारी के भार में निरन्तर (Consistent) कमी करने का प्रयास करना।
4. **ऊर्जा विकास**—देश में ऊर्जा संसाधनों (Energy Resources) की कुशलता एवं संरक्षण के साथ ही घरेलू साधनों के तीव्र विकास पर जोर देना।
5. **जीवन-स्तर में सुधार**—देश में सामान्य रूप से जीवन-स्तर में सुधार पर जोर देना तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के जीवन-स्तर में सुधार के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं (Minimum Requirements) की पूर्ति कार्यक्रम को लागू करना।
6. **जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण**—देश में लघु परिवार की ऐच्छिक भावना को प्रोत्साहित करके जनसंख्या वृद्धि की दर (Rate or Population Growth) को नियन्त्रित करने का प्रयास करना।
7. **क्षेत्रीय विषमताओं में कमी**—आर्थिक विकास में यह ध्यान रखना कि देश में क्षेत्रीय विषमताओं (Regional Disparity) में प्रगतिशील रूप में कमी लाई जा सके।
8. **आर्थिक विषमताओं में कमी**—सरकारी नीतियों एवं सेवाओं में निर्धनों के पक्ष में पुनर्वितरणात्मक तत्त्व शामिल करना, जिससे देश में आय एवं सम्पत्ति (Property) के वितरण की असमानताओं में कमी हो सके।
9. **योजना में व्यापक जन भागिता**—शिक्षा और संचार के उचित माध्यमों एवं संस्थागत व्यवस्थाओं के विकास द्वारा इस बात का प्रयास करना कि आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में सभी वर्गों के व्यक्तियों की सक्रिय भागिता (Active Participation) हो।

TOUCH 'n' PASS

10. **विकास लक्ष्यों में समन्वय**—देश में पर्यावरणीय (Ecological) तथा वातावरणीय (Environmental) सम्पत्तियों में सुधार तथा संरक्षण के विकास में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्यों (Targets) में समन्वय बनाए रखना।

छठवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल परिव्यय ₹ 1,09,292 करोड़ था। इस योजना में फैक्टर लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.2% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था और वास्तविक उपलब्धि 5.54% रही।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1990)
Seventh Five Year Plant (April 1, 1985 to March 31, 1990)

सातवीं योजना के उद्देश्यों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

(1) योजना का विकेन्द्रीकरण (Decentralisation of Plan), (2) उत्पादक रोजगारों का अधिकतम सृजन, (3) खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता (Self sufficiency in Cereals), (4) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का तेजी से क्रियान्वयन, (5) सामाजिक उपभोग के स्तर में वृद्धि, (6) आत्म-निर्भरता के स्तर में वृद्धि (7) छोटे परिवार की स्वीकृति एवं महिलाओं की सकारात्मक भूमिका, (8) संरचनात्मक कठिनाइयों में कमी, (9) उद्योगों में कुशलता, आधुनिकीकरण एवं प्रतियोगिता, (10) ऊर्जा की बचत तथा गैर-परम्परागत साधनों का विकास, (11) विज्ञान एवं तकनीक का समन्वय (Integration of seience and Technology), (12) पर्यावरण एवं वातारण, (13) इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय ₹ 2,18,730 करोड़ था।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1997)
Eighth Five Year Plan (April 1, 1992 to March 31, 1997)

आठवीं पंचवर्षीय योजना में निम्न उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई थी—

1. **रोजगार सृजन**—आठवीं योजना में पर्याप्त मात्रा में रोजगार अवसर उत्पन्न करने पर ध्यान दिया गया, जिससे वर्ष 2000 तक लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो सके।
2. **जनसंख्या नियन्त्रण**—जनता के सक्रिय सहयोग और प्रेरणाओं तथा प्रतिबन्धों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान।
3. **प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता**—प्राथमिक शिक्षा (Primary Education) को अनिवार्य बनाने तथा 15 वर्ष से 35 वर्ष और गैर-साक्षरता को पूरक समाप्त करने पर बल।
4. **जल एवं स्वास्थ्य सेवाएँ**—योजना अवधि में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था और अधिक विकसित करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तृत करने पर जोर दिया गया।
5. **कृषि विकास**—खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने तथा निर्यात के लिए कृषि उत्पादों में आधिक्य (Surplus) बढ़ाने के लिए कृषि विकास एवं विविधीकरण (Variation) पर ध्यान।
6. **आधारभूत संरचना**—देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को निरन्तर एवं स्थिर आधार पर बनाए रखने की दृष्टि से ऊर्जा, परिवहन, सन्देशवाहन तथा सिंचाई जैसी आधारभूत संरचना (Fundamental Structure) को सुदृढ़ करना।

आठवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय, ₹ 4,34,100 करोड़ था। यह उल्लेखनीय है कि सन् 1991 में देश में आर्थिक सुधारों का प्रारम्भ किया गया था और उन्हीं सुधारों के सन्दर्भ में आठवीं योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2002)
Ninth Five Year Plan (April 1, 1997 to March 31, 2002)

नौवीं पंचवर्षीय योजना स्वतंत्र भारत के पचासवें वर्ष में प्रारम्भ की गई। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार थे—

1. **रोजगार और ग्रामीण विकास**—पर्याप्त रोजगार प्रदान करने और गरीबी (Poverty) की समाप्ति के लिए कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता।
2. **स्थिरता के साथ विकास**—मूल्य में स्थिरता (Stability) बनाए रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना।
3. **पोषण सुरक्षा**—सभी को और विशेष रूप से समाज में कमजोर वर्गों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा (Nutrition Security) निश्चित करना।
4. **मूलभूत सामाजिक सेवाएँ**—स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत सेवाओं के विकास को प्राथमिकता।

TOUCH 'n' PASS

5. **जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण**—योजना में जनसंख्या वृद्धि (Population Growth) पर समुचित नियन्त्रण पर बल दिया गया।
6. **क्षेत्रीय सन्तुलन**—देश में क्षेत्रीय असन्तुलन (Regional imbalance) को दूर करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और सहायक क्रियाओं के आधुनिकीकरण पर बल देना।
7. **आत्मनिर्भरता**—आर्थिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयासों को सुदृढ़ करना।
8. **सामाजिक**—आर्थिक परिवर्तन तथा विकास एजेन्ट के रूप में महिलाओं तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यकों को शक्तियाँ प्रदान करना।
9. पंचायत राज संस्थाओं, सहकारिताओं तथा स्वयंसेवी वर्गों जैसे जन भागीदारी वाली संस्थाओं को बढ़ावा देना एवं उनका विकास करना।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2007)
Tenth Five Year Plans (April 1, 2002 to March 31, 2007)

यह योजना 21 दिसम्बर, 2002 को राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Developemnt Council) द्वारा अनुमोदित की गई थी। योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार थे—

1. **विकास दर**—वर्ष 2002-07 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Developemnt Product) (GDP) में 8% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य।
2. **जीवन की गुणवत्ता में सुधार**—इस योजना में सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया। इसमें केवल खाद्यान्न तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उपयुक्त स्तर को ही शामिल नहीं किया गया बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आधारिक सफाई इत्यादि आधारभूत सामाजिक सेवाओं को भी प्राप्त करने के प्रयास पर जोर दिया गया।
3. **निर्धनता में कमी**—निर्धनता अनुपात को वर्ष 2007 तक 5% बिन्दुओं तक घटाने का प्रयास।
4. **लाभकारी रोजगार**—योजना में श्रमबल (Workpower) में हुई अतिरिक्त (Additional) वृद्धि को उच्चकोटि का लाभकारी रोजगार प्रदान करना।
5. **सर्वव्यापी शिक्षा**—वर्ष 2007 के अन्त तक सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा (Universal Primary Education) की सुविधा सुलभ कराना।
6. **लिंग अन्तरों में कमी**—शिक्षा और मजदूरी की लिंग दरों में 50% कमी करना।
7. **जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी**—वर्ष 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर को 16.2% के स्तर पर लाना।
8. **साक्षरता दर में वृद्धि**—योजना के अन्त तक साक्षरता दर (Literacy Rate) को बढ़ाकर 75% तक करना।
9. **शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी**—वर्ष 2007 तक शिशु मृत्यु दर को 45 तथा मातृत्व मृत्यु दर को 2 प्रति एक हजार जीवित जन्म तक कम करना।
10. **पर्यावरण संरक्षण**—इसके अन्तर्गत वर्ष 2007 तक वनों तथा वृक्षों के अन्तर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25% करना तथा सभी प्रदूषित नदियों की सफाई का कार्य पूर्ण करने पर जो दिया गया।
11. **पेयजल का प्रावधान**—योजना के अन्त तक प्रत्येक गाँव में पेयजल का प्रबन्ध करना।
12. **विकास, समानता और धारणीयता**—इस योजना में समता तथा सामाजिक न्याय के साथ निरन्तर विकास (Consistent Development) पर जोर दिया गया।
13. **सभी राज्यों में सन्तुलित विकास**—सभी राज्यों में सन्तुलित विकास निश्चित करने का प्रयास करना।

दसवीं योजना में विकास दर का लक्ष्य 8% वार्षिक रखा गया। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय की राशि ₹ 15,92,000 करोड़ रखी गयी थी, लेकिन वास्तविक व्यय ₹ 15,25,639 करोड़ हुआ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2012)
Eleventh Five Year Plan (April 1, 2007 to March 31, 2012)

1 अप्रैल, 2007 से प्रारम्भ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-2012 की अवधि में औसतन 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजनावधि में सूखे एवं वैश्विक मन्दी के कारण वर्ष 2008-09 में 6.7

TOUCH 'n PASS

प्रतिशत व 2009-10 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि ही प्राप्त की जा सकी है। वर्ष 2010-11 में भी वृद्धि 8.5 प्रतिशत ही रहने का अनुमान था। इस कारण 24 जुलाई, 2010 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की 55वीं बैठक में योजना के लक्ष्य को 9 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। अंतत: 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7.9% वार्षिक वृद्धि प्राप्त की गई। इससे पहले दसवीं योजना (2002-07) में औसतन 7.6 प्रतिशत व नौवीं पंचवर्षीय योजना में 5.52 प्रतिशत वार्षिक विकास दर प्राप्त की गई थी।

9 प्रतिशत विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कृषि क्षेत्र के विकास की दर को 4 प्रतिशत तक ले जाना, औद्योगिक व सेवा क्षेत्र की दर को बढाकर 9 से 11 प्रतिशत तक करना, आयात की विकास दर को बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत तक तथा निर्यात की दर को 16.4 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

इसके लिए कर ढाँचे में सुधार के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त करना, 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (एसईजेड्स) को बढ़ावा देना, उद्योगों का आधुनिकीकरण, निवेश के अनुकूल वातावरण, श्रम आधारित उत्पादन की इकाइयों की स्थापना, कुटीर उद्योगों की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन के अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम में जरूरी बदलाव करने पर जोर दिया गया। सड़क, रेल, वायु एवं जल परिवहन, ऊर्जा उत्पादन-वितरण, जनसंचार, जलापूर्ति, सिंचाई तथा जल सम्भरण पर जीडीपी के 4.6 प्रतिशत निवेश को बढ़ाकर 7 से 8 प्रतिशत के स्तर तक ले जाने की बात की गयी।

ग्यारहवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय ₹ 36,44,718 करोड़ रखा गया था। लेकिन वास्तविक व्यय ₹ 36,76,936 करोड़ हुआ।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2017)
Twelfth Five Year Plan (April 1, 2012 to March 31, 2017)

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी (Inclusive) विकास की व्यूह रचना की गई थी। इस योजना में ऊर्जा, परिवहन, ग्रामीण व अवसंरचना पर ध्यान दिया गया था। इसके साथ ही कृषि, विनिर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास, नवोन्मेष तथा पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया था।

बारहवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि का लक्ष्य 8.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष रखा गया था, सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत प्रति वर्ष रहीं।

बारहवीं योजना (2012-17) के पाँच वर्षों में 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 की कीमतों पर) की वृद्धि दर क्रमश: 5.1%, 6.9%, 7.2%, 7.6% तथा 7.1% रही। इन्हीं वर्षों में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर क्रमश: 2.4%, 4.5%, 7.5%, 8.8% तथा 5.6% रही। इसी तरह बारहवीं योजना में कृषि क्षेत्र का स. घ. उ. में क्रमश: 1.2%, 3.7%–0.2%, 0.7% तथा 4.9% का योगदान रहा।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का आकार ₹ 80,50,113 करोड़ रखा गया था, जिसमें केन्द्र का हिस्सा ₹ 43,33,739 करोड़ तथा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा ₹ 37,16,385 करोड़ था।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना देश की अंतिम योजना थी, क्योंकि योजना प्रक्रिया अब समाप्त कर दी गई है। 1950 में स्थापित योजना आयोग के स्थान पर अब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) का गठन किया गया है जो 1 जनवरी, 2015 से अस्तित्त्व में आया है। यह आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा तथा केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाली संस्था का दायित्व वहन करेगा।

प्र.5. भारत में बहु-स्तरीय योजना के विभिन्न चरणों का वर्णन विस्तार से कीजिए।
Describe various steps of multi-level plan in India in detail.

उत्तर

भारत में बहु-स्तरीय योजना के पाँच चरण
(Five Steps of Multi-Level Plan in India)

बहु-स्तरीय क्षेत्रीय योजना की अवधारणा को 'विभिन्न क्षेत्रों के लिए योजना' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मिलकर एक प्रणाली और अधीनस्थ प्रणाली बनाते हैं। बहु-स्तरीय नियोजन में, नियोजन के विभिन्न स्तर उच्च स्तरीय नियोजन के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसी प्रकार, उच्च स्तरीय क्षेत्रीय योजनाएँ निचले स्तर की योजनाओं के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करती हैं। ऐसी योजनाओं में योजना प्रक्रिया में लोगों की सीधी भागीदारी (Participation) होती है। बहु-स्तरीय नियोजन में, प्रत्येक क्षेत्र / इकाई एक प्रणाली का गठन करती है और इसलिए, नियोजन प्रक्रिया (Planning Process) अधिक प्रभावी हो जाती है। भारत में बहु-स्तरीय योजना के निम्नलिखित पाँच चरणों को मान्यता दी गई है। इसमे निम्न शामिल हैं।

TOUCH 'n' PASS

राष्ट्रीय स्तर की योजना
(National Level Planning)

राष्ट्रीय स्तर पर, योजना आयोग देशों की योजना के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। प्रधानमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष हैं। यह न केवल देश के लिए योजनाएँ तैयार करता है बल्कि केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न मंत्रालयों के क्षेत्रीय विकास कार्यों का समन्वय भी करता है। योजना आयोग के कार्यों की देखरेख राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से की जाती है।

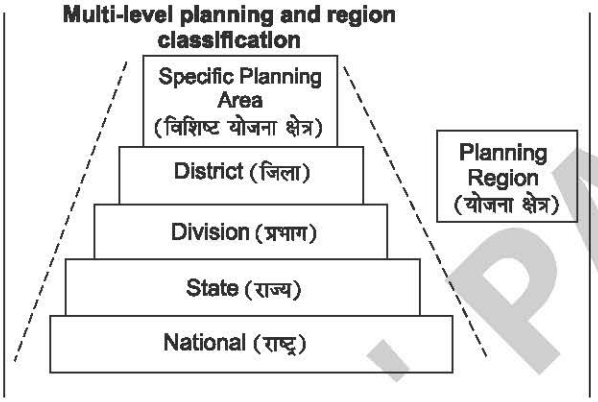

संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से योजना आयोग (Planning Commission) को संवैधानिक दर्जा (Constitutional Status) दिया गया है। कोई भी बड़ी योजना योजना आयोग की पूर्वानुमति के बिना क्रियान्वित नहीं की जा सकती। आयोग तीन प्रकार की योजनाएँ बनाता है।

(i) 15-25 वर्षों के लिए संभावित योजनाएँ
(ii) पंचवर्षीय योजनाएँ
(iii) पंचवर्षीय योजना के ढाँचे के भीतर वार्षिक योजनाएँ।

योजना आयोग का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, इसमें पूर्णकालिक (Wholetime) सदस्य होते हैं जो योजना बनाने में प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं और पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पूर्णकालिक सदस्यों में उपाध्यक्ष होते हैं और इसमें अर्थशास्त्र, उद्योग, विज्ञान और सामान्य प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसमें वित्त, कृषि, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून, मानव संसाधन विकास और योजना राज्य मंत्री जैसे प्रासंगिक विभागों के मंत्री भी शामिल हैं।

संगठन संरचना एवं कार्य
(Organisation Structure and Function)

इसमें 11 मुख्य विभाग और 20 अधीनस्थ विभाग हैं और यह 31 प्रभाग बनाता है जिसके लिए योजना आयोग योजना पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके कार्य के दो मुख्य विभाग हैं। वे सामान्य योजना प्रभाग और कार्यक्रम प्रशासन प्रभाग हैं। आयोग का मुख्य कार्य योजना बनाना है। अन्य कार्यों में देश में आर्थिक सर्वेक्षण, मानव संसाधन और पूँजी मूल्यांकन शामिल हैं। इसका संबंध देश के विकास में बाधा डालने वाले किसी भी कारक को हटाने से भी है।

योजना आयोग
(Planning Commission)

योजना आयोग हमारे देश में योजना प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए तकनीकी निकाय है। इसकी स्थापना सरकार द्वारा मार्च, 1950 में की गई थी। इसके कार्य हैं—

(i) तकनीकी कर्मियों सहित देश की सामग्री, पूँजी और मानव संसाधनों का आकलन करना और उन संसाधनों को बढ़ाने की संभावनाओं की जाँच करना जो देश की आवश्यकताओं के संबंध में कम पाए जाते हैं।
(ii) देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग हेतु योजना बनाना।

TOUCH 'n' PASS

(iii) प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के लिए, उन चरणों को परिभाषित करें जिनमें योजना को पूरा किया जाना चाहिए और प्रत्येक चरण को उचित रूप से पूरा करने के लिए संसाधनों के आवंटन का प्रस्ताव रखें। उन कारकों को इंगित करना जो आर्थिक विकास को बाधित करते हैं और उन स्थितियों को निर्धारित करना है जो वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए बनाई जानी चाहिए।

(iv) मशीनरी की प्रकृति का निर्धारण करना, जो योजना के प्रत्येक चरण के सभी पहलुओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगी।

(v) समय-समय पर, योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में प्राप्त प्रगति का मूल्यांकन करना और नीति और उपायों के समायोजन की सिफारिश करना, जो इस तरह के मूल्यांकन को आवश्यक साबित कर सकते हैं।

(vi) ऐसी अंतरिम या सहायक सिफारिशें करना जो उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों के निर्वहन को सुविधाजनक बनाने के लिए या मौजूदा आर्थिक स्थितियों, वर्तमान नीतियों, उपायों और विकास कार्यक्रमों पर विचार करने या ऐसी विशिष्ट समस्याओं की जाँच के लिए उपयुक्त प्रतीत हों। इसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सलाह के लिए भेजा जाएगा।

1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर 'नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग' कर दिया गया, जो भारत सरकार का एक नीतिगत विचार है, जिसकी स्थापना सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। भारत की राज्य सरकारें आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग कर रही हैं। इसकी पहलों में '15 साल का रोड मैप', '7 साल का विजन, रणनीति और कार्य योजना', अमृत, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, चिकित्सा शिक्षा सुधार, कृषि सुधार (मॉडल लैंड लीजिंग कानून, कृषि उपज विपणन समिति के सुधार) शामिल हैं। राज्यों की रैंकिंग के लिए अधिनियम, कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक), स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन में राज्य के प्रदर्शन को मापने वाले सूचकांक, कृषि और गरीबी उन्मूलन पर कार्य बल। इसके कार्य हैं—

(i) राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।

(ii) यह मानते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।

(iii) ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ तैयार करने और इन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर उत्तरोत्तर एकत्र करने के लिए तंत्र विकसित करना।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन क्षेत्रों को विशेष रूप से संदर्भित किया गया है, उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है।

(v) हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न मिलने का खतरा हो सकता है।

(vi) राष्ट्रीय विकास एजेंडा और ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अन्य गतिविधियाँ करना।

राज्य स्तरीय योजना (State Level Planning)

राज्य स्तर पर नियोजन का तंत्र लगभग राष्ट्रीय स्तर जैसा ही है। राज्य योजना बोर्ड राष्ट्रीय योजना आयोग की तरह कार्य करता है और विभिन्न मंत्रालयों और जिलों की विकास योजनाओं का समन्वय करता है। इसके पास राज्य योजना के निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी भी है। योजनाओं के निर्माण और संसाधनों के आवंटन के संबंध में यह योजना आयोग के साथ लगातार संपर्क में है।

देश की संघीय व्यवस्था के तहत राज्यों को कुछ राज्य विषयों में स्वायत्तता प्राप्त है और वे योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य स्तर पर सभी प्रकार के आर्थिक और सामाजिक डेटा उपलब्ध होते हैं और क्षेत्रीय हितों और माँगों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएँ तैयार की जा सकती हैं। इसलिए, राज्य स्तर पर योजना के अधिक कठोर अभ्यास की आवश्यकता है। जो राज्य अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत हैं और योजना निर्माण और कार्यान्वयन में रुचि दिखा रहे हैं, वे विकास कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

TOUCH 'n PASS

किसी राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र की तरह, राज्यपाल सीधे तौर पर उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता जो उसमें निहित हैं। इनका प्रयोग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के माध्यम से किया जाता है। मंत्रिपरिषद की सलाह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होती है। मंत्रिपरिषद सचिवालय के माध्यम से काम करती है जिसका नेतृत्व एक सचिव करता है। सचिवालय के मुख्य कार्य मंत्रियों को नीति निर्माण और उनकी विधायी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता करना, नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय, व्यय का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, प्रशासन का कुशल संचालन आदि से संबंधित हैं।

1. विकास विभाग (जिसमें कृषि और पशुपालन, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक कार्य और उद्योग विभाग शामिल हैं)।
2. समाज कल्याण विभाग (शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण विभाग सहित)।
3. समन्वय विभाग (गृह, राजस्व, वित्त और योजना विभाग वाले)।

केंद्र सरकार के पास संघ सूची (Union List) में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है जबकि राज्य सरकारों के पास राज्य सूची (State List) में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। जहाँ तक समवर्ती सूची (Concurrent List) में शामिल विषयों का सवाल है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास उन पर कानून बनाने की शक्तियाँ हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्रीय कानून ही मान्य (Valid) होता है। उद्योग, खनिज, रेलवे और दूरसंचार जैसी संगठित गतिविधियाँ केंद्र की ज़िम्मेदारियों के अंतर्गत आती हैं, जबकि कृषि, भूमि राजस्व का संग्रह, सिंचाई, बिजली, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन और कई अन्य महत्त्वपूर्ण विषय राज्यों के नियंत्रण में आते हैं।

जिला स्तरीय योजना (District Level Planning)

जिला स्तरीय नियोजन की अवधारणा स्थानीय स्तरीय नियोजन के सिद्धांत पर आधारित है। यह भी माना जाता है कि योजना की सफलता के लिए स्थानीय संसाधनों को अधिक से अधिक जुटाने और उपयोग करने की आवश्यकता है। राज्य के नीचे, जिला अपने स्थान और प्रशासनिक लाभों के कारण योजना में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए न केवल इसके पास पर्याप्त प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता (Administrative and Technological Speciality) और डेटा और जानकारी का अच्छा स्रोत है, बल्कि लोगों की भागीदारी को शामिल करने और योजना के लाभों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली भी है। जिला बोर्ड में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो योजना बनाने की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए, विद्वानों का एक बड़ा समूह है जो जिले को सूक्ष्म स्तरीय योजना की एक आदर्श और व्यवहार्य इकाई मानता है।

जिला योजना एक जिले में स्थानीय सरकारी क्षेत्र के लिए उपलब्ध संसाधनों (प्राकृतिक, मानवीय और वित्तीय) को ध्यान में रखते हुए एक एकीकृत (Integrated) योजना तैयार करने और जिला स्तर और उससे नीचे सौंपी गई क्षेत्रीय गतिविधियों और योजनाओं और स्थानीय के माध्यम से कार्यान्वित (Implement) की जाने वाली योजना तैयार करने की प्रक्रिया है। किसी राज्य में सरकारें. राज्य स्तर से नीचे विकेन्द्रीकृत (Decentralised) योजना के लिए जिला सबसे उपयुक्त प्रशासनिक इकाई है क्योंकि इसमें आवश्यक विविधता है और यह योजना और कार्यान्वयन में लोगों को शामिल करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए काफी छोटा है; जिला नियोजन एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है। इसकी सामग्री निम्न होगी—

(i) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र
(ii) जल स्रोतों की उपलब्धता एवं विकास
(iii) उद्योग - विशेष रूप से पारंपरिक, खाद्य प्रसंस्करण सहित छोटे उद्योग
(iv) बिजली सहित बुनियादी ढाँचा
(v) पेयजल एवं स्वच्छता
(vi) साक्षरता, स्कूली शिक्षा
(vii) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएँ
(viii) गरीबी उन्मूलन और बुनियादी जरूरतें
(ix) लिंग और बच्चे
(x) सामाजिक न्याय-एससी/एसटी, विकलांग व्यक्ति

TOUCH 'n' PASS

ब्लॉक स्तरीय योजना (Block Level Planning)

ब्लॉक सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की एक महत्त्वपूर्ण इकाई है। ये विकास खंड पहली पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan) के दौरान शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बनाए गए थे। प्रत्येक जिले को कई ब्लॉकों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 100 गाँव शामिल थे, जिनकी आबादी लगभग 60,000 थी।

कार्यक्रम में स्थानीय संसाधनों को जुटाने, निर्णय लेने और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी की कल्पना की गई। इसलिए, ब्लॉक विकास अधिकारी और विभिन्न विशेषज्ञों और ग्राम स्तर के कार्यकर्त्ताओं (अधिकारियों) की एक टीम के नेतृत्व में ब्लॉक स्तर पर योजना की एक नई इकाई बनाई गई। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1978-1983) में क्षेत्र नियोजन का विकल्प चुना गया। रोजगार के उद्देश्यों को प्राप्त करने और ग्रामीण विकास पर जोर देने के लिए ब्लॉक स्तरीय योजना को प्राथमिकता।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय श्रम अधिशेष को अवशोषित करना और विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन (Implementation) में लोगों की अधिक भागीदारी (Participation) थी। इसलिए, 1983 के अंत तक राष्ट्रीय प्रणाली में एकीकृत ब्लॉक स्तरीय योजना को अपनाने की प्रणाली उपलब्ध थी।

यह कृषि, सिंचाई (मुख्य रूप से लघु सिंचाई), मृदा संरक्षण, पशुपालन, मछलीपालन (Fishery), वानिकी, कृषि उत्पादों के लघु प्रसंस्करण, लघु और कुटीर उद्योगों, स्थानीय स्तर के बुनियादी ढाँचे के निर्माण और विकास से संबंधित एक कार्य उन्मुख योजना है। सामाजिक सेवाएँ जैसे जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, आश्रय, स्वच्छता, स्थानीय परिवहन और कल्याण योजनाएँ (Welfare Schemes)। ब्लॉक स्तरीय योजना की पूरी प्रक्रिया सात चरणों से होकर गुजरती है। इसमे शामिल हैं—

(i) पहचान चरण
(ii) संसाधन सूची चरण योजना निर्माण चरण
(iii) रोजगार योजना चरण
(iv) क्षेत्रीय या लेआउट योजना चरण
(v) क्रेडिट योजना चरण
(vii) एकीकरण और कार्यान्वयन चरण (Integration and Implemententation step)

ऐसी योजना के मुख्य उद्देश्यों में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कौशल का निर्माण, उत्पादकता में सुधार और स्थानीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग शामिल है। इस प्रकार ऐसी योजना का मुख्य फोकस (Focus) लक्ष्य समूह की पहचान, रोजगार पैदा करने के लिए विकास योजनाओं की शुरूआत, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाना और समाज के कमजोर वर्ग (Vulnerable Class) के लिए विशेष कार्यक्रमों का कार्यान्वयन है।

ब्लॉक स्तरीय योजना के उद्देश्य

ब्लॉक योजना के उद्देश्य, जहाँ तक संभव हो, राष्ट्रीय योजना लक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिए। ब्लॉक स्तरीय योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(i) क्षेत्र में इष्टतम विकास और सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से, विशेषकर गरीबों के रोजगार और आय (Income) में वृद्धि
(ii) विकास से प्राप्त लाभ का इस प्रकार वितरण करना कि वे कमजोर वर्गों, अर्थात् सीमांत किसानों (Marginal Farmers), खेतिहर मजदूरों आदि तक पहुँचें।
(iii) क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढाँचे का निर्माण
(iv) न्यूनतम आवश्यकता और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता और पहुँच बढ़ाना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुँच का विस्तार करना
(v) क्षेत्र में गरीबों और कमजोर लोगों के हितों की रक्षा के लिए संस्थानों/संगठनों का निर्माण करना प्रौद्योगिकी को उन्नत करना, उत्पादकता बढ़ाना और कौशल निर्माण में योगदान देना
(vi) क्षेत्र की विकास संभावनाओं का अधिकतम उपयोग
(vii) बेरोजगारी की समस्या का समाधान
(viii) स्व रिलायंस
(ix) सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करना

TOUCH 'n PASS

पंचायत स्तरीय योजना
(Panchayat Level Planning)

पंचायत राज प्रणाली में तीन स्तरीय संरचना शामिल है: ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर पहला स्तर आमतौर पर ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) के रूप में जाना जाता है, ब्लॉक स्तर पर दूसरा स्तर पंचायत समिति के रूप में और जिला स्तर पर तीसरा स्तर जिला परिषद के रूप में जाना जाता है।

पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायत (जिसे ग्राम सभा भी कहा जाता है) को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन की देखभाल के लिए अधिकृत किया गया है। संबंधित राज्य को ग्राम सभा को स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ और कार्य निर्धारित करने की विवेकाधीन (Discretionary) शक्तियाँ दी गई हैं।

पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले के लिए एक एकीकृत विकास योजना तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन करने की भी सलाह दी गई है। हर पाँच साल में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्य और पंचायतों के बीच राजस्व के वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत और अनुदान के निर्धारण के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन करने का भी निर्देश दिया गया है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता।

पंचायत स्तर पर योजना का कार्यान्वयन ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) और सचिव की जिम्मेदारी है और इसकी निगरानी ग्राम सभा द्वारा की जाती है। मौजूदा प्रावधानों के तहत, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) और जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) आदि जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को निष्पादित करने के लिए ग्राम सभा (ग्राम पंचायत) को सीधे केंद्र से धन आवंटित किया जा रहा है।

पंचायत को कृषि, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने, चिकित्सा राहत, मातृत्व, महिला और बाल कल्याण, सामान्य चरागाहों के रखरखाव, गाँव की सड़कों, टैंकों, कुओं, स्वच्छता और अन्य सामाजिक-आर्थिक कार्यों के कार्यान्वयन (Implementation) की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कार्यक्रम—कुछ स्थानों पर, वे प्राथमिक शिक्षा की देखरेख और भू-राजस्व एकत्र करने के लिए भी अधिकृत हैं। वर्तमान में, ग्राम पंचायतें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में लाभार्थियों की पहचान में शामिल देश में लगभग 2.20 लाख ग्राम पंचायतें, 5,300 पंचायत समितियाँ और 400 जिला परिषदें हैं।

यह पाया गया है कि पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि विकास के मुद्दों के राजनीतिक और आर्थिक आयामों से काफी हद तक अनभिज्ञ हैं और उनमें योजना और प्रबंधकीय कौशल की कमी है।

केंद्रीकृत योजना के विपरीत बहु-स्तरीय योजना एक ऐसा अभ्यास है जहाँ स्थानीय संस्थान न केवल कार्यान्वयन स्तर पर सक्रिय रूप से शामिल होते हैं बल्कि एमएलपी एक अधिक एकीकृत प्रयास है जो योजना प्रक्रिया में प्रशासनिक, भौगोलिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय स्तरों के सभी पदानुक्रमों को शामिल करना चाहता है। यह सूचना सृजन, डेटा संग्रह, नीति सुझाव, योजना कार्यान्वयन और सभी विकासात्मक गतिविधियों की निगरानी में निचले पदानुक्रमित स्तरों की सक्रिय भागीदारी को शामिल करना चाहता है।

एक नियोजन प्रक्रिया या तो एकल स्तरीय या बहुस्तरीय हो सकती है। एकल स्तरीय नियोजन में योजनाओं का निर्माण एवं निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है; प्रक्रिया केंद्रीकृत है और निचले क्षेत्रीय स्तर केवल कार्यान्वयन चरण में ही सामने आते हैं। दूसरी ओर, बहु-स्तरीय योजना प्रक्रिया में, राष्ट्रीय क्षेत्र को छोटी क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित किया जाता है, उनकी संख्या देश के आकार, प्रशासनिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक सेटिंग्स के आधार पर होती है। पंचायत को निम्नलिखित जिम्मेदारी भी सौंपी गई हैं।

(i) कृषि को बढ़ावा देना
(ii) ग्रामीण उद्योग
(iii) चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान
(iv) मातृत्व, महिला एवं बाल कल्याण
(v) सामान्य चरागाहों, गाँव की सड़कों, तालाबों, कुओं को बनाए रखना
(vi) स्वच्छता
(vii) अन्य सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
(viii) गरीबी निवारण कार्यक्रम।

TOUCH 'n PASS

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. भारत में आर्थिक नियोजन कब अपनाया गया?
(क) 1947-48 (ख) 1950-51 (ग) 1952-53 (घ) 1955-56
उत्तर (ख) 1950-51

प्र.2. बारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था?
(क) 2007-12 (ख) 2009-14 (ग) 2011-16 (घ) 2012-17
उत्तर (घ) 2012-17

प्र.3. भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य रहा–
(क) आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करना (ख) आर्थिक असमानताओं को कम करना
(ग) रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.4. भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी–
(क) ग्यारहवीं (ख) बारहवीं (ग) तेरहवीं (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) बारहवीं

प्र.5. नीति आयोग का गठन कब किया गया?
(क) 1 जनवरी, 1950 (ख) 1 जनवरी, 1991 (ग) 1 जनवरी, 2015 (घ) 1 जनवरी, 2020
उत्तर (ग) 1 जनवरी, 2015

प्र.6. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है?
(क) नीति आयोग (ख) भारत के राष्ट्रपति (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद (घ) वित्त मंत्रालय
उत्तर (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद

प्र.7. भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था?
(क) बुनियादी ढाँचे का विकास (ख) बंदरगाहों का विकास
(ग) उद्योगों का विकास (घ) कृषि का विकास
उत्तर (घ) कृषि का विकास

प्र.8. राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है?
(क) उपराष्ट्रपति (ख) आरबीआई गवर्नर (ग) गृह मंत्री (घ) प्रधानमंत्री
उत्तर (घ) प्रधानमंत्री

प्र.9. भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारम्भ हुई?
(क) 1951 (ख) 1952 (ग) 1949 (घ) 1950
उत्तर (क) 1951

प्र.10. राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी–
(क) 1952 (ख) 1971 (ग) 1958 (घ) 1964
उत्तर (क) 1952

प्र.11. नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने निम्नलिखित में से किस आयोग का स्थान लिया?
(क) लोक सेवा आयोग (ख) सिविल सेवा आयोग (ग) चुनाव आयोग (घ) योजना आयोग
उत्तर (घ) योजना आयोग

प्र.12. नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
(क) प्रधानमंत्री (ख) गृह मंत्री (ग) भारत के राष्ट्रपति (घ) वित्त मंत्री
उत्तर (क) प्रधानमंत्री

TOUCH 'n' PASS

प्र.13. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था–
(क) क्षेत्रीय असंतुलन का उन्मूलन (ख) भोजन, कार्य और उत्पादकता
(ग) सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास (घ) गरीबी उन्मूलन
उत्तर (ग) सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास

प्र.14. वार्षिक योजना की अवधि है–
(क) 1964-66 से 1967-69 तक (ख) 1966-67 से 1968-69 तक
(ग) 1962-65 से 1966-68 तक (घ) 1960-64 से 1967-68 तक
उत्तर (ख) 1966-67 से 1968-69 तक

प्र.15. बारहवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक दर कितनी रही?
(क) 6.4 प्रतिशत (ख) 6.5 प्रतिशत (ग) 6.6 प्रतिशत (घ) 6.7 प्रतिशत
उत्तर (घ) 6.7 प्रतिशत

प्र.16. योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे?
(क) श्री आरपी सिन्हा (ख) श्री श्यामल घोष
(ग) श्री विनय कोहली (घ) श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया
उत्तर (घ) श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया

प्र.17. योजना आयोग की स्थापना कब हुई?
(क) 1948 (ख) 1949 (ग) 1950 (घ) 1951
उत्तर (ग) 1950

प्र.18. 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया?
(क) नीति आयोग (ख) स्टैंड अप इंडिया योजना
(ग) नाबार्ड (घ) सेबी
उत्तर (क) नीति आयोग

प्र.19. नीति आयोग का क्या तात्पर्य है?
(क) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत (ख) भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान
(ग) प्रौद्योगिकी भारत के लिए राष्ट्रीय हित (घ) भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय हित
उत्तर (ख) भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान

प्र.20. प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की?
(क) जवाहर लाल नेहरू (ख) लाल बहादुर शास्त्री (ग) श्रीमती इंदिरा गांधी (घ) जोसेफ स्टालिन
उत्तर (घ) जोसेफ स्टालिन

प्र.21. प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी?
(क) 1928 (ख) 1922 (ग) 1924 (घ) 1926
उत्तर (क) 1928

प्र.22. भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की?
(क) मोरारजी देसाई (ख) चरण सिंह (ग) जवाहर लाल नेहरू (घ) राजीव गांधी
उत्तर (ग) जवाहर लाल नेहरू

प्र.23. प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था?
(क) सेवा क्षेत्र का विकास (ख) प्राथमिक क्षेत्र का विकास
(ग) कृषि क्षेत्र का विकास (घ) इनमे से कोई भी नहीं
उत्तर (ख) प्राथमिक क्षेत्र का विकास

TOUCH 'n' PASS

प्र.24. प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था?

(क) समग्र उत्पादन फलन (ख) बुनियादी विकास मॉडल
(ग) हैरोड-डोमर मॉडल (घ) नव-शास्त्रीय विकास मॉडल

उत्तर (ग) हैरोड-डोमर मॉडल

प्र.25. प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था?

(क) वित्त का विकास (ख) प्रौद्योगिकी का विकास
(ग) द्वितीयक क्षेत्र का विकास (घ) कृषि का विकास

उत्तर (घ) कृषि का विकास

प्र.26. प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था?

(क) विभाजन के बाद देश का पुनर्निर्माण करें (ख) उद्योग एवं कृषि को बढ़ावा देना
(ग) सस्ती स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.27. निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी?

(क) भाखड़ा (ख) चिनाब (ग) भीम (घ) चंबल

उत्तर (क) भाखड़ा

प्र.28. प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई थी?

(क) भारतीय विज्ञान संस्थान (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
(ग) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (घ) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

उत्तर (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

प्र.29. प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया था?

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद (घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

उत्तर (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

प्र.30. दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था?

(क) सिंचाई (ख) सेवा क्षेत्र (ग) सार्वजनिक क्षेत्र (घ) कृषि

उत्तर (ग) सार्वजनिक क्षेत्र

प्र.31. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया?

(क) रोमर विकास मॉडल (ख) शास्त्रीय मॉडल
(ग) उत्पादन संभावना फ्रंटियर (घ) महालनोबिस मॉडल

उत्तर (घ) महालनोबिस मॉडल

प्र.32. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी?

(क) आर्थिक विकास संस्थान
(ख) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च
(ग) आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र
(घ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-इंटीग्रेटिव मेडिसिन का भारतीय।

उत्तर (ख) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च

प्र.33. किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ?

(क) पहला (ख) दूसरा (ग) तीसरा (घ) चौथी

उत्तर (ग) तीसरा

TOUCH 'n' PASS

प्र.34. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन-से वर्ष योजनागत अवकाश थे?

(क) 1966-1969 (ख) 1965-1968 (ग) 1967-1970 (घ) 1964-1967

उत्तर (क) 1966-1969

प्र.35. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में योजना अवकाशों को क्रियान्वित करने का कारण नहीं था?

(क) युद्ध (ख) संसाधनों की कमी

(ग) महँगाई में वृद्धि (घ) आयात में वृद्धि

उत्तर (घ) आयात में वृद्धि

प्र.36. चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?

(क) इंदिरा गाँधी (ख) नरेंद्र मोदी

(ग) मनमोहन सिंह (घ) अटल बिहारी वाजपेयी

उत्तर (क) इंदिरा गाँधी

प्र.37. चौथी योजना के दौरान कौन-सी कृषि पहल लागू की गई थी?

(क) ई-NAM (ख) सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन

(ग) हरित क्रांति (घ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

उत्तर (ग) हरित क्रांति

प्र.38. चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन-सा युद्ध हुआ?

(क) कारगिल युद्ध (ख) भारत-पाकिस्तान युद्ध

(ग) बांग्लादेश मुक्ति संग्राम (घ) (क) और (ख) दोनों

उत्तर (घ) (क) और (ख) दोनों

प्र.39. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था?

(क) गरीबी निर्मूलन (ख) औद्योगीकरण (ग) रक्षा (घ) कृषि

उत्तर (क) गरीबी निर्मूलन

प्र.40. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार कर दिया?

(क) वीपी सिंह (ख) मोरारजी देसाई

(ग) चन्द्रशेखर (घ) पीवी नरसिम्हा राव

उत्तर (ख) मोरारजी देसाई

❑

TOUCH 'n' PASS

- यद्यपि इस पुस्तक को यथासम्भव शुद्ध एवं त्रुटिरहित प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया गया है, तथापि इसमें कोई कमी अथवा त्रुटि अनिच्छाकृत ढंग से रह गई हो तो उससे कारित क्षति अथवा सन्ताप के लिए लेखक, प्रकाशक तथा मुद्रक का कोई दायित्व नहीं होगा। सभी विवादित मामलों का न्यायक्षेत्र मेरठ न्यायालय के अधीन होगा।
- इस पुस्तक में समाहित सम्पूर्ण पाठ्य-सामग्री (रेखा व छायाचित्रों सहित) के सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन हैं। अतः कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक का नाम, टाइटिल-डिजाइन तथा पाठ्य-सामग्री आदि को आंशिक या पूर्ण रूप से तोड़-मरोड़कर प्रकाशित करने का प्रयास न करें, अन्यथा कानूनी तौर पर हर्जे-खर्चे व हानि के जिम्मेदार होंगे।
- इस पुस्तक में रह गई तथ्यात्मक त्रुटियों तथा अन्य किसी भी कमी के लिए विद्वत् पाठकगण से भूल-सुधार/सुझाव एवं टिप्पणियाँ सादर आमन्त्रित हैं। प्राप्त सुझावों अथवा त्रुटियों का समायोजन आगामी संस्करण में कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के भूल-सुधार/सुझाव आप info@vidyauniversitypress.com पर भी ई-मेल कर सकते हैं।